

अंतर्वस्तु

- ❖ सामग्री की तालिका
- ❖ तालिकाओं की सूची
- ❖ चित्रों की सूची
- ❖ नक्शों की सूची
- ❖ लघुरूप
- ❖ शब्दावली
- ❖ कार्यकारी सार
- ❖ मुख्य रिपोर्ट

तालिका सूची

1	विस्तृत परियोजना ब्यौरा.....	27
1.1	परियोजना की पृष्ठभूमि	27
1.1.1	अंतर राज्य/अंतर्राष्ट्रीय पहलू.....	27
1.1.2	डेवलपर/ विकासकर्ता की पृष्ठभूमि	28
1.2	परियोजना का मूल आधार	29
1.3	परियोजना विवरण	30
1.3.1	परियोजना का आकार.....	30
1.3.2	अवस्थान	35
1.3.3	क्षमता और उत्पाद.....	38
1.3.4	परियोजना लागत व जोखिम का ब्यौरा.....	41
1.4	अनुकल्पों की परीक्षा	43
1.5	परियोजना के सन्निर्माण की अवस्थाये	44
1.6	मूल डिजाइन की विशिष्टिया और आकर तथा सुविधाओं का प्रकार	45
1.6.1	नदी का डायवर्सन कार्य	45
1.6.2	बांध	45
1.6.3	प्रवेश संरचना	45
1.6.4	दबाव दस्ता/शाफ्ट	46
1.6.5	पावर हाउस और ट्रांसफार्मर हॉल.....	46
1.6.6	टेल रेस टनल और आउटफॉल स्ट्रक्चर	46
1.6.7	एक्सेस टनल.....	46
1.6.8	मुख्य प्रवेश सुरंग.....	47

1.7	सहायक अवसंरचनात्मक सुविधाओं की आवश्यकता.....	47
1.8	कार्यबल अपेक्षाएं.....	47
1.9	पर्यावरण समाघात निर्धारण का ब्यौरा एवम तकनीकी साध्यता रिपोर्ट.....	48
1.10	लागू किये गए विधान और नीतियां.....	48
1.10.1	सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की तैयारी.....	48
1.10.2	भूमि अर्जन की प्रक्रिया.....	48
1.10.3	भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम, 2013 में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार	49
1.10.4	हिमाचल प्रदेश RTFCTLARR नियम 2015.....	50
2	दल संरचना, दृष्टिकोण, प्रणाली एवं सामाजिक समाघात निर्धारण की अनुसूची.....	54
2.1	दल विवरण.....	54
2.2	प्रयुक्त पद्धति और उपकरण का विवरण व औचित्य.....	55
2.2.1	लक्ष्य.....	55
2.2.2	उद्देश्य.....	55
2.2.3	दृष्टिकोण और पद्धति.....	56
2.2.4	पद्धति का औचित्य.....	58
2.3	सामाजिक समाघात निर्धारण के लिए सूचना संग्रहण करने के लिए संसाधन.....	59
2.4	नमूना प्रणाली का उपयोग.....	63
2.5	सूचना अथवा डाटा स्रोतों के प्रयोग का पर्यवलोकन.....	64
2.6	प्रमुख पणधारियों के साथ परामर्श और की गई लोक सुनवाई के संक्षिप्त विचरण की अनुसूची.....	71
3	भूमि निर्धारण.....	72
3.1	भूमि तालिका की सूचना और प्राथमिक स्रोतों से जानकारी.....	72
3.2	परियोजना के प्रभावों के आधीन पूर्ण समाघात शेत्र.....	75
3.3	परियोजना के लिए भूमि की आवश्यकता.....	76

3.4	परियोजना के लिए आवश्यक भूमि के उपयोग हेतु प्रस्तावित पहले से ही खरीदी गई भूमि, अलग-अलग, लीज़ / अर्जित और प्रत्येक भूखंड के लिए प्रस्तावित उपयोग	77
3.5	परियोजना के लिए अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि की मात्रा और स्थान	79
3.6	भूमि का वर्तमान उपयोग ,प्रकृति, और वर्गीकरण	82
3.7	सिंचाई क्रम	83
3.8	जोत / भूमि का आकार, स्वामित्व पैटर्न	84
3.9	भूमि वितरण और आवासीय मकानों की संख्या	86
3.10	भूमि की कीमतें और हाल ही में स्वामित्व और हस्तांतरण में परिवर्तन	87
4	प्रभावित परिवारों और आस्तियों का अनुमान और गणना	96
4.1	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित व्यक्ति	96
4.1.1	किराएदार / व्यवसायी	98
4.1.2	जनजाति और पारंपरिक वन निवासी	98
4.1.3	सामान्य संपत्ति संसाधनों पर निर्भरता	98
4.1.4	राज्य सरकार द्वारा दी गई भूमि	99
4.1.5	आजीविका के लिए भूमि पर निर्भरता	99
4.2	उत्पादक आस्तियों और महत्वपूर्ण भूमि की सूची	99
5	सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक प्रोफाइल	101
5.1	परियोजना गांवों में जनसंख्या का जनसांख्यिकीय विवरण	102
5.1.1	परियोजना प्रभावित लोगों का जनसांख्यिकीय विवरण	103
5.1.2	लिंग अनुपात	105
5.1.3	सामाजिक समूह	107
5.1.4	साक्षरता	110
5.2	आर्थिक प्रोफाइल	112
5.2.1	मुख्य कार्य जनसंख्या	113

5.2.2	सीमांत श्रमिक.....	115
5.2.3	गैर-कार्यशील जनसंख्या.....	117
5.3	आय और गरीबी स्तर	118
5.4	दुर्बल समूह.....	118
5.5	भूमि उपयोग और आजीविका	120
5.6	स्थानीय आर्थिक गतिविधियाँ	123
5.7	ऐसे कारक जो स्थानीय आजीविका में योगदान करते हैं.....	124
5.8	रिश्तेदारी पद्धति.....	126
5.9	प्रशासनिक, राजनीतिक और नागरिक समाज संगठन	126
5.10	क्षेत्रीय गतिशीलता और ऐतिहासिक परिवर्तन प्रक्रियाएं.....	127
5.11	जीवंत पर्यावरण की गुणवत्ता	128
6	सामाजिक प्रभाव	129
6.1	प्रभावों की पहचान करने के लिए रूपरेखा और दृष्टिकोण.....	129
6.2	परियोजना के विभिन्न चरणों में प्रभावों का विवरण	130
6.3	प्रभाव क्षेत्रों की सांकेतिक सूची.....	134
6.3.1	भूमि मालिकों पर प्रभाव.....	134
6.3.2	आजीविका और आय पर प्रभाव	135
6.3.3	भौतिक संसाधनों पर प्रभाव.....	136
6.3.4	जैव विविधता और पर्यावरण पर प्रभाव.....	138
6.3.5	सार्वजनिक सेवाओं और उपयोगिताओं पर प्रभाव.....	138
6.3.6	स्वास्थ्य, संस्कृति और सामाजिक सामंजस्य पर प्रभाव.....	140
6.3.7	लिंग आधारित प्रभाव.....	140
6.4	PAPs द्वारा प्रभावित के रूप में प्रभाव का अनुमान	142
6.5	सुन्नी बांध जल विद्युत् परियोजना के बारे में जागरूकता.....	147

6.6	परियोजना के लिए सहमति	148
6.7	प्रतिकर वरीयताएँ	148
6.8	प्राप्त नकद प्रतिकर का उपयोग	149
7	अर्जन पर लागत और लाभ और सिफारिशों का विश्लेषण.....	150
7.1	लोक प्रयोजन का आकलन	150
7.2	कम विस्थापन विकल्प और न्यूनतम भूमि की आवश्यकता.....	151
7.3	सामाजिक प्रभावों की प्रकृति और तीव्रता	152
7.4	सुझाये गये शमन उपाय की व्यवहार्यता.....	155
7.4.1	अंतिम सिफारिश	157
8	सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना.....	158
8.1	कमी करने पर दृष्टीकोण	158
8.2	समाघात से बचने, कम करने और प्रतिपूर्ति करने के उपाय	158
8.2.1	सामाजिक उपाय.....	158
8.2.2	आधारिक संरचनाओं के उपाय	159
8.2.3	पुनर्वास व पुनर्व्यवस्थापन के उपाय	162
8.2.4	पर्यावरण उपाय	164
8.2.5	अन्य उपाय	166
8.3	R&R और अधिनियम 2013 में शामिल उपाय.....	167
8.4	SIMP कार्यान्वयन का व्यय.....	172
8.5	आवश्यक निकाय द्वारा दिए गए उपाय.....	181
8.6	पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन योजना के कार्यान्वयन के लिए संस्थागत व्यवस्था.....	181
8.7	शिकायत निवारण समिति (G.R.C).....	181
8.1	183
8.2	183

8.3	183
8.4	183
8.5	183
8.6	183
8.7	183
8.7.1	शिकायत निवारण के चरण.....	183
9	सन्दर्भ	187
10	अनुलग्नक	188

तालिकाओं की सूची

तालिका 1-1: परियोजना का आकर.....	31
तालिका 1-5: परियोजना लागत का अनुमान.....	42
तालिका 1-6: डैम ब्लॉकों का विवरण.....	45
तालिका 3-4: अर्जित भूमि का उपयोग.....	77
तालिका 3-6 : अर्जन के तहत भूमि का वर्तमान उपयोग.....	82
तालिका 3-7: अर्जन के तहत भूमि का सिचाई क्रम.....	83
तालिका 3-8: होल्डिंग/स्वामित्व आकार और पैटर्न.....	84
तालिका 3-9: स्वामित्व का पैटर्न.....	85
तालिका 3-11: भूमि वितरण और आवासीय घरों की संख्या.....	86
तालिका 4-1: परियोजना से सीधे प्रभावित लोग (PAPs).....	96
तालिका 5-1: परियोजना क्षेत्र का जनसांख्यिकीय विवरण.....	102
तालिका 5-15: परियोजना क्षेत्र में भूमि का उपयोग.....	120
तालिका 5-16: परियोजना क्षेत्र में प्रमुख फसलें.....	121

चित्रों की सूची

चित्र 1-1: एस.जे.वि.एन.: संगठनात्मक संरचना.....	29
चित्र 2-1: प्राथमिक सर्वेक्षण के दौरान ली गई तसवीरें.....	61
चित्र 2-2: केन्द्रित समूह चर्चा के दौरान ली गई तसवीरें.....	62
चित्र 5-1: परियोजना क्षेत्रों में सेक्स-वार वितरण.....	103
चित्र 5-2: परियोजना क्षेत्र में साक्षरता की स्थिति.....	111
चित्र 5-3: परियोजना से प्रभावित लोगो की वार्षिक घरेलू आय.....	118
चित्र 5-4: परियोजना प्रभावित लोगो द्वारा उगाई जाने वाली मुख्या फसलें.....	122

सुन्नी बांध जल विद्युत् परियोजना (382 MW) के लीये की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

लघुरूप

BPL	गरीबी रेखा से नीचे
CA	चार्टर्ड एकाउंटेंट
CHC	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र
CPRs	ससमुदायिक संपत्ति संसाधन
CS	कंपनी सचिव
CWC	केन्द्रीय जल आयोग
EIA	पर्यावरण प्रभाव आकलन
FC	वित्तीय शुल्क
FRL	पूर्ण जलाशय स्तर
GSI	भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण
HEP	जल विद्युत् परियोजना
H.P RTFCTLARR Rules	हिमाचल प्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनार्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (सामाजिक समाघात निर्धारण और सहमति) नियम, 2015
HPS	हाइड्रो पावर स्टेशन
SIAU	सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई
HR	मानव संसाधन
IDC	निर्माण के दौरान ब्याज
IPH	सिंचाई और जन स्वास्थ्य विभाग
L 2	स्तर 2 स्वास्थ्य सुविधा
L 3	स्तर 3 स्वास्थ्य सुविधा
LADF	स्थानीय क्षेत्र विकास निधि
LHEP	लुहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट
NGO	गैर सरकारी संगठन
NHM	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
OBC	अन्य पिछड़ी जातियां
PAFs	परियोजना प्रभावित परिवार
PAPs	परियोजना विस्थापित परिवार
PDFs	परियोजना विस्थापित परिवार
PHC	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र
PMAY	प्रधानमंत्री आवास योजना
PWD	लोक निर्माण विभाग

सुन्नी बांध जल विद्युत् परियोजना (382 MW) के लीये की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

RTFCTLARR Act	भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013
R&R	पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन
SC	अनुसूचित जाति
SIA	सामाजिक समाघात निर्धारण
SIMP	सामाजिक समाघात प्रबंध योजना
SJVN	सतलुज जल विद्युत निगम
ST	अनुसूचित जनजाति
TRT	टेल रेस सुरंग

शब्दावली

- ❖ **अधिनियम** का अर्थ है: भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनार्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम संख्या 30)।
- ❖ **प्रशासक** का अर्थ है, अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और पुनार्व्यस्थापन के उद्देश्य से नियुक्त एक अधिकारी।
- ❖ **प्रभावित क्षेत्र** का मतलब ऐसे क्षेत्र से है, जिन्हें भूमि अर्जन के उद्देश्यों के लिए उपयुक्त सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है।
- ❖ **प्रभावित परिवार में शामिल हैं:**
 - i. एक परिवार जिसकी भूमि या अन्य अचल संपत्ति का अर्जन किया गया है।
 - ii. ऐसा परिवार जिसके पास कोई जमीन नहीं है, लेकिन ऐसे परिवार के सदस्य (सदस्य) शायद खेतिहर मजदूर, किरायेदारों के किसी भी रूप में या सूदखोरी का अधिकार रखने वाले, कारीगरों के प्रति शेयर-फसल या जो प्रभावित क्षेत्र में काम कर रहे हों, तीन वर्ष, भूमि के अर्जन से पहले, जिसका आजीविका का प्राथमिक स्रोत भूमि के अर्जन से प्रभावित होता है।
 - iii. अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी जिन्होंने भूमि के अर्जन के कारण अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2 का 2007) के तहत मान्यता प्राप्त अपने किसी भी वन अधिकार को खो दिया है।
 - iv. परिवार जिसका अर्जन से पहले तीन वर्षों के लिए आजीविका का प्राथमिक स्रोत जंगलों या जल निकायों पर निर्भर है और इसमें वन उपज, शिकारी, फिशर लोक और नाव के आदमी शामिल हैं और भूमि के अर्जन के कारण ऐसी आजीविका प्रभावित होती है।
 - v. परिवार का कोई सदस्य जिसे राज्य सरकार या केंद्र सरकार ने अपनी किसी भी योजना के तहत जमीन सौंपी हो और ऐसी जमीन अर्जन के तहत हो।
 - vi. शहरी क्षेत्रों में किसी भी भूमि पर रहने वाले परिवार को भूमि के अर्जन से पहले तीन साल या उससे अधिक समय के लिए रहने की अनुमति या भूमि के अर्जन से पहले तीन साल तक आजीविका का प्राथमिक स्रोत ऐसी भूमि के अर्जन से प्रभावित होता है।

❖ **कृषि भूमि का अर्थ है:**

- i. कृषि या बागवानी।
- ii. डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, पिप्पी कल्चर, सेरीकल्चर, सीड फार्मिंग ब्रीडिंग ऑफ मवेशी या नर्सरी उगाने वाली औषधीय जड़ी-बूटियाँ।
- iii. फसलों, पेड़ों, घास या बगीचे की उपज का उत्पादन; तथा
- iv. पशुओं के चरने के लिए प्रयुक्त भूमि।

❖ **गरीबी रेखा से नीचे या BPL परिवार** भारत के योजना आयोग द्वारा परिभाषित गरीबी रेखा से नीचे गिरने वाले परिवारों को संदर्भित करता है, साथ ही समय-समय पर हिमाचल प्रदेश की BPL सूची में शामिल लोगों को भी शामिल करता है।

❖ **केंद्र सरकार** भारत सरकार को संदर्भित करती है।

❖ **कलेक्टर** का अर्थ एक राजस्व जिले का कलेक्टर होता है, और इसमें एक डिप्टी कमिश्नर और विशेष रूप से उपयुक्त सरकार द्वारा नामित कोई भी अधिकारी शामिल होता है, जो अधिनियम 2013 के तहत कलेक्टर के कार्य करता है।

❖ **आयुक्त** का मतलब अधिनियम 2013 की धारा 44 की उप-धारा (1) के तहत नियुक्त पुनर्वास और पुनर्वास के लिए आयुक्त से है।

❖ **प्रतिकर** अधिनियम, 2013 के विभिन्न प्रावधानों के तहत प्रतिकर के रूप में दी जाने वाली राशि को संदर्भित करता है, निजी संपत्ति, संरचनाओं और परियोजना के लिए अर्जित अन्य संपत्तियों के लिए, जिनमें पुनर्वास और पुनर्वास अधिकार शामिल हैं।

❖ **अर्जन की लागत में शामिल हैं:**

- i. प्रतिकर की राशि, जिसमें इतना सोलाशियम शामिल है, भूमि अर्जन और पुनर्वास और पुनर्वास प्राधिकरण या न्यायालय द्वारा आदेशित किसी भी बढ़ाया प्रतिकर और इस तरह या अदालत द्वारा प्रभावित परिवारों को देय के रूप में निर्धारित किसी भी अन्य राशि पर दिया ब्याज।
- ii. अर्जन की प्रक्रिया में भूमि और खड़ी फसलों को नुकसान लागत के लिए भुगतान किए

जाने की मांग।

- iii. विस्थापित या प्रतिकूल रूप से प्रभावित परिवारों के निपटान के लिए भूमि और भवन के अर्जन की लागत।
 - iv. पुनर्वास क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के विकास की लागत।
 - v. एक्ट 2013 के अंतर्गत पुनर्वास व पुनर्स्थापन के खर्चों के प्रावधान।
 - vi. प्रशासनिक लागत:
 - क) भूमि अर्जन के लिए, परियोजना स्थल और परियोजना क्षेत्र की भूमि से बाहर दोनों सहित, प्रतिकर की लागत के ऐसे प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए जो उपयुक्त सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।
 - ख) मालिक के पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन के लिए इसलिए भूमि और अन्य प्रभावित परिवार जिनकी भूमि का अर्जन किया गया है या अर्जन किया जाना प्रस्तावित है या ऐसे अर्जन से प्रभावित अन्य परिवार हैं।
 - vii. SIA स्टडी लेने के तहत लागत।
- ❖ **विस्थापित परिवार** का मतलब किसी भी परिवार से है, जो जमीन के अर्जन के कारण प्रभावित क्षेत्र से हटाकर पुनर्वास क्षेत्र में बसाया जाना है।
 - ❖ **परिवार** में एक व्यक्ति, उसके पति या पत्नी, नाबालिक बच्चे, नाबालिक भाई और उस पर निर्भर नाबालिक बहनें शामिल हैं:
बशर्ते परिवारों द्वारा निर्जन विधवाओं, तलाकशुदा और महिलाओं को अलग परिवार माना जाएगा।
 - ❖ **भूमि** में भूमि से उत्पन्न होने वाले लाभ शामिल हैं, और पृथ्वी से जुड़ी चीजें या स्थायी रूप से पृथ्वी से जुड़ी किसी भी चीज के लिए उपवास किया गया है।
 - ❖ **भूमि अर्जन** का मतलब भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम, 2013 में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता के अधिकार के तहत भूमि का अर्जन है।
 - ❖ **भूमिहीन** का अर्थ है ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग जो हो सकते हैं:
लागू होने के समय के लिए किसी भी राज्य कानून के तहत माना या निर्दिष्ट; या भूमिहीन के एक मामले में खंड (i) के तहत निर्दिष्ट नहीं किया जा सकता है, जैसा कि उपयुक्त सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।

❖ **भूमि स्वामी** में कोई भी व्यक्ति शामिल है-

- (i) जिसका नाम दर्ज किया गया है वह संबंधित प्राधिकारी के रिकॉर्ड में भूमि या भवन का मालिक है या वहां का हिस्सा है; या
- (ii) कोई भी व्यक्ति जिसे अनुसूचित अनुसूचित जनजाति पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 की अधिनियम संख्या 2) या किसी अन्य कानून के तहत वन अधिकार प्रदान किया जाता है; या
- (iii) राज्य के किसी भी कानून के तहत भूमि पर पट्टा अधिकार दिए जाने का हकदार कौन है, जिसमें निर्दिष्ट भूमि या शामिल हैं
- (iv) कोई भी व्यक्ति जिसे न्यायालय या प्राधिकरण के आदेश के अनुसार घोषित किया गया हो;

❖ **सीमांत किसान** का अर्थ है, एक हेक्टेयर से सिंचित भूमि या एक हेक्टेयर तक सिंचित भूमि के साथ एक किसान।

❖ **बाजार मूल्य** का अर्थ है धारा 26 क के अनुसार भूमि निर्धारण का मूल्य अधिनियम 2013।

❖ **अधिसूचना** का अर्थ है भारत के राजपत्र में प्रकाशित एक अधिसूचना या, जैसा कि मामला हो सकता है, एक राज्य का राजपत्र और अभिव्यक्ति "अधिसूचित" तदनुसार निर्धारित की जाएगी।

❖ **परियोजना** का अर्थ है सुन्नी बांध जल विद्युत् परियोजना (382MW)।

❖ **लोक प्रयोजन** का अर्थ है, धारा 2 एक्ट 2013 की उप-धारा (1) के तहत निर्दिष्ट गतिविधियाँ।

❖ **पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन (R & R)** का अर्थ है RFCTLARR अधिनियम 2013 के अनुसार पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन।

❖ अपेक्षित निकायका मतलब सतलुज जल विद्युत् निगम (SJVNL) लिमिटेड है।

❖ **अनुसूचित क्षेत्र** का अर्थ अनुसूचित क्षेत्रों से है जैसा कि पंचायतों के प्रावधानों (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 (1996 का 40) के प्रावधानों 2 में परिभाषित किया गया है।

❖ **छोटे किसान** का अर्थ है, दो हेक्टेयर तक की नन-सिंचित भूमि के साथ या एक हेक्टेयर तक की सिंचित भूमि के साथ एक किसान, लेकिन सीमांत किसान की जोत से अधिक।

❖ **सामाजिक समाघात निर्धारण** का मतलब अधिनियम की धारा 4 के उपधारा (1) के तहत किया गया मूल्यांकन है।

- ❖ **सामाजिक समाघात प्रबंध योजना** का अर्थ है अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया के भाग के रूप में तैयार की गई योजना।
- ❖ **राज्य सरकार या “सरकार”** का अर्थ है हिमाचल प्रदेश सरकार
- ❖ **किरायेदार** वे व्यक्ति होते हैं जिनके पास भूमि के अर्जन से पहले तीन साल के लिए बोनाफाइड टेनेंसी समझौते होते हैं, एक संपत्ति के मालिक के पास स्पष्ट संपत्ति खिताब के साथ, निवास, व्यवसाय या अन्य उद्देश्यों के लिए एक संरचना या भूमि पर कब्जा करने के लिए।
- ❖ **दुर्बल समूहों** में अलग-अलग लोगों जैसे कि एक धब्बा, विधवा, और महिलाओं के नेतृत्व वाले घर, साठ साल से अधिक उम्र के व्यक्ति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य समूह शामिल हैं, जो राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट किए जा सकते हैं।
- ❖ **महिला मुखिया सदन की पकड़** का मतलब है कि एक महिला के नेतृत्व वाला परिवार और पुरुष कमाने वाला सदस्य नहीं है। यह महिला एक विधवा, अलग या निर्जन महिला हो सकती है।

कार्यकारी सार

परियोजना और लोक प्रयोजन

सुन्नी डैम हाइड्रो-इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट जिसे लुहरी स्टेज- III के रूप में भी जाना जाता है, नदी प्रवाह प्रकार की 382 मेगावाट योजना है और लुहरी HEP के बहु-चरण विकास का एक हिस्सा है। यह परियोजना रामपुर और कोल डैम¹ जलविद्युत परियोजनाओं के बीच, सतलुज नदी की जल क्षमता का दोहन करने के लिए है।

इस परियोजना में 90% भरोसेमंद वर्ष में 1,369 MU विद्युत ऊर्जा का उत्पादन प्रस्तावित है। सतलुज नदी की जल क्षमता का दोहन करने के लिए सुन्नी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट प्रस्तावित किया गया था। परियोजना में सतलुज नदी के पर नदी के तल से ऊपर ± 71 मीटर ऊंचे बांध और दाएं किनारे पर भूमिगत बिजली घर के निर्माण की परिकल्पना की गई है।

हिमाचल प्रदेश अपनी पांच प्रमुख नदियों में विशाल पनबिजली क्षमता के साथ धन्य है। हिमाचल प्रदेश की सरकार का इरादा इस परियोजना के निर्माण के लिए शिमला जिले के बठोरा , ग्रेहना , कोठी, ओगली, पंदोआ , तलाह , झुंझन, मजरोग, भरारा, जैशी, खेरा, लुनुसु और मालगी गांवों तथा मंडी जिले के बलोग, बेलुढाँक , भौरा, फाफान, जकलीन, खाराली और परलोग गांव में ज़मीन के अर्जन का है।

हिमाचल प्रदेश में पनबिजली ऊर्जा के दोहन के लिए रणनीति का पालन न्यूनतम लागत और न्यूनतम पर्यावरणीय प्रभावों के साथ अधिक से अधिक ऊर्जा का उत्पादन करना है। जलविद्युत क्षमता का तेजी से दोहन निश्चित रूप से राज्य के आर्थिक स्वास्थ्य में सुधार करेगा क्योंकि सभी नए प्रतिष्ठानों पर परियोजना लागत की 12 प्रतिशत मुफ्त बिजली और 1.5% LADF (स्थानीय क्षेत्र विकास निधि), से राज्य के संसाधनों में एक महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। उत्तरी क्षेत्र में बिजली की बढ़ती मांग और बढ़ते ऊर्जा की कमी को पूरा करने के लिए परियोजना की आवश्यकता भी उत्पन्न होती है।

RTFCTLARR अधिनियम, 2013 की धारा 2 उपधारा 1 (बी) के अनुसार, सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना (382 मेगावाट) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए बुनियादी ढांचा परियोजनाओं (ऊर्जा उत्पादन) की परिभाषा के तहत अच्छी तरह से उचित है।

¹(SJVN, 2018)

स्थान /अवस्थिति

प्रस्तावित परियोजना हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी के बेसिन पर स्थित है और इसके बाएं किनारे पर जिला शिमला और जिला मंडी उनके दाहिने किनारे पर है। यह बांध खैरा गाँव (जिला शिमला) के पास देशांतर 77°12'39 "E और अक्षांश 31°14'53" N पर स्थित है।

भूमि अर्जन का आकार और विशेषता

परियोजना के लिए भूमि की कुल आवश्यकता 44,03,889 वर्ग मीटर है। कुल भूमि में से 38,71,915 वर्ग मीटर वन भूमि है और 5,31,974 वर्ग मीटर निजी भूमि है। यह दो जिलों शिमला और मंडी के तहत कोटगढ़ / कुमारसैन, करसोग और शिमला उप मंडलों में तीन तहसील जैसे सुन्नी, कुमारसैन और करसोग के अंतर्गत 9 ग्राम पंचायतों में कुल 20 गांवों को कवर करता है । प्राथमिक सर्वेक्षण के अनुसार 4,683 की कुल आबादी वाले कुल 1,034 परिवार हैं, जिनमें से 1,847 लोग परियोजना के लिए अर्जित की गई जमीन के मालिक हैं।

अर्जित की जा रही भूमि के कुल 1847 शीर्षक धारकों में से, 1045 सम्बंधित खसरे में अपनी भूमि को 100% खो देंगे। अधिकांश PAPs के पास या तो उसी पंचायत या किसी अन्य पंचायत में अतिरिक्त भूमि है। इस प्रकार, उनमें से कोई भी पूरी तरह से उस भूमि पर निर्भर नहीं है जो अर्जित हो रही है, यही वजह है कि उन्होंने प्रतिकर के रूप में नकदी रखना पसंद किया है। PAPs में 93% लोगों ने बताया कि भूमि का शेष भाग अर्जन के बाद भी उपयोग करने योग्य है। PAPs में से 141 अर्जन में अपने घर खो रहे हैं और उन्होंने उसी ग्राम पंचायत में कहीं भी परियोजना सहायता प्राप्त पुनर्वास के लिए मांग की है।

अर्जित की जा रही भूमि और PAPs के बारे में अधिक जानकारी के लिए अध्याय 3 और 4 के तहत विस्तार से चर्चा की गई है।

अनुकल्पो पर विचार

सुन्नी बांध जल विद्युत् परियोजना, लुहरी परियोजना का हिस्सा है, जो तीन चरणों में तीन बाँधों के निर्माण पर विचार करती है। जो लुहरी हाइड्रो-इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्टेज- I (210 मेगावाट), लुहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्टेज- II (163 मेगावाट) और सुन्नी डैम हाइड्रो-इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट (382 मेगावाट) है

सुन्नी बांध जल विद्युत् परियोजना के बहाव में 800 MW कोल डैम जल विद्युत् परियोजना है। लुहरी परियोजना के अपस्ट्रीम में 412 MW रामपुर HEP स्थित है, जो उससे आगे की ओर 1500 MW नाथपा झाकड़ी परियोजना के अतिरिक्त पानी के निर्वहन का उपयोग करता है।

विशेष रूप से, वर्तमान में लगभग 250 किलोमीटर की दूरी पर नाथपा झाकड़ी और कोल डैम के बीच सतलुज नदी पर लगातार 6 HEP चालू हैं। चूंकि सुन्नी बांध HEP लुहरी परियोजना का हिस्सा है और कोल डैम और लुहरी स्टेज -2 HEP के बीच स्थित है, इसलिए, परियोजना के लिए किसी भी वैकल्पिक स्थान के लिए सीमित गुंजाइश है। हालांकि, डैम और पावर हाउस के लिए न्यूनतम विस्थापन के साथ सर्वोत्तम स्थान को अंतिम रूप देने और इंजीनियरिंग मापदंडों को ध्यान में रखते हुए परियोजना के लेआउट के बारे में विकल्पों का विस्तार से अध्ययन किया गया था।

प्रोजेक्ट लेआउट के चयन का पता लगाने के लिए निम्नलिखित वैकल्पिक अध्ययन किए गए:

- **विकल्प 1:** बाएं किनारे पर बांध और सतह का पॉवर हाउस।
- **विकल्प 2:** डैम और अंडरग्राउंड पावर हाउस, 2 D कवर के साथ पावर हाउस दाहिने किनारे पर
- **विकल्प 3:** बाएं किनारे पर बांध और सतह का पॉवर हाउस।
- **विकल्प 4:** डैम और भूमिगत पावर हाउस, दाएँ किनारे में 4D कवर के साथ पावर हाउस के लिए

प्रत्येक विकल्प का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने के बाद अंत में अस्थायी डायवर्जन सुरंग के साथ विकल्प-4 का चयन किया गया है। जिन विकल्पों का अध्ययन किया गया था उनका विवरण अनुभाग 1.4 विकल्पों की परीक्षा के तहत पाया जा सकता है।

सामाजिक समाघात

परियोजना के लिए प्रस्तावित भूमि के अर्जन का आजीविका, रोजगार, आय, उत्पादन, स्वास्थ्य, कल्याण और समुदाय के जीवन की गुणवत्ता, सामाजिक-सांस्कृतिक प्रणालियों और पर्यावरण पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से असर पड़ेगा।

क्षेत्र में प्रस्तावित सुन्नी जल विद्युत् परियोजना को लेकर एक सामान्य आशा है। अध्ययन में पाया गया कि प्राथमिक हितधारकों में से 91%, अर्जन के लिए अपनी भूमि को आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार थे, बशर्ते कि उचित प्रतिकर का भुगतान किया जाए और केवल 8% ने अर्जन प्रक्रिया का विरोध किया। पंचायतों के साथ समूह चर्चा के दौरान, ग्रामीणों और द्वितीयक हितधारकों में परियोजना के प्रति बहुत

सकारात्मक राय मिली, क्योंकि यह बुनियादी ढांचे के विकास (सामाजिक और भौतिक दोनों) और रोजगार व व्यवसाय के अवसरों में वृद्धि के मामले में पूरे क्षेत्र में समग्र विकास लाएगा। साथ ही उन्होंने उस क्षेत्र की भूमि की कीमतों में वृद्धि का अनुमान लगाया जो उनके लिए एक लाभदायक कारक होगा।

हालांकि, वे नकारात्मक प्रभावों के बारे में भी आशंकित थे जो उचित रूप से शमन नहीं किए जाने पर, परियोजना से बढ़ सकते हैं। क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए हितधारकों के बीच विवादों में वृद्धि के बारे में चिंताएं थीं कि दुर्बल समूहों को छोड़ दिया जा सकता है या उनको धोखा दिया जा सकता है। इसके अलावा, प्रतिकर राशि प्राप्त करने के बाद से, PAF की वित्तीय स्थिति में बदलाव होगा जो बदले में उनकी खरीद क्षमता को बदल देगा और वित्तीय कुप्रबंधन के जोखिम को भी बढ़ाएगा क्योंकि कई जमींदार विशेष रूप से वित्तीय प्रबंधन के बारे में को ठीक से शिक्षित नहीं हैं। क्षतिपूर्ति राशि वितरित होने के बाद परियोजना क्षेत्र में धोखाधड़ी के मामलों में भी वृद्धि हो सकती है। खर्च के पैटर्न में बदलाव के कारण सांस्कृतिक प्रथाओं और परंपराओं में बदलाव की भी संभावना है।

अर्जन के कारण सार्वजनिक अवसंरचना जैसे रोपवे, पुल, श्मशान घाट, सड़क, मौजूदा सिंचाई सुविधाओं सहित सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य अधोसंरचना का नुकसान भी होगा और पीने के पानी के स्रोतों, घाटों, जंगलों, चरागाहों आदि जैसे सामान्य संपत्ति संसाधनों का नुकसान भी होगा। सुन्नी HEP के लिए कुल 78 संरचनाओं का अर्जन किया जा रहा है। इनमें 38 आवासीय संरचनाएं, मंडी जिले के गाँव परलोग में 1 स्कूल, 3 पंपहाउस, 12 घर, शिमला जिले के मालगी गांव में 1 पुल, 6 रोपवे, 9 बिजली के खंभे, 3 पानी के नल, 2 पंप और 3 जल आपूर्ति पाइपलाइन शामिल हैं। अध्याय 4 में बुनियादी ढांचे और परिसंपत्तियों के नुकसान के विवरण पर चर्चा की गई है। PAPs और साथ ही ग्रामीणों को इस बात की चिंता थी कि अर्जन करने वाले निकाय द्वारा उन्हें कैसे विकल्प प्रदान किए जाएंगे, ताकि यह उनकी दैनिक दिनचर्या में बाधा न बने। ग्रामीणों के पास पशुओं के चारे और जलाऊ लकड़ी के लिए समीपवर्ती चरागाह भूमि और जंगल पर निर्भरता है।

परियोजना के निर्माण चरण के दौरान, हितधारकों का परियोजना के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण था क्योंकि यह उनके लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार और व्यापार के अवसर पैदा

करेगा। प्रवासन के कारण वस्तुओं की खपत में वृद्धि होगी, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। हालाँकि, उन्होंने परियोजना के लिए श्रमिकों के प्रवास के बारे में भी चिंता व्यक्त की क्योंकि यह स्वास्थ्य सुविधाओं, शैक्षणिक सुविधाओं, सड़कों आदि जैसे मौजूदा बुनियादी ढांचे पर दबाव बढ़ाएगा। स्थानीय लोगों और प्रवासियों के बीच संघर्ष में वृद्धि की संभावना हो सकती है और हितधारकों ने यह भी कहा कि प्रवासन के कारण क्षेत्र में अपराध दर और असामाजिक गतिविधियों में वृद्धि की संभावना है। यह क्षेत्र सांस्कृतिक मिश्रण का भी गवाह बन सकता है। इसके अलावा, भारी परिवहन वाहनों, सामग्री परिवहन और निर्माण के कारण यातायात, वायु और ध्वनि प्रदूषण की समस्या भी होगी। निर्माण गतिविधियों और उत्खनन के कारण क्षेत्र में स्वास्थ्य समस्याओं में भी वृद्धि हो सकती है।

निर्माण के बाद के चरण के बारे में, हितधारकों ने कहा कि यह क्षेत्र में प्रदूषण को कम और जीवन के माहौल को बेहतर कर सकता है। LADA जैसे फंडों के कारण यह क्षेत्र आगे विकास का भी गवाह बनेगा। इस अवस्था के दौरान एक सांस्कृतिक स्थिरता भी देखी जा सकती है। हालाँकि, उन्होंने कुछ नकारात्मक प्रभावों पर भी प्रकाश डाला, जो इस चरण के दौरान उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे कि निर्माण गतिविधियों में गिरावट के कारण स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और व्यापार के अवसर कम होंगे और इससे परियोजना में शामिल अस्थायी कार्य बल को बेरोजगारी भी हो सकती है।

क्षेत्र स्थानीय अर्थव्यवस्था में अचानक गिरावट और निर्माण चरण में शामिल अस्थायी श्रमिकों के प्रवास के कारण माल और सेवाओं की कम खपत का गवाह बन सकता है। नतीजतन, निर्माण चरण के दौरान आय के स्तर में वृद्धि के कारण बड़े हुए जीवन स्तर बनाए रखने में लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है।

कमी करने के उपाय

संभावित चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करने के लिए, निम्न शमन उपाय प्रस्तावित किए गए हैं:

➤ सामाजिक उपाय

1. यदि हितधारकों के बीच कोई विवाद है, तो इस विवाद को पहले हल किया जाना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कानूनी मालिक को प्रतिकर दिया जाए।
2. करयाली पंचायत के स्थानीय लोगों द्वारा मांग की जाती है कि जब करयाली ग्राम पंचायत में जलाशय का निर्माण किया जा रहा है, तो परियोजना का नाम सुन्नी HEP से बदलकर जैशी-करयाली HEP करने की मांग की है।
3. गांवों में स्थानीय देवताओं के मंदिरों के निर्माण / उन्नयन के लिए धन उपलब्ध कराना।

4. परियोजना क्षेत्र के सभी गांवों और पंचायतों में सामुदायिक हॉल का निर्माण
5. महिला मंडल, युवक मंडल ग्राम पंचायत कार्यालयों के रूप में उपयोग किए जाने वाले भवन / संरचनाओं का निर्माण, मरम्मत और उन्नयन।
6. निर्णय लेने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने और अपने पारंपरिक कौशल को बढ़ाने और नए कौशल विकसित करके पिछड़े वर्ग श्रेणियों जैसे महिलाओं और सीमांत वर्गों के उत्थान के लिए प्रयास किए जाने चाहिए।
7. परियोजना प्रभावित व्यक्तियों और परिवारों के लिए परिवार के सदस्यों के लिए नौकरी प्रदान करना
8. खेल परिसरों के निर्माण के माध्यम से खेलों को बढ़ावा देना और युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करना
9. अन्य चल रही विकास योजना से सहायता / ऋण

➤ **आधारभूत संरचना के उपाय**

1. परियोजना क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में सभी मौसम योग्य पक्की सड़कों के लिए गाँव की सड़कों और लिंक सड़कों का उन्नयन।
2. परियोजना क्षेत्र की सभी पंचायतों में उचित जल निकासी सुविधाओं का निर्माण।
3. परियोजना क्षेत्र की सभी ग्राम पंचायतों में स्ट्रीटलाइट प्रदान करें।
4. परियोजना क्षेत्र की सभी पंचायतों को विशेष रियायती दरों पर बिजली प्रदान करना।
5. परियोजना क्षेत्र के गांवों और पंचायतों को स्वास्थ्य सुविधा जैसे PHC, डिस्पेंसरी, अस्पताल, मोबाइल हेल्थ वन, एम्बुलेंस और एम्बुलेंस सड़क का प्रावधान।
6. परियोजना क्षेत्र के सभी गांवों और पंचायतों में सिंचाई की सुविधा प्रदान करें।
7. परियोजना क्षेत्र के सभी गांवों और पंचायतों में पेयजल सुविधाओं का प्रावधान।
8. स्कूल और छात्रवृत्ति - स्कूलों में बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना और प्रभावित क्षेत्र में PAF के छात्रों के लिए विशेष छात्रवृत्ति कार्यक्रम।
9. परियोजना क्षेत्र और परिवेश के लिए तकनीकी शिक्षा संस्थान और व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र।
10. सभी मौसम सड़कें -SIA टीम की निगरानी और ग्रामीणों की मांग के अनुसार, सभी मौसम सड़कें और पुल क्षेत्र में बनाए और बनाए जा सकते हैं।

उनमें से कुछ सुझाव, सर्वेक्षण और FGDs के अनुसार नीचे दिए गए हैं-

- खेरा से ओगली, (चेबरी पंचायत) तक पक्की सड़क का निर्माण।
- खेरा से शील तक पक्की सड़क (चेबड़ी पंचायत) का निर्माण।
- चेबड़ी पंचायत में पंचायत भवन से सरकेड़ी तक पक्की सड़क का निर्माण।

- चेबड़ी पंचायत में खेरा से रोपा तक पक्की सड़क का निर्माण।
- चेबड़ी पंचायत में खेरा से शमशान घाट तक पक्की सड़क का निर्माण।
- मोगरा पंचायत में झुँझन से लंबीधार तक 6 कि० मी० लम्बी पक्की सड़क का निर्माण।
- मोगरा पंचायत में 8 कि० मी० लम्बी पक्की सड़क झुँझन से मोगरा तक का निर्माण।
- मोगरा पंचायत में 5 कि० मी० लम्बी पक्की सड़क परखेरा से कुंडाधार तक का निर्माण।
- कोठी, मालगी, धारू और तुलाह को मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए सड़क का निर्माण।
(ओगली पंचायत)

11. नदी पर पुल: निम्नलिखित पुलों का सुझाव दिया गया है -

- झुँझन से सुकेत (मोगरा पंचायत मंडी) नदी पर पुल का निर्माण।
- बिंदला पंचायत को पुल द्वारा संपर्क।
- ओगली पंचायत में नदी पार करने के लिए ग्रामीणों द्वारा उपयोग किए जाने वाले मौजूदा रोपवे अर्जन के तहत आ रहा है, एक विकल्प के रूप में एक पुल का निर्माण किया जा सकता है।

12. वैकल्पिक शमशान घाट उपलब्ध कराएँ जाएँ जहाँ भी वे अर्जन के तहत आ रहे हैं ।

13. जल निकासी - प्रभावित ग्राम पंचायतों में उचित जल निकासी की सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता है।

➤ पुनर्वास के उपाय

1. जो PAF विस्थापित हो रहे हैं और भूमि हारे हुए लोगों के लिए भी जो अर्जित भूमि के प्रतिकर के रूप में भूमि का चयन करते हैं, अपेक्षित निकाय को उसी ग्राम पंचायत या पड़ोसी ग्राम पंचायत में भूमि प्रदान करनी चाहिए।
2. PAF जिनके घरों का अर्जन किया जा रहा है, उन्हें उचित प्रतिकर दिया जाए और अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत पुनर्वास के कारण होने वाली असुविधा के लिए अतिरिक्त प्रतिकर दिया जाए।
3. कई पंचायतों को लगता है कि प्रतिकर की गणना के लिए जमीन की सर्किल दरें बहुत कम हैं। इसलिए, प्रतिकर की गणना से पहले भूमि की सर्किल दरों को संशोधित और बढ़ाने का अनुरोध किया है।

➤ **पुनर्वास और आजीविका बहाली के उपाय**

1. आगामी परियोजना में स्थानीय ग्रामीणों के लिए व्यावसायिक अवसर और अन्यथा निर्माण, आपूर्ति और परिवहन के लिए अनुबंध।
2. आय बहाली के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र।
3. विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत श्रमिक वर्ग की आबादी के लिए कौशल उन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करना
4. परियोजना प्रभावित ग्रामीणों के लिए आगामी HEP परियोजना में नौकरी के अवसर।

➤ **पर्यावरण के उपाय**

I) **परियोजना क्षेत्र में वनीकरण और वृक्षारोपण**

II) **ध्वनि प्रदूषण और वाहनों के आवागमन को कम करने के उपाय**

शोर प्रदूषण और यातायात को कम से कम किया जा सकता है:

- a) भारी परिवहन वाहनों के प्रवेश के लिए दिन के विशिष्ट घंटे को परिभाषित करना।
- b) एक दिन में परियोजना स्थल में प्रवेश करने / छोड़ने वाले भारी वाहनों की संख्या को विनियमित करना।
- c) हॉर्न के उपयोग को कम करने के लिए ड्राइवरों को सख्त निर्देश।
- d) परिवहन वाहनों पर दबाव हॉर्न पर पूर्ण प्रतिबंध।
- e) सड़कों और यातायात की स्थितियों पर अनावश्यक अधिभार से बचने के लिए पूरे दिन में समान रूप से परिवहन वाहनों के प्रवेश और निकास के निश्चित समय।
- f) भारी वाहनों के चालकों को गति सीमा का पालन करने के लिए तथा छोटे वाहनों को प्राथमिकता देने और नियमित ओवरटेक करने देने के लिए सख्त निर्देश।

III) **वायु प्रदूषण घटाने के उपाय**

वायु प्रदूषण को कम करने के उपाय परिवहन, निर्माण, उत्खनन, खनन और डंपिंग के दौरान धूल के कारण उत्पन्न होने वाले वायु प्रदूषण को निर्माण स्थल, परिवहन वाहनों जैसे ट्रकों, टिपरों आदि के खनन और डंपिंग साइटों को उचित तरीके से ढकने से कम किया जा सकता है। साथ ही, परियोजना क्षेत्र में पूरे दिन नियमित जल स्प्रे भी वायु प्रदूषण को कम करने में मदद करेगा।

चेबड़ी पंचायत के ग्रामीणों ने डंपिंग साइट को गांव से दूर स्थानांतरित करने का अनुरोध किया है क्योंकि वे वायु प्रदूषण से चिंतित हैं कि उन्हें इसका सामना करना पड़ेगा।

➤ **जल प्रदूषण, जल जनित रोग और बढ़ी हुई आर्द्रता को कम करने के उपाय**

- 1) जल प्रदूषण को, खुदाई और खनन के दौरान नदी में न्यूनतम डंपिंग को सख्ती लागू करने से कम किया जा सकता है।
- 2) डंपिंग साइट को नदी के किनारों से दूर बनाया जाना चाहिए ताकि बारिश और मानसून के दौरान मलबा विशेष रूप से नदी में प्रवेश करने से बचें।
- 3) निर्माण सामग्री की भंडारण इकाइयों को विशेष रूप से रेत को नदी के किनारे से दूर रखना चाहिए।
- 4) जलाशय निर्माण के बाद जलाशय में विशेष रूप से छिड़काव नियमित रूप से किया जाना चाहिए ताकि जल जनित बीमारियों से बचा जा सके।
- 5) जलाशय के कारण नमी में वृद्धि वनीकरण द्वारा कम से कम हो सकती है। हालांकि विदेशी सजावटी पेड़ों के बजाय स्थानीय पेड़ों को लगाने के लिए विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके अलावा, केवल उन किस्मों के पेड़ों को लगाया जाना चाहिए जो नमी को कम करते हैं और परिवेश को अपेक्षाकृत ठंडा रखने में मदद करते हैं

➤ **जल स्तर में वृद्धि के कारण भूमि स्लाइड के जोखिम को कम करने के उपाय**

सक्षम अधिकारी नदी के बहाव की जांच करने और नदी में पानी के स्तर में वृद्धि के कारण भूस्खलन के जोखिम को कम करने के लिए कमजोर स्थानों पर तटबंध की दीवारों / रिटेनिंग दीवारों आदि का निर्माण सुनिश्चित कर सकते हैं।

➤ **अन्य शमन उपाय**

- a) **पर्यटन को बढ़ावा देना:** क्षेत्र को पर्यटन स्थल के साथ-साथ पानी से संबंधित गतिविधियों / खेल, राफ्टिंग, शिविर आदि के लिए हब के रूप में विकसित किया जा सकता है।
- b) **मत्स्य पालन** को बढ़ावा देना: यह परियोजना मत्स्य पालन के विकास के लिए जन्मजात परिस्थितियाँ प्रदान करेगी। मछली पकड़ने का लाइसेंस जारी करने के साथ प्रभावित क्षेत्र के इच्छुक व्यक्तियों को मछली पालन में प्रशिक्षण भी दिया जा सकता है।
- c) **पशुपालन** को बढ़ावा देने से छोटे और सीमांत किसानों को उनकी आय बढ़ाने में मदद होगी। दुग्ध सहकारी क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा सकता है जिससे न केवल परियोजना प्रभावित परिवारों को बल्कि पूरे क्षेत्र को लाभ होगा।
- d) **स्व-सहायता समूहों (SHG)** का गठन और सुदृढीकरण: महिलाओं को एक साथ आने और स्व-सहायता समूह बनाने और मौजूदा लोगों को उचित प्रशिक्षण के साथ मजबूत बनाने और उन्हें

विभिन्न योजनाओं के तहत दिए गए ऋण के माध्यम से अपनी आजीविका अर्जित करने की सुविधा प्रदान करने के लिए अवसर प्रदान करना। हस्तकला, डेयरी, शॉल बनाना, सिलाई और कढ़ाई आदि प्रस्तुत की जा सकती हैं।

- e) **आय बहाली के लिए संस्थागत संपर्क और कौशल उन्नयन:** अर्जन करने वाली संस्था कुछ व्यावसायिक / कौशल प्रशिक्षण के अवसर प्राप्त करने के लिए प्रभावित परिवार के सदस्यों को जुटाने के लिए एक सक्रिय भूमिका निभा सकती हैं और कच्चे माल, आदानों के अलावा विपणन और क्रेडिट सुविधाएं के लिए अग्रामी व अधोग्रामी संबंध स्थापित करने में भी सहायता कर सकते हैं।
- f) **परियोजना-आधारित रोजगार:** परियोजना से संबंधित रोजगार के अवसर जैसे परियोजना निर्माण, रखरखाव, आपूर्ति और परिवहन अनुबंध के तहत काम प्रभावित परिवारों को दिया जा सकता है।
- g) **स्थानीय क्षेत्र विकास समिति**
परियोजना क्षेत्र में स्थानीय क्षेत्र विकास निधि (LADF) का सही तरीके से उपयोग करने के लिए, एक स्थानीय क्षेत्र विकास समिति (LADC) का गठन किया जा सकता है, जिसमें विभिन्न हितधारक शामिल होते हैं जैसे कि सरकारी विभाग, परियोजना प्रभावित परिवारों के सदस्य, निकाय अधिकारियों की आवश्यकता आदि।
- h) **सर्किल दरों में संशोधन**
मंडी जिला और शिमला जिले की मोगरा पंचायत में पड़ने वाले गांवों के कई PAPs और PAF को लगता है कि उनकी भूमि की मौजूदा सर्कल दरें बहुत कम हैं। इसलिए उन्होंने प्रतिकर की गणना से पहले सर्कल दरों को संशोधित करने और बढ़ाने का अनुरोध किया है।
- i) **बेहतर वित्तीय प्रबंधन** के लिए PAPs और PAF के लिए जागरूकता शिविर और वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन।

सामाजिक लागत और फायदों का निर्धारण

कुल 5,31,974 वर्ग मीटर भूमि के प्रस्तावित अर्जन के लिए अनुमानित प्रतिकर 9,16,61,331 रुपये है। अर्जन के प्रभाव में 14,824 फल देने वाले पेड़ और 26,691 गैर-फल असर वाले पेड़ों के लिए, कुल 1,54,193,000 रुपये का प्रतिकर अनुमानित है।

अर्जन के तहत जाने वाले 38 आवासीय संरचनाओं में रहने वाले परिवारों के लिए रु 2,85,76,000 का पुनर्वास और पुर्नस्थापन लागत अनुमानित है।

सुन्नी बांध जल विद्युत् परियोजना (382 MW) के लीये की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

इस प्रकार, 10% विविध लागत सहित, भूमि अर्जन के लिए R & R सहित कुल लागत रु 114,21,02,233/- अनुमानित है।

विश्लेषण पर, परियोजना की सामाजिक लागत और लाभ बड़े पैमाने पर परियोजना से प्रभावित परिवारों की सामाजिक लागत को स्पष्ट करते हैं। RTFCTLARR अधिनियम, 2013 के तहत भुगतान किए जाने वाले क्षतिपूर्ति प्रावधानों का ध्यान रखें कि परियोजना से प्रभावित होने वाले PAPs और PAF को होने वाले नुकसान और असुविधा की भरपाई उदारता से की जाती है। अधिनियम न केवल उस भूमि का प्रतिकर देता है जिसे अर्जित किया जा रहा है, बल्कि इससे जुड़ी संरचनाओं और परिसंपत्तियों के लिए भी। इसके अलावा अधिनियम में खड़ी फसलों और पेड़ों (फल और गैर-फल दोनों) के लिए क्षतिपूर्ति की गई है। विस्थापन के मामले में, अधिनियम निर्वासन के लिए निर्वाह और परिवहन भत्ते के रूप में अतिरिक्त प्रतिकर प्रदान करता है। आजीविका के नुकसान के लिए, अधिनियम PAPs को उसकी आजीविका को फिर से स्थापित करने के लिए या तो उसे वैकल्पिक रोजगार स्रोत या एक बार सहायता प्रदान करके क्षतिपूर्ति करता है।

अध्ययन के दौरान यह देखा गया कि परियोजना की क्षेत्र में सामान्य स्वीकृति है। वास्तव में, अधिकांश प्राथमिक और माध्यमिक हितधारक इस परियोजना को लागू करने के लिए तत्पर हैं क्योंकि यह क्षेत्र में समग्र विकास लाएगा। यहां तक कि सर्वेक्षण से 91% प्राथमिक हितधारक अर्जन के लिए अपनी सहमति देने के लिए तैयार हैं बशर्ते कि उनके मुद्दों का समाधान हो। सामाजिक प्रभाव और शमन उपायों के तहत मुद्दों पर चर्चा की गई है। FGD के दौरान पंचायतें भी परियोजना के पक्ष में थीं क्योंकि वे LADF और सीएसआर जैसे फंडों के माध्यम से अपनी ग्राम पंचायतों के विकास के बारे में आशावादी थीं।

प्रभावित क्षेत्र के लोग रोजगार के अवसरों में वृद्धि, भूमि की कीमत और छोटे और मध्यम व्यापार उपक्रमों के लिए दायरा बढ़ाने को लेकर आशान्वित हैं। वे बेहतर सड़क नेटवर्क और जल निकासी सुविधाओं, उच्च आवृत्ति और बेहतर गुणवत्ता वाली परिवहन सेवाओं, बेहतर ढांचागत सुविधाओं की उम्मीद कर रहे हैं और यह क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के HEP मानचित्र में एक मील का पत्थर बन जाएगा।

व्यापक स्तर पर, परियोजना हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा लागू की जाने न्यूनतम लागत और न्यूनतम पर्यावरण नकारात्मक प्रभावों के साथ जितना संभव हो उतनी ऊर्जा का उत्पादन करने वाली रणनीति की सराहना करती है। जल-विद्युत ऊर्जा क्षमता के तेजी से दोहन से निश्चित रूप से राज्य के आर्थिक स्वास्थ्य में सुधार होगा क्योंकि सभी नए प्रतिष्ठानों से 12 प्रतिशत मुफ्त बिजली और परियोजना लागत का 1.5% LADF (स्थानीय क्षेत्र विकास निधि), से राज्य के संसाधनों में एक महत्वपूर्ण सीमा तक वृद्धि होगी। उत्तरी क्षेत्र में बिजली की बढ़ती मांग और बढ़ते ऊर्जा की कमी को पूरा करने के लिए परियोजना की आवश्यकता भी उत्पन्न होती है।

इसलिए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि परियोजना का लाभ प्रभावित क्षेत्र, जिले और राज्य के लोगों को दिया जाएगा। यदि प्रस्तावित शमन योजना का पालन किया जाता है, तो यह नकारात्मक प्रभावों को कम करके सामाजिक प्रभावों को कम करने में मदद करेगा और सकारात्मक प्रभावों को बढ़ाएगा, जिससे प्रतिकूल सामाजिक लागतों पर प्रभाव पड़ेगा।

1 विस्तृत परियोजना ब्यौरा

1.1 परियोजना की पृष्ठभूमि

सुन्नी बांध HEP नदी प्रवाह प्रकार की है और लुहरी HEP के बहु-चरण विकास का एक हिस्सा है। इस परियोजना की कल्पना वर्ष 2008 में की गई थी और इसे हिमाचल प्रदेश और भारत सरकार के संयुक्त उपक्रम सतलुज जल विद्युत् निगम लिमिटेड द्वारा सुरंगों का निर्माण किए बिना तीन चरणों में बनाने का प्रस्ताव किया गया था। यह परियोजना तीन चरणों में तीन बांधों के निर्माण पर विचार करती है। लुहरी हाइड्रो-इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्टेज- I (210 मेगावाट), लुहरी हाइड्रो-इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्टेज- II (172 मेगावाट) और सुन्नी डैम हाइड्रो-इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट (382 मेगावाट)। यह परियोजना रामपुर और कोल डैम जलविद्युत् परियोजनाओं के बीच सतलुज नदी की जल क्षमता का दोहन करने के लिए है।



यह परियोजना हिमाचल प्रदेश के शिमला और मंडी जिलों के खैरा गाँव के पास स्थित है। इस परियोजना में 90% भरोसेमंद वर्ष में 1,369 MU विद्युत् ऊर्जा का उत्पादन प्रस्तावित है। सतलुज नदी की जल क्षमता का दोहन करने के लिए सुन्नी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट प्रस्तावित किया गया था। इस परियोजना में खैरा गाँव के पास सतलुज नदी के पार नदी के तल के ऊपर कंक्रीट गुरुत्व ± 71 मीटर के ऊँचे और दाहिने किनारे पर भूमिगत बिजली घर के निर्माण की योजना है।

1.1.1 अंतर राज्य/अंतर्राष्ट्रीय पहलू

परियोजना सतलुज बेसिन में स्थित है, जो सिंधु बेसिन का एक हिस्सा है, और 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हस्ताक्षरित सिंधु जल संधि के प्रासंगिक प्रावधान द्वारा नियंत्रित किया जाना है। चूंकि

सतलुज सिंधु बेसिन के पूर्व की ओर बहने वाली नदी है, इसलिए भारत के पास इसके जल बंटवारे का अधिकार प्राप्त है। अतः इंटर स्टेट / अंतर्राष्ट्रीय पहलू स्पष्ट है।

1.1.2 डेवलपर/ विकासकर्ता की पृष्ठभूमि

SJVNL एक सुस्थापित, आईएसओ 9001 और ISO 14001 प्रमाणित कंपनी है। यह बहु-आयामी/ अनुशासनात्मक संगठन है और इसने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की योजना और क्रियान्वयन के लिए पर्याप्त विशेषज्ञता हासिल कर ली है। एकल जलविद्युत परियोजना कंपनी से शुरू होकर, SJVNL का आज हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और नेपाल और भूटान पड़ोसी देशों में पनबिजली परियोजनाओं में एक पदचिह्न है।

SJVNL लिमिटेड, एक मिनी रत्न, श्रेणी- I और अनुसूची - A सीपीएसई, बिजली मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में 24 मई, 1988 को भारत सरकार (GOI) और हिमाचल प्रदेश सरकार (GOHP) के संयुक्त उपक्रम के रूप में अस्तित्व में आयी । SJVNL अब एक सूचीबद्ध कंपनी है, जिसके 62.44% शेयर भारत सरकार के पास है, 26.85% हिमाचल प्रदेश सरकार और शेष 10.71% जनता के पास है।

सहायक कंपनी

- SJVNL अरुण -3 पावर डेवलपमेंट कंपनी प्रा० लिमिटेड (SAPDC) पूरी तरह से स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है जो नेपाल में 900 मेगावाट की अरुण -3 परियोजना के कार्यान्वयन के लिए गठित है।
- SJVNL थर्मल प्राइवेट लिमिटेड- बिहार में 1320 मेगावाट बक्सर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के निष्पादन के लिए पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।

संयुक्त उपक्रम

क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (CPTC) - 86km लंबी, 400 kV D/C मुजफ्फरपुर नेपाल कनेक्शन बिंदु से मुजफ्फरपुर सब स्टेशन तक ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण व रख रखाव कार्य हेतु भूटान में 600 मेगावाट की खोलोंगचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना के निष्पादन के लिए खोलोंगछु हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड। परियोजना इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सड़कों और पुलों का काम चल रहा है और मुख्य कार्यों के लिए निविदाएँ आमंत्रित की गयी हैं।

वित्तीय प्रदर्शन

वित्त वर्ष 2017-18 के लिए कंपनी की कुल आय रु 2587.07 करोड़ और 12.12.88 करोड़ कर के भुगतान के बाद लाभ अर्जित किया है । SJVNL ने वित्त वर्ष 2017-18 के लिए कुल लाभांश 864.56 करोड़ रुपए (लाभांश कर को छोड़कर) का भुगतान किया है।

SJVNL - एक मिनी रत्न कंपनी

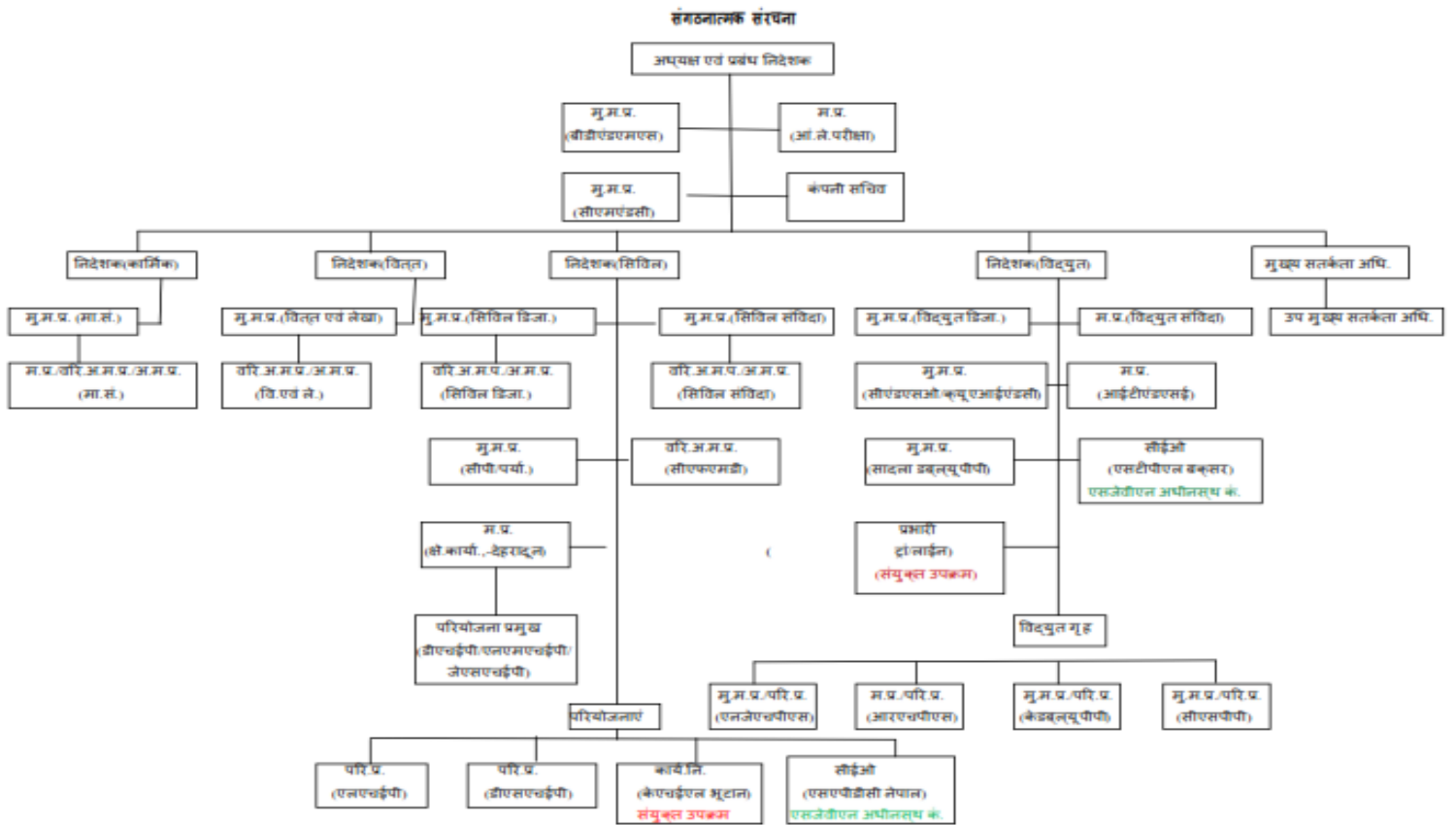
SJVNL लिमिटेड को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2008 में "मिनी रत्न: श्रेणी- I" का दर्जा दिया गया था।

सुन्नी बांध जल विद्युत् परियोजना (382 MW) के लीये की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

SJVNL - अनुसूची 'ए' कंपनी

लोक उद्यम विभाग द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हुए, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों मानकों को पूरा करने पर SJVNL को 2008 में अनुसूची 'ए' पीएसयू के रूप में उन्नत किया गया था।

चित्र 1-1: एस.जे.वि.एन.: संगठनात्मक संरचना



नोट: *परियोजनाओं का तात्पर्य अन्वेषणाधीन, निर्माण पूर्व तथा निर्माणाधीन चरण की परियोजनाओं से है।

1.2 परियोजना का मूल आधार

हिमाचल प्रदेश अपनी पांच प्रमुख नदियों में विशाल पनबिजली क्षमता के साथ धन्य है। हिमाचल प्रदेश सरकार सतलुज नदी की जल क्षमता का दोहन करने के लिए सुन्नी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट (382 MW) के निर्माण हेतु शिमला और मंडी जिले के दस गांवों में भूमि अर्जन करने का इरादा रखती है। यह नदी प्रवाह प्रकार की प्रस्तावित योजना है और SJVNL लिमिटेड इस कार्य की कार्यान्वयन एजेंसी है।

हिमाचल प्रदेश में पनबिजली ऊर्जा के दोहन के लिए रणनीति का पालन न्यूनतम लागत और न्यूनतम पर्यावरणीय प्रभावों के साथ अधिक से अधिक ऊर्जा का उत्पादन करना है। पनबिजली ऊर्जा क्षमता का तेजी से दोहन से निश्चित रूप से राज्य की आर्थिकता में सुधार होगा क्योंकि सभी नए परियोजना प्रतिष्ठानों से 12 प्रतिशत मुफ्त बिजली और 1.5% LADF राज्य के संसाधनों को एक महत्वपूर्ण सीमा तक बढ़ा देगा। उत्तरी क्षेत्र में बिजली की बढ़ती मांग और बढ़ते ऊर्जा की कमी को पूरा करने के लिए परियोजना की आवश्यकता भी उत्पन्न होती है।

RTFCTLARR अधिनियम, 2013 की धारा 2 उप-खंड 1 (बी) के अनुसार, सुन्नी डैम हाइड्रो-इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (382 मेगावाट) लोक प्रयोजनके लिए बुनियादी ढांचा परियोजनाओं (ऊर्जा उत्पादन) की परिभाषा के तहत अच्छी तरह से उचित है।

इसलिए, हिमाचल प्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्वास (सामाजिक समाघात निर्धारण और सहमति) नियम, 2015 में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार के नियम 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग, के तहत , भूमि जिसका अर्जन किया जा रहा है, के लिए एक सामाजिक प्रभाव अध्ययन आयोजित किया जाना है

1.3 परियोजना विवरण

1.3.1 परियोजना का आकार

इस परियोजना में खैरा गाँव के पास सतलुज नदी और दाहिने किनारे पर भूमिगत बिजली घर के ऊपर ±71 मीटर ऊँचे एक कंक्रीट ग्रेविटी बांध के निर्माण की परिकल्पना की गई है। निर्माण की कुल लागत 2911.85 करोड़ आंकी गई है। परियोजना के विभिन्न घटकों के डिजाइन, आयाम और क्षमता का विवरण नीचे दिया गया है:

सुन्नी बांध जल विद्युत् परियोजना (382 MW) के लीये की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

तालिका 1-1: परियोजना का आकर

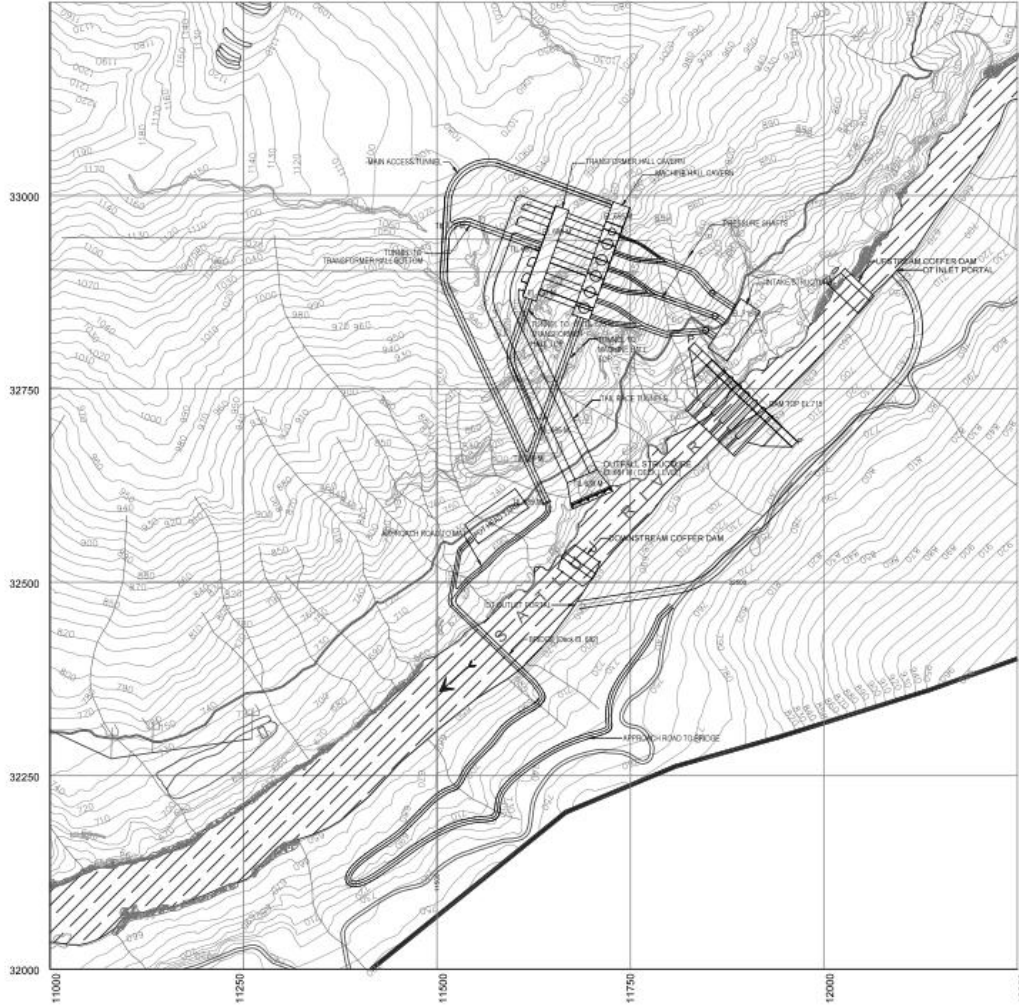
क्र०स.	घटक	अवस्थिति	डिजाइन	आयाम	क्षमता
1.	नदी डायवर्सन कार्य	नदी घाटी के बाईं ओर	घोड़े के नाल का आकार	10 m व्यास, ऊचाई: 1. अपस्ट्रीम कोफेर डैम : ±18.80 m 2. डाउनस्ट्रीम कोफेर डैम: ±9.20 m	773 m ³ /s
2.	डैम	नदी का दाहिना किनारा	कंक्रीट ग्रेविटी 6 इन्तेगरल गेटेद स्पिलवे of 8.5m (W) X 16.0m (H)	ऊचाई : ±71m नीव स्तर: ±623m पूर्ण जलाशय स्तर:712.0 m न्यूनतम ड्रा डाउन स्तर: El.709.50m बाँध शीर्ष लम्बाई : 185m शीर्ष पे बाँध की लम्बाई: 178m	15473 m ³ /.sec ग्रॉस पॉइज: 82.5 MCM लाइव स्टोरेज: 7.9 MCM
3.	प्रवेश संरचना	नदी का दाहिना किनारा	कचरा स्क्रीन युक्त प्रवेश गेट्स स्टॉपलॉग गेट्स के साथ	सेण्टर लाइन ऑफ इन्टेक: ±696.26m	744.07 m ³ /sec इन्टेक -1 and 2: 270.8 m ³ /sec each Intake-3: 171.27 m ³ /sec
4.	दाब शाफ्ट		3 दाब शाफ्ट		726.95 m ³ /sec
5.	पावर हाउस और ट्रांसफार्मर हॉल	नदी के दाहिने किनारे पर भूमिगत	पावर हाउस पहाड़ी के भीतर ±220 मी०, ऊपरी कवर ± 226 मी० ट्रांसफार्मर हॉल और मशीन हाल के बीच 50.0 मी चट्टान	पाँवर हाउस : 171.0m (L) x 22.5 m (W) x 50.5 m (H) ट्रांसफार्मर हॉल की गुफा: 176.0m (L)x17.5m(W)x27m(H)	382 MW (4 x 73 MW - मुख्या यूनिट, 1 x 73 MW+ 1 x 17 MW-पर्यावरण इकाईया)

सुन्नी बांध जल विद्युत् परियोजना (382 MW) के लीये की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

क्र०स.	घटक	अवस्थिति	डिजाइन	आयाम	क्षमता
6.	टेल रेस टनल और आउटफॉल स्ट्रक्चर		घोड़े के नाल का आकार	9.0m व्यास टेल रेस टनल की लम्बाई: ±280.0m क्रेस्ट स्तर of El 647.2 m	
7.	सुरंगों तक पहुँचें		15 में 1 अधिकतम ढलान युक्त और बड़े वाहनों के आवागमन में आसानी के लिए उन्हें यथासंभव सीधा रखना		
8.	मुख्य प्रवेश सुरंग		डी-आकार 16 में 1 का अधिकतम ढलान। सुरंग के बीच जंक्शन पर एक बड़ा खंड बनाया जाएगा मशीन हॉल लोडिंग और इरेक्शन बे के द्वारा पार्किंग क्षेत्र बनाया जाएगा	8.5m व्यास, 590 m की लम्बाई	

*स्रोत: सुन्नी HEP DPR स्थापना रिपोर्ट

मानचित्र 1-1: सामान्य लेआउट योजना, सुन्नी बाँध



NOTES:
 1. THE LAYOUT AND NO. OF UNITS ARE TENTATIVE AT THIS STAGE, WHICH WILL BE FINALIZED AFTER FREEZING OF FRL AND HYDROLOGICAL STUDIES.

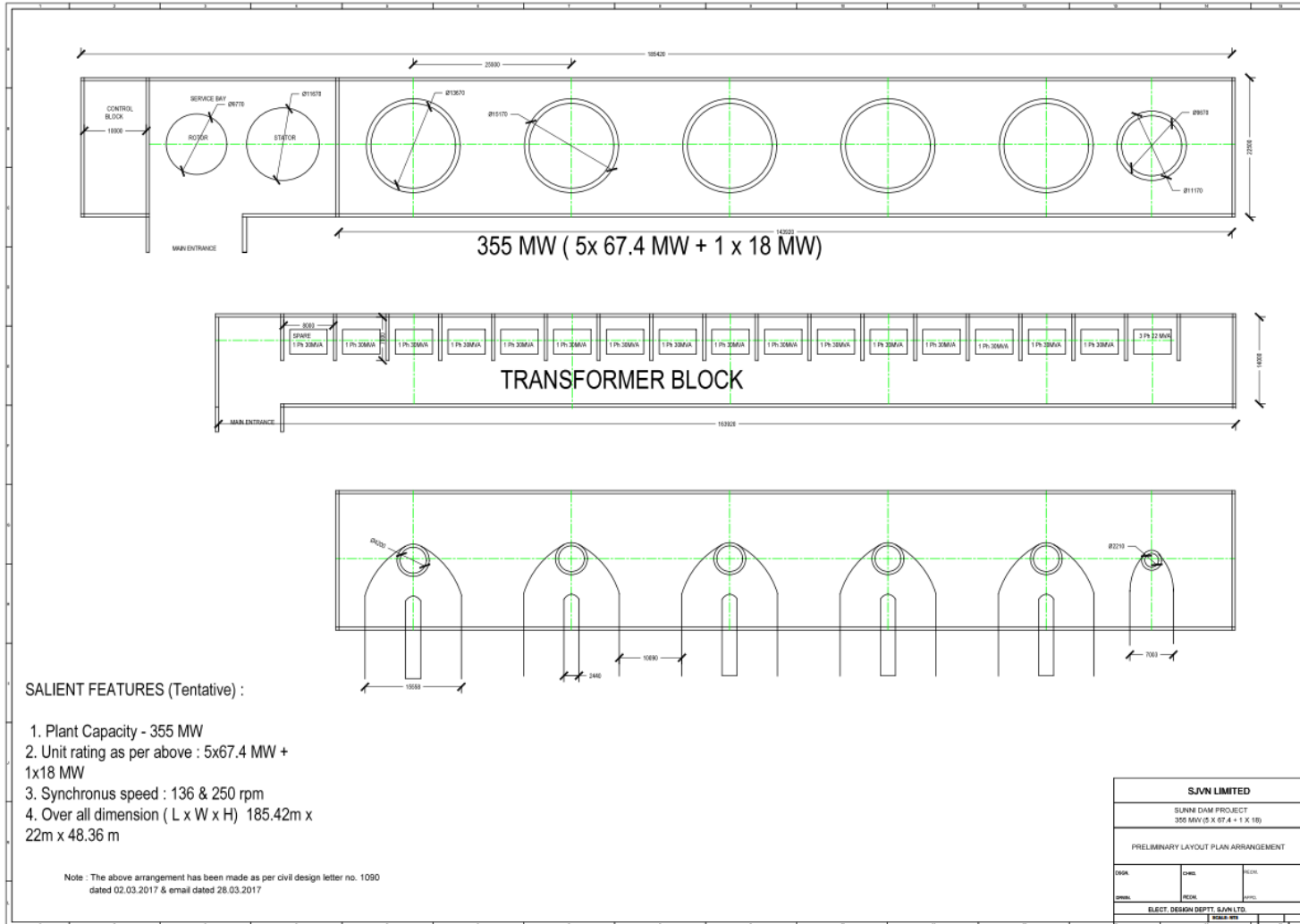
DAM AXIS CO-ORDINATES (PP')		
POINTS	EASTING	NORTHING
P	11832.294	32809.643
P'	11965.556	32682.158

DAM AXIS CO-ORDINATES (PP')		
POINTS	LONGITUDE	LATITUDE
P	77°12'34"	31°14'57"
P'	77°12'39"	31°14'53"

एन.जी.एल. लिमिटेड SJVN LIMITED		
SUNNI DAM (H.P.)		
GENERAL LAYOUT PLAN		
अनुमोदित DATE	अंकित DATE	पृष्ठ NO.
मालिक	उपयुक्त	
संशोधक		

सुन्नी बांध जल विद्युत् परियोजना (382 MW) के लीये की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

मानचित्र 1-2: प्रारंभिक लेआउट योजना की व्यवस्था



Sunni HEP

1.3.2 अवस्थान

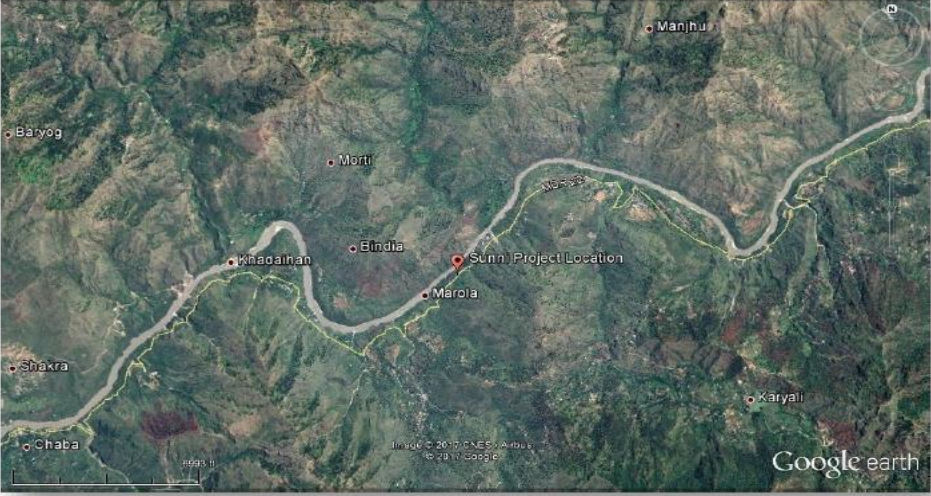
प्रस्तावित परियोजना शिमला और हिमाचल प्रदेश के मंडी जिलों में खैरा ग्राम के पास सतलुज बेसिन नदी के किनारे जिला शिमला और जिला मंडी में स्थित है।

प्रस्तावित बांध देशांतर 77°12'39 "E और अक्षांश 31°14'53" N पर स्थित है। परियोजना के अपस्ट्रीम पर 412 मेगावाट का रामपुर *HPएस* है, जो आगे की 1500 मेगावाट नाथपा-झाकड़ी परियोजना से छोड़े गये पानी का उपयोग करता है।

सुन्नी बांध पनबिजली परियोजना के बहाव में 800 मेगावाट का कोल डैम HPS (FRL 642 मीटर) है। रामपुर *HPएस* और प्रस्तावित सुन्नी बांध परियोजना के बीच, लुहरी HEP स्टेज- I (लगभग 50 किमी ऊपर) और लुहरी HEP स्टेज- II (LHEP- I और सुन्नी बांध के बीच) भी प्रस्तावित हैं।

निम्नलिखित मानचित्र परियोजना के स्थान और सीमा को प्रदर्शित करता है। तालिका 1-2 शिमला और मंडी जिले में पड़ने वाले गाँवों की सूची प्रदान करती है जहाँ भूमि अर्जन हो रहा है।

तालिका 1-1: परियोजना गाँव की सूची

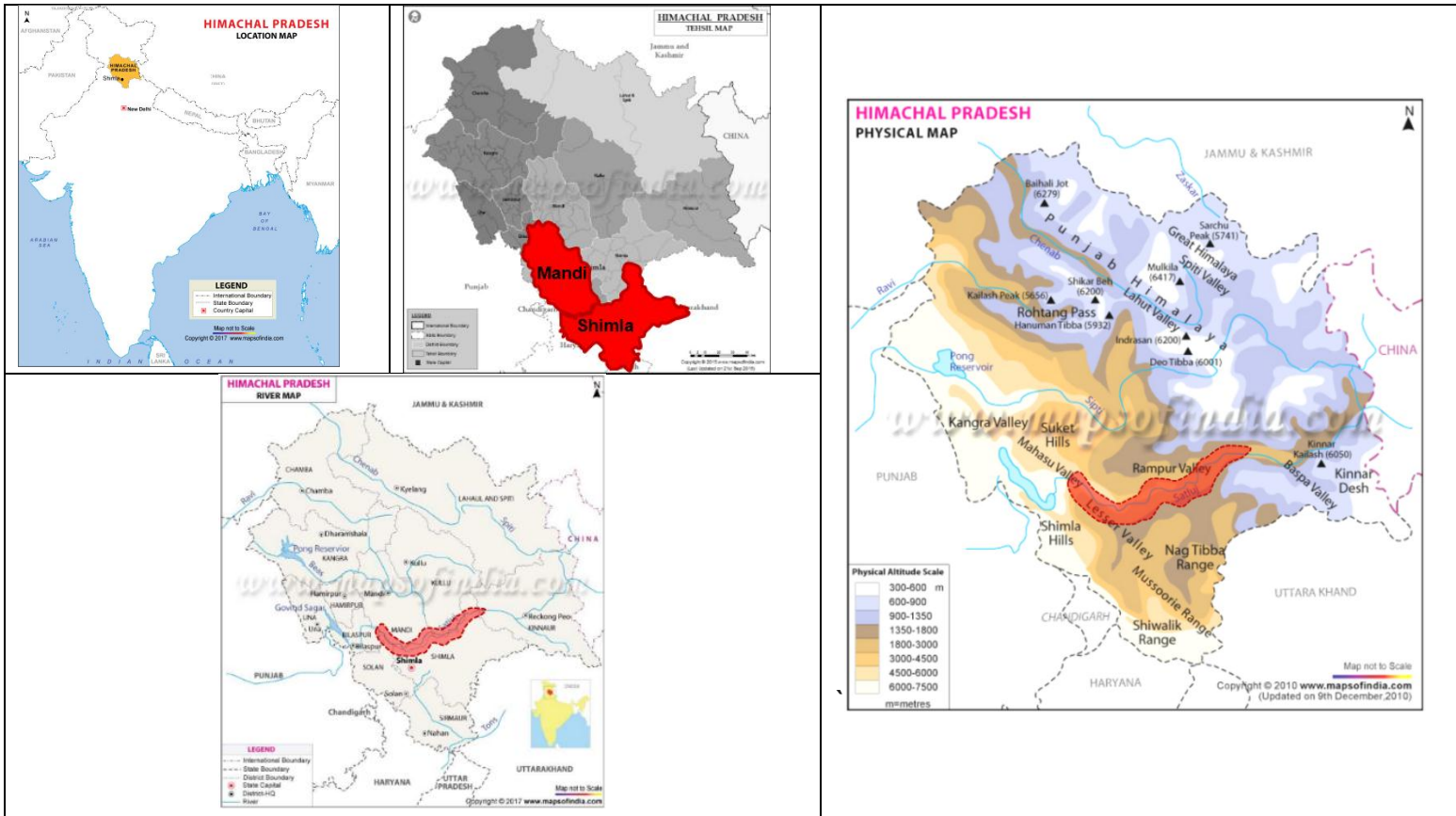
क्र स	शिमला ज़िला	मंडी ज़िला	<p style="text-align: center;">मानचित्र 1-3: प्रयोजन क्षेत्र का स्थान</p> 
1	बाठौरा	बलोग	
2	ग्रहना	बेलुढाँक	
3	कोठी	भौरा	
4	ओगली	फ़ाफ़न	
5	पंदोआ	जकलीन	
6	तलाह	खरयाली	
7	झुँझन	परलोग	
8	मझरोग		
9	भरारा		
10	जैशी		
11	खैरा		
12	लुँसू		
13	मालगी		

सुन्नी बांध जल विद्युत् परियोजना (382 MW) के लीये की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

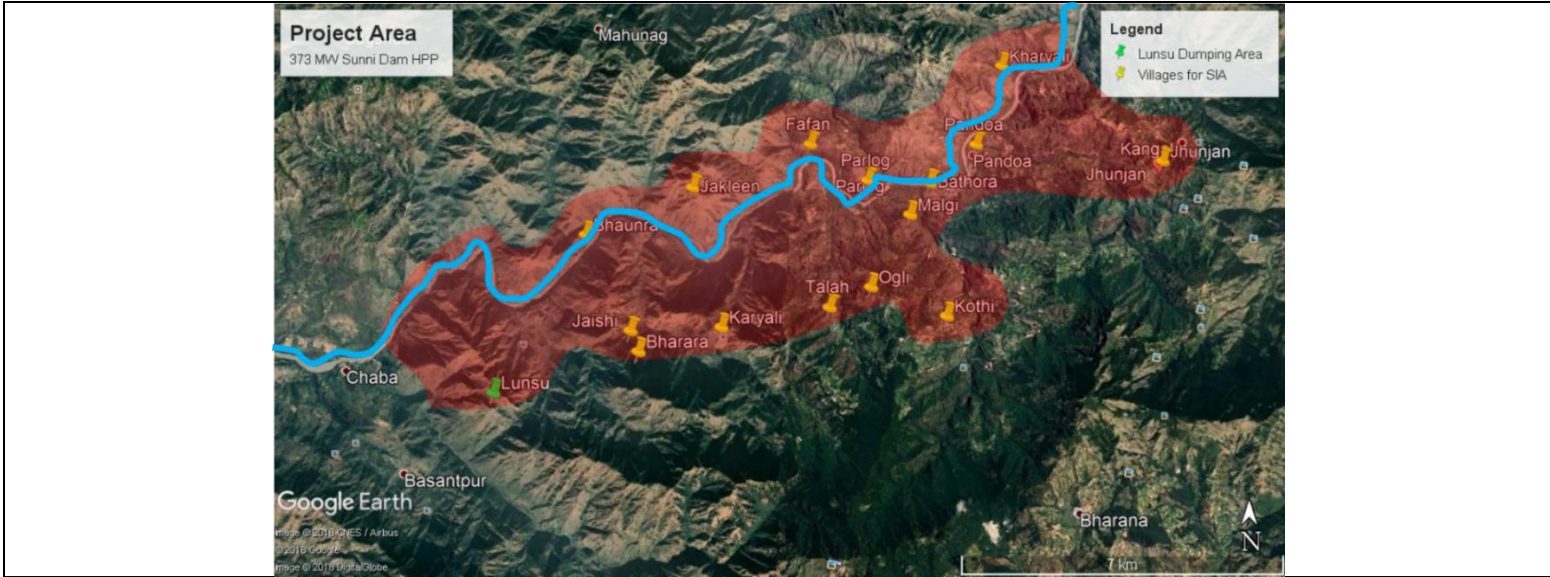
1.3.2.1 परियोजना क्षेत्र में पहुँच

परियोजना स्थल राजधानी शिमला से 50 किमी दूर, हरियाणा के कालका में निकटतम रेलवे स्टेशन (ब्राडगेज) से लगभग 145 किमी दूर स्थित है। साइट पर NH-5 के बाद SH-13 और MDR- 22 के माध्यम से वाया शिमला, नालदेहरा, चाबा से संपर्क किया जा सकता है। निकटतम हवाई अड्डा जुब्बड हट्टी (शिमला) में परियोजना स्थल से लगभग 70 किमी दूर है। निकटतम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परियोजना स्थल से 160 किमी की दूरी पर चंडीगढ़ में स्थित है। डैम साइट से निकटतम गांव ज़िला शिमला में खेरा है और नज़दीकी शहरी क्षेत्र सुन्नी 30 किमी दूर है।

मानचित्र 1-4: प्रस्तावित परियोजना की अवस्थिति



सुन्नी बांध जल विद्युत् परियोजना (382 MW) के लीये की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।



1.3.2.2 भौतिक और भू-आकृति :

यह परियोजना दक्षिण में धौलाधार रेंज और उत्तर में उच्च हिमालयी रेंज के बीच इनर लेस हिमालय में स्थित है। सतलुज नदी, तिब्बत के ऊंचाई वाले इलाकों में स्थित जल ग्रहण क्षेत्र की मुख्य निकासी है। यह भू आकृति क्षेत्र एक युवा पर्वत श्रृंखला में स्थित है तीव्र ढलान घाटी जिसकी विशेषता है। इसलिए, घाटी की अधिकांश ढलानें खड़ी हैं और सतलुज नदी ऊंची पहुंच वाले संकीर्ण वी-आकार की घाटियों के भीतर सीमित है। परियोजना की पहुंच के क्षेत्र में समतल भूमि को दायीं और बायीं दोनों नदी के किनारों पर देखा जा सकता है। सतलुज नदी के दाहिने तट पर पहाड़ी पर्वतमाला NW-SE और बाएं किनारे पर NE-SW है। यह क्षेत्र सतलुज के जल निकासी बेसिन का हिस्सा है, जो लगभग दक्षिण-पश्चिम दिशा में बहती है। बेहनखड, कोटलू खड्ड, गुम्मा खड्ड और बहारी खड्ड सतलुज नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ हैं। इस क्षेत्र में जल निकासी संरचना और लिथोलॉजी द्वारा नियंत्रित ट्रेलिस पैटर्न के लिए उप-वृक्ष के समान प्रदर्शित करता है।

1.3.2.3 भूकंपीयता

हिमाचल प्रदेश हिमालयी क्षेत्र में पड़ता है, जो दुनिया के सबसे अधिक सक्रिय क्षेत्रों में से एक है। परियोजना क्षेत्र उत्तर पश्चिम हिमालयी भूकंपीय बेल्ट (नरुला एट एल (2000) के मुख्य हिमालयी भूकंपीय क्षेत्र के शिमला ब्लॉक में स्थित है परियोजना भारत के भूकंपीय मानचित्र के अनुसार भूकंप क्षेत्र V में है (IS: 1893: 1984))। यह उत्तर में मेन सेंट्रल थ्रस्ट और दक्षिण में मेन बाउंड्री फॉल्ट / थ्रस्ट द्वारा सीमांकित किया गया है, और व्याख्यात्मक मौलिक अनुप्रस्थ दोष द्वारा पूर्व और पश्चिम में सीमित है। कांगड़ा ब्लॉक इसके पश्चिम में और पूर्व में गढ़वाल ब्लॉक स्थित है।

सुन्नी बांध जल विद्युत् परियोजना (382 MW) के लीये की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

1.3.3 क्षमता और उत्पाद

नीचे दी गई तालिका में परियोजना के विभिन्न घटकों की कुल क्षमता और आउटपुट का विवरण है:

तालिका 1-3: सुन्नी बांध जल विद्युत् परियोजना की क्षमता और आउटपुट

जल विज्ञान/हाईड्रोलोजी	
डायवर्सन साइट का कैचमेंट एरिया	52955km ²
90% भरोसेमंद/आधार वर्ष	2001-2002
नदी के डायवरजन हेतु बहाव	773.00m ³ /sec
संभावित अधिकतम बहाव	15473.00m ³ /sec
जलाशय	
पूर्ण बांध स्तर	EL712.00 m
न्यूनतम निचला स्तर	EL709.50 m
पूर्ण बांध स्तर पर कुल भण्डारण	82.50X10 ⁶ m ³
पूर्ण बांध स्तर पर मृतवत भण्डारण	64.2X10 ⁶ m ³
पूर्ण बांध स्तर पर जीवंत भण्डारण	7.9X10 ⁶ m ³
बांध की लम्बाई	20.70 km (approx.)
डी सिल्ट बेसिन	बांध डी सिल्ट बेसिन के तौर पर कार्य करेगा
बांध	
बांध का प्रकार	कंक्रीट ग्रेविटी
बांध का ऊपरी स्तर	EL 715.00 m
बांध पर औसत नदी का स्तर	EL 644.00 m
नदी के स्तर से बांध की ऊँचाई	71.00 m
बांध की ऊपर के स्तर की लम्बाई	178.00 mm
बांध की ऊपर के स्तर की चौड़ाई	8.00 m

सुन्नी बांध जल विद्युत् परियोजना (382 MW) के लीये की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

अतिप्रवाह ब्लॉक की लंबाई	87.00 m
गैर-अतिप्रवाह ब्लॉक की लंबाई	97.42 m
स्पिलवे	
डिज़ाइन फ्लड (PMF)	15473.00 m ³ /sec
स्पिलवे का प्रकार	कॉम्बिनेशन ऑफ़ अप्पर level स्पिलवे (ULS) and लो level स्पिलवे (LLS) (sluice spillway)
ऊर्जा अपव्यय प्रणाली	स्टीलिंग बेसिन
लो लेवल स्पिल वे (अंडर स्लूस स्पिल वे)	
प्रकार	Sluice type
बे/खण्डों की संख्या	Six (06) (Block No 3 to 8)
खोलने का आकार	8.5 m (W) X 16.0m (H)
गेट के प्रकार व संख्या	Radial, Six (06)
प्रत्येक खंड की चौड़ाई	14.5 m
LLS ब्लॉक की चौड़ाई	87.00m
क्रेस्ट स्तर क्रेस्ट लेवल	EL 660.00 m
अपर लेवल स्पिल वे ओवर फ्लो	
प्रकार	Ogee with open crest overflow
बे के संख्या	One (01) (Block No. 7)
आकार	5.0m(W)X4.5m(H)
गेट के प्रकार व संख्या	Flap Gate, One (01)
प्रत्येक खंड की चौड़ाई	14.5 m
अपर लेवल स्पिल वे ब्लॉक की चौड़ाई	14.5 m
अपर लेवल स्पिल वे क्रेस्ट	EL 707.00 m
VI) नदी डायवरजन	

सुन्नी बांध जल विद्युत् परियोजना (382 MW) के लीये की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

नदी डायवरजन प्रवाह	773.00 m ³ /sec
डायवरजन योजना	कोफ़र डैम और डायवर्सन टनल द्वारा
डायवरजन टनल स्थिति	नदी का वाम तट
टनलों की संख्या	एक (01)
डायवरजन टनल का घेरा व आकार	10.0 m, घोड़े की नाल के आकार में
टनल की लम्बाई	670 m
VII) पावर इंटेक	
इंटेक की संख्या	तीन (03)
इन्वर्ट स्तर	EL685.0
इंटेक डायवरजन 1 और 2 का प्रवाह	
इंटेक डायवरजन 3 का प्रवाह	
इंटेक गेट का आकार	5.7m(W)X8.0m(H)
VIII) प्रेशर शाफ्ट	
प्रेशर शाफ्ट की संख्या	तीन आगे छः में विभाजित
प्रेशर शाफ्ट 1 और 2 हेतु (मुख्य यूनिट)डिज़ाईन प्रवाह	277.84m ³ /sec
प्रेशर शाफ्ट 3 हेतु डिज़ाईन प्रवाह	
पेन स्टॉक का घेरा	7.5 m और 5.4m after विभाजन के बाद
पेन स्टॉक की लम्बाई	± 250.0 m
IX) पावर हाऊस	
प्रकार	भूमिगत
स्थान	नदी का राइट बैंक
मशीन हाल का आकार	185.42 m (L) X 22 m(W) X 48.36 m(H)
सामान्य टेल वाटर लेवल	EL 651.20 m

सुन्नी बांध जल विद्युत् परियोजना (382 MW) के लीये की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

न्यूनतम टेल वाटर लेवल	EL 647.50 m
ग्रोस हेड	59.97m
रेटिड हेड	57.85m
टरबाईन प्रकार	Francis
यूनिट की संख्या	Six (06)
डिज़ाईन प्रवाह	726.95 m ³ /sec
(मुख्य यूनिट) इंस्टालड क्षमता	4*73MW
इंस्टालड क्षमता (अन्य यूनिट)	1*73MW + 1*17MW
कुल इंस्टालड क्षमता	382MW
X) टेल रेस टनल	
संख्या	दो
टनल का आकार	10.5m dia & 9.0m dia, Horse Shoe Shaped
टनल की लम्बाई	280m
XI) ऊर्जा उत्पादन	
डिज़ाईन ऊर्जा (मुख्य यूनिट)	987.84GWh
डिज़ाईन ऊर्जा (अन्य यूनिट)	393.93GWh
वार्षिक ऊर्जा	1381.77GWh
वार्षिक लोड फ़ैक्टर (मुख्य यूनिट)	40.04%
वार्षिक लोड फ़ैक्टर (पर्यावरण यूनिट)	51.60 %

*स्रोत: सुन्नी HEP DPR के लिए इंसेप्शन रिपोर्ट

1.3.4 परियोजना लागत व् जोखिम का ब्यौरा

इस परियोजना की लागत मार्च 2017 मूल्य स्तर पर आईडीसी और वित्तपोषण शुल्क सहित, 2911.85 करोड़ रुपए अनुमानित है।

सुन्नी बांध जल विद्युत् परियोजना (382 MW) के लीये की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

परियोजना से वार्षिक ऊर्जा 1299 GWh के उत्पादन का आकलन किया गया है। लागत अनुमान नीचे दिए गए हैं:

तालिका 1-2: सुन्नी बांध परियोजना लागत

मार्च 17 के आकलन पर कुल व्यय	रूपया 2414.20 करोड़
निर्माण के दौरान ब्याज	रूपया 487.46 करोड़
वित्तीय चार्ज	रूपया 10.19 करोड़
कुल बेसिक कीमत, निर्माण के दौरान ब्याज व वित्तीय चार्ज सहित	रूपया 2911.85 करोड़
परियोजना के लिए शुल्क निम्नानुसार हैं:	
वर्ष शुल्क	रूपया 5.40/kWh
स्तरित शुल्क	रूपया 5.07/kWh

इस विशेष परियोजना के लिए संबंधित जोखिमों से संबंधित कोई जानकारी उपलब्ध नहीं थी। हालाँकि, कुछ जोखिम जो परियोजना से जुड़े हो सकते हैं, वे इस प्रकार हैं:

- परियोजना के निर्माणपूर्व , निर्माण और बाद के निर्माण चरणों के दौरान स्थानीय लोगों / राजनीतिक दलों / सामुदायिक संगठन द्वारा आंदोलन और प्रतिरोध।
- परियोजना, विशेषतः बांध, सुरंगें, शाफ्ट, पुल, नदी के डायवर्सन कार्य के निर्माण के दौरान जोखिम आदि ।
- विस्फोटक सामग्री और भारी उपकरण जैसे कि गर्डर्स, टर्बाइन, शाफ्ट आदि के परिवहन के दौरान जोखिम।
- निर्माण के कारण जीर्ण वायु और जल प्रदूषण का खतरा।
- निर्माण के दौरान प्रवास के कारण स्थानीय लोगों और बाहरी लोगों के बीच झड़पों का जोखिम और क्षेत्र में अपराध की दर में वृद्धि।
- निर्माण और निर्माण के बाद के चरणों में नदी में जलाशयों के निर्माण और जल स्तर में वृद्धि के कारण भूस्खलन, आर्द्रता और जल जनित रोगों का खतरा।

1.4 अनुकल्पों की परीक्षा

सुन्नी बांध जल विद्युत् परियोजना, लुहरी परियोजना का हिस्सा है, जो तीन चरणों में तीन बांधों के निर्माण पर विचार करती है जो लुहरी हाइड्रो-इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्टेज- I (210 मेगावाट), लुहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्टेज- II (163 मेगावाट) और सुन्नी डैम हाइड्रो-इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट (382 मेगावाट) है।

सुन्नी बांध जल विद्युत् परियोजना के बहाव में 800 MW कोल डैम जल विद्युत् परियोजना है। लुहरी परियोजना के अपस्ट्रीम में 412 MW रामपुर HEP स्थित है, जो उससे आगे की ओर 1500 MW नाथपा झाकड़ी परियोजना के अतिरिक्त पानी के निर्वहन का उपयोग करता है।

विशेष रूप से, वर्तमान में लगभग 250 किलोमीटर की दूरी पर नाथपा-झाकरी और कोल डैम के बीच सतलुज नदी पर लगातार 6 HEP चालू हैं। चूंकि सुन्नी बांध HEP लुहरी परियोजना का हिस्सा है और कोल डैम और लुहरी स्टेज -2 HEP के बीच स्थित है, इसलिए, परियोजना के लिए किसी भी वैकल्पिक स्थान के लिए सीमित गुंजाइश छोड़ रहा है। हालांकि, डैम और पावर हाउस के लिए न्यूनतम विस्थापन के साथ सर्वोत्तम स्थान को अंतिम रूप देने और इंजीनियरिंग मापदंडों को ध्यान में रखते हुए परियोजना के लेआउट के बारे में विकल्पों का विस्तार से अध्ययन किया गया था।

इन विकल्पों पर नीचे विस्तार से चर्चा की गई है

- विकल्प 1: बाएं किनारे पर बांध और सतह का पॉवर हाउस।
- विकल्प 2: डैम और अंडरग्राउंड पावर हाउस, 2 डी कवर के साथ पावर हाउस दाहिने किनारे पर
- विकल्प 3: बाएं किनारे पर बांध और सतह का पॉवर हाउस।
- विकल्प 4: डैम और भूमिगत पावर हाउस, दाएँ किनारे में 4D कवर के साथ पावर हाउस के लिए

विकल्प 1: बाएं किनारे पर बांध और सतह पर पॉवर हाउस।

नदी के बायीं किनारे पर बांध और सतह पर पॉवर हाउस (प्रस्तावित बाँध की धुरी के बांध ± 400 मीटर बहाव) पर एक विकल्प का अध्ययन किया गया था। चूंकि, दाएं किनारे की तुलना में बाएं किनारे का ढलान बहुत कोमल है; अतः बाएं किनारे पर सतह बिजली घर की संभावना का अध्ययन किया गया है। यह देखा गया कि पावर हाउस साइट में नाला के मुहाने पर पंख प्रकार की संरचना होती है और नाला के मलबे को हटाने के बाद पर्याप्त जगह उपलब्ध होगी। हालांकि, नालों के कैचमेंट के अध्ययन से संकेत मिलता है कि नाले में बहने वाली मलबे से पावर हाउस साइट पर आने का संभावित खतरा होगा। पावर हाउस हमेशा ढलान दृश्य बिंदु की स्थिरता से प्रभावित होता है । इसलिए, वैकल्पिक -1 को खारिज कर दिया गया था।

विकल्प 2: बाँध और 2D कवर के साथ भूमिगत पावर हाउस नदी के दाहिने किनारे पर।

वर्तमान प्रस्तावित स्थल पर बांध और 2 D कवर के साथ भूमिगत पावर हाउस नदी के दाहिने किनारे पर का अध्ययन किया गया था। हालांकि, सीडब्ल्यूसी के साथ विस्तृत विचार-विमर्श के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया कि कवर पर्याप्त नहीं है। इसलिए, वैकल्पिक -2 को अस्वीकार कर दिया गया था।

विकल्प 3: दाहिने किनारे पर बांध और सतह का पॉवर हाउस

वर्तमान प्रस्तावित स्थल पर बांध के विकल्प के साथ-साथ दाहिने किनारे पर सतह के पॉवर हाउस का अध्ययन किया गया था। एचसीडी, सीडब्ल्यूसी के साथ इस विकल्प पर भी चर्चा की गई और बड़े पैमाने पर ढलान काटने और खुदाई कार्य के कारण इसे अस्वीकार कर दिया गया।

विकल्प 4 : डैम और भूमिगत पावर हाउस, राइट बैंक में पावर हाउस के लिए 4D कवर के साथ

4D कवर वाले भूमिगत पावर हाउस के साथ वर्तमान प्रस्तावित स्थल पर बांध के विकल्प का अध्ययन किया गया था। विकल्प पर HCD, CWC के साथ चर्चा की गई और विस्तृत विचार-विमर्श के बाद, इस विकल्प को सबसे उपयुक्त पाया गया। GSI, नई दिल्ली ने भी इस विकल्प पर सहमति व्यक्त की। इसके अलावा इस विकल्प का अध्ययन अस्थायी के साथ-साथ स्थायी मोड़ सुरंग के साथ भी किया गया था। यह देखा गया है कि, स्थायी संरचना के रूप में डायवर्सन टनल का उपयोग करने के लिए, बांध के स्तर को 660 मीटर तक बढ़ाया जा सकता है यानी स्पिलवे के क्रेस्ट स्तर तक, जो बदले में 6-8 मीटर तक अपस्ट्रीम कोफर डैम की ऊँचाई को बढ़ा देगा। इसके अलावा, निर्माण समय भी बढ़ेगा क्योंकि स्थायी लाइन वाले सुरंग के निर्माण के लिए एक और मौसम की आवश्यकता होगी। इसलिए, अस्थायी डायवर्सन सुरंग के साथ विकल्प -4 का चयन किया गया है।

1.5 परियोजना के सन्निर्माण की अवस्थाये

सुन्नी बिजली परियोजना को 5 साल में पूरा करने का प्रस्ताव है। परियोजना की चरणबद्धता को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है क्योंकि डीपीआर अभी भी प्रक्रिया में है।

1.6 मूल डिजाइन की विशिष्टिया और आकर तथा सुविधाओं का प्रकार

1.6.1 नदी का डायवर्सन कार्य

नदी घाटी के बाईं ओर डायवर्सन टनल के निर्माण की संभावना है। 10 मीटर व्यास, घोड़े की नाल के आकार का डायवर्सन टनल 773 m³/s तक के डायवर्सन फ्लड को पास करने के लिए बनाया गया है। अपस्ट्रीम कोफ़र डैम की ऊँचाई ±18.80 मीटर और डाउनस्ट्रीम कॉफ़र बांध की ऊँचाई ±9.20 मीटर होगी।

1.6.2 बांध

प्रस्तावित बाँध ±71m ऊँचा, अधिकतम गहरी नींव स्तर ±623, मीटर ऊंचा, ठोस गुरुत्वाकर्षण बांध 8.5m (W) X 16.0m (H) के आकार वाले 6 स्पिलवे प्रस्तावित किए गए हैं। स्पिलवे के डिजाइन को 15473m³/sec के संभावित अधिकतम बाढ़ के अनुरूप बनाया गया है। पूर्ण जलाशय स्तर को 712.0 मीटर और न्यूनतम ड्रा डाउन स्तर 709.50 मी पर रखा गया है। बांध 82.5 एमसीएम का सकल तालाब और 7.9 MCM का लाइव भंडारण प्रदान करेगा। शीर्ष पर बांध की लंबाई 178 मीटर होगी। प्रस्तावित बांध को 11 ब्लाक में विभाजित किया गया अहै जैसा कि नीचे के सारणी में सारणीबद्ध किया गया है:

तालिका 1-3: डैम ब्लाकों का विवरण

क्र स	विवरण	कुल लम्बाई (मी)	ब्लॉकों की संख्या	ब्लाक न0	टिप्पणी
1.	बाएं किनारे पर NOF सेक्शन	46	2	1 to 2	कुल नं का ब्लॉकों = 11
2.	ओवर फ्लो ब्लॉक	87	6	3 to 8	
3.	दाहिने किनारे पर NOF सेक्शन	52	3	9 to 11	

1.6.3 प्रवेश संरचना

जलाशय से भूमिगत बिजली घर तक 744.07m³/sec के डिजाइन डिस्चार्ज को बदलने के लिए दाहिने किनारे पर इंटेक संरचना प्रस्तावित है। प्रवेश संरचना की केंद्र रेखा 712.0 m से 709.50 m होगी। तैरने वाले मलबे व जलमग्न मलबे को रोकने के लिए कचरा स्क्रीन प्रदान की जाएगी। कचरा रैक सफाई की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। कचरा स्क्रीन इतनी योजनाबद्ध हैं कि पासिंग वेग 1.5 m/s से नीचे हैं जैसा कि आईएस में वर्णित है: 9761-1995- हाइड्रोपावर इंटेक- हाइड्रोलिक डिजाइन के लिए मानदंड।

इंटेक -1 और 2 ($270.8 \text{ m}^3/\text{s}$ प्रत्येक) से डिस्चार्ज मुख्य इकाइयों के लिए उपयोग किया जाएगा और इंटेक्स -3 ($171.6 \text{ m}^3/\text{s}$) के माध्यम से निर्वहन पर्यावरण इकाइयों के लिए उपयोग किया जाएगा। स्टॉपलॉग गेटों के साथ इंटेक गेट जलाशय में लगाए जाने के दौरान निरीक्षण और रखरखाव को सक्षम करने और अत्यधिक बाढ़ के दौरान दबाव शाफ्ट प्रवेश क्षेत्र के भीतर भारी तलछट जमा पानी को रोकने के लिए प्रदान किए जाते हैं।

1.6.4 दबाव दस्ता/शाफ्ट

संचालन और रखरखाव के लचीलेपन के लिए, 3 नग दबाव शाफ्ट का प्रस्ताव किया गया है जो $729.95 \text{ m}^3/\text{s}$ के कुल निर्वहन को पारित करने के लिए छह में विभाजित किया जाएगा।

1.6.5 पावर हाउस और ट्रांसफार्मर हॉल

171.0 मीटर (L) x 22.5 मीटर (W) x 50.5 मीटर (H) के आकार वाले भूमिगत बिजली घर को दाएँ बैंक पर 382 मेगावाट (4×673 मेगावाट - मुख्य इकाइयों, 1×73 मेगावाट + 1×17 मेगावाट) की क्षमता के साथ प्रदान किया जाएगा। - पर्यावरण इकाइयों। पावर हाउस की गुफा में ± 220 मीटर के शीर्ष कवर के साथ पहाड़ी के अंदर ± 226 मीटर प्रस्तावित है। इसके अलावा, ट्रांसफार्मर हॉल और मशीन हॉल के बीच न्यूनतम 50.0 मीटर रॉक कवर उपलब्ध है। मशीन के प्रारंभिक लेआउट प्लान की व्यवस्था नीचे दी गई है:

1.6.6 टेल रेस टनल और आउटफॉल स्ट्रक्चर

टर्बाइनों से निकलने वाले पानी को 2 ड्राफ्ट ट्यूबों के माध्यम से 10.5 मीटर और 9 मीटर व्यास के घोड़े के आकार के टेल रेस टनल में उतारा जाएगा। टेल रेस सुरंग की लंबाई 280 मीटर होगी। सतलुज नदी तक पानी के निर्वहन के लिए TRT के बाद आउटफिट गेटेड संरचना 647.2 मीटर के सबसे निचले स्तर प्रस्तावित है।

1.6.7 एक्सेस टनल

मशीन हॉल और ट्रांसफार्मर हॉल तक पहुंच सुरंगों को (8.5m स्वास D-प्रकार $\pm 590\text{m}$) वाहनों के आकार और उनके माध्यम से ले जाने के लिए आवश्यक उपकरणों के आकार के आधार पर प्रस्तावित किया गया है, 16 में 1 की अधिकतम ढलान और बड़े वाहनों आवागमन में आसानी के लिए उन्हें जितना संभव हो उतना सीधा कर सकते हैं।

1.6.8 मुख्य प्रवेश सुरंग

मुख्य पहुँच सुरंग लगभग 700 मी लंबायी के साथ 5 में 1 की अधिकतम ढलान के साथ होगी। यह अनुमान लगाया गया है कि सुरंग और मशीन हॉल लोडिंग और इरेक्शन बे के बीच जंक्शन पर पार्किंग क्षेत्र बनाने के लिए एक बड़ा खंड बनाया जाएगा।

1.7 सहायक अवसंरचनात्मक सुविधाओं की आवश्यकता

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तैयार दिशानिर्देशों के अनुसार सुचारू और निर्बाध निष्पादन के लिए निर्माण से पूर्व, निर्माण के दौरान और निर्माण के बाद किसी भी पनबिजली परियोजना में सहायक इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं की आवश्यकता होती है:

1. पहुँच मार्ग
 - (i) परियोजना के लिए सड़कें
 - (ii) परियोजना क्षेत्र में सड़कें
2. रेल प्रमुख
3. पोर्ट सुविधाएं, (जैसा लागू हो)
4. निर्माण शक्ति की आवश्यकता
5. बिजली की आपूर्ति की सुविधा
6. निर्माण के दौरान और परियोजना के पूरा होने के बाद आवश्यक दूरसंचार सुविधाएं
7. परियोजना उपनिवेश / भवन
8. कार्यालय स्थान
9. कार्यशालाएं
10. पेयजल की सुविधा
11. अन्य

1.8 कार्यबल अपेक्षाएं

परियोजना के निष्पादन के लिए पुल और संपर्क रोड, कार्यालय भवन, कॉलोनियों, कार्यशालाओं, जल आपूर्ति और सीवरेज निपटान प्रणाली के निर्माण के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाना चाहिए, इसके बाद विभिन्न परियोजना घटकों जैसे डायवर्सन टनल, कॉफ़र बांध, कंक्रीट निर्माण बांध का निर्माण करना , इंटेक स्ट्रक्चर और पेनस्टॉक्स, सरफेस पावर हाउस, टेल रेस चैनल आदि का निर्माण किया जाना चाहिए ।

परिणामस्वरूप, 310 व्यक्तियों का कुल अनुमानित स्थायी / नियमित रोजगार और 56,57,500 व्यक्ति-दिन का अस्थायी रोजगार उत्पन्न होगा।

1.9 पर्यावरण समाघात निर्धारण का ब्यौरा एवम तकनीकी साध्यता रिपोर्ट

परियोजना के लिए कोई तकनीकी व्यवहार्यता रिपोर्ट अभी तक SJVNL द्वारा तैयार नहीं की गई है। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन रिपोर्ट प्रक्रियाधीन है। डीपीआर की तैयारी भी प्रगति पर है। हालांकि, परियोजना के सामान्य लेआउट का वर्णन करने वाली एक स्थापना रिपोर्ट तैयार की गई है।

1.10 लागू किये गए विधान और नीतियां

1.10.1 सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की तैयारी

RTFCTLARR अधिनियम, 2015 की धारा 4 में कहा गया है कि जब भी उपयुक्त सरकार किसी लोक प्रयोजनके लिए भूमि का अर्जन करने का इरादा रखती है, तो वह प्रभावित क्षेत्र में ग्राम स्तर या वार्ड स्तर पर संबंधित पंचायत से, उनके साथ, इस तरह से और ऐसी तारीख से जैसे कि सरकार द्वारा निर्दिष्ट अधिसूचना हो (अधिनियम की धारा 4) के तहत परामर्श करेगी और परामर्श में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करेगी।

HP RTFCTLARR नियम, 2015 के नियम 3 उपधारा (1) में कहा गया है कि राज्य सरकार अधिनियम के प्रयोजन के लिए, इनमें से FORM-I के भाग-बी के अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण करने के लिए एक अधिसूचना जारी करेगी। सामाजिक समाघात निर्धारण शुरू करने से संबंधित नियम हिंदी और अंग्रेजी दोनों संबंधित पंचायत या नगर पालिका या नगर निगम जैसा भी मामला हो सहित जिला कलेक्टर के संबंधित कार्यालयों में, उप-मंडलाधिकारी और तहसील को उपलब्ध कराए जाएंगे। कम से कम दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन के माध्यम और प्रभावित क्षेत्रों में विशिष्ट स्थानों पर अधिसूचना चिपकाकर भी प्रभावित क्षेत्र में व्यापक प्रचार किया जाएगा, इसके अलावा, अधिसूचना राज्य सरकार की वेबसाइट पर भी अपलोड की जाएगी: (HP RTFCTLARR नियम, 2015)

1.10.2 भूमि अर्जन की प्रक्रिया

- सरकार ग्रामीण क्षेत्रों (और शहरी क्षेत्रों के मामले में समकक्ष निकायों के साथ) में ग्राम सभा के परामर्श से एक सामाजिक समाघात निर्धारण (SIA) अध्ययन करेगी।
- इसके बाद, सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का मूल्यांकन विशेषज्ञ समूह द्वारा किया जाएगा। विशेषज्ञ समूह में परियोजना से संबंधित विषय पर दो गैर-आधिकारिक समाज वैज्ञानिक, पुनर्वास पर दो विशेषज्ञ और एक तकनीकी विशेषज्ञ शामिल होंगे।

- सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट की जांच समिति द्वारा की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भूमि अर्जन का प्रस्ताव कुछ निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करता है।
- सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के मूल्यांकन की तारीख से 12 महीने के भीतर भूमि प्राप्त करने के इरादे का संकेत देने वाली एक प्रारंभिक अधिसूचना जारी की जानी चाहिए।
- इसके बाद, सरकार अर्जित की जाने वाली भूमि की सीमा निर्धारित करने के लिए एक सर्वेक्षण करेगी।
- इस प्रक्रिया पर किसी भी आपत्ति को कलेक्टर द्वारा सुना जाएगा। इसके बाद, यदि सरकार संतुष्ट है कि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि का एक विशेष टुकड़ा अर्जित किया जाना चाहिए, तो भूमि का अर्जन करने की घोषणा की जाती है।
- इस घोषणा के प्रकाशित होने के बाद, सरकार भूमि का अर्जन करेगी।
- अर्जन की प्रक्रिया पूरी होने तक प्रारंभिक अधिसूचना की तारीख से निर्दिष्ट भूमि के लिए कोई लेनदेन की अनुमति नहीं दी जाएगी

1.10.3 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम, 2013 में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार

भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ने (RTFCTLARR Act,2013) ने भू अर्जन अधिनियम 1894 की जगह ली, जो औपनिवेशिक काल से अस्तित्व में था। पुराने भू अर्जन अधिनियम की त्रुटियों को दूर कर नए RTFCTLARR Act को ताजा करने की कोशिश की गई व भू अर्जन प्रक्रिया को ज्यादा प्रभावी बनाया गया।

अधिनियम में भूमालिकों के, औद्योगिकीकरण/ रियल एस्टेट की वृद्धि और ढांचागत उद्योगों के हितों में एकरूपता व भूमि अर्जन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने का प्रयास है। इस तरह अधिनियम का उद्देश्य इसे आधुनिक समय की जरूरतों के मुताबिक बनाना है।

अधिनियम में जिन लोगों की जमीन अर्जित की जानी है उनके अनिवार्य पुनर्व्यवस्थापन व पुनर्वास और उन्हें उचित प्रतिकर के भुगतान का प्रावधान किया गया है। अगर सरकार की ओर से जनउद्देश्य या पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप की परियोजनाओं के लिए अर्जन किया जाता है तो अधिनियम में बढ़े मुआवजों का प्रावधान है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में बाजार भाव से चार गुणा व शहरी क्षेत्रों में दुगुना हो सकता है। अधिनियम

को भूमालिकों व बाकी प्रभावित व्यक्तियों के हितों को संरक्षित करने के लिए जरूरी व लाभदायक माना गया ।

1.10.3.1 RTFCTLARR अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं

अधिनियम अर्जन के साथ- साथ R&R के लिए भी प्रावधानों को साफ करता है। मौजूदा प्रावधानों से जुड़े मुख्य बदलाव यह हैं (1) भू अर्जन की प्रक्रिया (2) अर्जन से विस्थापित हुए लोगों के अधिकार (3) प्रतिकर की गणना का तरीका (4) सभी तरह के अर्जन के लिए R&R की जरूरत।

1.10.3.2 भूमालिकों को प्रतिकर

RTFCTLARR Act 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत भूमि अर्जन के लिए प्रतिकर निर्धारित किया जाएगा ।

1.10.3.3 पुनर्वास और पुनार्व्यस्थापन की प्रक्रिया

पुनर्वास और पुनार्व्यस्थापन दो अलग-अलग गतिविधियाँ हैं।

- पुनार्व्यस्थापन भौतिक पुनर्वास के साथ जुड़ा हुआ है या उन्हें एक नए पुनर्वास कॉलोनी में पुनर्स्थापित कर रहा है।

- पुनर्वास PAPs की आजीविका की बहाली के साथ जुड़ा हुआ है। एक साथ रखे गए इन दोनों पहलुओं में पूर्ण शारीरिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बहाली शामिल है।

RTFCTLARR अधिनियम में हर अर्जन के मामले में R&R की आवश्यकता होती है। एक बार अर्जन के लिए प्रारंभिक अधिसूचना प्रकाशित होने के बाद, एक प्रशासक नियुक्त किया जाएगा। प्रशासक एक सर्वेक्षण करेगा और R&R योजना तैयार करेगा। यह योजना तब शहरी क्षेत्रों के मामले में स्थानीय निकायों में चर्चा की जाएगी। R&R योजना पर किसी भी आपत्ति को प्रशासक द्वारा सुना जाएगा। इसके बाद, प्रशासक एक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे कलेक्टर को प्रस्तुत करेगा। कलेक्टर योजना की समीक्षा करेंगे और इसे R&R के लिए नियुक्त आयुक्त को सौंपेंगे। एक बार जब आयुक्त R&R योजना को मंजूरी दे देता है, तो सरकार R&R के उद्देश्य के लिए आवश्यक क्षेत्रों की पहचान करने के लिए एक घोषणा जारी करेगी। तब प्रशासक योजना के निष्पादन के लिए जिम्मेदार होगा। आयुक्त योजना के कार्यान्वयन की देखरेख करेगा।

1.10.4 हिमाचल प्रदेश RTFCTLARR नियम 2015

हिमाचल प्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनार्व्यस्थापन (सामाजिक समाघात निर्धारण और सहमति) नियमों, 2015 में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, दिनांक 09 अप्रैल, 2015 की अधिसूचना अधिसूचित किया गया था और जैसा कि आवश्यक था हिमाचल प्रदेश (ई-राजपत्र), हिमाचल प्रदेश में

प्रकाशित किया गया था। भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन अधिनियम, 2013 में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता के अधिकार की धारा 112 के तहत (2013 का अधिनियम संख्या 30)। वे पूरे हिमाचल प्रदेश राज्य तक विस्तारित हैं

हिमाचल प्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन (सामाजिक समाघात निर्धारण और सहमति) नियमों में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, केंद्रीय अधिनियम, 2013 पर नियोजित, भूमि अर्जन के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश राज्य में सामाजिक मूल्यांकन अध्ययन करने के लिए प्रक्रिया की अनुमति देता है। नियमों का मुख्य आकर्षण हैं- (A) फॉर्म II और III के अनुसार SIA और SIMP का संचालन, (B) सार्वजनिक सुनवाई का संचालन करना (C) सहमति।

1.10.4.1 SIA और SIMP का संचालन करना

प्रपत्र II: सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट राज्य सरकार को उसके प्रारंभ होने की तारीख से छह महीने के भीतर प्रस्तुत की जाएगी और इसमें लिखित रूप में दर्ज प्रभावित परिवारों के विचार शामिल होंगे। यह प्रपत्र SIA रिपोर्ट की संरचना और सामग्री को विस्तृत करता है।

प्रपत्र III: सामाजिक समाघात प्रबंध योजना परियोजना के प्रभाव को संबोधित करने के लिए किए जाने वाले आवश्यक उपायों को लागू करती है और सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाएगी। यह फॉर्म SIMP की सामग्री पर एक दिशानिर्देश प्रदान करता है।

प्रपत्र II और प्रपत्र III परिशिष्ट में इस रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं।

1.10.4.2 जन सुनवाई का आयोजन -

सामाजिक समाघात निर्धारण के मुख्य निष्कर्षों को बाहर निकालने के लिए प्रभावित क्षेत्रों में सार्वजनिक सुनवाई का आयोजन किया जाना चाहिए , निष्कर्षों पर प्रतिक्रिया की मांग और अंतिम रिपोर्ट में इसे शामिल करने के लिए अतिरिक्त जानकारी और विचारों की तलाश की जानी चाहिए।

जनसुनवाई की तारीख और स्थल की घोषणा की जाएगी और तीन सप्ताह में सार्वजनिक सूचनाओं और पोस्टरों के माध्यम जिसका अर्जन करने के लिए प्रस्तावित पांच किलो मीटर की भूमि के दायरे में स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर, रेडियो में प्रसारण, और राज्य सरकार की वेबसाइट पर सूचना अपलोड करने के अलावा ग्राम पंचायत या नगरपालिका वार्ड प्रतिनिधियों के साथ सीधे संचार के माध्यम से तीन सप्ताह पहले प्रचारित किया जाएगा।

सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट और सामाजिक समाघात प्रबंध योजना हिंदी और अंग्रेजी दोनों में संबंधित पंचायत या नगर पालिका या नगर निगम जैसा कि मामला हो, को उपलब्ध कराई जाएगी, प्रभावित क्षेत्रों और कार्यालयों में ग्राम स्तर या वार्ड स्तर पर हो सकता है। जिला कलेक्टर, उप-मंडलाधिकारी, तहसीलदारों और राज्य सरकार की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा।

जन सुनवाई में भाग लेने के लिए आवश्यक निकाय, नामित भूमि अर्जन और पुनर्वास और पन्स्थापन अधिकारी, जन प्रतिनिधियों, स्थानीय स्वैच्छिक संगठनों और मीडिया के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाएगा।

जनसुनवाई की कार्यवाही की वीडियो रिकार्डिंग की जाएगी और उसी के अनुसार लिपिबद्ध की जाएगी। यह रिकार्डिंग और ट्रांसक्रिप्शन अंतिम सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट और सामाजिक समाघात प्रबंध योजना के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।

1.10.4.3 सहमति

राज्य सरकार, संबंधित जिला कलेक्टर के माध्यम से फॉर्म-IV के भाग-ए में प्रभावित भूमि मालिकों की पूर्व सहमति प्राप्त करेगी। उसी समय राज्य सरकार पूर्व सहमति प्रक्रिया और भूमि अर्जन के लिए भूमि अधिकारों से संबंधित अभिलेखों को अद्यतन करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी, प्रभावित क्षेत्रों में भूमि और अन्य राजस्व रिकॉर्डों में शीर्षक, ताकि भूमि मालिकों, भूमि पर रहने वालों और व्यक्तियों के नाम को आरंभ करने के लिए पहचाना जाए।

1.10.4.3.1 ग्राम सभा की सहमति-

- i. प्रभावित क्षेत्र में जन सुनवाई कार्य जाने का उद्देश्य है की SIA द्वारा दी गयी मुख्य खोजें,सलाहें व अतिरिक्त जानकारी और लोगों क विचार जो अंतिम रिपोर्ट में डाली जाए।
- ii. जिला कलेक्टर ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों के परामर्श से तीन सप्ताह पहले प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम सभा की बैठक की तारीख, समय और स्थल की सूचना देगा और ग्राम सभा के सदस्यों को इसमें भाग लेने के लिए प्रेरित करने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाएगा।
- iii. बैठक में भाग लेने वाले सभी सदस्यों के नाम और हस्ताक्षर रिकॉर्ड में लिए जाएंगे।
- iv. सहमति को मान्य मानने के लिए ग्राम सभा के कुल सदस्यों में कोरम हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या 4) में निर्धारित है।

- v. प्रस्तावित अर्जन के लिए फॉर्म-IV के भाग-बी में या सहमति देने से बहुमत के साथ एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा और इस प्रस्ताव में पुनर्वास और पुन्र्स्थापन, क्षतिपूर्ति, प्रभाव प्रबंधन और शमन के लिए बातचीत की शर्तें होंगी, जो आवश्यक निकाय के द्वारा वचनबद्ध हो, के साथ जिला कलेक्टर या नामित जिला अधिकारी द्वारा प्रतिबद्ध और जिन पर हस्ताक्षर किए गए हो ।

1.10.4.3.2 प्रभावित भूमि मालिकों की सहमति।

प्रभावित ज़मीन मालिकों की बैठक के दौरान ज़िला अधिकारियों की मौजूदगी में, आवश्यक निकाय और S/A टीम की सक्षम प्राधिकारी की बैठक के दौरान एक हस्ताक्षरित घोषणा प्राप्त की जाएगी, चाहे वह भूमि के अर्जन के लिए सहमति दे या न दे। यह पूरी बैठक वीडियो रिकॉर्डेड भी होगी और पूरी कार्यवाही लिखित रूप में प्रलेखित की जाएगी।

सहमति प्रक्रिया का परिणाम ग्राम पंचायत के कार्यालय और राज्य सरकार की वेब साइट पर उपलब्ध कराया जाएगा।

2 दल संरचना, दृष्टिकोण, प्रणाली एवं सामाजिक समाघात निर्धारण की अनुसूची

2.1 दल विवरण

SIA टीम की संरचना निम्न तालिका में दी गई है, जो सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन को करने के लिए जिम्मेदार है। टीम का प्रत्येक सदस्य अपने क्षेत्र का एक विशेषज्ञ है और पहले भी इस तरह के कई अध्ययन कर चुका है।

तालिका 2-1: टीम विवरण

क्र.सं.	नाम	योग्यता	लिंग	विशेषज्ञता
1	डा रणवीर सिंह	अर्थशास्त्र में पीएचडी एम। फिल कृषि आर्थिक	पुरुष	कृषि-अर्थशास्त्र अनुसंधान केंद्र, HPयू शिमला से विभागाध्यक्ष सेवानिवृत्त, SIA विशेषज्ञ, संपूर्ण सतलुज बेसिन के लिए आधारभूत सर्वेक्षण इनके निर्देशन में पूरा किया गया है ।
2	रमन शर्मा	एम ए समाजशास्त्र	पुरुष	सर्वेक्षण और डेटा विश्लेषण, प्रभाव आकलन और सामुदायिक जुटाव में विशेषज्ञ
3	जितेंद्र शर्मा	एम बी ए	पुरुष	एक्सपर्ट सोशल मोबिलाइजेशन
4	विराल मिस्त्रा	शहरी और क्षेत्रीय योजना में विशेषज्ञता के साथ बी.टेक सिविल इंजीनियरिंग, परास्नातक	पुरुष	शहरी और क्षेत्रीय योजना, ईआईए, SIA और R&R में विशेषज्ञ
5	गौरी सरिवास्तव	बी आर्क, शहरी नियोजन और आवास में विशेषज्ञता के साथ योजना में परास्नातक	महिला	हाउसिंग एंड R&R परियोजना समन्वयक में विशेषज्ञ
6	एम आर शर्मा	सामाजिक कार्य में स्नातक	पुरुष	सर्वेक्षण और सांख्यिकीय शोधकर्ता
7	प्रतिभा	एम ए	महिला	सर्वेक्षण और सांख्यिकीय शोधकर्ता, और लिंग विशेषज्ञ
8	सचिन चौहान	एम काम	पुरुष	आई. टी विशेषज्ञ
9	मीनाक्षी भारद्वाज	एम.ए. समाजशास्त्र	महिला	अन्वेषक और लिंग विशेषज्ञ

सुन्नी बांध जल विद्युत् परियोजना (382 MW) के लीये की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

प्राथमिक सर्वेक्षण में भाग लेने वाले क्षेत्र सर्वेक्षणकर्ताओं की सूची निम्नलिखित है:

तालिका 2-1: सर्वेक्षकों की सूची

S. No	Name	Qualification	Gender	Designation
1	लाभ सिंह	एम एस डवल्यू	पुरुष	सर्वेक्षक
2	प्रवीण	एम एस डवल्यू	पुरुष	सर्वेक्षक
3	राकेश कुमार	वाणिज्य स्नातक	पुरुष	सर्वेक्षक
4	विशाल ठाकुर	स्नातक	पुरुष	सर्वेक्षक
5	मुकेश कुमार	डिप्लोमा (ITI)	पुरुष	सर्वेक्षक
6	पंकज	विज्ञान स्नातक	पुरुष	सर्वेक्षक
7	विजय कुमार	डिप्लोमा (Mechanical)	पुरुष	सर्वेक्षक
8	मोहम्मद	समाजशास्त्र	पुरुष	सर्वेक्षक
9	राहुल	एम एस डवल्यू	पुरुष	सर्वेक्षक
10	राहुल	समाजशास्त्र	पुरुष	सर्वेक्षक
11	राजेंद्र ठाकुर	एम बी ए	पुरुष	सर्वेक्षक

2.2 प्रयुक्त पद्धति और उपकरण का विवरण व औचित्य

2.2.1 लक्ष्य

अध्ययन का उद्देश्य हिमाचल प्रदेश के अधिकार और भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्वास (सामाजिक समाघात निर्धारण और सहमति) नियमों, 2015 में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता के अनुसार एक सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करना है।

2.2.2 उद्देश्य

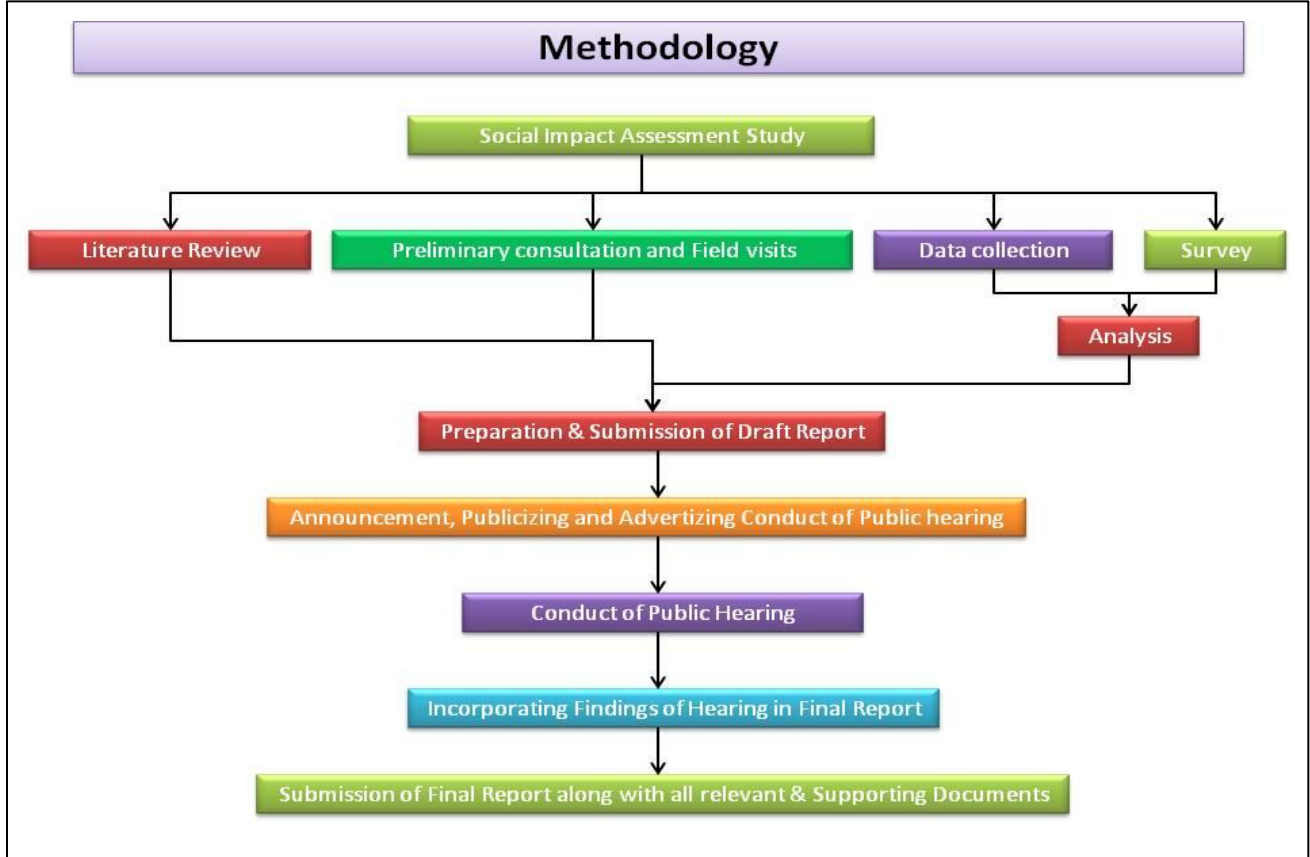
- 1 क्या प्रस्तावित अर्जन आरटीएफसीटीएलआरआर अधिनियम, 2013 की धारा 2 के तहत सूचीबद्ध मानदंडों के अनुसार लोक प्रयोजनका कार्य करता है या नहीं, इसका आकलन करना।
- 2 प्रभावित परिवारों का अनुमान और उनके बीच विस्थापित होने की संभावना वाले परिवारों की संख्या का आकलन ।

- 3 प्रस्तावित अर्जन से भूमि, सार्वजनिक और निजी, घरों, बस्तियों और अन्य सामान्य संपत्तियों की प्रचुरता प्रभावित होने की संभावना का आकलन ।
- 4 क्या अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि की सीमा परियोजना के लिए आवश्यक न्यूनतम पूर्ण सीमा है।
- 5 क्या वैकल्पिक जगह पर भूमि अर्जन पर विचार किया गया है और संभव नहीं है।
- 6 परियोजना के सामाजिक प्रभावों का अध्ययन, और प्रकृति और उन्हें संबोधित करने की लागत और परियोजना के समय लागत पर इन लागतों के प्रभाव ने परियोजना के लाभों को देखा।
- 7 HP RTFCTLARR नियमों, 2015 के FORM-II के अनुसार प्रभावित क्षेत्र और पुनर्वास स्थल की सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक प्रोफाइल तैयार करना (यदि कोई हो)।
- 8 HP RTFCTLARR नियमों, 2015 के प्रपत्र III के अनुसार एक सामाजिक समाघात प्रबंध योजना तैयार करना।

2.2.3 दृष्टिकोण और पद्धति

सामाजिक समाघात निर्धारण करने और SIMP तैयार करने के लिए जो पद्धति अपनाई गयी , वह नीचे वर्णित है। S/A RTFCTLARR अधिनियम 2013 और HP RTFCTLARR नियम, 2015 के अनुसार तैयार किया गया । नीचे चित्र प्रवाह चार्ट के रूप में S/A अध्ययन के दृष्टिकोण और कार्यप्रणाली को प्रस्तुत करता है।

चित्र 1: अध्ययन प्रधिती



* स्रोत: SIA टीम

नीचे दी गई विस्तृत कार्यप्रणाली है जिसे अध्ययन करने के लिए अपनाया गया है ।

1. परियोजना संदर्भ का विश्लेषण

- समीक्षा साहित्य समीक्षा
- माध्यमिक डेटा

2. हितधारकों की पहचान और विश्लेषण

- माध्यमिक डेटा
- प्राथमिक डेटा
- साइट विश्लेषण
- विभिन्न प्राथमिक सर्वेक्षण (संकेतिक विश्लेषण के माध्यम से विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मापदंडों का गुणात्मक और मात्रात्मक विश्लेषण)

3. सामाजिक कारकों और चर की पहचान

- प्राथमिक सर्वेक्षण (गुणात्मक और मात्रात्मक विश्लेषण)
- FGD (हितधारक प्रतिनिधि, संबंधित अधिकारी / अधिकारी)
- हितधारक परामर्श

4. डेटा विश्लेषण और प्राथमिकता मूल्यांकन

- प्राथमिक और माध्यमिक डेटा एकत्र का विश्लेषण
- FGD से तैयार किए गए संदर्भ
- स्टेकहोल्डर परामर्श से तैयार किए गए निष्कर्ष
- साइट सर्वेक्षण से अवलोकन

5. हितधारकों से परामर्श और शमन योजनाओं का विकास

- FGD और जन सुनवाई आयोजित करना
- FGD और जन सुनवाई से निष्कर्षों और निष्कर्षों की खोज में शमन योजनाओं का विकास

6. शमन योजना और जन भागीदारी को लागू करना

- कार्यान्वयन एजेंसी, संबंधित अधिकारियों / अधिकारियों और सार्वजनिक भागीदारी के साथ समन्वय से

7. सक्रिय हितधारक भागीदारी के साथ निगरानी सुनिश्चित करना और इसे संशोधित करना

2.2.4 पद्धति का औचित्य

सामाजिक समाघात अध्ययन एक समयबद्ध अध्ययन है और आगामी परियोजना के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि पर आर्थिक, आर्थिक, सामाजिक रूप से निर्भर लोगों के हित की चिंता करता है। उपरोक्त कार्यप्रणाली को सामाजिक समाघात अध्ययन करने और सुनिश्चित करने के लिए अपनाया जाता है, संविधान के तहत स्थापित स्थानीय स्वशासन और ग्राम सभाओं के परामर्श से, आगामी सुन्नी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए भूमि अर्जन के लिए एक मानवीय, भागीदारीपूर्ण, सूचित और पारदर्शी प्रक्रिया और प्रदान करना प्रभावित परिवारों के लिए उचित और उचित प्रतिकर जिनकी भूमि का अर्जन किया जाना प्रस्तावित किया गया है या इस अर्जन से प्रभावित हैं और ऐसे प्रभावित व्यक्तियों के लिए उनके पुनर्वास और पुनर्वास के लिए पर्याप्त प्रावधान करते हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए कि अर्जन का संचयी परिणाम होना

चाहिए कि प्रभावित व्यक्ति विकास में भागीदार बने अर्जन के बाद के अपने सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए अग्रणी हों ।

2.2.4.1 सामाजिक प्रभाव अध्ययन के लिए परामर्श हेतु हितधारकों की पहचान

सभी प्रमुख हितधारकों की एक सूची तैयार की गई जो परियोजना से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होगी। तब सूची को अंततः तीन व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया गया :

1. **प्राथमिक हितधारक:** इनमें अर्जित की जाने वाली भूमि के मालिक, उनके परिवार, जिनके नाम जमाबंदी पर दर्ज हैं और जो संपत्ति में अपनी भागीदारी का दावा करते हैं, जिनके पास अर्जित भूमि पर किसी भी प्रकार की आजीविका / निर्भरता है। ।
2. **द्वितीयक हितधारक:** इनमें व्यावसायिक संस्थाएँ, नागरिक समाज / राजनीतिक / धार्मिक / गैर सरकारी संगठन, युवक और महिला मंडल और क्षेत्र के स्थानीय निवासी शामिल हैं। ये हितधारक सीधे अर्जन से प्रभावित नहीं होंगे, लेकिन परियोजना के कारण उन पर अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ सकता है।
3. **संस्थागत हितधारक:** उनमें सरकार शामिल है; अर्ध-सरकारी संस्थान जैसे कि पंचायत, डीसी ऑफिस, पुलिस आदि जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस परियोजना से जुड़े या प्रभावित हो सकते हैं।

हितधारकों की पहचान के बाद डेस्क समीक्षा की जाती है। राजस्व मानचित्र, जिला जनगणना हैंड बुक, जिला गजेटियर, जिला सांख्यिकी, मौजूदा आजीविका परियोजनाओं, सरकारी रोजगार योजनाओं, RTFCTLARR अधिनियम, 2013, HP RTFCTLARR नियम, 2015, R&R पालिसी और सेवा क्षेत्रों के बारे में दस्तावेज जिसमें संबंधित जिलों / ब्लॉकों में बड़े पैमाने पर लोग शामिल हैं, सरकारी और गैर सरकारी स्रोत से एकत्र किए गए थे। सरकारी सूत्रों और समीक्षा की। ऐसे प्रासंगिक डेटा का संग्रह और समीक्षा मुख्य रूप से संबंधित क्षेत्र की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों और बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता और सेवा वितरण प्रणाली के बारे में समझ विकसित करने हेतु की जाती है।

2.3 सामाजिक समाघात निर्धारण के लिए सूचना संग्रहण करने के लिए संसाधन

अध्ययन को अंजाम देने हेतु जानकारी प्राथमिक और माध्यमिक दोनों स्रोतों से एकत्र की गई थी। इन स्रोतों पर निम्नलिखित अनुभाग में विस्तार से चर्चा की गई है:

- **माध्यमिक स्रोतों से डेटा**

जनगणना के आंकड़ों, सांख्यिकीय हाथ की पुस्तकों, संबंधित विभागों और अन्य साहित्य जैसे कई तिमाहियों से माध्यमिक स्रोतों की जानकारी एकत्र की गई थी। इस प्रकार, माध्यमिक स्रोतों की जानकारी ने प्राथमिक डेटा को पूरक किया जो प्रभावित लोगों और अन्य हितधारकों से क्षेत्र सर्वेक्षण के माध्यम से प्राप्त किया गया था। विस्तृत क्षेत्र जांच करने से पहले परियोजना क्षेत्र के भौतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सेट-अप के बारे में एक समझ बनाई गई थी।

- **प्राथमिक स्रोत**

हाउस होल्ड सर्वे, फील्ड विजिट और FGD के माध्यम से प्राथमिक डेटा एकत्र किया गया था। घरेलू सर्वेक्षण और FGD के लिए प्रश्नावली और कार्यक्रम SIA टीम द्वारा तैयार किए गए थे और किसी भी संभावित अंतर की जांच के लिए अंतिम रूप देने से पहले परीक्षण किया गया था। प्रश्नावली को पेशेवर सर्वेक्षकों / प्रगणकों द्वारा प्रशासित किया गया था जिन्हें SIA के टीम लीडर द्वारा प्रशिक्षण दिया गया था। परियोजना क्षेत्र को जानने के लिए उन्हें एक दिन के लिए परियोजना स्थल पर ले जाया गया। डेटा की गुणवत्ता पर जोर दिया गया था ताकि निष्कर्ष प्रामाणिक और विश्वसनीय हो। सर्वेक्षण से एकत्र किए गए डेटा को आउटपुट तालिका के प्रसंस्करण और उत्पादन के लिए उचित जांच और तार्किक जांच के बाद एमएस एक्सेल पर डिजिटल किया गया था।

- **अध्ययन के उपकरणों की तैयारी**

प्राथमिक हितधारकों के बारे में प्रामाणिक जानकारी एकत्र करने और उन पर प्रभाव की तीव्रता को इकट्ठा करने के लिए एक संरचित प्रश्नावली तैयार की गई थी। प्रश्नावली में गुणात्मक और मात्रात्मक जानकारी की विस्तृत श्रृंखला शामिल है। सुझावों और संशोधन के लिए एक मसौदा प्रश्नावली विकसित कर HP SIAU को प्रस्तुत किया गया था। क्षेत्र में पूर्व परीक्षण के बाद प्रश्नावली को अंतिम रूप दिया गया था। गांवों में विभिन्न हितधारकों द्वारा कथित सकारात्मक और नकारात्मक परियोजना प्रभावों सहित निर्णय लेने आदि, सकारात्मक प्रभावों को बढ़ाने और नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए उनके सुझाव सहित उपलब्ध सामाजिक और भौतिक बुनियादी ढांचे की स्थिति, अर्जन, शिक्षा की स्थिति, स्वास्थ्य की स्थिति, रोजगार की स्थिति, महिलाओं की भूमिका के कारण किसी भी सामान्य संपत्ति के नुकसान के बारे में जानकारी एकत्र

करने के लिए पंचायत स्तर पर विभिन्न हितधारकों के साथ समूहबद्ध चर्चा आयोजित करने के लिए अनुसूचियां तैयार की गईं।

- **प्राथमिक सर्वेक्षण**

एक पूर्व संरचित प्रश्नावली की मदद से प्राथमिक हितधारकों का एक सर्वेक्षण किया गया था। प्रश्नावली में PAF की पहचान, PAF के परियोजना और पुनर्वास और पुनर्स्थापन बारे विचार सहित, उनके सामाजिक प्रोफाइल, पारिवारिक विवरण, व्यवसाय, आय के स्रोत, परिवार के खर्च, घरेलू संपत्ति, प्रभावित संरचना की जानकारी, वाणिज्यिक / स्व-रोजगार गतिविधियों, रोजगार पैटर्न, राय जैसे पहलू शामिल थे । प्रश्नावली के अधिकांश भाग को PAF की राय और विचारों को प्रति बिंबित करने वाले लोगों को छोड़कर पूर्व-कोडित किया गया है, जिन्हें खुले अंत में छोड़ दिया गया है।

चित्र 2-1: प्राथमिक सर्वेक्षण के दौरान ली गई तसवीरें



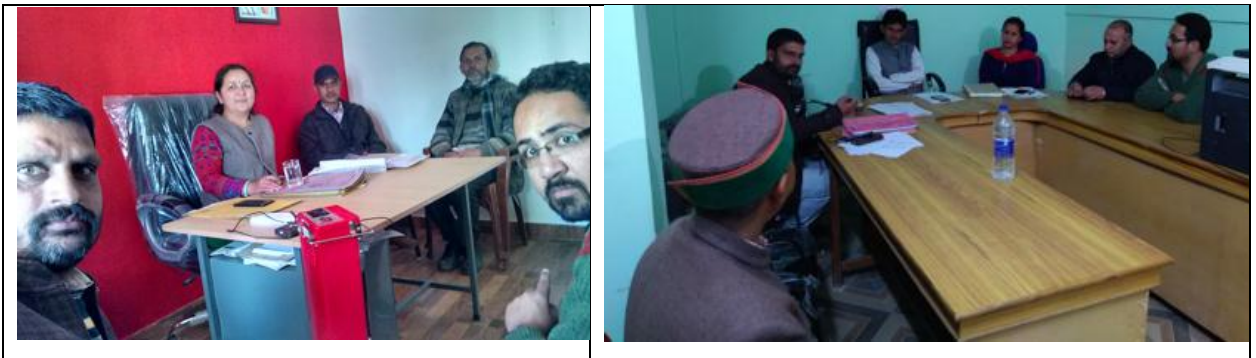
सुन्नी बांध जल विद्युत् परियोजना (382 MW) के लीये की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।



- **FGD**

अध्ययन के पहलुओं में, एक हितधारकों, जन प्रतिनिधियों और सामुदायिक नेताओं के साथ परामर्श था। परामर्श ने हितधारकों और SIA टीम के बीच संचार की रेखा को खोल दिया। इससे समुदाय द्वारा प्रभावित प्रभावों की पहचान करने में मदद मिली।

चित्र 2-2: केन्द्रित समूह चर्चा के दौरान ली गई तसवीरें



सुन्नी बांध जल विद्युत् परियोजना (382 MW) के लीये की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।



- डेटा संग्रह और ग्राउंड सत्यापन का पर्यवेक्षण

कोर टीम के सदस्यों द्वारा डेटा संग्रह का पर्यवेक्षण किया गया था और साथ ही सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण के तहत आने वाले पांच प्रतिशत परिवारों के लिए जमीनी सत्यापन किया गया था।

2.4 नमूना प्रणाली का उपयोग

अध्ययन के लिए, टीम ने राजस्व विभाग से प्राप्त सूची के अनुसार सभी PAF को कवर करने का लक्ष्य रखा। प्राथमिक डेटा मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों तकनीकों का उपयोग करके उत्पन्न किया गया था:

- मात्रात्मक तकनीक: प्राथमिक हितधारकों के बीच एचएच सर्वेक्षण के लिए पूर्व-परीक्षणित, संरचित प्रश्नावली ।
- गुणात्मक तकनीक: गुणात्मक तकनीकों में सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन (PRA), आजीविका विश्लेषण, वरीयता रैंकिंग, FGD और सार्वजनिक परामर्श शामिल थे।

2.5 सूचना अथवा डाटा स्रोतों के प्रयोग का पर्यवलोकन

SIA और SIMP को, भूमि अर्जन पुनर्वास और पुन्रस्थापन (सामाजिक समाघात निर्धारण और सहमति) नियम, 2015 में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता के अधिकार के फार्म-II के अनुसार फील्ड विजिट और स्टेकहोल्डर परामर्श के माध्यम से एकत्रित जानकारी, डेटा और आँकड़ों के आधार पर तैयार किया गया था, । नीचे आवश्यक डेटा एकत्र करने के लिए उपयोग किए जाने वाले डेटा स्रोतों का विवरण दिया गया है:

तालिका 2-3: सूचना और डेटा स्रोतों का अवलोकन

क्र स	सूचना	प्राथमिक स्रोत	गौण स्रोत
A	सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक पैरामीटर		
1.	परियोजना क्षेत्र में जनसंख्या का जनसांख्यिकीय विवरण		प्राथमिक जनगणना सार
	आयु, लिंग, जाति, धर्म	परिवार सर्वेक्षण	जनगणना, 2011
	साक्षरता, स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति	परिवार सर्वेक्षण	जनगणना, 2011
2.	गरीबी का स्तर	परिवार सर्वेक्षण फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा	
3.	कमजोर वर्ग	परिवार सर्वेक्षण	
4.	रिश्तेदारी पैटर्न और परिवार में महिलाओं की भूमिका	परिवार सर्वेक्षण	
5.	सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन।	फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा	
6.	प्रशासनिक संगठन	फोकस/ मुद्दा	सरकारी विभाग
7.	राजनीतिक संगठन।	समूह चर्चा	सरकारी विभाग
8.	नागरिक समाज संगठन और सामाजिक आंदोलन	फोकस/ मुद्दा	सरकारी विभाग
9.	भूमि का उपयोग और आजीविका	परिवार सर्वेक्षण, क्षेत्र सर्वेक्षण	भू अभिलेख , राजस्व ततिमे, जमाबंदी के दस्तावेज

सुन्नी बांध जल विद्युत् परियोजना (382 MW) के लीये की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

क्र स	सूचना	प्राथमिक स्रोत	गौण स्रोत
	कृषि और गैर-कृषि उपयोग	परिवार सर्वेक्षण, क्षेत्र सर्वेक्षण	भू अभिलेख , राजस्व ततीमा , जमाबंदी के दस्तावेज
	भूमि की गुणवत्ता - मिट्टी, पानी, पेड़ आदि।		
	पशु	परिवार सर्वेक्षण	
	औपचारिक और अनौपचारिक काम और रोजगार।	परिवार सर्वेक्षण, फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा	सोसिओ इकनोमिक कास्ट सेंसुस डाटा
	घरेलू श्रम और महिलाओं के काम का विभाजन	परिवार सर्वेक्षण	
	प्रवास	परिवार सर्वेक्षण, फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा	
	घरेलू आय का स्तर	परिवार सर्वेक्षण	
	आजीविका की प्राथमिकताएँ	परिवार सर्वेक्षण ,हितधारक परामर्श	
	खाद्य सुरक्षा	परिवार सर्वेक्षण ,हितधारक परामर्श , फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा	
10.	स्थानीय आर्थिक गतिविधियाँ	परिवार सर्वेक्षण ,हितधारक परामर्श , फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा	
	औपचारिक और अनौपचारिक, स्थानीय उद्योग	परिवार सर्वेक्षण ,हितधारक परामर्श , फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा	
	क्रेडिट तक पहुंच	परिवार सर्वेक्षण ,हितधारक परामर्श , फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा	
	मजदूरी दर	परिवार सर्वेक्षण ,हितधारक परामर्श , फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा	
	महिलाओं की विशिष्ट आजीविका गतिविधियाँ	परिवार सर्वेक्षण ,हितधारक परामर्श , फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा	

सुन्नी बांध जल विद्युत् परियोजना (382 MW) के लीये की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

क्र स	सूचना	प्राथमिक स्रोत	गौण स्रोत
11.	ऐसे कारक जो स्थानीय आजीविका में योगदान करते हैं	परिवार सर्वेक्षण ,हितधारक परामर्श , फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा	
	प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच	परिवार सर्वेक्षण ,हितधारक परामर्श , फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा	
	सामान्य संपत्ति संसाधन निजी संपत्ति	परिवार सर्वेक्षण ,हितधारक परामर्श , फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा	
	सड़कें, परिवहन	हितधारक परामर्श , फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, क्षेत्र सर्वेक्षण	
	सिंचाई की सुविधा	हितधारक परामर्श , फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, क्षेत्र सर्वेक्षण	
	बाजारों तक पहुंच	हितधारक परामर्श , फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, क्षेत्र सर्वेक्षण	
	पर्यटक के लिए स्थल	हितधारक परामर्श , फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, क्षेत्र सर्वेक्षण	
	आजीविका संवर्धन कार्यक्रम	हितधारक परामर्श , फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, क्षेत्र सर्वेक्षण	
	सहकारिता और अन्य आजीविका से संबंधित संघ	हितधारक परामर्श , फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, क्षेत्र सर्वेक्षण	
12.	परिवेश/वातावरण की गुणवत्ता	हितधारक परामर्श , फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, क्षेत्र सर्वेक्षण	
	धारणाएँ, सौंदर्य गुण, आसक्ति और आकांक्षाएँ	हितधारक परामर्श , फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, क्षेत्र सर्वेक्षण	
	सेटलमेंट का तरीका	परिवार सर्वेक्षण , फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा	भू अभिलेख , राजस्व ततिमे , जमाबंदी के दस्तावेज
	सामुदायिक और नागरिक स्थान	फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, हितधारक परामर्श	

सुन्नी बांध जल विद्युत् परियोजना (382 MW) के लीये की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

क्र स	सूचना	प्राथमिक स्रोत	गौण स्रोत
	धार्मिक और सांस्कृतिक अर्थ के स्थल	फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, क्षेत्र सर्वेक्षण	
	भौतिक अवसंरचना (जल आपूर्ति सीवरेज प्रणाली आदि सहित)	हितधारक परामर्श , फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, क्षेत्र सर्वेक्षण	
	सार्वजनिक सेवा संरचना (स्कूल, स्वास्थ्य सुविधाएं, आंगनवाड़ी केंद्र, सार्वजनिक वितरण प्रणाली)	हितधारक परामर्श , फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, क्षेत्र सर्वेक्षण	
	सुरक्षा, अपराध, हिंसा	हितधारक परामर्श , फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, क्षेत्र सर्वेक्षण	
	महिलाओं के लिए सामाजिक एकत्रीकरण बिंदु।	हितधारक परामर्श , फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, क्षेत्र सर्वेक्षण	
B	प्रमुख प्रभाव क्षेत्र		
1	भूमि, आजीविका और आय पर प्रभाव	परिवार सर्वेक्षण , फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा	
	रोजगार का स्तर और प्रकार	परिवार सर्वेक्षण , फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा	
	इंट्रा-घरेलू रोजगार पैटर्न	परिवार सर्वेक्षण , फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा	
	आय का स्तर	परिवार सर्वेक्षण , फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा	
	खाद्य सुरक्षा	परिवार सर्वेक्षण , फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा	
	जीवन स्तर	परिवार सर्वेक्षण , फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा	
	उत्पादक संसाधनों पर पहुंच और नियंत्रण	परिवार सर्वेक्षण , फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा	
	आर्थिक निर्भरता, या भेद्यता	परिवार सर्वेक्षण , फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा	
	स्थानीय अर्थव्यवस्था का विघटन	परिवार सर्वेक्षण , फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा	

सुन्नी बांध जल विद्युत् परियोजना (382 MW) के लीये की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

क्र स	सूचना	प्राथमिक स्रोत	गौण स्रोत
	प्रभाव का जोखिम	परिवार सर्वेक्षण , फोकस/मुद्दा समूह चर्चा	
	महिलाओं की आजीविका के विकल्प तक पहुँच	परिवार सर्वेक्षण , फोकस/मुद्दा समूह चर्चा	
2	भौतिक संसाधनों पर प्रभाव	हितधारक परामर्श , फोकस/मुद्दा समूह चर्चा, क्षेत्र सर्वेक्षण	
	प्राकृतिक संसाधनों, मिट्टी, हवा, पानी, जंगलों पर प्रभाव	हितधारक परामर्श , फोकस/मुद्दा समूह चर्चा, क्षेत्र सर्वेक्षण	
	आजीविका के लिए भूमि और सामान्य संपत्ति प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव	हितधारक परामर्श , फोकस/मुद्दा समूह चर्चा, क्षेत्र सर्वेक्षण	
3	निजी संपत्ति, सार्वजनिक सेवाओं और उपयोगिताओं पर प्रभाव	हितधारक परामर्श , फोकस/मुद्दा समूह चर्चा, क्षेत्र सर्वेक्षण	
	मौजूदा स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं की क्षमता	हितधारक परामर्श , फोकस/मुद्दा समूह चर्चा, क्षेत्र सर्वेक्षण	
	आवास सुविधाओं की क्षमता	हितधारक परामर्श , फोकस/मुद्दा समूह चर्चा, क्षेत्र सर्वेक्षण	
	स्थानीय सेवाओं की आपूर्ति पर दबाव।	हितधारक परामर्श , फोकस/मुद्दा समूह चर्चा, क्षेत्र सर्वेक्षण	
	बिजली और पानी की आपूर्ति, सड़कों, स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की पर्याप्तता	परिवार सर्वेक्षण , फोकस/मुद्दा समूह चर्चा, क्षेत्र सर्वेक्षण	
	निजी परिसंपत्तियों जैसे बोरवेल, अस्थायी शेड आदि पर प्रभाव।	परिवार सर्वेक्षण , फोकस/मुद्दा समूह चर्चा	
4	स्वास्थ्य पर असर	परिवार सर्वेक्षण , फोकस/मुद्दा समूह चर्चा, हितधारक परामर्श	
	प्रवास के कारण स्वास्थ्य पर असर पड़ता है	परिवार सर्वेक्षण , फोकस/मुद्दा समूह चर्चा, हितधारक परामर्श	

क्र स	सूचना	प्राथमिक स्रोत	गौण स्रोत
	परियोजना गतिविधियों के कारण स्वास्थ्य पर विशेष प्रभाव पड़ता है: (i) महिलाओं के स्वास्थ्य पर प्रभाव	परिवार सर्वेक्षण , फोकस/मुद्दा समूह चर्चा, हितधारक परामर्श	
	संस्कृति और सामाजिक सामंजस्य पर प्रभाव	परिवार सर्वेक्षण , फोकस/मुद्दा समूह चर्चा, हितधारक परामर्श	
	structures स्थानीय राजनीतिक संरचनाओं का परिवर्तन	परिवार सर्वेक्षण , फोकस/मुद्दा समूह चर्चा, हितधारक परामर्श	
	जनसांख्यिकीय परिवर्तन	परिवार सर्वेक्षण , फोकस/मुद्दा समूह चर्चा, हितधारक परामर्श	
	अर्थव्यवस्था-पारिस्थितिकी संतुलन में बदलाव	परिवार सर्वेक्षण , फोकस/मुद्दा समूह चर्चा, हितधारक परामर्श	
5	मानदंडों, विश्वासों, मूल्यों और सांस्कृतिक जीवन पर प्रभाव	परिवार सर्वेक्षण , फोकस/मुद्दा समूह चर्चा, हितधारक परामर्श	
	अपराध और अवैध गतिविधियाँ	परिवार सर्वेक्षण , फोकस/मुद्दा समूह चर्चा, हितधारक परामर्श	
	अव्यवस्था का तनाव	परिवार सर्वेक्षण , फोकस/मुद्दा समूह चर्चा, हितधारक परामर्श	
	पारिवारिक सामंजस्य के अलगाव का प्रभाव	परिवार सर्वेक्षण , फोकस/मुद्दा समूह चर्चा, हितधारक परामर्श	
	महिला के विरुद्ध क्रूरता	परिवार सर्वेक्षण , फोकस/मुद्दा समूह चर्चा, हितधारक परामर्श	

क्र स	सूचना	प्राथमिक स्रोत	गौण स्रोत
6	परियोजना चक्र के विभिन्न चरणों में प्रभाव। सामाजिक प्रभावों का प्रकार, समय, अवधि और तीव्रता परियोजना चक्र के चरणों के साथ निकटता से संबंधित होगी।	परिवार सर्वेक्षण , फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, हितधारक परामर्श	
	पूर्व-निर्माण चरण <ul style="list-style-type: none"> • सेवाओं के वितरण में रुकावट • उत्पादक निवेश में गिरावट • जमीन की अटकलें • अनिश्चितता का तनाव • 	परिवार सर्वेक्षण , फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, हितधारक परामर्श	
	निर्माण चरण <ul style="list-style-type: none"> • विस्थापन और पुनर्वास • प्रवासी निर्माण कार्यबल की सूजन • स्वास्थ्य उन लोगों पर प्रभाव डालता है जो निर्माण स्थल के करीब रहते हैं • 	परिवार सर्वेक्षण , फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, हितधारक परामर्श	
	ऑपरेशन का चरण <ul style="list-style-type: none"> • निर्माण चरण की तुलना में रोजगार के अवसरों में कमी • परियोजना के आर्थिक लाभ • नए बुनियादी ढांचे पर लाभ • सामाजिक संगठन के नए पैटर्न 	परिवार सर्वेक्षण , फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, हितधारक परामर्श	
	डी-कमीशन चरण <ul style="list-style-type: none"> • आर्थिक अवसरों का नुकसान • पर्यावरणीय गिरावट और आजीविका पर इसका प्रभाव 	परिवार सर्वेक्षण , फोकस/ मुद्दा समूह चर्चा, हितधारक परामर्श	

क्र स	सूचना	प्राथमिक स्रोत	गौण स्रोत
	प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव	परिवार सर्वेक्षण , फोकस/मुद्दा समूह चर्चा, हितधारक परामर्श	
	विभेदक प्रभाव <ul style="list-style-type: none"> महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और अलग-अलग लोगों पर प्रभाव जेंडर इम्पैक्ट असेसमेंट चेकलिस्ट और वल्नेरेबिलिटी और रेजिलिएशन मैपिंग जैसे उपकरणों के माध्यम से पहचाने जाने वाले प्रभाव 	परिवार सर्वेक्षण , फोकस/मुद्दा समूह चर्चा, हितधारक परामर्श	
	संचयी प्रभाव <ul style="list-style-type: none"> प्रश्न में परियोजना के लिए पहचाने गए प्रभावों के साथ क्षेत्र में अन्य परियोजनाओं के मापने योग्य और संभावित प्रभाव परियोजना क्षेत्र में सीधे तौर पर नहीं बल्कि स्थानीय या क्षेत्रीय रूप से आधारित लोगों पर प्रभाव। 	परिवार सर्वेक्षण , फोकस/मुद्दा समूह चर्चा, हितधारक परामर्श	

*स्रोत: SIA दल

2.6 प्रमुख पणधारियों के साथ परामर्श और की गई लोक सुनवाई के संक्षिप्त विचरण की अनुसूची

मसौदा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद सार्वजनिक सुनवाई आयोजित की जाएगी और फलस्वरूप प्रमुख हितधारकों और विवरण के साथ परामर्श के कार्यक्रम अंतिम रिपोर्ट में शामिल किए जाएंगे।

3 भूमि निर्धारण

यह अध्याय सुन्नी बांध HEP द्वारा अर्जित की जाने वाली कुल भूमि के विवरण पर केंद्रित है, जिसमें परियोजना के तहत विभिन्न गतिविधियों के लिए भूमि की कुल आवश्यकता और विभिन्न पंचायतों के तहत खरीदी जाने वाली भूमि का उपयोग शामिल है। उपलब्ध नक्शे और प्राथमिक सर्वेक्षण सहित प्राथमिक स्रोतों का उपयोग भूमि की प्रकृति, वर्तमान उपयोग और वर्गीकरण का पता लगाने के लिए किया जाता है। पिछले तीन वर्षों के लिए भूमि के स्वामित्व पैटर्न, हस्तांतरण और उपयोग पर एक संक्षिप्त विवरण का भी आकलन किया गया था।

3.1 भूमि तालिका की सूचना और प्राथमिक स्रोतों से जानकारी

शिमला और मंडी जिले में विभिन्न पंचायतों में सुन्नी HEP के तहत अधिगृहीत की जाने वाली भूमि के उद्देश्य या इच्छित उपयोग का विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

तालिका 3-1: भूमि सूची

जिले का नाम	उप मंडल का नाम	पंचायत	गाँव	वन भूमि (है०)	निजी भूमि	कुल भूमि	भू मालिकों के नाम	अर्जित होने वाले भवन/संरचना की संख्या
शिमला	शिमला	चेबड़ी	लुँसू	4-2235	1-1729	5-964	83	---
			खेरा	9-0884	1-0148	10-1032	329	1
				10-0556	---	10-0556		-
				10-3264	---	10-3264		-
				2-0605	8-9541	11-0146		-
		करयाली	जैशी	18-2007	3-7634	21-9641	306	6
			भराड़ा	17-5203	6-1109	23-6312	229	19
		ओगली	तलाह	23-5863	3-2225	26-8088	54	1
			ओगली	22-1604	4-7889	26-9493	112	5
			कोठी	6-3146	0-5522	6-668	33	1
			मालगी	5-5998	8-5650	14-1648	217	2
		बाग	बठोरा	7-2771	3-8662	11-1433	156	2

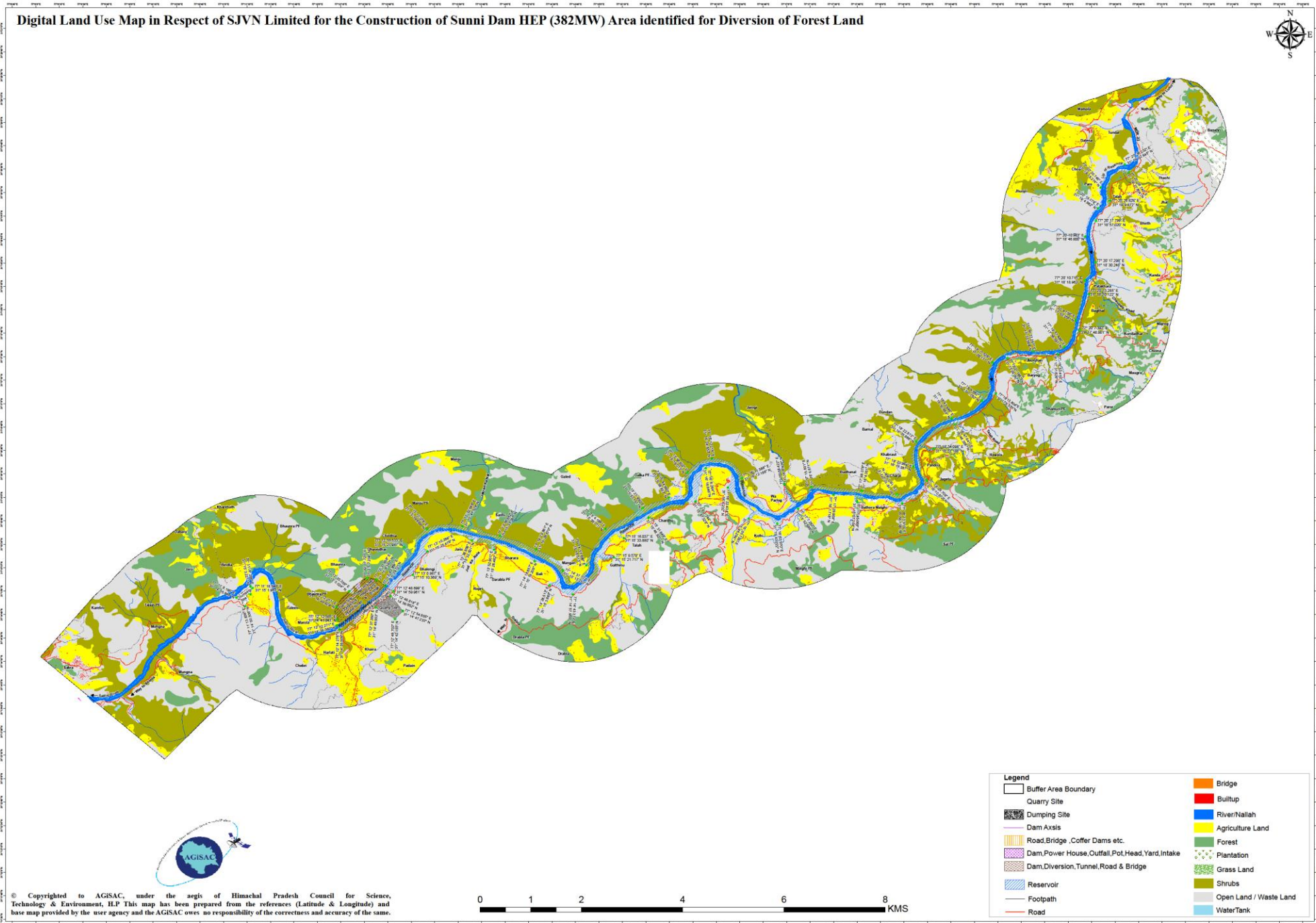
सुन्नी बांध जल विद्युत् परियोजना (382 MW) के लीये की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

जिले का नाम	उप मंडल का नाम	पंचायत	गाँव	वन भूमि (है०)	निजी भूमि	कुल भूमि	भू मालिकों के नाम	अर्जित होने वाले भवन/संरचना की संख्या
			पंदोआ	15-0423	0-4448	15-4871	20	3
			ग्रहना	6-5505	0-941	7-446	3	1
शिमला उप मंडल में कुल				158-0064	43-1498	201-1562	1542	41
	कोटगढ़/ कुमारसेन	मोगरा	झुझन	13-3032	0-8678	14-1710	64	1
			मज़ोग	11-8470	0-2365	12-0835	17	1
		बनाहर	भूट	2-7544	-	2-7544	-	-
			तलाह	9-4813	-	9-4813	-	-
कुमारसेन उपमंडल में कुल				37-3859	1-1043	38-4902	81	2
शिमला ज़िला में कुल				195-3923	44-2541	239-6464	1623	43
जिले का नाम	उप मंडल का नाम	पंचायत	गाँव	वन भूमि (है०)	निजी भूमि	कुल भूमि	भू मालिकों के नाम	अर्जित होने वाले भवन/संरचना की संख्या
मंडी	करसोग	बिंदला	भौरा	02-0000	-	02-0000	98	-
				30-8900	-	30-8900	-	-
				11-4338	2-9055	14-3393	-	-
			बलोग	13-0163	1-7213	14-7376	22	2
		सरत्योला	जकलीन	10-1163	0-4981	10-6144	14	-
			मांगन	20-6737	-	20-6737	-	-
		परलोग	फ़ाफ़न	16-6807	0-6308	17-3115	13	3
			खनौच	4-1160		4-1160	-	-
			परलोग	11-0502	1-1722	12-2224	13	-
			बेलुडाँक	37-9211	1-9823	39-9034	42	2
		शौट	खरयाली	25-7963	0-0321	25-8284	22	-
		नंज	चोआ	2-1234		2-1234	-	-
			तुंडल	5-9849	-	5-9849	-	-
मण्डी ज़िला में कुल				191-8027	8-9423	200-7450	224	7

*स्रोत: भू-अभिलेख और राजस्व विभाग

नक्शा 3.1: परियोजना क्षेत्र का भूमि उपयोग नक्शा

Digital Land Use Map in Respect of SJVN Limited for the Construction of Sunni Dam HEP (382MW) Area identified for Diversion of Forest Land



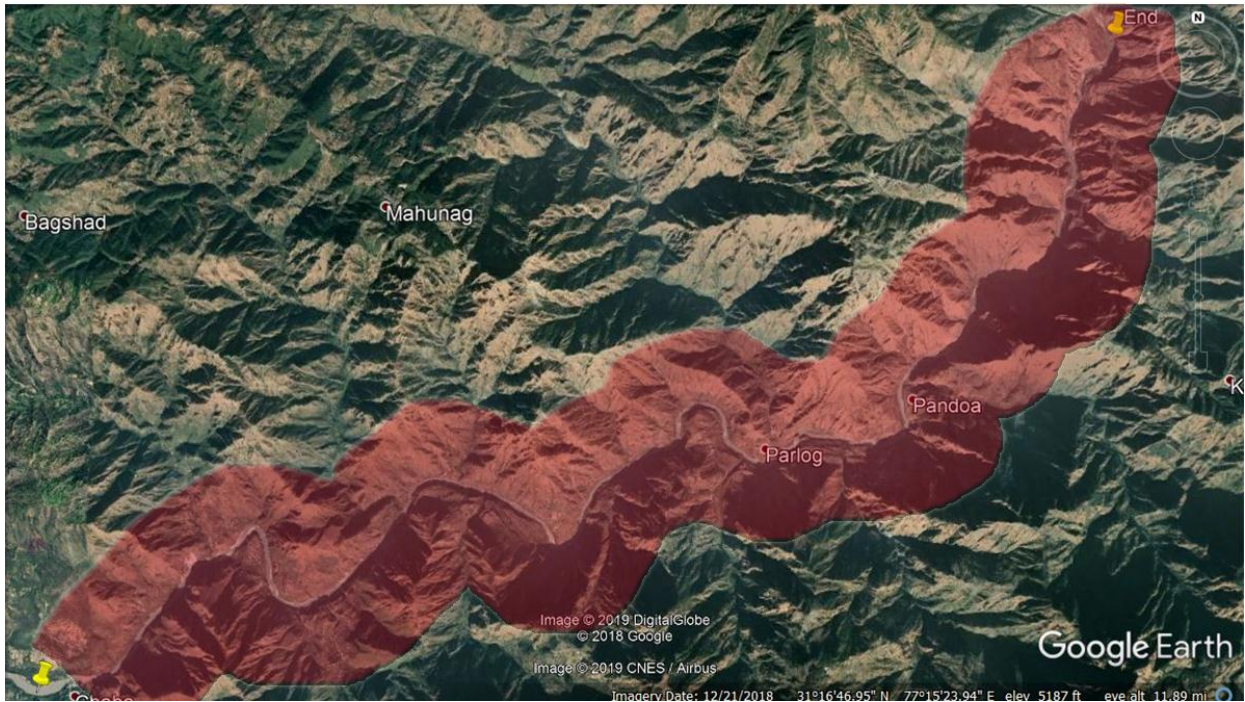
3.2 परियोजना के प्रभावों के आधीन पूर्ण समाघात क्षेत्र

सुन्नी HEP के लिए कुल भूमि की आवश्यकता 44,03,889 *sq. m* है। जिस में से कुल 38,71,915 *sq. m* वन भूमि है, 5,31,974 *sq. m* निजी भूमि है। नीचे दी गई तालिका कुल सरकारी और निजी भूमि को प्रदर्शित करती है और जिसका उपयोग किया जाना है:

तालिका 3-2: विभिन्न परियोजना घटकों के तहत क्षेत्र की आवश्यकता

क्र स	अंग	वनभूमि <i>sq. m</i>	निजीभूमि <i>sq. m</i>	कुल <i>sq. m</i>
1	जलाशय क्षेत्र	31,85,471	4,20,546	36,06,017
2	बांध परिसर और बिजलीघर	3,28,900	0	3,28,900
3	क्वारी साइट	1,03,264	0	1,03,264
4	डंपिंग साइट	42,235	11,729	53,964
5	सड़क पुल और नौकरी की सुविधा (कार्यालय सहित)	1,91,440	10,148	2,01,588
6	कालोनी क्षेत्र	20,605	89,551	1,10,156
	कुल	38,71,915	5,31,974	44,03,889

मानचित्र 3-2: परियोजना के प्रभाव में क्षेत्र



सुन्नी बांध जल विद्युत् परियोजना (382 MW) के लीये की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।



3.3 परियोजना के लिए भूमि की आवश्यकता

चयनित भूमि कुल 44,03,889 हेक्ट है। इसमें दो जिलों में कुल 20 गाँव शामिल हैं, शिमला और मंडी में 788 परिवार और 3,687 की कुल आबादी है। नीचे दिया गया है कि दोनों जिलों में अलग-अलग शीर्षकों के तहत अर्जित की गई भूमि का विवरण है :

तालिका 3-3: विभिन्न परियोजना घटकों के तहत क्षेत्र की आवश्यकता

क्र स .	अंग	ज़िला शिमला (हेक्ट)			ज़िला मण्डी (हेक्ट)			ज़िला शिमला व मण्डी में कुल भूमि (5+8)
		सरकारी भूमि	निजी भूमि	कुल भूमि	सरकारी भूमि	निजी भूमि	कुल भूमि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	डम्पिंग	4-22-35	1-17-29	5-39-64	-	-	-	5-39-64
2	सड़क और पुल	9-08-84	1-01-48	10-10-32	02-00-00	-	02-00-00	12-10-32
3	डैम एंड पावर हाउस	10-05-56	-	10-05-56	30-89-00	-	30-89-00	40-94-56
4	क्वारी साईट	10-32-64	-	10-32-64	-	-	-	10-32-64
5	कालोनी	2-06-05	8-95-41	11-01-46	-	-	-	11-01-46
6	जलाशय	159-63-79	33-11-23	192-75-02	158-91-27	8-94-23	167-85-50	360-60-52

सुन्नी बांध जल विद्युत् परियोजना (382 MW) के लीये की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

क्र स .	अंग	ज़िला शिमला (हेक्ट)			ज़िला मण्डी (हेक्ट)			ज़िला शिमला व मण्डी में कुल भूमि (5+8)
		सरकारी भूमि	निजी भूमि	कुल भूमि	सरकारी भूमि	निजी भूमि	कुल भूमि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
कुल		195-39-23	44-25-41	239-64-64	191-80-27	8-94-23	200-74-50	440-39-14

*स्रोत: सतलुज जल विद्युत् निगम (SJVN)

3.4 परियोजना के लिए आवश्यक भूमि के उपयोग हेतु प्रस्तावित पहले से ही खरीदी गई भूमि, अलग-अलग, लीज़ / अर्जित और प्रत्येक भूखंड के लिए प्रस्तावित उपयोग

इस SIA रिपोर्ट की तैयारी के समय, प्रोजेक्ट गतिविधियों के लिए किसी भी भूमि के लिए आवश्यक बाँडी को खरीदा या लिया नहीं गया है।

तालिका 3-1: अर्जित भूमि का उपयोग

ज़िला	उपमंडल	पंचायत	गाँव	कुल भूमि (हेक्ट)	प्रस्तावित उपयोग
शिमला	शिमला	चेबड़ी	लुँसू	5-3964	डम्पिंग
			खेरा	10-1032	सड़क व पुल
				10-0556	बांध
				10-3264	क्वारी
				11-0146	कालोनी
		खरयाली	जैशी	21-9641	जलाशय
			भरारा	23-6312	जलाशय
		ओगली	तलाह	26-8088	जलाशय
			ओगली	26-9493	जलाशय

सुन्नी बांध जल विद्युत् परियोजना (382 MW) के लीये की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

ज़िला	उपमंडल	पंचायत	गाँव	कुल भूमि (हेक्ट)	प्रस्तावित उपयोग	
			कोठी	6-8668	जलाशय	
			मालगी	14-1648	जलाशय	
		बाग	बठोरा	11-1433	जलाशय	
			पंदोआ	15-4871	जलाशय	
			ग्रहना	7-2446	जलाशय	
Total in Shimla Division				201-1562		
	कोटगढ़/कुमारसेन	मोगरा	झुँझन	14-1710	जलाशय	
				मझरोग	12-0835	जलाशय
			बनाहर	भुट्ट	2-7544	जलाशय
				तलाह	9-4813	जलाशय
कोटगढ़/कुमारसेन में कुल				38-4902		
ज़िला शिमला में कुल				239-6464		
ज़िला	उपमंडल	पंचायत	गाँव	कुल भूमि (हेक्ट)	अंग	
मंडी	करसोग	बिंदला	भौरा	02-0000	सड़क व पुल	
				30-8900	बांध & P/H	
				14-3393	जलाशय	
			बलोग	14-7376	जलाशय	
		सरत्योला	जकलीन	10-6144	जलाशय	
			मांगन	20-6737	जलाशय	
		परलोग	फ़ाफ़न	17-3115	जलाशय	
			खनौच	4-1160	जलाशय	

सुन्नी बांध जल विद्युत् परियोजना (382 MW) के लीये की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

ज़िला	उपमंडल	पंचायत	गाँव	कुल भूमि (हेक्ट)	प्रस्तावित उपयोग
			परलोग	12-2224	जलाशय
			बेलुढाँक	39-9034	जलाशय
		शौट	खरयाली	25-8284	जलाशय
		नँज	चोआ	2-1234	जलाशय
			तुंडल	5-9849	जलाशय
ज़िला मण्डी में कुल .				200-7450	

*स्रोत: सतलुज जल विद्युत् निगम

3.5 परियोजना के लिए अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि की मात्रा और स्थान

सुन्नी HEP को 755 खसरा वाले शिमला और मंडी जिले के 20 गांवों में फैली 53.1964 हेक्टेयर निजी भूमि के अर्जन की आवश्यकता है। नीचे दिए गए अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि की मात्रा और स्थान की एक विस्तृत सूची है:

तालिका 3-2: अर्जन के अंतर्गत आ रही भूमि की मात्रा

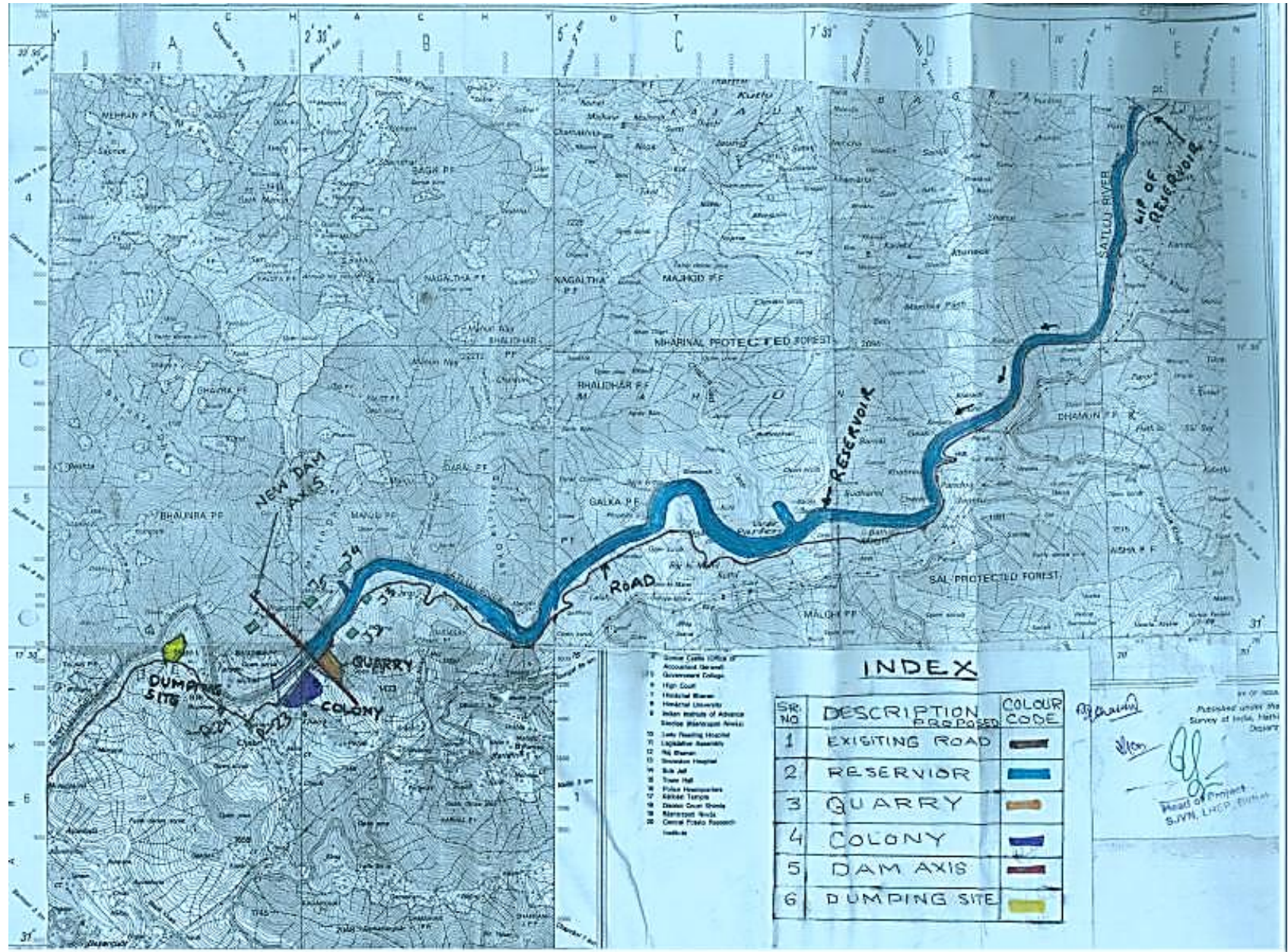
ज़िला	पंचायत	क्र स	गाँव	निजी भूमि (हेक्ट)	कुल खसरा संख्या
शिमला	चेबड़ी	1.	लुँसू	1.1729	7
		2.	खेरा	9.9689	120
	करयाली	3.	जैशी	3.7634	100
		4.	भराड़ा	6.1109	71
	ओगली	5.	तलाह	3.2225	35
		6.	ओगली	4.7889	61
		7.	कोठी	0.5522	3
		8.	मालगी	8.565	135
	बाग	9.	बठोरा	3.8662	47
		10.	पंदोआ	0.4448	12
		11.	ग्रहना	0.6941	2
	मोगरा	12.	झुँझन	0.8678	16

सुन्नी बांध जल विद्युत् परियोजना (382 MW) के लीये की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

ज़िला	पंचायत	क्र स	गाँव	निजी भूमि (हेक्ट)	कुल खसरा संख्या
		13.	मझरोग	0.2365	5
Mandi	बिंदला	14.	भौरा	2.9055	65
		15.	बलोग	1.7213	37
	सरत्योला	16.	जकलीन	0.4981	7
	परलोग	17.	फ़ाफ़न	0.6308	11
		18.	परलोग	1.1722	8
		19.	बेलुढाँक	1.9823	11
	शौट	20.	खरयाली	0.0321	2
कुल				53.1964	755

* स्रोत: सतलुज जल विद्युत् निगम

नक्शा 3-1: प्रस्तावित अर्जन का स्थान



3.6 भूमि का वर्तमान उपयोग ,प्रकृति, और वर्गीकरण

परियोजना के तहत दोनों जिलों में प्राप्त होने वाली कुल निजी भूमि में से 63% की खेती की जाती है और 37% का उपयोग नहीं किया जाता है। अर्जन के तहत कुल भूमि में से शिमला जिले में 59% भूमि पर खेती की जाती है और अर्जन के तहत 41% भूमि का उपयोग नहीं किया जाता है। इसी तरह, मंडी जिले में अर्जन के तहत कुल भूमि में से 83% भूमि पर खेती की जाती है और 17% भूमि का उपयोग नहीं किया जाता है। नीचे दी गई तालिका दोनों जिलों में फसल के पैटर्न और फसलों के प्रकार देती है:

तालिका 3-2 : अर्जन के तहत भूमि का वर्तमान उपयोग

क्र स	वर्ग	फसल का प्रकार	ज़िला	
			शिमला (हेक्ट)	मण्डी (हेक्ट)
1	खेती योग्य	धानी अक्वल	-	4-49-64
2		धानी दोयम	-	0-22-14
3		बरानी अक्वल	-	01-37-13
4		बरानी दोयम	-	1-25-39
5		बगीचा बरानी फलदार	-	0-08-72
कुल कृषि			-	7-43-02
6	खेती के लिए अनप्रयुक्त	बंजर काबील काश्त	-	0-42-61
7		खड़ेटर	-	00-00-65
8		बनी	-	0-71-70
9		घर मुमकीन	-	0-36-25
कुल कृषि अनप्रयुक्त			-	01-51-21
10	खेती योग्य	क्यार अक्वल	4-79-74	-
11		क्यार दोयम	3-68-43	-
12		बाखल अक्वल	9-69-53	-
13		बाखल दोयम	7-59-31	-
14		बगीचा बा अक्वल फलदार	0-2-96	-
15		बागीच बा दोयम फलदार	0-17-60	-
16		बागीच बा दोयम बिला फलदार	0-07-41	-
कुल कृषि			26-24-98	-
17	खेती के लिए अनप्रयुक्त	बंजर कदीम	6-53-08	-
18		बंजर जदीद	0-24-93	-
19		घासनी	9-84-60	-

सुन्नी बांध जल विद्युत् परियोजना (382 MW) के लीये की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

क्र स	वर्ग	फसल का प्रकार	ज़िला	
			शिमला (हेक्ट)	मण्डी (हेक्ट)
20		गैर मुमकीं	1-37-82	-
कुल कृषि अनप्रयुक्त			18-00-43	-
कुल			44-35-41	8-94-23

* स्रोत: सतलुज जल विद्युत् निगम

3.7 सिंचाई क्रम

अर्जन के तहत कुल 53.19 हेक्टेयर भूमि में से केवल 9.44 हेक्टेयर भूमि सिंचित है और शेष 43.75 हेक्टेयर भूमि गैर-सिंचित है। नीचे दी गई तालिका में शिमला और मंडी जिले में अर्जन के तहत 26 गांवों में सिंचित और गैर-सिंचित भूमि का विस्तृत वितरण दिखाया गया है:

तालिका 3-3: अर्जन के तहत भूमि का सिंचाई क्रम

क्र स	ज़िला	गाँव	सिंचित भूमि (हेक्टेयर)	असिंचित भूमि (हेक्टेयर)	कण भूमि (हेक्टेयर)
1	शिमला	लुँसू	-	1-17-29	1-17-29
2		खैरा	-	9-96-89	9-96-89
3		जैशी	1-30-35	2-45-99	3-76-34
4		भराड़ा	0-70-79	5-40-30	6-11-09
5		तलाह	-	3-22-25	3-22-25
6		ओगली	-	4-78-89	4-78-89
7		कोठी	0-54-31	0-00-91	0-55-22
8		मालगी	0-89-77	7-66-73	8-56-50
9		बठोरा	1-09-42	2-77-20	3-86-62
10		पंदोआ	-	0-44-48	0-44-48
11		ग्रहना	-	0-69-41	0-69-41
12		झुँझन	-	0-86-78	0-86-78
13		मझरोग	0-18-15	0-05-50	0-23-65

सुन्नी बांध जल विद्युत् परियोजना (382 MW) के लीये की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

क्र स	ज़िला	गाँव	सिंचित भूमि (हेक्टेयर)	असिंचित भूमि (हेक्टेयर)	कण भूमि (हेक्टेयर)
शिमला में कुल			4-72-79	39-52-62	44-25-41
1	मंडी	भौरा	2-12-95	00-77-60	2-90-55
2		बलोग	1-58-46	0-13-67	1-72-13
3		जकलीन	0-22-13	0-27-68	0-49-81
4		फ़ाफ़न	-	0-63-08	0-63-08
5		परलोग	0-78-24	0-38-98	1-17-22
6		बेलुढाँक	-	1-98-23	1-98-23
7		खरयाली	-	0-03-21	0-03-21
मंडी में कुल			4-71-78	4-22-45	8-94-23
Total			09-44-57	43-75-07	53-19-64

*स्रोत: सतलुज जल विद्युत निगम

3.8 जोत / भूमि का आकार, स्वामित्व पैटर्न

जिला शिमला और मंडी के कुल 1847 शीर्षक धारकों में से जिनकी जमीन / संपत्ति परियोजना के लिए अर्जित हो रही है, 73% पुरुष हैं और 27% महिलाएँ हैं। साथ ही, 91% शीर्षक धारकों के पास संयुक्त स्वामित्व है और 9% शीर्षकधारक भूमि / संपत्ति के एकल मालिक हैं।

तालिका 3-4: होल्डिंग/स्वामित्व आकार और पैटर्न

ज़िला	पंचायत	क्रमांक	गाँव	कुल खसरा न०	खसरा का कुल क्षेत्र	एकल स्वामित्व	संयुक्त स्वामित्व	स्वामित्व संख्या
शिमला	चेबरी	1.	लुँसू	7	1.1729	0	7	83
		2.	खेरा	120	9.9689	3	117	329
	खरयाली	3.	जैशी	100	3.7634	15	85	306
		4.	भरारा	71	6.1109	1	70	229
	ओगली	5.	तलाह	35	3.2225	8	27	54
		6.	ओगली	61	4.7889	7	54	112
		7.	कोठी	3	0.5522	0	3	33

सुन्नी बांध जल विद्युत् परियोजना (382 MW) के लीये की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

ज़िला	पंचायत	क्रमांक	गाँव	कुल खसरा न०	खसरा का कुल क्षेत्र	एकल स्वामित्व	संयुक्त स्वामित्व	स्वामित्व संख्या
	बाग	8.	मालगी	135	8.565	2	133	217
		9.	बठोरा	47	3.8662	1	46	156
		10.	पंदोआ	12	0.4448	3	9	20
	मोगरा	11.	ग्रहना	2	0.6941	0	2	3
		12.	झुंझन	16	0.8678	1	15	64
		13.	मझरोग	5	0.2365	0	5	17
मण्डी	बिंदला	14.	भौरा	65	2.9055	4	61	98
		15.	बलोग	37	1.7213	2	35	22
	सरत्योला	16.	जकलीन	7	0.4981	0	7	14
	परलोग	17.	फ़ाफ़न	11	0.6308	3	8	13
		18.	परलोग	8	1.1722	2	6	13
		19.	बेलुढाँक	11	1.9823	2	9	42
	शौट	20.	खरयाली	2	0.0321	0	2	22
कुल			755	53.1964	54	701	1847.00	

*स्रोत: भू-अभिलेख और राजस्व विभाग

जैसा कि अर्जन के तहत 20 गांवों में कुल 755 खसरों में से ऊपर तालिका में दिखाया गया है, 54 खसरों में एकल मालिक हैं और 701 खसरों में संयुक्त मालिक हैं।

तालिका 3-5: स्वामित्व का पैटर्न

क्र स	ज़िला	कुल मालिक	संयुक्त स्वामित्व	एकल स्वामित्व
1	शिमला	1623	1584	39
2	मण्डी	224	8	8
कुल		1847	1592	47

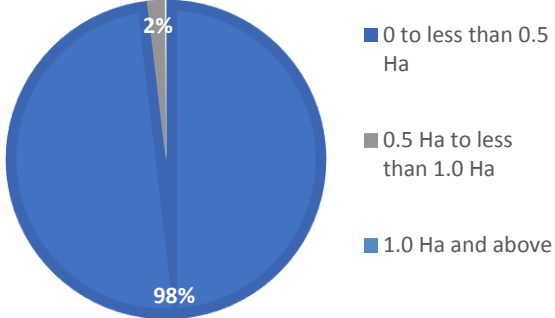
*स्रोत: भू-अभिलेख और राजस्व विभाग

कुल 1847 शीर्षकधारियों में से 1592 (97%) संयुक्त मालिक हैं और 47 (3%) एकल मालिक हैं।

पूरे परियोजना क्षेत्र में छोटी भूमि जोत का पूर्वानुभव है। होल्डिंग का औसत आकार 0.0705 हेक्टेयर है। कुल 755 शीर्षकधारियों में से, 98% का आकार 0.5 हेक्टेयर से कम है, उनमें से केवल 2% के पास 0.5 हेक्टेयर से 1.0 हेक्टेयर के बीच है और केवल एक व्यक्ति के पास 1.0 हेक्टेयर से अधिक की जोत भूमि है जो परियोजना के लिए अर्जित हो रही है।

तालिका 3-10: जोत का आकार

वर्ग	स्वामित्व संख्या
0 से 0.5 हेक्टेयर के बीच	741
0.5 हेक्टेयर से 1.0 हेक्टेयर के बीच	13
1.0 हेक्टेयर से जादा	1
कुल	755



*स्रोत: भू अभिलेख और राजस्व विभाग

3.9 भूमि वितरण और आवासीय मकानों की संख्या

शिमला और मंडी जिलों में क्रमशः 1623 और 224 शीर्षक धारक हैं। कुल 614 खसरा में शिमला से 44.25 हेक्टेयर का कुल क्षेत्रफल और मंडी से 8.94 हेक्टेयर का कुल 141 खसरा सुन्नी परियोजना के लिए अर्जित हो रहा है। 146 मालिकों के साथ कुल 38 आवासीय मकान अर्जन के तहत आ रहे हैं, 31 शिमला से और 7 मंडी जिले से हैं।

नीचे दी गई सारणी में दोनों जिलों में भूमि ग्राम वार का विस्तृत वितरण दिया गया है:

तालिका 3-6: भूमि वितरण और आवासीय घरों की संख्या

क्रमांक	ज़िला	गाँव	कुल खसरा संख्या	स्वामित्व संख्या	घरों की संख्या	स्वामियों की संख्या जिनके घर अर्जित होने हैं	कुल भूमि (Ha)
1	शिमला	लुँसू	7	83	-	-	1-17-29
2		खैरा	120	329	1	28	9-96-89
3		जैशी	100	306	2	11	3-76-34

सुन्नी बांध जल विद्युत् परियोजना (382 MW) के लीये की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

क्रमांक	ज़िला	गाँव	कुल खसरा संख्या	स्वामित्व संख्या	घरों की संख्या	स्वामियों की संख्या जिनके घर अर्जित होने है	कुल भूमि (Ha)	
4		भराड़ा	71	229	18	36	6-11-09	
5		तलाह	35	54	1	1	3-22-25	
6		ओगली	61	112	3	8	4-78-89	
7		कोठी	3	33	1	1	0-55-22	
8		मालगी	135	217	1	7	8-56-50	
9		बठोरा	47	156	-	-	3-86-62	
10		पंदोआ	12	20	2	11	0-44-48	
11		ग्रहना	2	3	1	3	0-69-41	
12		झूझन	16	64	1	15	0-86-78	
13		मझरोग	5	17	-	-	0-23-65	
शिमला में कुल			614	1623	&	121	44-25-41	
1		मंडी	भौरा	65	98	-	-	2-90-55
2			बलोग	37	22	2	2	1-72-13
3	जकलीन		7	14	-	-	0-49-81	
4	फ़ाफ़न		&	13	3	13	0-63-08	
5	परलोग		11	13	-	-	1-17-22	
6	बेलुढाँक		&	42	2	10	1-98-23	
7	खरयाली		8	22	-	-	0-03-21	
मंडी में कुल			141	224	7	25	8-94-23	
कुल			755	1847	38	146	53-19-64	

*स्रोत: सतलुज जल विद्युत निगम

3.10 भूमि की कीमतें और हाल ही में स्वामित्व और हस्तांतरण में परिवर्तन

पिछले तीन वर्षों (2016-17, 2017-18 और 2018-19) के लिए सर्कल दरें राजस्व विभाग से नीचे उल्लिखित श्रेणियों के लिए प्राप्त की गई है

श्रेणी- I (0-25 मीटर)

संपत्ति / भूमि जिसमें संबंधित खसरा नंबर या उसके किसी भी बिंदु पर सड़क से 25 मीटर की दूरी तक जमीन है।

श्रेणी- II (20% <आधार दर) (25-50 मीटर)

संपत्ति / भूमि जिसमें संबंधित खसरा संख्या या उसके भाग का कोई बिंदु ऐसी सड़क से 25 से 50 मीटर की दूरी पर नहीं है।

श्रेणी- III (40% <आधार दर) (50-100 मीटर)

संपत्ति / भूमि जिसमें संबंधित खसरा संख्या या उसके भाग का कोई बिंदु ऐसी सड़क से 50 से 100 मीटर की दूरी पर नहीं है।

श्रेणी- IV (50% <आधार दर) (100-1000 मीटर)

संपत्ति / भूमि जिसमें संबंधित खसरा नंबर या उसके भाग का कोई बिंदु ऐसी सड़क से 100 से 1000 मीटर की दूरी पर नहीं है।

श्रेणी-वी (60% <आधार दर) (> 1000 मीटर)

संपत्ति / भूमि जिसमें संबंधित खसरा संख्या या उसके भाग का कोई बिंदु ऐसी सड़क से 1000 मीटर या उससे अधिक नहीं है।

राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग या अन्य सड़कों से विभिन्न दूरी पर स्थित खेती और गैर-खेती वाली भूमि के प्रत्येक उप-श्रेणी के लिए विभिन्न दरें उपलब्ध हैं।

संबंधित पटवार सर्कल के तहत विभिन्न गांवों में खेती और गैर-खेती की जमीनों के मूल्य नीचे तालिका में प्रस्तुत किए गए हैं। प्रस्तुत सर्किल दरें भूमि की प्रति बिस्वा/ रुपये में हैं और पिछले तीन वर्षों में प्रचलित दरों में उच्चतम हैं।

सुन्नी बांध जल विद्युत् परियोजना (382 MW) के लीये की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

तालिका 3 12: 1-04-2018 से 31-03-2019 तक परियोजना क्षेत्र की सर्किल दरें

क्रमांक	ज़िला	पतवार सर्कल	पंचायत	गाँव	क्षेत्र इकाई	सड़क प्रकार	वर्ग -I (0-25 मी०)		वर्ग -II(20% < आधार कीमत) (25-50 मी०)		वर्ग -III(40% < आधार कीमत)(50-100 मी०)		वर्ग -IV(50% < आधार कीमत)(100-1000 मी०)		वर्ग -V(60% < आधार कीमत)(>100 मी०)	
							खेती में प्रयुक्त	खेती में अनप्रयुक्त	खेती में प्रयुक्त	खेती में अनप्रयुक्त	खेती में प्रयुक्त	खेती में अनप्रयुक्त	खेती में प्रयुक्त	खेती में अनप्रयुक्त	खेती में प्रयुक्त	खेती में अनप्रयुक्त
1	मंडी	तलहाड	बिंदला	भौरा	वर्ग मी०	राष्ट्रीय राजमार्ग	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						राज्य राजमार्ग	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						अन्य सड़क	1532	1277	1226	1022	919	766	766	638	613	511
2	मंडी	तलहाड	बलोग	वर्ग मी०	राष्ट्रीय राजमार्ग	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					राज्य राजमार्ग	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					अन्य सड़क	1532	1277	1226	1022	919	766	766	638	613	511	
3	परलोग	तलहाड	फ़ाफ़न	वर्ग मी०	राष्ट्रीय राजमार्ग	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					राज्य राजमार्ग	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					अन्य सड़क	863	719	690	575	518	431	431	360	345	288	

सुन्नी बांध जल विद्युत् परियोजना (382 MW) के लीये की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

क्रमांक	ज़िला	पतवार सर्कल	पंचायत	गाँव	क्षेत्र इकाई	सड़क प्रकार	वर्ग -I (0-25 मी०)		वर्ग -II(20% < आधार कीमत)(25-50 मी०)		वर्ग -III(40% < आधार कीमत)(50-100 मी०)		वर्ग -IV(50% < आधार कीमत)(100-1000 मी०)		वर्ग -V(60% < आधार कीमत)(>100 0 मी०)	
							खेती में प्रयुक्त	खेती में अनप्रयुक्त	खेती में प्रयुक्त	खेती में अनप्रयुक्त	खेती में प्रयुक्त	खेती में अनप्रयुक्त	खेती में प्रयुक्त	खेती में अनप्रयुक्त	खेती में प्रयुक्त	खेती में अनप्रयुक्त
4	परलोग	परलोग	परलोग	वर्ग मी०	राष्ट्रीय राजमार्ग	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					राज्य राजमार्ग	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					अन्य सड़क	863	719	690	575	518	431	431	360	345	288	
5	परलोग	बेलुढाँक	वर्ग मी०	राष्ट्रीय राजमार्ग	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				राज्य राजमार्ग	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				अन्य सड़क	583	486	467	389	350	292	292	243	233	194		
6	परलोग	शौट	खरयाली	वर्ग मी०	राष्ट्रीय राजमार्ग	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					राज्य राजमार्ग	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					अन्य सड़क	558	465	446	372	335	279	279	232	223	186	

सुन्नी बांध जल विद्युत् परियोजना (382 MW) के लीये की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

क्रमांक	ज़िला				क्षेत्र इकाई	सड़क प्रकार	वर्ग -I (0-25 मी०)		वर्ग -II(20% < आधार कीमत (25-50 मी०)		वर्ग -III(40% < आधार कीमत)(50-100 मी०)		वर्ग -IV(50% < आधार कीमत)(100-1000 मी०)		वर्ग -V(60% < आधार कीमत)(>1000 मी०)	
							खेती में प्रयुक्त	खेती में अनप्रयुक्त	खेती में प्रयुक्त	खेती में अनप्रयुक्त	खेती में प्रयुक्त	खेती में अनप्रयुक्त	खेती में प्रयुक्त	खेती में अनप्रयुक्त	खेती में प्रयुक्त	खेती में अनप्रयुक्त
7	सुरत्योला	सुरत्योला	जकलीन	वर्ग मी०	राष्ट्रीय राजमार्ग	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					राज्य राजमार्ग	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					अन्य सड़क	1122	935	898	748	673	561	561	468	449	374	
8	करयाली	करयाली	भराड़ा	वर्ग मी०	राष्ट्रीय राजमार्ग	1692	1410	1354	1128	1015	846	846	705	677	564	
					राज्य राजमार्ग	1410	1175	1128	940	846	705	705	588	564	470	
					अन्य सड़क	1128	940	902	752	677	564	564	470	451	376	
9	करयाली	करयाली	जैशी	वर्ग मी०	राष्ट्रीय राजमार्ग	1692	1410	1354	1128	1015	846	846	705	677	564	
					राज्य राजमार्ग	1410	1175	1128	940	846	705	705	588	564	470	
					अन्य सड़क	1128	940	902	752	677	564	564	470	451	376	
10	कांगल	मोगरा	मझरोग	वर्ग	राष्ट्रीय राजमार्ग	857	714	685	571	514	428	428	357	343	286	

सुन्नी बांध जल विद्युत् परियोजना (382 MW) के लीये की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

क्रमांक	ज़िला	पतवार सर्कल	पंचायत	गाँव	क्षेत्र इकाई	सड़क प्रकार	वर्ग -I (0-25 मी०)		वर्ग -II(20% < आधार कीमत)(25-50 मी०)		वर्ग -III(40% < आधार कीमत)(50-100 मी०)		वर्ग -IV(50% < आधार कीमत)(100-1000 मी०)		वर्ग -V(60% < आधार कीमत)(>1000 मी०)	
							खेती में प्रयुक्त	खेती में अनप्रयुक्त	खेती में प्रयुक्त	खेती में अनप्रयुक्त	खेती में प्रयुक्त	खेती में अनप्रयुक्त	खेती में प्रयुक्त	खेती में अनप्रयुक्त	खेती में प्रयुक्त	खेती में अनप्रयुक्त
							राज्य राजमार्ग	अन्य सड़क	राष्ट्रीय राजमार्ग	राज्य राजमार्ग	अन्य सड़क	राष्ट्रीय राजमार्ग	राज्य राजमार्ग	अन्य सड़क	राष्ट्रीय राजमार्ग	राज्य राजमार्ग
11	कांगल			झुंझन	वर्ग मी०	राष्ट्रीय राजमार्ग	857	714	685	571	514	428	428	357	343	286
						राज्य राजमार्ग	714	595	571	476	428	357	357	298	286	238
						अन्य सड़क	571	476	457	381	343	286	286	238	228	190
12	चेबडी	चेबडी	लुसू	वर्ग मी०	राष्ट्रीय राजमार्ग	1692	1410	1354	1128	1015	846	846	705	677	564	
					राज्य राजमार्ग	1410	1175	1128	940	846	705	705	588	564	470	
					अन्य सड़क	1128	940	902	752	677	564	564	470	451	376	
13	चेबडी		खेरा	वर्ग मी०	राष्ट्रीय राजमार्ग	1692	1410	1354	1128	1015	846	846	705	677	564	
					राज्य राजमार्ग	1410	1175	1128	940	846	705	705	588	564	470	

सुन्नी बांध जल विद्युत् परियोजना (382 MW) के लीये की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

क्रमांक	ज़िला	पतवार सर्कल	पंचायत	गाँव	क्षेत्र इकाई	सड़क प्रकार	वर्ग -I (0-25 मी०)		वर्ग -II(20% < आधार कीमत)(25-50 मी०)		वर्ग -III(40% < आधार कीमत)(50-100 मी०)		वर्ग -IV(50% < आधार कीमत)(100-1000 मी०)		वर्ग -V(60% < आधार कीमत)(>100 0 मी०)	
							खेती में प्रयुक्त	खेती में अनप्रयुक्त	खेती में प्रयुक्त	खेती में अनप्रयुक्त	खेती में प्रयुक्त	खेती में अनप्रयुक्त	खेती में प्रयुक्त	खेती में अनप्रयुक्त	खेती में प्रयुक्त	खेती में अनप्रयुक्त
							अन्य सड़क	राष्ट्रीय राजमार्ग	राज्य राजमार्ग	अन्य सड़क	राष्ट्रीय राजमार्ग	राज्य राजमार्ग	अन्य सड़क	राष्ट्रीय राजमार्ग	राज्य राजमार्ग	अन्य सड़क
14	ओगली	ओगली	तलाह	वर्ग मी०	राष्ट्रीय राजमार्ग	2527	2106	2022	1685	1516	1264	1264	1053	1011	847	
					राज्य राजमार्ग	2106	1755	1685	1404	1264	1053	1053	878	842	702	
					अन्य सड़क	1685	1404	1348	1123	1011	842	842	702	674	562	
15	ओगली	ओगली	ओगली	वर्ग मी०	राष्ट्रीय राजमार्ग	2527	2106	2022	1685	1516	1264	1264	1053	1011	847	
					राज्य राजमार्ग	2106	1755	1685	1404	1264	1053	1053	878	842	702	
					अन्य सड़क	1685	1404	1348	1123	1011	842	842	702	674	562	
16	ओगली	मालगी	वर्ग मी०	राष्ट्रीय राजमार्ग	2527	2106	2022	1685	1516	1264	1264	1053	1011	847		
				राज्य राजमार्ग	2106	1755	1685	1404	1264	1053	1053	878	842	702		
				अन्य सड़क	1685	1404	1348	1123	1011	842	842	702	674	562		

सुन्नी बांध जल विद्युत् परियोजना (382 MW) के लीये की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

क्रमांक	ज़िला	पतवार सर्कल	पंचायत	गाँव	क्षेत्र इकाई	सड़क प्रकार	वर्ग -I (0-25 मी०)		वर्ग -II(20% < आधार कीमत (25-50 मी०)		वर्ग -III(40% < आधार कीमत)(50-100 मी०)		वर्ग -IV(50% < आधार कीमत)(100-1000 मी०)		वर्ग -V(60% < आधार कीमत)(>1000 मी०)	
							खेती में प्रयुक्त	खेती में अनप्रयुक्त	खेती में प्रयुक्त	खेती में अनप्रयुक्त	खेती में प्रयुक्त	खेती में अनप्रयुक्त	खेती में प्रयुक्त	खेती में अनप्रयुक्त	खेती में प्रयुक्त	खेती में अनप्रयुक्त
17	ओगली			कोठी	वर्ग मी०	राष्ट्रीय राजमार्ग	2527	2106	2022	1685	1516	1264	1264	1053	1011	847
						राज्य राजमार्ग	2106	1755	1685	1404	1264	1053	1053	878	842	702
						अन्य सड़क	1685	1404	1348	1123	1011	842	842	702	674	562
18	सैज़			बठोरा	वर्ग मी०	राष्ट्रीय राजमार्ग	2527	2106	2022	1685	1516	1264	1264	1053	1011	847
						राज्य राजमार्ग	2106	1755	1685	1404	1264	1053	1053	878	842	702
						अन्य सड़क	1685	1404	1348	1123	1011	842	842	702	674	562
19	सैज़		बाग	पंदोआ	वर्ग मी०	राष्ट्रीय राजमार्ग	2527	2106	2022	1685	1516	1264	1264	1053	1011	847
						राज्य राजमार्ग	2106	1755	1685	1404	1264	1053	1053	878	842	702
						अन्य सड़क	1685	1404	1348	1123	1011	842	842	702	674	562
20	सैज़			ग्रहना	वर्ग	राष्ट्रीय राजमार्ग	983	819	786	655	590	491	491	410	393	328

सुन्नी बांध जल विद्युत् परियोजना (382 MW) के लीये की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

क्रमांक	ज़िला	पतवार सर्कल	पंचायत	गाँव	क्षेत्र इकाई	सड़क प्रकार	वर्ग -I (0-25 मी०)		वर्ग -II(20% < आधार कीमत)(25-50 मी०)		वर्ग -III(40% < आधार कीमत)(50-100 मी०)		वर्ग -IV(50% < आधार कीमत)(100-1000 मी०)		वर्ग -V(60% < आधार कीमत)(>100 0 मी०)	
							खेती में प्रयुक्त	खेती में अनप्रयुक्त	खेती में प्रयुक्त	खेती में अनप्रयुक्त	खेती में प्रयुक्त	खेती में अनप्रयुक्त	खेती में प्रयुक्त	खेती में अनप्रयुक्त	खेती में प्रयुक्त	खेती में अनप्रयुक्त
							राज्य राजमार्ग	अन्य सड़क	राज्य राजमार्ग	अन्य सड़क	राज्य राजमार्ग	अन्य सड़क	राज्य राजमार्ग	अन्य सड़क	राज्य राजमार्ग	अन्य सड़क
							820	683	656	546	492	410	410	342	328	273
							655	546	524	437	393	328	328	273	262	218

*स्रोत: भू-अभिलेख और राजस्व विभाग

पिछले तीन वर्षों की अवधि में S/A की टीम द्वारा स्वामित्व में कोई बदलाव नहीं पाया । HP SIAU द्वारा प्रदान की गई सूची की तुलना में, किसी भी भूस्वामी की मृत्यु के मामले में एकमात्र अपवाद भूमि के स्वामित्व को अपने बच्चों / पत्नी को हस्तांतरित कर दिया गया है। स्वामित्व में ये परिवर्तन आज तक राजस्व विभाग के साथ दर्ज नहीं किए गए हैं।

वर्तमान ज़मींदारों में से कई ने साझा किया कि उनकी बहन की शादी के बाद, भाई जमीन के व्यावहारिक मालिक हैं क्योंकि वे भूमि की रक्षा कर रहे हैं और कृषि उत्पादों का उत्पादन भी कर रहे हैं। कई उत्तरदाताओं के अनुसार, यह उनकी आजीविका के मुख्य स्रोतों में से एक है और भूमि को आगे विभाजित करने से वे आर्थिक रूप से कमजोर हो जाएंगे। उन्होंने यह भी साझा किया कि बहनें अपने वैवाहिक परिवार के स्वामित्व के तहत भूमि की खेती में लगी हुई हैं। हालांकि कई मामलों में, बहनों ने मौखिक रूप से स्वामित्व को अपने भाइयों को हस्तांतरित कर दिया है, कोई भी हस्तांतरण राजस्व विभाग के साथ पंजीकृत नहीं है।

4 प्रभावित परिवारों और आस्तियों का अनुमान और गणना

4.1 प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित व्यक्ति

53.1964 हेक्टेयर निजी भूमि का प्रस्तावित अर्जन शिमला और मंडी जिलों के 20 गांवों में 1847 लोगों को सीधे प्रभावित कर रहा है। नीचे दिए गए प्रत्येक गांव में अर्जन से सीधे प्रभावित होने वाले लोगों की संख्या की सूची दी गई है:

तालिका 4-1: परियोजना से सीधे प्रभावित लोग (PAPs)

जिले का नाम।	पंचायत का नाम	क्र.सं.	गाँव का नाम	खसरा का कुल क्षेत्रफल	शीर्षक धारकों की कुल संख्या
शिमला	चेबड़ी	1.	लुँसू	1.1729	83
		2.	खेरा	9.9689	329
	करयाली	3.	जैशी	3.7634	306
		4.	भरारा	6.1109	229
	ओगली	5.	तलाह	3.2225	54
		6.	ओगली	4.7889	112
		7.	कोठी	0.5522	33
		8.	मालगी	8.565	217
	बाग	9.	बठोरा	3.8662	156
		10.	पंदोआ	0.4448	20
		11.	ग्रहना	0.6941	3
	मोगरा	12.	झुँझन	0.8678	64
		13.	मझरोग	0.2365	17
मंडी	बिंदला	14.	भौरा	2.9055	98
		15.	बलोग	1.7213	22
	सरत्योला	16.	जकलीन	0.4981	14
	परलोग	17.	फ़ाफ़न	0.6308	13

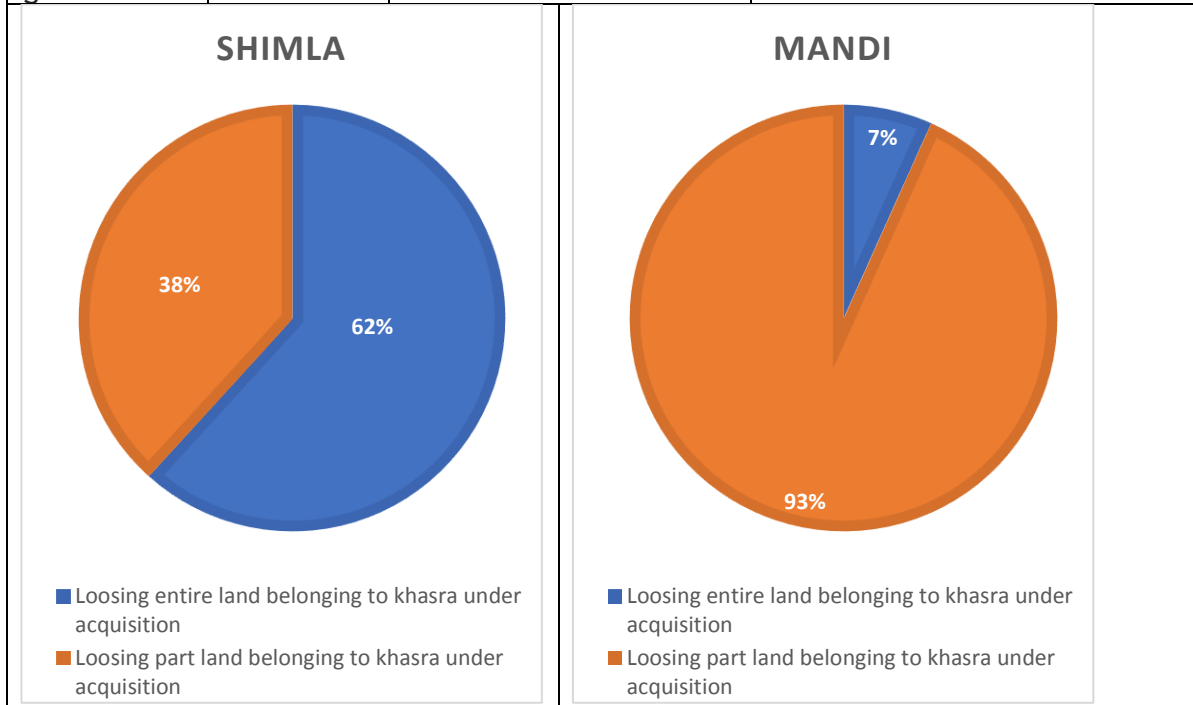
सुन्नी बांध जल विद्युत् परियोजना (382 MW) के लीये की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

जिले का नाम।	पंचायत का नाम	क्र.सं.	गाँव का नाम	खसरा का कुल क्षेत्रफल	शीर्षक धारकों की कुल संख्या
		18.	परलोग	1.1722	13
		19.	बेलुढाँक	1.9823	42
	शौट	20.	खरयाली	0.0321	22
कुल				53.1964	1847.00

* स्रोत: सतलुज जल विद्युत् निगम

तालिका 4 2: सम्बंधित खसरे में पूर्ण भूमि को खोने वाले लोगों की संख्या

क्र स	ज़िला	कुल मालिक	अर्जन के तहत सम्बंधित खसरे में पूर्ण भूमि को खोने वाले लोगों की संख्या	अर्जन के तहत संबंधित भूमि खसरा में आंशिक भाग खोने वाले लोगों की संख्या
1	शिमला	1623	1002	621
2	मण्डी	224	15	209
कुल		1847	1045	802



* स्रोत: राजस्व और भूमि रिकॉर्ड विभाग

शिमला जिले में, कुल 1623 शीर्षकधारकों में से 1002 (62%) अर्जन के तहत जमीन के पूरे भाग को खो देंगे और 621 (38%) इसका केवल एक हिस्सा खो देंगे । मंडी जिले में, कुल 224 शीर्षकधारकों में से 15 (7%) अर्जन के तहत भूमि के पूरे पार्सल को खो देंगे और 209 (93%) इसका केवल हिस्सा खो देंगे । हालाँकि, उन सभी के पास अतिरिक्त जमीन या तो उसी पंचायत या किसी अन्य पंचायत में है। इस प्रकार, उनमें से कोई भी अर्जित होने वाली भूमि पर पूरी तरह से निर्भर नहीं है, यही वजह है कि उन्होंने उस भूमि के लिए प्रतिकर के रूप में नकद लेना पसंद किया, जो *अर्जित* हो रही है।

इसके अलावा, प्राथमिक सर्वेक्षण के दौरान साक्षात्कार में आए कुल 966 शीर्षकधारकों में से, 18 (2%) ने जवाब दिया कि उनकी जमीन के हिस्से के अर्जन के बाद शेष पार्सल भूमि के लिए उपयोगी नहीं रहेगा और 948 (98%) ने जवाब दिया कि शेष पूर्ण भाग भूमि अर्जन के बाद उपयोगी रहेगी।

कुल 1847 शीर्षकधारियों में से, 146 (8%) अर्जन में अपने घर खो रहे हैं और उन्होंने परियोजना सहायता के लिए एक ही ग्राम पंचायत में कहीं भी अधिमानतः पुनर्वास की मांग की।

* *नोट: यहाँ यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि, भूमि को खोने वाले लोगों उनकी 100% भूमि हानि/आंशिक भूमि हानि/आश्रय की हानि का अंतिम आकलन राज्य सरकार के सक्षम अधिकारियों द्वारा किया जाना चाहिए*

4.1.1 किराएदार / व्यवसायी

सर्वेक्षण के दौरान अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि पर कोई भी किरायेदार नहीं पाया गया सभी प्रभावित परिवार अपने परिवारों के साथ रहने के लिए घरों का उपयोग करते हैं और स्वयं द्वारा खेती की करते हैं

4.1.2 जनजाति और पारंपरिक वन निवासी

एसटी श्रेणी में आने वाले कोई भी प्रभावित परिवार या पारंपरिक वनवासी नहीं हैं, जिन्होंने अपना कोई वन अधिकार खो दिया है।

4.1.3 सामान्य संपत्ति संसाधनों पर निर्भरता

साक्षात्कार और FGD के दौरान यह पाया गया कि अधिकांश ग्रामीणों के पास पशुओं के चारा और ईंधन की लकड़ी के संग्रह के लिए अर्जित की जा रही वन भूमि पर निर्भरता है । साथ ही, ग्रामीणों द्वारा इस भूमि को चरागाह के रूप में उपयोग किया जाता है। बहुत से ग्रामीणों ने वन भूमि का अर्जन करने के लिए विकल्प मुहैया कराने की मांग की विशेषकर गांव झुनझुन और मोगरा पंचायत का मजरोग। इसके अलावा,

अधिकांश गांवों के श्मशान घाट अर्जन के तहत खो जाएंगे, जिसके लिए ग्रामीणों ने उन्हें वैकल्पिक श्मशान घाट उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।

PAPs के अलावा, ग्रामीणों सहित अधिकांश पंचायतों, जिनकी भूमि का अर्जन नहीं किया जा रहा है, के लिए चारा और ईंधन-लकड़ी के उद्देश्य से अर्जित किए जा रहे जंगल पर भी अत्यधिक निर्भरता थी। पंचायतों के साथ FGDs के दौरान यह मुद्दा प्रस्तावित अर्जन से ग्रामीणों की प्रमुख चिंताओं में से एक था। इसी तरह, वे उन श्मशान घाटों के बारे में चिंतित थे जो परियोजना द्वारा जलमग्न हो जाएंगे। उन्होंने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समान वैकल्पिक वन संसाधन और वैकल्पिक श्मशान घाट उपलब्ध कराने की मांग की है।

4.1.4 राज्य सरकार द्वारा दी गई भूमि

ऐसे लोग नहीं हैं जिन्हें राज्य सरकार ने अपनी किसी भी योजना के तहत जमीन सौंपी हो और ऐसी जमीन अर्जन के तहत हो

4.1.5 आजीविका के लिए भूमि पर निर्भरता

कुल 53.1964 हेक्टेयर में से अर्जन के तहत भूमि, 33.68 हेक्टेयर (63%) भूमि खेती योग्य है और केवल 9.46 हेक्टेयर (18%) भूमि सिंचित है। इस खेती योग्य भूमि के सभी मालिकों ने साझा किया कि वे अर्जन से 3 साल से अधिक समय से कृषि से अपनी आजीविका का हिस्सा कमा रहे हैं।

4.2 उत्पादक आस्तियों और महत्वपूर्ण भूमि की सूची

प्राथमिक सर्वेक्षण के दौरान PAPs के साथ उपलब्ध परिसंपत्तियों की एक विस्तृत सूची SIA टीम द्वारा तैयार की गई थी जैसे वाहन, हाउस होल्ड उपकरण, उनकी भूमि पर उपयोगिताओं, पशुधन, पेड़, आदि। उपलब्ध संपत्ति की स्थिति न केवल क्षेत्र में रहने के मानक को इंगित करती है, बल्कि PAPs की सामर्थ्य का सूचक भी है। यह देखते हुए कि 1345 उत्तरदाताओं के साथ विभिन्न उपलब्ध संपत्तियों की विस्तृत सूची है, जो परियोजना से प्रभावित हो रहे हैं:

तालिका 4-3 : उत्पादक आस्तियों की सूची

क्र स	वर्ग	विवरण	PAPs संख्या	PAPs का %
1.	वाहन	ट्रक	3	0.22%
2.		ट्रॉलियों	2	0.15%
3.		कार	95	7.06%

सुन्नी बांध जल विद्युत् परियोजना (382 MW) के लीये की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

क्र स	वर्ग	विवरण	PAPs संख्या	PAPs का %
4.		बाइक / स्कूटर	17	1.26%
5.	House Hold Equipment	फ्रिज	847	62.97%
6.		वॉशिंग मशीन	168	12.49%
7.		पंखा	305	22.68%
8.		एयर कंडीशनर	7	0.52%
9.		रूम हीटर	96	7.14%
10.		टेबल फैन	60	4.46%
11.		टीवी	1180	87.73%
12.		रेडियो	223	16.58%
13.		कंप्यूटर	38	2.83%
14.		मोबाइल फोन	1233	91.67%
15.		माइक्रोवेव ओवन	2	0.15%
16.	गीज़र	21	1.56%	

* स्रोत : प्राथमिक सर्वेक्षण

प्रस्तावित अर्जन से लगभग 14824 फल देने वाले पेड़ प्रभावित हो रहे हैं और लगभग 26691 गैर-फलदार पेड़ अर्जन के प्रभाव में हैं। लगभग 130 कुएँ, 3 पानी के नल, 2 हैंडपंप, 7 मौजूदा पानी की टंकी, 9 बिजली के खंभे, 3 पानी की आपूर्ति पाइपलाइन, 4 शौचालय और 4 रसोई वर्तमान में कार्यात्मक अर्जन के तहत जाएंगे।

तल्लिका 4-4: भूमि पर आस्तियों की सूची

क्र स	भूमि पर आस्तिया	प्रभाव के अधीन (संख्या .)
1.	फलों वाले पेड़ों की संख्या	14824
2.	गैर-फल देने वाले पेड़ों की संख्या	26691
3.	कुएँ	130
4.	पानी का नल	3

सुन्नी बांध जल विद्युत् परियोजना (382 MW) के लीये की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

क्र स	भूमि पर आस्तिया	प्रभाव के अधीन (संख्या .)
5.	पानी की टंकी	7
6.	हैंड पंप	2
7.	जल आपूर्ति पाइपलाइन	3
8.	विद्युत पोल संचरण लाइन	9
9.	प्रसाधन	4
10.	रसोई	4

* स्रोत: प्राथमिक सर्वेक्षण

नीचे दी गई तालिका परियोजना क्षेत्र में PAPs के स्वामित्व वाले सभी पशुधन को सूचीबद्ध करती है।

तालिका 4-5: पशुधन की सूची

पशुधन	संख्या
गाय	1442
भैंस	8
भेड़	19
बकरी	67
पोल्ट्री पक्षी	23
बैल / बुल	122
खच्चर	2

* स्रोत: प्राथमिक सर्वेक्षण

सर्वेक्षण के अनुसार , निजी भूमि के अलावा, अन्य महत्वपूर्ण भूमि जहां ग्रामीणों के पास आर्थिक और सामाजिक निर्भरता थी, तथा अर्जन के तहत आ रही थी वह वन भूमि और सतलुज नदी के तट पर श्मशान भूमि के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली भूमि है ।

5 सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक प्रोफाइल

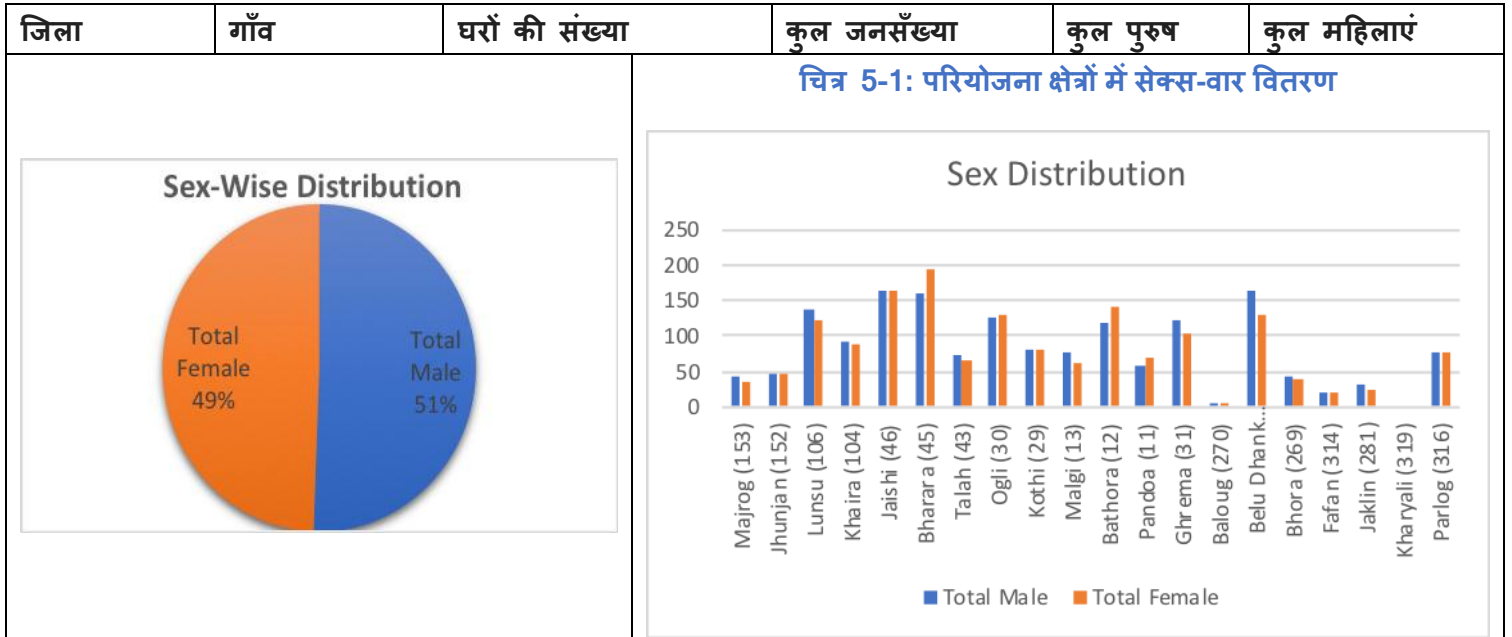
5.1 परियोजना गांवों में जनसंख्या का जनसांख्यिकीय विवरण

भारत की जनगणना 2011 के अनुसार,परियोजना के तहत आने वाले सुन्नी HEP के लिए जिन 20 गाँवों में भूमि का अर्जन किया जा रहा है, वहाँ की कुल जनसंख्या 3230 है और कुल घरों की संख्या 670 है। इन गाँवों में कुल जनसंख्या 1634 (51%) है। पुरुष और 1596 (49%) महिलाएं हैं। घरों और आबादी का विस्तृत वितरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

तालिका5-1: परियोजना क्षेत्र का जनसांख्यिकीय विवरण

जिला	गाँव	घरों की संख्या	कुल जनसँख्या	कुल पुरुष	कुल महिलाएं
शिमला	मजरोग	16	79	42	37
शिमला	झुझन	18	94	47	47
शिमला	लुन्सू	52	258	136	122
शिमला	खैरा	38	179	91	88
शिमला	जैशी	60	327	165	162
शिमला	भरारा	62	356	161	195
शिमला	तलाह	24	137	72	65
शिमला	ओगली	52	255	124	131
शिमला	कोठी	28	159	80	79
शिमला	मलगी	34	137	75	62
शिमला	बथोरा	58	259	119	140
शिमला	पन्दोअ	36	128	57	71
शिमला	ग्रेहना	47	225	121	104
मंडी	बलोग	3	11	7	4
मंडी	बेलुधांक	71	295	164	131
मंडी	भौरा	14	85	44	41
मंडी	फफान	9	39	20	19
मंडी	जक्लिन	10	55	32	23
मंडी	खर्याली	0	0	0	0
मंडी	परलोग	38	152	77	75
कुल		670	3230	1634	1596

सुन्नी बांध जल विद्युत् परियोजना (382 MW) के लीये की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।



*Source: Census, 2011

5.1.1 परियोजना प्रभावित लोगों का जनसांख्यिकीय विवरण

प्राथमिक सर्वेक्षण के अनुसार, 20 गांवों के 1034 परियोजना प्रभावित घरों की कुल आबादी जहां आगामी सुन्नी HEP के लिए भूमि अर्जित की जा रही है, 4683 है। कुल 4683 लोगों में से 2398 (51%) पुरुष और 2285 (49%) महिलाएं हैं। परियोजना प्रभावित घरों में लिंगानुपात 953 है। घरों और आबादी का विस्तृत वितरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

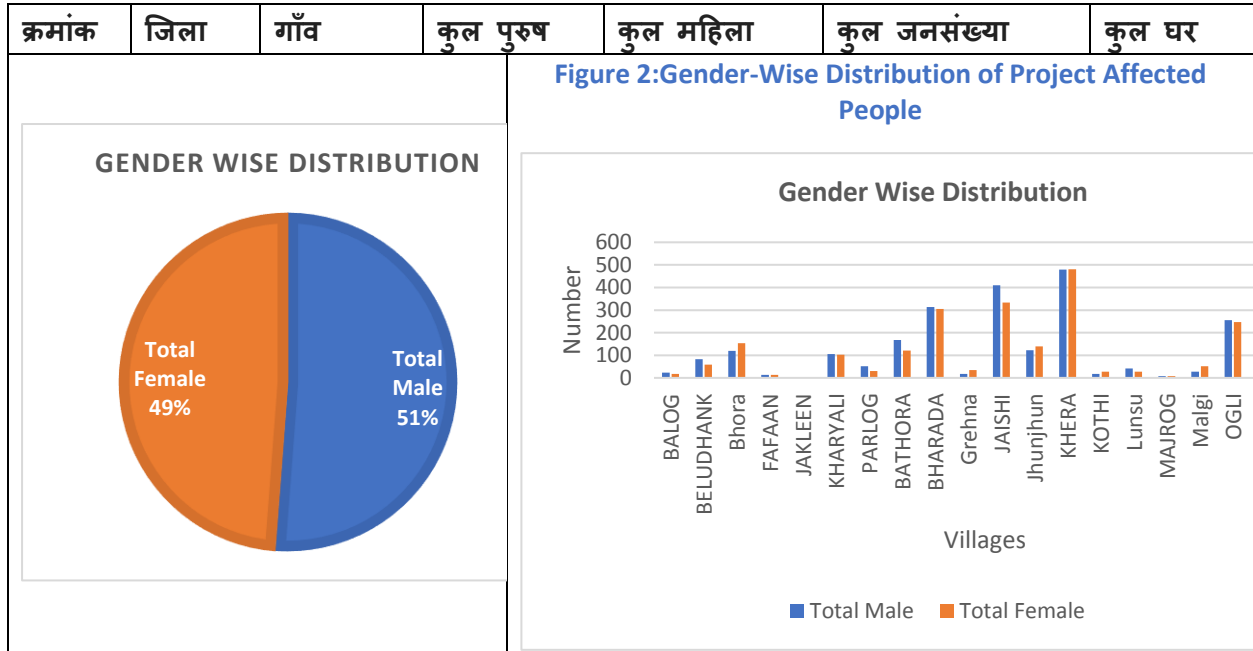
तालिका 5-2: परियोजना प्रभावित परिवारों की जनगणना

क्रमांक	जिला	गाँव	कुल पुरुष	कुल महिला	कुल जनसंख्या	कुल घर
1.	मंडी	बलोग	23	18	41	11
2.	मंडी	बेलुधांक	83	58	141	36
3.	मंडी	भौरा	119	154	273	53
4.	मंडी	फफान	14	13	27	8
5.	मंडी	ज्वकलिन	2	3	5	1

सुन्नी बांध जल विद्युत् परियोजना (382 MW) के लीये की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

क्रमांक	जिला	गाँव	कुल पुरुष	कुल महिला	कुल जनसंख्या	कुल घर
6.	मंडी	खर्याली	105	102	207	30
7.	मंडी	परलोग	52	30	82	10
8.	शिमला	बठोरा	168	121	289	76
9.	शिमला	भरारा	313	305	618	147
10.	शिमला	ग्रेहना	18	34	52	13
11.	शिमला	जैशी	410	334	744	189
12.	शिमला	झुनझुन	122	139	261	38
13.	शिमला	खैरा	479	480	959	204
14.	शिमला	कोठी	17	27	44	15
15.	शिमला	लुन्सू	42	28	70	11
16.	शिमला	मजरोग	8	7	15	6
17.	शिमला	मालगी	28	51	79	18
18.	शिमला	ओगली	255	247	502	99
19.	शिमला	पन्दोआ	87	91	178	44
20.	शिमला	तलाह	53	43	96	25
Total			2398	2285	4683	1034

सुन्नी बांध जल विद्युत् परियोजना (382 MW) के लीये की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।



*स्रोत: प्राथमिक सर्वेक्षण.

5.1.2 लिंग अनुपात

जनगणना 2011 के अनुसार, इन 20 गांवों में लिंगानुपात प्रति हजार पुरुषों पर 976 महिलाओं का है जो राज्य के औसत 972 से अधिक है, लेकिन राज्य के ग्रामीण लिंगानुपात 986 से कम है। परियोजना गांवों का बाल लिंगानुपात 1079 है जो कि राज्य के बच्चों के अनुपात 909 के लिंगानुपात से अधिक है और राज्य का ग्रामीण औसत 986 है। कुल जनसंख्या का 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग में, 52% महिलाएं हैं और 48% पुरुष हैं। नीचे दिए गए बच्चे की आबादी का एक गांववार विस्तृत वितरण है:

तालिका 5-3: परियोजना क्षेत्र में बाल जनसंख्या

क्रमांक	जिला	गाँव	बाल जनसंख्या (0-6 आयु वर्ग में जनसंख्या)		
			कुल	कुल पुरुष	कुल महिला
1.	शिमला	मजरोग	11	6	5
2.	शिमला	झुझन	9	6	3

सुन्नी बांध जल विद्युत् परियोजना (382 MW) के लीये की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

क्रमांक	जिला	गाँव	बाल जनसंख्या (0-6 आयु वर्ग में जनसंख्या)		
			कुल	कुल पुरुष	कुल महिला
3.	शिमला	लुन्सू	17	9	8
4.	शिमला	खैरा	26	15	11
5.	शिमला	जैशी	44	28	16
6.	शिमला	भरारा	50	22	28
7.	शिमला	तलाह	17	11	6
8.	शिमला	ओगली	28	12	16
9.	शिमला	कोठी	23	8	15
10.	शिमला	मलगी	13	8	5
11.	शिमला	बथोरा	18	5	13
12.	शिमला	पन्दोआ	23	6	17
13.	शिमला	ग्रेहना	14	4	10
14.	मंडी	बलोग	0	0	0
15.	मंडी	बेलुधांक	35	16	19
16.	मंडी	भौरा	12	7	5
17.	मंडी	फफान	2	2	0
18.	मंडी	जक्लिन	2	1	1

सुन्नी बांध जल विद्युत् परियोजना (382 MW) के लीये की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

क्रमांक	जिला	गाँव	बाल जनसंख्या (0-6 आयु वर्ग में जनसंख्या)		
			कुल	कुल पुरुष	कुल महिला
19.	मंडी	खर्याली	0	0	0
20.	मंडी	परलोग	22	10	12
Total			366	176	190

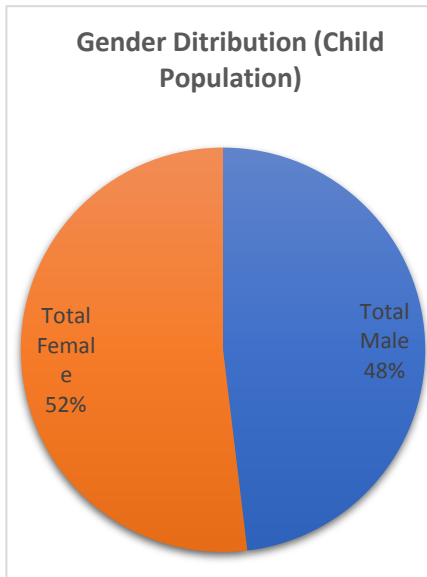
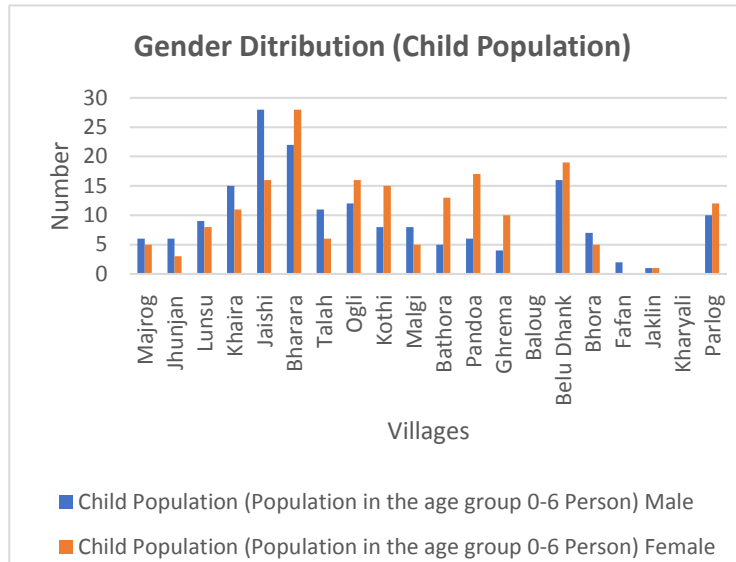


Figure 3: Child Gender Distribution in Project Area



*स्रोत: जनगणना 2011

5.1.3 सामाजिक समूह

जनगणना 2011 के अनुसार, कुल 644 अनुसूचित जाति के लोग हैं, जिनमें से 314 पुरुष हैं और 330 परियोजना क्षेत्र में महिलाएं हैं। प्रभाव क्षेत्र में कोई अनुसूचित जनजाति नहीं हैं।

तालिका 5-4: परियोजना क्षेत्र में अनुसूचित जाति की जनसंख्या

जिला का नाम	नाम	अनुसूचित जाति की जनसंख्या		
		कुल	पुरुष	महिला
शिमला	मजरोग	22	11	11
शिमला	झुझन	0	0	0
शिमला	लुन्सू	27	12	15
शिमला	खैरा	0	0	0
शिमला	जैशी	167	84	83
शिमला	भरारा	85	34	51
शिमला	तलाह	45	21	24
शिमला	ओगली	34	15	19
शिमला	कोठी	58	26	32
शिमला	मलगी	27	17	10
शिमला	बठोरा	21	10	11
शिमला	पन्दोआ	16	8	8
शिमला	गेहना	42	21	21
मंडी	बलोग	0	0	0
मंडी	बेलुधांक	50	27	23
मंडी	भौरा	4	3	1
मंडी	फफान	0	0	0
मंडी	जक्लिन	0	0	0
मंडी	खरयाली	0	0	0
मंडी	परलोग	46	25	21
कुल		644	314	330

* स्रोत: जनगणना, 2011

5.1.3.1 परियोजना प्रभावित क्षेत्र में सामाजिक समूह

प्राथमिक सर्वेक्षण के अनुसार, कुल 4683 PAP में से, 4145 (89%) सामान्य श्रेणी में आते हैं, 524 (11%) अनुसूचित जाति हैं और उनमें से 14 (0.3%) अन्य पिछड़े वर्ग के हैं। तालिका में नीचे दिए गए 20 गांवों में अलग-अलग सामाजिक समूहों में PAPs का एक विस्तृत गांव वार वितरण है, जहां आने वाले सुन्नी बांध HEP के लिए भूमि का अर्जन किया जा रहा है:

सुन्नी बांध जल विद्युत् परियोजना (382 MW) के लीये की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

तालिका 5-5: PAPs में सामाजिक समूह

क्रमांक	जिला	गाँव	समान्य	पिछड़ा	अनुसूचित	कुल
1.	मंडी	बलोग	41			41
2.	मंडी	बेलुधांक	141			141
3.	मंडी	भौरा	268		5	273
4.	मंडी	फफान	5		22	27
5.	मंडी	जक्लिन	5			5
6.	मंडी	खर्याली	195		12	207
7.	मंडी	परलोग	79	3		82
8.	शिमला	बथोरा	275		14	289
9.	शिमला	भरारा	591		27	618
10.	शिमला	ग्रेहना	52			52
11.	शिमला	जैशी	586	10	148	744
12.	शिमला	झुझन	261			261
13.	शिमला	खैरा	944		15	959
14.	शिमला	कोठी	3		41	44
15.	शिमला	लुन्सू	70			70
16.	शिमला	मज्रोग	15			15
17.	शिमला	मलगी	79			79
18.	शिमला	ओगली	346	1	155	502

सुन्नी बांध जल विद्युत् परियोजना (382 MW) के लीये की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

19.	शिमला	पन्दोअ	93		85	178
20.	शिमला	तलाह	96			96
कुल			4145	14	524	4683

5.1.4 साक्षरता

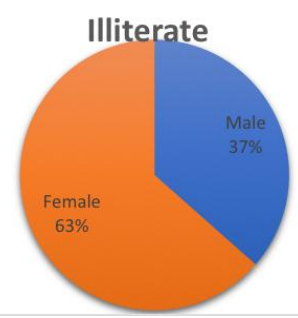
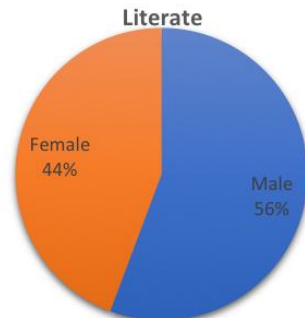
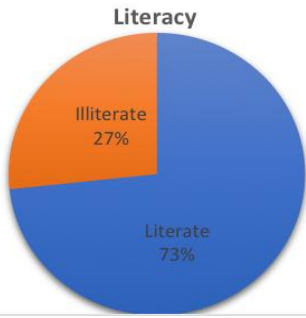
2011 की भारत की जनगणना के अनुसार, हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर 83% और हिमाचल प्रदेश ग्रामीण की साक्षरतादर 82% है। जबकि परियोजना क्षेत्रके कुल 3230 लोगों में से केवल 73% जनसंख्या ही साक्षर है (जो राज्य के समग्र और ग्रामीण हिस्से की साक्षरता दर से कम है) और 27% निरक्षर है। इसमें से 73% साक्षर जनसंख्या 56% पुरुष और 44% महिलाएँ हैं। 27%, अनपढ़ आबादी में 63% महिलाएं और 37% पुरुष हैं। नीचे दी गई तालिका में साक्षरता की स्थिति का एक विस्तृत गांववार वितरण है:

तालिका 5-6: परियोजना क्षेत्र में साक्षरता स्थिति

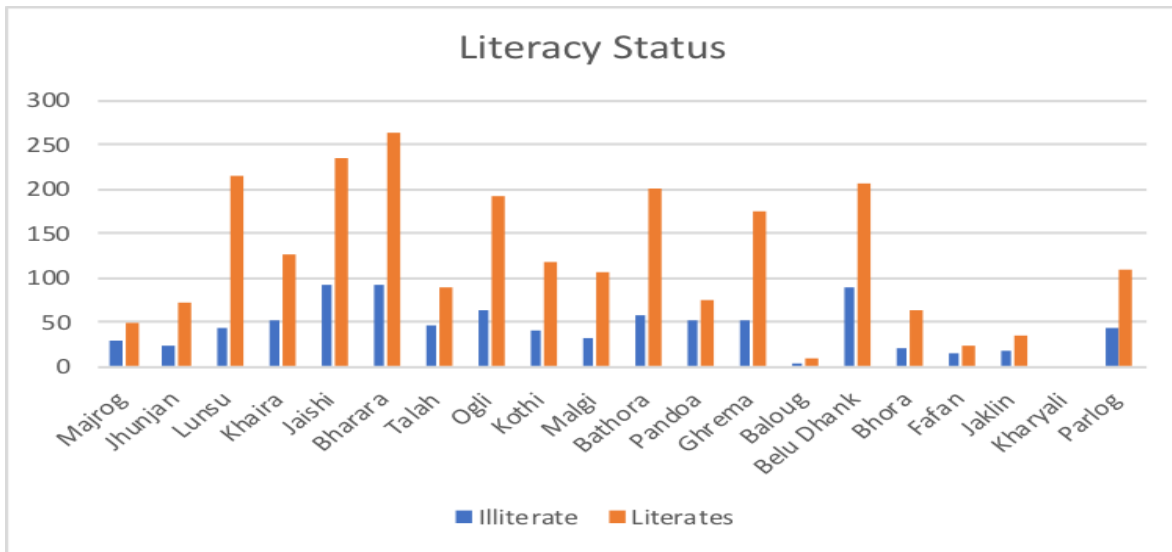
क्रमांक	जिला	गाँव	साक्षर			निरक्षर		
			कुल	पुरुष	महिलाएं	कुल	पुरुष	महिलाएं
1	शिमला	मजरोग	50	27	23	29	15	14
2	शिमला	झुझन	71	35	36	23	12	11
3	शिमला	लुन्सू	214	120	94	44	16	28
4	शिमला	खैरा	127	69	58	52	22	30
5	शिमला	जैशी	235	124	111	92	41	51
6	शिमला	भरारा	263	129	134	93	32	61
7	शिमला	तलाह	90	50	40	47	22	25
8	शिमला	ओगली	192	103	89	63	21	42
9	शिमला	कोठी	119	67	52	40	13	27
10	शिमला	मलगी	105	59	46	32	16	16
11	शिमला	बठोरा	201	103	98	58	16	42
12	शिमला	पन्दोआ	76	44	32	52	13	39
13	शिमला	ग्रेहना	174	109	65	51	12	39
14	मंडी	बलोग	9	7	2	2	0	2
15	मंडी	बेलुधांक	207	136	71	88	28	60

सुन्नी बांध जल विद्युत् परियोजना (382 MW) के लीये की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

16	मंडी	भौरा	64	34	30	21	10	11
17	मंडी	फफान	25	16	9	14	4	10
18	मंडी	जक्लिन	36	24	12	19	8	11
19	मंडी	खरयाली	0	0	0	0	0	0
20	मंडी	परलोग	109	63	46	43	14	29
कुल			2367	1319	1048	863	315	548



चित्र 5-2: परियोजना क्षेत्र में साक्षरता की स्थिति



*स्रोत: जनगणना, 2011

5.1.4.1 PAPs की साक्षरता स्थिति

प्राथमिक सर्वेक्षण के अनुसार, कुल 4683 PAPs में से, 1240 (27%) हाई स्कूल पास हैं, 897 (20%) माध्यामिक पास हैं, 658 (14%) ने 5 वीं से 8 वीं कक्षा, 504 (11%) ने 5 वीं कक्षा तक की पढ़ाई की है, उनमें से 403 (9%) स्नातक हैं, 211 (5%) पोस्ट ग्रेजुएट हैं, 104 (2%) साक्षर हैं और 666 (14%) निरक्षर हैं। तालिका में नीचे दिए गए PAPs के बीच साक्षरता की स्थिति है:

सुन्नी बांध जल विद्युत् परियोजना (382 MW) के लीये की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

तालिका 5-7: PAPs में साक्षरता की स्थिति

क्रमांक	शिक्षा	महिला	पुरुष	कुल
1	उच्च विद्यालय	491	749	1240
2	माध्यामिक विद्यालय	326	571	897
3	5 वीं से 8 वीं कक्षा के बीच	328	330	658
4	5 वीं कक्षा तक	300	204	504
5	निरक्षर	467	199	666
6	स्नातक	174	229	403
7	स्नातक से ऊपर	95	116	211
8	साक्षर	34	70	104
कुल		2215	2468	4683

साक्षरता की स्थिति

श्रेणी	प्रतिशत
High School	27%
Intermediate	20%
Between 5th to 8th Grade	14%
Up to 5th Grade	11%
Illiterate	14%
Graduate	9%
Above Graduate	5%

- 5: High School
- 6: Intermediate
- 4: Between 5th to 8th Grade
- 3: Up to 5th Grade
- 2: Illiterate
- 7: Graduate
- 8: Above Graduate

5.2 आर्थिक प्रोफाइल

जनगणना 2011 के अनुसार, परियोजना क्षेत्र में कुल 3230 लोगों में से 1990 (62%) 18 वर्ष से 60 वर्ष के आयु वर्ग के बीच कार्य बल की श्रेणी में आते हैं। इस 62% में से 53% (1053) पुरुष हैं और 47% (937) महिलाएँ हैं।

तालिका 5-8: परियोजना क्षेत्र कार्य बल

जिला का नाम	नाम	कुल जनसंख्या	कार्य बल		
			संपूर्ण	पुरुष	महिला
शिमला	मजरोग	79	52	27	25
शिमला	झुझन	94	74	36	38
शिमला	लुन्सू	258	173	99	74
शिमला	खैरा	179	117	60	57
शिमला	जैशी	327	218	103	115
शिमला	भरारा	356	224	100	124
शिमला	तलाह	137	87	42	45
शिमला	ओगली	255	161	70	91

सुन्नी बांध जल विद्युत् परियोजना (382 MW) के लीये की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

जिला का नाम	नाम	कुल जनसंख्या	कार्य बल		
			संपूर्ण	पुरुष	महिला
शिमला	कोठी	159	104	55	49
शिमला	मलगी	137	55	46	9
शिमला	बठोरा	259	79	68	11
शिमला	पन्दोआ	128	78	36	42
शिमला	ग्रेहना	225	152	82	70
मंडी	बलोग	11	7	5	2
मंडी	बेलुधांक	295	218	126	92
मंडी	भौरा	85	45	24	21
मंडी	फफान	39	28	15	13
मंडी	ज्वकलिन	55	34	18	16
मंडी	खरयाली	0	0	0	0
मंडी	परलोग	152	84	41	43
Total		3230	1990	1053	937

* स्रोत: जनगणना, 2011

5.2.1 मुख्य कार्य जनसंख्या

जनगणना 2011 के अनुसार, परियोजना प्रभावित गांवों में कुल 1990 में से 1281 (64%) मुख्य कार्य जनसंख्या की श्रेणी में आते हैं, जो ऐसे लोग हैं जो एक वर्ष में 180 दिनों से अधिक के लिए कार्यरत हैं। इसमें से 1281, 754 (59%) पुरुष हैं और 527 (41%) महिलाएं हैं। नीचे दी गई तालिका में कृषक, खेतिहर मजदूर, घरेलू व्यवसाय और अन्य जैसे विभिन्न श्रेणियों में मुख्य कामकाजी आबादी का एक गांववार विवरण है।

कुल मुख्य कामकाजी आबादी में से 1042 (81.34%) कृषक हैं, 11 (0.86%) खेतिहर मजदूर हैं, 5 (0.39%) घरेलू उद्योगों में शामिल हैं और 223 (17.41%) अन्य श्रमिकों द्वारा वर्गीकृत हैं।

सुन्नी बांध जल विद्युत् परियोजना (382 MW) के लीये की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

तालिका 5-9: परियोजना क्षेत्र में मुख्या कामकाजी जनसँख्या

जिला का नाम	नाम	कुल कार्य बल	मुख्य किसान जनसंख्या			मुख्य कृषि मजदूर जनसंख्या			मुख्य घरेलू उद्योग जनसंख्या			मुख्य अन्य श्रमिक जनसंख्या			कुल मुख्य कार्य जनसंख्या		
			कुल	पुरुष	महिलाएं	कुल	पुरुष	महिलाएं	कुल	पुरुष	महिलाएं	कुल	पुरुष	महिलाएं	कुल	पुरुष	महिलाएं
शिमला	मजरोग	52	30	18	12	0	0	0	0	0	0	6	5	1	36	23	13
शिमला	झुझन	74	20	17	3	0	0	0	0	0	0	10	9	1	30	26	4
शिमला	लुन्सू	173	144	72	72	0	0	0	0	0	0	29	27	2	173	99	74
शिमला	खैरा	117	106	51	55	0	0	0	0	0	0	11	9	2	117	60	57
शिमला	जैशी	218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	19	4	23	19	4
शिमला	भरारा	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	22	6	28	22	6
शिमला	तलाह	87	51	17	34	0	0	0	2	2	0	12	11	1	65	30	35
शिमला	ओगली	161	119	40	79	0	0	0	3	3	0	24	17	7	146	60	86
शिमला	कोठी	104	1	1	0	0	0	0	0	0	0	21	17	4	22	18	4
शिमला	मलगी	55	40	36	4	0	0	0	0	0	0	8	6	2	48	42	6
शिमला	बठोरा	79	63	54	9	0	0	0	0	0	0	8	7	1	71	61	10
शिमला	पन्दोआ	78	57	26	31	2	0	2	0	0	0	18	10	8	77	36	41
शिमला	ग्रेहना	152	141	74	67	7	4	3	0	0	0	4	4	0	152	82	70
मंडी	बलोग	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
मंडी	बेलुधांक	218	192	110	82	2	1	1	0	0	0	3	3	0	197	114	83
मंडी	भौरा	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	2	3	1	2
मंडी	फफान	28	28	15	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	15	13
मंडी	जक्लिन	34	32	16	16	0	0	0	0	0	0	2	2	0	34	18	16
मंडी	खरयाली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
मंडी	परलोग	84	18	18	0	0	0	0	0	0	0	13	10	3	31	28	3
कुल		1990	1042	565	477	11	5	6	5	5	0	223	179	44	1281	754	527

* स्रोत: जनगणना, 2011

सुन्नी बांध जल विद्युत् परियोजना (382 MW) के लीये की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

तालिका5-10: परियोजना क्षेत्र में मुख्य कार्यशील जनसंख्या का वर्गीकरण

क्र.सं.	वर्ग	संपूर्ण	पुरुष	महिला
1	मुख्य किसान जनसंख्या	81.34%	74.93%	90.51%
2	मुख्य कृषि मजदूर जनसंख्या	0.86%	0.66%	1.14%
3	मुख्य घरेलू उद्योग जनसंख्या	0.39%	0.66%	0.00%
4	मुख्य अन्य श्रमिक जनसंख्या	17.41%	23.74%	8.35%
	कुल मुख्य कार्य जनसंख्या	100.00%	100.00%	100.00%

* स्रोत: जनगणना, 2011

5.2.2 सीमांत श्रमिक

जनगणना 2011 के अनुसार, परियोजना के गांवों में कुल 1990 कार्यबल में से, 709 (36%) व्यक्ति मामूली रूप से कार्यरत हैं जो हर साल 180 दिनों से कम के लिए कार्यरत हैं। इस 709 में से, 299 (42%) पुरुष हैं और 410 (58%) महिलाएं हैं। नीचे दी गई तालिका में किसानों, खेतिहर मजदूरों, हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज की आबादी और अन्य जैसे विभिन्न श्रेणियों में सीमांत कामकाजी आबादी का एक गांव वार वर्गीकरण है।

तालिका 5-11: परियोजना क्षेत्र में सीमांत श्रमिक

जिला का नाम	का नाम	कुल कार्य बल	सीमांत श्रमिक															
			कल्टीवेटर			कृषि मजदूर			घरेलू उद्योग			अन्य कार्यकर्ता			संपूर्ण			
			संपूर्ण	पुरुष	महिला	संपूर्ण	पुरुष	महिला	संपूर्ण	पुरुष	महिला	संपूर्ण	पुरुष	महिला	संपूर्ण	पुरुष	महिला	
शिमला	मजरोग	52	16	4	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	4	12
शिमला	झुझन	74	42	10	32	0	0	0	1	0	1	1	0	1	44	10	34	
शिमला	लुन्सू	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
शिमला	खैरा	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
शिमला	जैशी	218	122	18	104	36	31	5	1	1	0	36	34	2	195	84	111	
शिमला	भरारा	224	124	22	102	24	19	5	2	2	0	46	35	11	196	78	118	
शिमला	तलाह	87	21	11	10	0	0	0	0	0	0	1	1	0	22	12	10	
शिमला	ओगली	161	15	10	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	10	5	
शिमला	कोठी	104	81	36	45	1	1	0	0	0	0	0	0	0	82	37	45	

सुन्नी बांध जल विद्युत् परियोजना (382 MW) के लीये की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

जिला का नाम	का नाम	कुल कार्य बल	सीमांत श्रमिक														
			कल्टीवेटर			कृषि मजदूर			घरेलू उद्योग			अन्य कार्यकर्ता			संपूर्ण		
			संपूर्ण	पुरुष	महिला	संपूर्ण	पुरुष	महिला	संपूर्ण	पुरुष	महिला	संपूर्ण	पुरुष	महिला	संपूर्ण	पुरुष	महिला
शिमला	मलगी	55	6	4	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	7	4	3
शिमला	बठोरा	79	8	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	7	1
शिमला	पन्दोआ	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
शिमला	ग्रेहना	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
मंडी	बलोग	7	7	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	5	2
मंडी	बेलुधांक	218	21	12	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	12	9
मंडी	भौरा	45	42	23	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	23	19
मंडी	फफान	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
मंडी	जक्लिन	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
मंडी	खरयाली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
मंडी	परलोग	84	52	12	40	1	1	0	0	0	0	0	0	0	53	13	40
संपूर्ण		1990	557	4	383	62	52	0	5	3	2	85	70	15	709	9	410

* स्रोत: जनगणना, 2011

709 की कुल सीमांत कामकाजी आबादी में से 557 (78.56%) कृषक हैं, 62 (8.74%) कृषि मजदूर हैं, 5 (0.71%) घरेलू उद्योग में शामिल हैं और 85 (11.99%) कुछ अन्य काम कर रहे हैं।

तालिका 5-12: परियोजना क्षेत्र में सीमांत श्रमिक का वर्गिकरण

सीमांत श्रमिक				
क्र.सं.	वर्ग	कुल	पुरुष	महिला
1	कृषक	78.56%	58.19%	93.41%
2	कृषि मजदूर	8.74%	17.39%	2.44%
3	घरेलू उद्योग	0.71%	1.00%	0.49%
4	अन्य कार्यरत	11.99%	23.41%	3.66%
	संपूर्ण	100.00%	100.00%	100.00%

*स्रोत: जनगणना, 2011

5.2.3 गैर-कार्यशील जनसंख्या

जनगणना 2011 के अनुसार, परियोजना गांवों में कुल 3230 लोगों में से 1240 (38%) गैर-कार्यशील आबादी की श्रेणी में आते हैं। इस 1240 गैर-कामकाजी आबादी में, 47% (581) पुरुष हैं और 53% (659) महिलाएं हैं।

तालिका 5-13: परियोजना क्षेत्र में गैर कार्यशील जनसँख्या

जिलाकानाम	नाम	कुल जनसंख्या	गैर-कार्यशील जनसंख्या		
			संपूर्ण	पुरुष	महिला
शिमला	मजरोग	79	27	15	12
शिमला	झुझन	94	20	11	9
शिमला	लुन्सू	258	85	37	48
शिमला	खैरा	179	62	31	31
शिमला	जैशी	327	109	62	47
शिमला	भरारा	356	132	61	71
शिमला	तलाह	137	50	30	20
शिमला	ओगली	255	94	54	40
शिमला	कोठी	159	55	25	30
शिमला	मलगी	137	82	29	53
शिमला	बठोरा	259	180	51	129
शिमला	पन्दोआ	128	50	21	29
शिमला	ग्रेहना	225	73	39	34
मण्डी	बलोग	11	4	2	2
मण्डी	बेलुधांक	295	77	38	39
मण्डी	भौरा	85	40	20	20
मण्डी	फफान	39	11	5	6
मण्डी	जक्लिन	55	21	14	7
मण्डी	खरयाली	0	0	0	0
मण्डी	परलोग	152	68	36	32
कुल		3230	1240	581	659

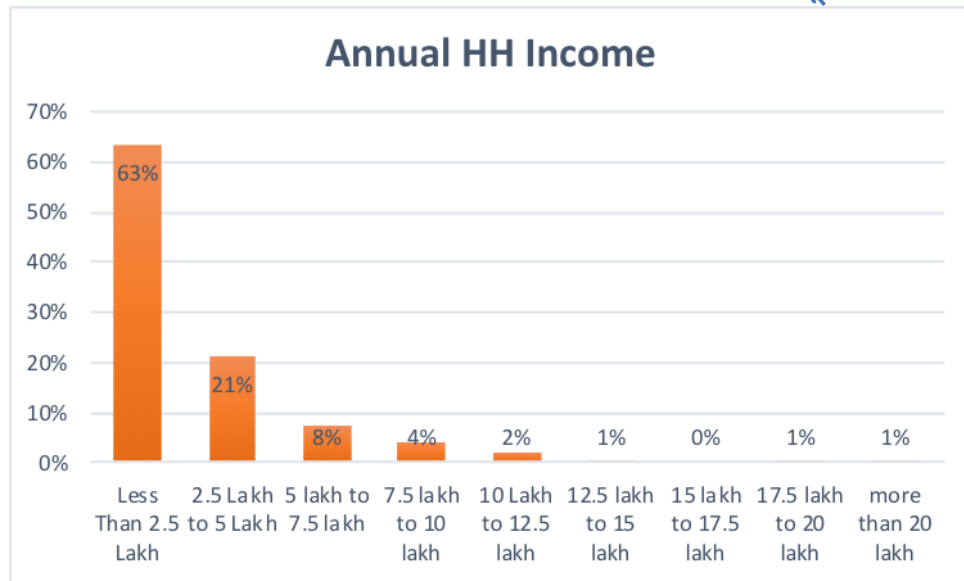
*स्रोत: जनगणना, 2011

5.3 आय और गरीबी स्तर

परियोजना में आय का मुख्य स्रोत प्राथमिक क्षेत्र है। घरेलू सर्वेक्षण के अनुसार, कुल PAP के लगभग 63% वार्षिक घर की आय 2.5 लाख रुपये से कम है। लगभग 21% की सालाना आय 2.5 लाख से 5 लाख रुपये के बीच है। उनमें से 8% के पास अपने घर की आमदनी 5 लाख से 7.5 लाख के बीच सालाना है, लगभग 2% के पास 10 लाख से 12.5 लाख है और शेष 35 के पास उनके वार्षिक आय 12.5 लाख रुपये से अधिक है।

परियोजना क्षेत्र में लगभग 2% व्यक्ति BPL की श्रेणी में आते हैं।

चित्र 5-3: परियोजना से प्रभावित लोगों की वार्षिक घरेलू आय



*स्रोत: प्राथमिक सर्वेक्षण

ऋण ग्रस्तता: उत्तरदाताओं ने साझा किया कि प्रभावित क्षेत्र में ऋणग्रस्तता कम है। कृषि उद्देश्यों के लिए ऋण लेने के बारे में केवल 4 लोगों ने साझा किया, उसके बाद 1 प्रतिवादी जिसने अपने घर के निर्माण के लिए ऋण लिया, 1 व्यक्ति ने निजी / वाणिज्यिक कार खरीदने के लिए ऋण लिया और एक व्यक्ति ने अपनी बेटी की शादी के लिए ऋण लिया।

5.4 दुर्बल समूह

दुर्बल समूह वे समूह हैं जो किसी भी परिस्थिति में कमजोर होंगे (जैसे कि जहां विकलांगता, बीमारी, उम्र, लिंग या किसी अन्य विशेषता के कारणों से वयस्क घर के लिए एक पर्याप्त आजीविका प्रदान करने में

असमर्थ हैं), और ऐसे समूह किसी भी उपलब्ध स्रोत से पर्याप्त आय प्रदान करने के लिए जिनके पास संसाधन बंदोबस्त अपर्याप्त हैं ।

भेदभाव का सामना करने वाले संवेदनशील समूहों में शामिल हैं- महिलाएं, वृद्धावस्था, शारीरिक और मानसिक विकलांगता, किसी बड़ी बीमारी से पीड़ित लोग आदि। कभी-कभी प्रत्येक समूह अपनी कई कमजोरियों के कारण कई बाधाओं का सामना करता है। उदाहरण के लिए, एक पितृसत्तात्मक समाज में, विकलांग महिलाओं को एक महिला होने और विकलांग होने के दोहरे भेदभाव का सामना करना पड़ता है।

नीचे दी गई सारणी परियोजना क्षेत्र में कमजोर घरों / व्यक्तियों की स्थिति को सारांशित करती है:

तालिका 5-14: परियोजना दुर्बल समूह

क्रमांक	कमजोर वर्ग	कुल PAPs	शीर्षक धारकों
1	महिला प्रधान घराने	400	391
2	शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति द्वारा संचालित घर	25	25
3	BPL परिवारों	82	80
4	विधवा महिला	141	93
5	तलाकशुदा महिला	11	11
6	पीडब्ल्यूडी महिलाओं	23	20
7	पीडब्ल्यूडी माल	17	17
8	पोलियो से पीड़ित लोग	3	3
9	पक्षाघात से पीड़ित लोग	3	3
10	अन्य प्रमुख बीमारी से पीड़ित लोग	5	3
11	एससी वर्ग	524	164
12	बुजुर्ग व्यक्तियों	633	399

कुल 1034 घरों में से, 400 (39%) महिलाओं की अध्यक्षता में हैं, जिनमें से 391 शीर्षकधारक हैं। 25 (2%) परिवार परियोजना क्षेत्र में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति के नेतृत्व में हैं।

साथ ही, लगभग 82 (2%) व्यक्ति हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रमाणित BPL जनसंख्या की श्रेणी में आते हैं। राज्य की BPL आबादी का औसत प्रतिशत 8.06% है एवम राज्य का ग्रामीण औसत 8.48% है

इसके अलावा, PAPs के बीच, 141 महिलाएं विधवा हैं, जिनमें से 93 शीर्षकधारक हैं, 11 महिलाएं तलाकशुदा हैं, 23 महिलाएं और 17 पुरुष शारीरिक रूप से अक्षम हैं और 11 व्यक्ति पोलियो और पक्षाघात सहित बड़ी बीमारी से पीड़ित हैं। 524 लोग एससी श्रेणी के हैं, जिनमें से 164 शीर्षकधारक हैं। 633 व्यक्ति 60 वर्ष से अधिक आयु के हैं, जिनमें से 399 शीर्षकधारक हैं।

5.5 भूमि उपयोग और आजीविका

अर्जन के तहत कुल निजी भूमि में से 63% भूमि पर खेती की जाती है और 37% भूमि का उपयोग नहीं किया जाता है। अर्जन आईडी के तहत कुल भूमि का केवल 18% सिंचित है और बाकी 82% गैर सिंचित है। नीचे दिए गए अर्जन के तहत खेती / असिंचित और सिंचित / गैर-सिंचित भूमि का एक तालिका जिलेवार वितरण है:

तालिका 5-2: परियोजना क्षेत्र में भूमि का उपयोग

	खेती	बीहड़	संपूर्ण	सिंचित	गैर-सिंचित	संपूर्ण
जिला	अर्जन के तहत निजी भूमि का क्षेत्रफल (हे)					
मंडी	7.4302	01.5121	8.9423	4.7178	4.2245	8.9423
शिमला	26.2498	18.0043	44.2541	4.7279	39.5262	44.2541
कुल	33.68	19.5164	53.1964	09.4457	43.7507	53.1964

*स्रोत: प्राथमिक सर्वेक्षण

एक अर्थव्यवस्था का फसल पद्धति किसानों के द्वारा विभिन्न फसलों के लिए दिए गए सापेक्ष महत्व को इंगित करता है। सीमित भूमि संसाधनों के साथ, आर्थिक, संस्थागत, ढांचागत और तकनीकी कारकों में परिवर्तन के अनुसार क्षेत्र में फसल पैटर्न) फसल-संयोजन (बदल जाता है। परियोजना क्षेत्र की कुल PAP में से, लगभग 91% अपनी भूमि का उपयोग खेती के लिए कर रहे हैं जो कि उनकी आजीविका का मुख्य स्रोत भी है। इन 91% में से, लगभग 93% सीजन के अनुसार विभिन्न फसलें उगाते हैं। नीचे दिए गए विभिन्न मौसमों में PAP द्वारा उगाई जाने वाली विभिन्न फसलों का विवरण दिया गया है:

तालिका 5-3: परियोजना क्षेत्र में प्रमुख फसलें

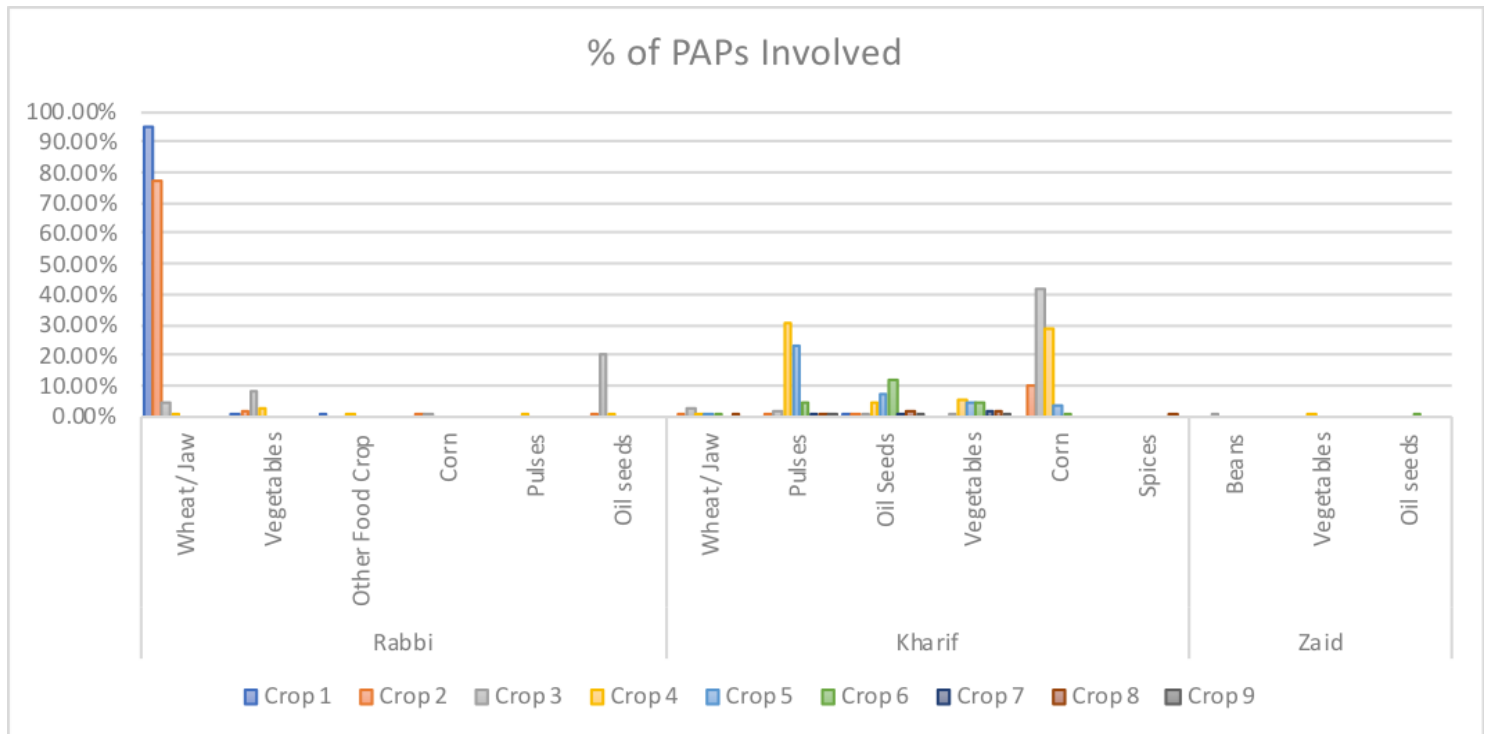
क्र.सं.	मौसम	फसल का नाम	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			फसल	फसल	फसल	फसल	फसल	फसल	फसल	फसल	फसल
			परियोजना से प्रभावित शामिल लोगो का %								
कृषि											
1	राब्बी	गेंहू/अनाज	94.64%	77.16%	4.50%	0.09%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2		सब्जिया	0.69%	1.56%	7.96%	2.16%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
3		अन्य खाद्य फसल	0.09%	0.00%	0.00%	0.09%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
4		मक्का	0.00%	0.52%	0.69%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
5		दालें	0.00%	0.00%	0.00%	0.69%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
6		तेल के बीज	0.00%	0.87%	20.24%	0.26%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
7	खरीफ	गेंहू/अनाज	0.00%	0.17%	2.60%	0.61%	0.69%	0.78%	0.00%	0.09%	0.00%
8		दालें	0.00%	0.87%	1.82%	30.36%	22.75%	4.76%	0.61%	0.52%	0.26%
9		तेल के बीज	0.09%	0.09%	0.61%	4.50%	7.53%	11.68%	0.95%	1.38%	0.26%
10		सब्जिया	0.00%	0.00%	0.43%	5.62%	4.33%	4.50%	1.64%	1.64%	0.35%
11		मक्का	0.00%	9.95%	41.44%	28.20%	3.03%	0.17%	0.00%	0.00%	0.00%
12		मसाले	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.61%	0.00%
13	जैद	फलिया	0.00%	0.00%	0.09%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

सुन्नी बांध जल विद्युत् परियोजना (382 MW) के लीये की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

14.		सब्जिया	0.00%	0.00%	0.00%	0.09%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
15.		तेल के बीज	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.09%	0.00%	0.00%	0.00%
बागवानी											
1.	बागवानी	सेब	0.00%	0.00%	0.09%	0.00%	0.52%	0.78%	0.78%	0.17%	0.00%
2.		पालम	0.00%	0.17%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.17%	0.35%
3.		अमरुद	0.00%	0.00%	0.09%	0.17%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
4.		अनार	0.00%	0.00%	0.43%	0.09%	0.00%	0.17%	0.87%	0.43%	0.09%
5.		आम	0.00%	0.00%	0.00%	0.26%	0.09%	0.09%	0.17%	0.52%	0.35%
6.		नींबू	0.00%	0.00%	0.61%	0.69%	0.61%	0.09%	0.35%	0.35%	0.52%
7.		आड़ू	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.17%

*स्रोत: प्राथमिक सर्वेक्षण

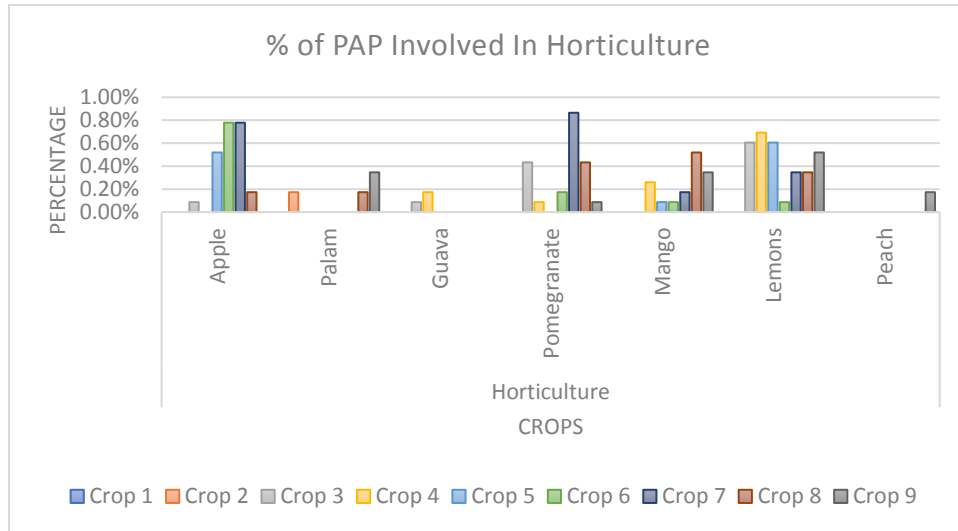
चित्र 5-4: परियोजना प्रभावित लोगो द्वारा उगाई जाने वाली मुख्या फसलें



*स्रोत: प्राथमिक सर्वेक्षण

रबी सीजन (अक्टूबर से फरवरी) की प्रमुख फसलें गेहूं और तेल के बीज हैं। खरीफ के मौसम (जुलाई से सितंबर) में मक्का, दालें, तेल के बीज और सब्जियाँ उगाई जाती हैं। ज़ैद के मौसम (मार्च से जून) के दौरान फलियाँ, सब्जियाँ और तेल के बीज उगाए जाते हैं।

चित्र 4: बागवानी में लिप्त PAPs



*स्रोत: प्राथमिक सर्वेक्षण

1% से भी कम PAPs बागवानी में लिप्त है जिसमें मुख्य फल सेब, अमरुद, पलम, अनार और आम हैं।

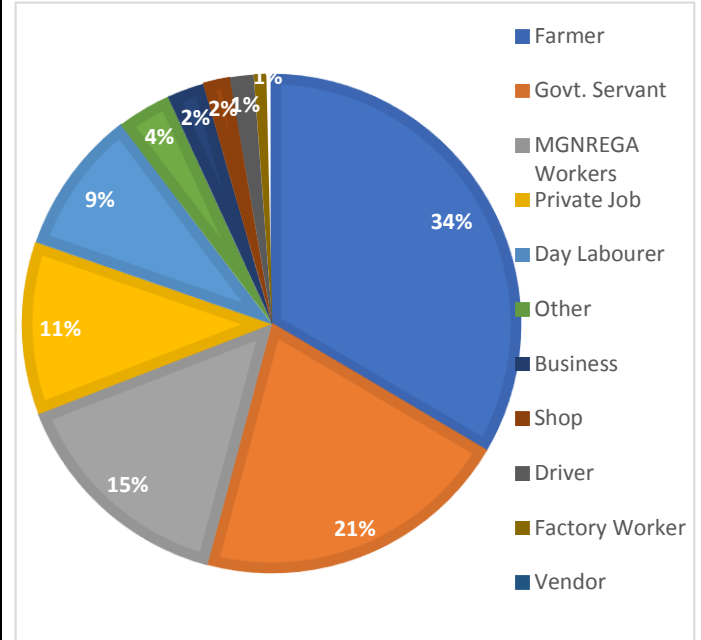
5.6 स्थानीय आर्थिक गतिविधियाँ

कुल 4683 PAPs में से, 2433 (52%) काम कर रहे हैं। इस 2433 में से 815 (33.5%) किसान हैं, 503 (20.7%) सरकारी कर्मचारी हैं, 364 (15%) MGNREGA कार्यकर्ता हैं, 272 (11.2%) निजी नौकरी कर रहे हैं, 228 (9.4%) दिहाड़ी मजदूर हैं और शेष हैं 251 (10.3%) कुछ अन्य काम कर रहे हैं जिनमें दुकानदार, ड्राइवर, कारखाने के कर्मचारी, विक्रेता, निर्माण श्रमिक और कबाड़ी शामिल हैं। नीचे दिए गए परियोजना क्षेत्र में मुख्य आर्थिक गतिविधियों की एक सूची है।

तालिका 5-1: परियोजना क्षेत्र में स्थानीय आर्थिक गतिविधियाँ

क्रमांक	आर्थिक गतिविधियाँ	महिला	पुरुष	कुल	कुल कामकाजी प्रतिशत
1	किसान	193	622	815	33.5%
2	सरकारी कर्मचारी	95	408	503	20.7%
3	MGNREGA कार्यकर्ता	329	35	364	15.0%
4	निजी नौकरी	41	231	272	11.2%
5	दैनिक मजदूर	18	210	228	9.4%
6	अन्य	28	57	85	3.5%
7	व्यपार	9	50	59	2.4%
8	दुकान	10	33	43	1.8%
9	चालक	2	34	36	1.5%
10	फैक्टरी मजदूर	17	2	19	0.8%
11	विक्रेता	3	1	4	0.2%
12	निर्माण मजदूर	1	3	4	0.2%
13	कबाड़ी वाला		1	1	0.0%
Total		746	1687	2433	100%

चित्र 5: परियोजना क्षेत्र में स्थानीय आर्थिक गतिविधियाँ



5.7 ऐसे कारक जो स्थानीय आजीविका में योगदान करते हैं

कई सामाजिक और प्राकृतिक कारक जैसे शिक्षा, लिंगानुपात, महिलाओं की सामाजिक स्थिति, बुनियादी ढांचे की उपलब्धता, कृषि-जलवायु परिस्थितियों, एक क्षेत्र की संस्थागत स्थितियों, प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता, पड़ोसी क्षेत्रों से संपर्क सहित आजीविका के विकल्पों और विकल्पों की उपलब्धता स्थानीय आजीविका में योगदान करते हैं।

एक क्षेत्र की कृषि संरचना भूमि के स्वामित्व और संचालन के संबंध में किसानों की विभिन्न श्रेणी की सापेक्ष स्थिति का वर्णन करती है। चूंकि भूमि PAPs की एक महत्वपूर्ण आय पैदा करने वाली संपत्ति के

रूप में बनती है, भूमि धारण पद्धति के कारण कृषि संरचना में बदलाव, सापेक्ष समृद्धि या परियोजना गांवों के विभिन्न वर्गों के हास को दर्शाता है।

चूंकि PAPs के 25% किसान हैं, इसलिए जलवायु परिस्थितियों और कृषि को प्रभावित करने वाले कारक स्थानीय आजीविका को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं। जलवायु परिस्थितियां कृषि पद्धति के वितरण को नियंत्रित करने वाले प्राथमिक प्रभाव हैं। मानव गतिविधि पर जलवायु के प्रभाव इतने महत्वपूर्ण और विविध हैं कि किसानों ने जान-बूझकर इसे अपने अस्तित्व के लिए जानने और समझने की कोशिश की है।

ऐसी स्थिति में जब भूमि का क्षेत्रफल कम या ज्यादा होता है, लेकिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है और विकास प्रक्रिया कृषि से गैर-कृषि तक बढ़ती जनसंख्या के अनुपातिक हस्तांतरण का कारण नहीं बनती है, तो कृषि पर निर्भर व्यक्तियों और परिवारों की पूर्ण संख्या अनिवार्य रूप से बढ़ जाएगी। इससे विकास के दौरान सीमांत किसानों और भूमिहीन खेतिहर मजदूरों की संख्या में समानुपातिक वृद्धि होगी। वास्तव में, दी गई संरचना उस क्षेत्र के लिए एक पूर्व शर्त निर्धारित करती है जिस क्षेत्र में उत्पादक संसाधन का उपयोग किया जाएगा। तकनीकी नवाचारों को अपनाने की दर भूमि धारण की मौजूदा संरचना से प्रभावित है। बदले में, संरचना ही प्रौद्योगिकी के प्रभाव में रूपांतरित हो जाती है।

ग्रामीण हिमाचल प्रदेश में, भूमि स्वामित्व वितरण एक विशिष्ट चरित्र प्रस्तुत करता है, जिसमें किसानों का एक बड़ा हिस्सा सीमांत है और बहुत कम लोगों को किसी भी मानक द्वारा बड़ा माना जा सकता है। वितरण एक तिरछा पैटर्न का अनुसरण करता है। इस तरह का एक पैटर्न विभिन्न स्तरों के बीच भूमि जोतों के असमान वितरण की तस्वीर देता है और उच्च स्तर की असमानता को इंगित करता है। हिमाचल प्रदेश की कृषि संरचना की एक महत्वपूर्ण विशेषता छोटे स्तर के किसान की निरंतरता है, जो संख्या और क्षेत्र दोनों में है।

आमतौर पर यह माना जाता है कि कृषि विकास ग्रामीण बुनियादी ढांचे पर निर्भर करता है, जैसे कि सिंचाई का प्रसार और गुणवत्ता, भूमि विकास, ग्रामीण विद्युतीकरण की सीमा और ग्रामीण सड़कों का प्रसार। मानव कौशल के स्तर के साथ, अच्छा बुनियादी ढांचा न केवल उत्पादन में जाने वाले मौजूदा संसाधनों की उत्पादकता को बढ़ाता है और इसलिए विकास में मदद करता है, यह अधिक निवेश को आकर्षित करने में भी मदद करता है, जिससे आगे वृद्धि की उम्मीद की जा सकती है।

5.8 रिश्तेदारी पद्धति

हिमाचल प्रदेश में, भूमि अधिकार केवल एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के लिए पारित किए जाते हैं। राज्य के नियमों के अनुसार, कोई भी प्रवासी "देवभूमि" में जमीन नहीं खरीद सकता है। इसलिए, यहां की भूमि पैतृक संपत्ति है और यह केवल बच्चों / पत्नी को समान रूप से वितरित की जाती है जब तक कि उनकी इच्छा अन्यथा नहीं कहती है।

कई मामलों में, यह देखा गया है कि मूल भूस्वामी के निधन के बाद भी वर्तमान भूमि मालिकों के नाम राजस्व विभाग के साथ अद्यतन नहीं किए गए हैं। किसी भी भूस्वामी की मृत्यु के मामले में, भूमि का स्वामित्व अपने बच्चों / पत्नी को स्वतः हस्तांतरित हो जाता है।

प्राथमिक सर्वेक्षण के दौरान, परियोजना क्षेत्र के कई वर्तमान भूस्वामियों ने साझा किया कि अपनी बहन की शादी के बाद, भाई जमीन के व्यावहारिक मालिक हैं क्योंकि वे भूमि की रक्षा कर रहे हैं और कृषि उत्पादों का उत्पादन भी कर रहे हैं। कई उत्तरदाताओं के अनुसार, यह उनकी आजीविका के प्रमुख स्रोतों में से एक है और भूमि को विभाजित करने से वे आर्थिक रूप से कमजोर हो जाएंगे। उन्होंने यह भी साझा किया कि बहनें अपने वैवाहिक परिवार की जमीन की खेती में लगी हुई हैं। हालांकि कई मामलों में, बहनों ने मौखिक रूप से स्वामित्व को अपने भाइयों को हस्तांतरित कर दिया है, कोई भी हस्तांतरण राजस्व विभाग के साथ पंजीकृत नहीं है।

5.9 प्रशासनिक, राजनीतिक और नागरिक समाज संगठन

निम्नलिखित संगठनों के परियोजना क्षेत्र में पदचिह्न पाए गए

➤ प्रशासनिक संगठन

1. पंचायत
2. पटवार कार्यालय
3. सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य
4. बिजली विभाग
5. कृषि विभाग
6. लोक निर्माण विभाग (PWD)

➤ राजनीतिक संगठन

1. भाजपा

2. कांग्रेस
3. सीपीएम
- **समुदाय आधारित और नागरिक समाज संगठन**
1. मन्दिर
2. महिला मण्डल
 - a. जागृति महिला मण्डल
 - b. ओगली महिला मण्डल
 - c. दुर्गा महिला मण्डल जैशी
 - d. जागृती महिला मण्डल बेलुधांक
 - e. महिला मण्डल खैर
 - f. जय कालेश्वर महिला मण्डल पन्धोआ
3. युवा जागरण मंच और युवक मण्डल
 - a. युवक मण्डल खैर
 - b. युवक मण्डल ओगली
 - c. युवक मण्डल जैशी
 - d. युवक मण्डल बेलुधांक
 - e. युवक मण्डल मण्डल पन्धोआ
 - f. युवक मण्डल चेबरी

5.10 क्षेत्रीय गतिशीलता और ऐतिहासिक परिवर्तन प्रक्रियाएं

परियोजना क्षेत्र की क्षेत्रीय गतिशीलता और ऐतिहासिक परिवर्तन प्रक्रियाओं को समझने के लिए, हमें दो जिलों यानी शिमला और मंडी के इतिहास और गतिशीलता को समझने की आवश्यकता है।

जिला शिमला

वर्तमान शिमला जिले में 19 छोटे पूर्ववर्ती शिमला पहाड़ी राज्य शामिल हैं जिन्हें 1948 में हिमाचल प्रदेश में मिला दिया गया था और महासू जिले का हिस्सा बनाया गया था। इन राज्यों के अलावा, पूर्ववर्ती पटियाला राज्य के पहाड़ी क्षेत्र और कोटखाई, कोटगढ़, शिमला शहर और प्रांतीय सरकार के जुतोग छावनी के क्षेत्र भी अलग-अलग चरणों में स्वतंत्रता के बाद जिले में शामिल किए गए थे।

19 वीं शताब्दी की शुरुआत में शिमला जिले की लगभग सभी रियासतें गोरखा आक्रमणों के अधीन थीं और वर्ष 1815 में आजाद हुईं थीं जब गोरखा अंग्रेजों से हार गए थे और नेपाल भाग गए थे। नतीजतन, संबंधित शासकों के क्षेत्र विशिष्ट शर्तों के तहत उन्हें बहाल किए गए थे। चूंकि सभी राज्य क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के हिसाब से छोटे आकार के थे, इसलिए ये पंजाब हिल्स राज्यों के तत्कालीन अधीक्षक के सीधे नियंत्रण में थे।

ये शासक अपने राज्यों के आंतरिक मामलों में स्वतंत्र थे। लगभग सभी राज्यों की स्थापना 8 वीं शताब्दी के बाद मैदानी इलाकों के साहसी लोगों द्वारा की गई थी। निकटतम शहरी स्थानीय निकाय यानी सुन्नी को 1991 की जनगणना में नारकंडा, जुब्बल, कोटभाई और चौपाल के साथ अधिसूचित क्षेत्र समितियों के रूप में बनाया गया था।

मण्डी ज़िला

15 अप्रैल, 1948 को हिमाचल प्रदेश के गठन पर मंडी और सुकेत की तत्कालीन रियासतों के समामेलन से मंडी जिला का गठन हुआ था। डॉ० जे हचिंसन और डॉ० वोगेल ने राज्यों के राजनीतिक इतिहास में अधिकांश राज्यों की तरह अनुमान लगाया। मंडी इसकी राजधानी से अपना नाम लेती है जो ब्यास के बाएं किनारे पर स्थित है। मंडी एक हिंदी शब्द है, जिसका अर्थ बाजार है और यह संभवतः संस्कृत शब्द 'मंडपिका' के साथ जुड़ा हो सकता है जिसका अर्थ एक खुला हॉल या शेड है और इसे संस्कृत के मूल शब्द 'मंड' से लिया गया है जिसका अर्थ है सजाना या वितरित करना।

सुन्नी खैरा गाँव (बांध स्थल) से लगभग 25 किमी दूर स्थित परियोजना क्षेत्र की निकटतम नगर पालिका है। राज्य की राजधानी शिमला परियोजना क्षेत्र से 44 किमी दूर स्थित है। क्षेत्र एमडीआर 22 के माध्यम से जुड़ा हुआ है जो नदी के समानांतर चलता है।

5.11 जीवंत पर्यावरण की गुणवत्ता

परियोजना क्षेत्र निचले हिमालयी बेल्ट की पहाड़ी स्थलाकृति पर स्थित है। इस क्षेत्र में समृद्ध हरे वातावरण के साथ पर्णपाती देवदार के जंगल और ग्रामीण पृष्ठभूमि है। परियोजना क्षेत्र की मुख्य अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है। निचले हिमालयी बेल्ट में होने के कारण, इस क्षेत्र में ग्रीष्मकाल में न तो अत्यधिक तापमान का सामना करना पड़ता है और न ही सर्दियों का। औसत वार्षिक तापमान 22-26 डिग्री सेल्सियस से लेकर चरम गर्मियों के तापमान तक लगभग 35-40 डिग्री सेल्सियस और सर्दियों के दौरान चरम न्यूनतम तापमान 2-5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इस क्षेत्र में वन्यजीवों की अच्छी मात्रा है। सर्वेक्षणों के दौरान यह देखा गया कि क्षेत्र में अक्सर जंगली जानवरों जैसे तेंदुए, जंगली जानवर, हिमालयी मोनाल, लाल जंगल फाउल (जंगली मुर्गा), लोमड़ी, खरगोश आदि दिखाई देते हैं। राज्य को सतलुज, स्वच्छ वायु और घने वन आवरण से पानी के पर्याप्त संसाधन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

6 सामाजिक प्रभाव

6.1 प्रभावों की पहचान करने के लिए रूपरेखा और दृष्टिकोण

सामाजिक समाघात आकलन, दरअसल विकास, जैसे कि बांधों, खानों, उद्योगों, राजमार्गों, बंदरगाहों, हवाई अड्डों, शहरी विकास और बिजली परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रस्तावित परियोजनाओं के नतीजों की संभावना का अग्रिम में, मूल्यांकन करना है। यह एक ऐसा उपकरण है जो निर्णयकर्ताओं को उनके कार्यों के संभावित नकारात्मक प्रभावों को दूर करने में मदद कर सकता है ताकि समय पर उन्हें रोकने या कम से कम किए जाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा सकें। निर्णय लेने की प्रक्रिया में सहायता के रूप में, SIA सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों के बारे में जानकारी प्रदान करता है जिन्हें किसी भी निर्णय में ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है जो परियोजना क्षेत्र में लोगों के जीवन को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है।

सामाजिक समाघात निर्धारण के लिए सिद्धांतों और दिशानिर्देशों पर अंतर-संगठनात्मक समिति (IOCPGSIA 2003) के अनुसार, सामाजिक प्रभावों की अवधारणा करने का एक पारंपरिक तरीका निम्नलिखित में से एक या अधिक परिवर्तनों के रूप में है:

- लोगों के जीवन का तरीका - वह यह है कि वे कैसे रहते हैं, काम करते हैं, खेलते हैं और एक दूसरे के साथ दिन-प्रतिदिन बातचीत करते हैं;

उनकी संस्कृति - अर्थात्, उनकी साझा मान्यताएं, रीति-रिवाज, मूल्य और भाषा या बोली;

- उनका समुदाय - इसका सामंजस्य, स्थिरता, चरित्र, सेवाएं और सुविधाएं;

- उनकी राजनीतिक प्रणाली - लोगों को अपने जीवन को प्रभावित करने वाले निर्णयों में भाग लेने में सक्षम होने की हद तक, लोकतांत्रिकरण का स्तर और इस उद्देश्य के लिए प्रदान किए गए संसाधन;

- उनका पर्यावरण - हवा और पानी की गुणवत्ता का लोग उपयोग करते हैं; भोजन की उपलब्धता और गुणवत्ता वे खाते हैं; खतरे या जोखिम, धूल और शोर का स्तर जो वे सामने आते हैं; स्वच्छता की पर्याप्तता, उनकी भौतिक सुरक्षा और संसाधनों तक उनकी पहुँच और नियंत्रण;

- उनका स्वास्थ्य और भलाई - स्वास्थ्य पूर्ण शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक भलाई की स्थिति है और न केवल बीमारियों या दुर्बलताओं की अनुपस्थिति;

- उनके व्यक्तिगत और संपत्ति के अधिकार - विशेष रूप से चाहे लोग आर्थिक रूप से प्रभावित हों, या व्यक्तिगत नुकसान का अनुभव करते हैं जिसमें उनके नागरिक स्वतंत्रता का उल्लंघन शामिल हो सकता है;

- उनके भय और आकांक्षाएँ - उनकी सुरक्षा के बारे में उनकी धारणाएँ, उनके समुदाय के भविष्य के बारे में उनकी आशांकाएँ, और उनके भविष्य और उनके बच्चों के भविष्य के लिए उनकी आकांक्षाएँ;

SIA के संचालन की प्रक्रिया को इस तरह से डिजाइन किया गया था जिसमें प्रस्तावित अर्जन के प्रभाव का आकलन करने के लिए सभी हितधारकों को व्यवस्थित दृष्टिकोण में शामिल किया गया था। प्रभावों की पहचान करने की रूपरेखा और दृष्टिकोण निम्नलिखित चरणों में दिखाया गया है।

चरण 1: पृष्ठभूमि अध्ययन और केस अध्ययन

चरण 2: विभिन्न PAPs की पहचान

चरण 3: प्राथमिक सर्वेक्षण प्रश्नावली की तैयारी

चरण 4: विभिन्न हितधारकों के साथ प्राथमिक सर्वेक्षण और FGD का संचालन

चरण 5: एकत्रित आंकड़ों का विश्लेषण

6.2 परियोजना के विभिन्न चरणों में प्रभावों का विवरण

जल-विद्युत् परियोजना के लिए प्रस्तावित भूमि के अर्जन से आजीविका, रोजगार, आय, उत्पादन, स्वास्थ्य और कल्याण और समुदाय के जीवन की गुणवत्ता, सामाजिक-सांस्कृतिक प्रणालियों और पर्यावरण पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष असर पड़ेगा। यह संपत्ति के अधिकार और आकांक्षाओं के बारे में संदेह और आशंका पैदा कर सकता है। विकास परियोजनाएं अलग-अलग समूहों को अलग तरह से प्रभावित करती हैं।

कई लोगों को फायदा होता है जब कुछ खोते हैं। अक्सर, प्रभाव दुर्बल समूहों के लिए जैसे कि महिलाओं के नेतृत्व वाले घर, विधवा, शारीरिक या मानसिक विकलांगता वाले व्यक्ति, BPL परिवार, आरक्षित श्रेणियों के लोग और बुजुर्ग व्यक्ति, के लिए विशेष रूप से गंभीर होते हैं।

क्षेत्र में, लगने वाले सुन्नी HEP परियोजना के लिए एक सामान्य आशा है। अध्ययन में पाया गया कि 91% प्राथमिक हितधारक अर्जन के लिए अपनी भूमि के आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार थे, बशर्ते कि उचित प्रतिकर का भुगतान किया जाए और केवल 8% ने अर्जन प्रक्रिया का विरोध किया। पंचायतों के साथ

केन्द्रित समूह चर्चा के दौरान, ग्रामीणों और माध्यमिक हितधारकों में परियोजना के प्रति बहुत सकारात्मक राय मिली, क्योंकि यह बुनियादी ढांचे के विकास (सामाजिक और भौतिक दोनों) और रोजगार में वृद्धि, व्यवसाय के अवसर के मामले में पूरे क्षेत्र में समग्र विकास लाएगा। साथ ही, उन्होंने उस क्षेत्र की भूमि की कीमतों में वृद्धि का अनुमान लगाया जो उनके लिए एक लाभदायक कारक होगा।

हालांकि, वे नकारात्मक प्रभावों के बारे में भी आशंकित थे जो उचित रूप से कम नहीं होने पर परियोजना से बढ़ सकते हैं। क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए हितधारकों के बीच विवादों में वृद्धि सहित दुर्बल समूहों को छोड़ दिया जा सकता है या धोखा दिया जा सकता है इस आशंका के बारे में चिंताएं थीं । इसके अलावा, प्रतिकर राशि प्राप्त करने के बाद से, PAF की वित्तीय स्थिति में बदलाव होगा जो बदले में उनकी खरीद क्षमता को बदल देगा और फंड मिस-मैनेजमेंट के जोखिम को भी बढ़ाएगा क्योंकि कई जमींदार ठीक से विशेष रूप से वित्तीय प्रबंधन के बारे में शिक्षित नहीं है। क्षतिपूर्ति राशि वितरित होने के बाद परियोजना क्षेत्र में धोखाधड़ी और धोखाधड़ी के मामलों में भी वृद्धि हो सकती है। खर्च के पैटर्न में बदलाव के कारण सांस्कृतिक प्रथाओं और परंपराओं में बदलाव की भी संभावना है।

अर्जन के कारण सार्वजनिक अवसंरचना जैसे रोपवे, पुल, श्मशान घाट, सड़क, मौजूदा सिंचाई सुविधाओं सहित आईपीएच इन्फ्रास्ट्रक्चर का नुकसान भी होगा और पीने के पानी के स्रोतों, घाटों, जंगलों, चरागाहों आदि जैसे सामुदायिक संपत्ति संसाधनों का नुकसान भी होगा। सुन्नी HEP के लिए कुल 78 संरचनाएँ प्राप्त की जा रही हैं। इनमें 38 आवासीय संरचनाएं हैं। मंडी जिले के गाँव परलोग में 1 स्कूल, 3 पंपहाउस, 12 घर, शिमला जिले के मालगी गाँव में 1 पुल और 6 रोपवे का भी अर्जन किया जा रहा है। अध्याय 4 में बुनियादी ढांचे और परिसंपत्तियों के नुकसान के विवरण पर चर्चा की गई है। PAPs और साथ ही ग्रामीणों को इस बात की चिंता थी कि अर्जन करने वाले निकाय द्वारा उन्हें कैसे विकल्प प्रदान किए जाएंगे, ताकि यह उनकी दैनिक दिनचर्या में बाधा न बने। ग्रामीणों के पास पशुओं के चारे और जलाऊ लकड़ी के लिए समीपवर्ती चरागाह भूमि और जंगल पर निर्भरता है।

परियोजना के निर्माण चरण के दौरान, हितधारकों का परियोजना के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण था क्योंकि यह उनके लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार और व्यापार के अवसर पैदा करेगा। प्रवासन के कारण वे वस्तुओं की खपत में वृद्धि करेंगे, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। हालांकि, उन्होंने इस परियोजना के लिए श्रम के प्रवास के बारे में भी चिंता व्यक्त की क्योंकि यह मौजूदा बुनियादी ढांचे जैसे स्वास्थ्य सुविधाओं, शैक्षिक सुविधाओं, सड़कों आदि पर दबाव बढ़ाएगा। स्थानीय लोगों और प्रवासियों के बीच टकराव बढ़ने की संभावना हो सकती है और हितधारकों ने यह भी कहा कि प्रवासन के कारण क्षेत्र में अपराध दर और असामाजिक गतिविधियों में वृद्धि की संभावना है। यह क्षेत्र सांस्कृतिक मिश्रण का भी गवाह बन सकता है। इसके अलावा, भारी परिवहन वाहनों, सामग्री परिवहन और निर्माण के कारण यातायात, वायु और ध्वनि प्रदूषण की समस्या भी होगी। निर्माण गतिविधियों और उत्खनन के कारण क्षेत्र में स्वास्थ्य समस्याओं में भी वृद्धि हो सकती है।

निर्माण के बाद के चरण के दौरान, हितधारकों ने कहा कि यह क्षेत्र में प्रदूषण कम और बेहतर जीवन का माहौल बना सकता है। LADA जैसे फंडों के कारण यह क्षेत्र आगे विकास का भी गवाह बनेगा। इस अवस्था

के दौरान एक सांस्कृतिक स्थिरता भी देखी जा सकती है। हालांकि, उन्होंने कुछ नकारात्मक प्रभावों पर भी प्रकाश डाला, जो इस चरण के दौरान उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे कि निर्माण गतिविधियों में गिरावट के कारण स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और व्यापार के अवसर कम होंगे और इससे परियोजना में शामिल अस्थायी कार्य बल को बेरोजगारी भी हो सकती है।

क्षेत्र स्थानीय अर्थव्यवस्था में अचानक गिरावट और निर्माण चरण में शामिल अस्थायी श्रमिकों के प्रवास के कारण माल और सेवाओं की कम खपत का गवाह बन सकता है। नतीजतन, निर्माण चरण के दौरान आय के स्तर में हुई वृद्धि के कारण लोगों को बदले हुए जीवन स्तर बनाए रखने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है।

परियोजना चक्र के विभिन्न चरणों में अध्ययन द्वारा पाई गई विभिन्न संभावित सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभावों का सार नीचे दिया गया है:

तालिका 6-1: परियोजना के विभिन्न चरणों में प्रभाव

अवस्था	सामाजिक समाघात	आर्थिक समाघात	सांस्कृतिक समाघात
पूर्व-निर्माण चरण	<ul style="list-style-type: none"> • क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए हितधारकों के बीच विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। • आगामी परिवर्तनों जैसे जल स्तर में वृद्धि, आर्द्रता, भूस्खलन में वृद्धि आदि। का संदेह और भय • श्मशान घाट का नुकसान • आम संपत्ति के नुकसान जैसे कि पीने के पानी के संसाधन, घाट, आदि का जीवन की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। 	<ul style="list-style-type: none"> • आगामी परियोजना के कारण आसपास के क्षेत्र में भूमि की कीमतें बढ़ सकती हैं। • PAF की वित्तीय स्थिति में अचानक आए प्रतिकर के कारण, उनकी क्रय क्षमता बदल सकती है और इससे फंड मिस-मैनेजमेंट का जोखिम भी बढ़ जाएगा। • बुनियादी ढांचे के नुकसान जैसे कि रोपवे, मौजूदा सिंचाई सुविधाएं आदि परियोजना प्रभावित और आसपास के क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव डालेंगे। • वन भूमि का अर्जन ग्रामीणों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा क्योंकि उन पर पास चारा और 	<ul style="list-style-type: none"> आगामी परियोजना के कारण लाभान्वित होने वाले लोगों के खर्च पैटर्न में बदलाव के साथ, सांस्कृतिक प्रथाओं और परंपराओं पर प्रभाव पड़ेगा।

अवस्था	सामाजिक समाघात	आर्थिक समाघात	सांस्कृतिक समाघात
		जलाऊ लकड़ी के संग्रह के लिए उच्च निर्भरता है।	
निर्माण चरण	<p>निर्माण श्रमिकों और तकनीकी कर्मचारियों के प्रवासन से मौजूदा स्वास्थ्य देखभाल केंद्र, स्वच्छता पर बोझ बढ़ेगा ।</p> <p>प्रवासन से मौजूदा शैक्षणिक संस्थानों पर भी दबाव बढ़ा सकता है।</p> <p>सामाजिक विभाजन उन लोगों के बीच पैदा हो सकता है जो परियोजना से लाभान्वित हो रहे हैं और जो लोग अप्रभावित रहते हैं।</p> <p>आगामी परियोजना की वजह से क्षेत्र के समग्र विकास के कारण निवासियों के जीवन स्तर में सुधार हो सकता है।</p> <p>इन-माइग्रेशन के परिणामस्वरूप स्थानीय लोगों में सुरक्षा और सुरक्षा की भावना कम हो सकती है।</p> <p>बाहरी लोगों के साथ संघर्ष बढ़ सकता है और क्षेत्र में अपराध और असामाजिक गतिविधियों में वृद्धि देखी जा सकती है।</p> <p>यह क्षेत्र निर्माण, खदान आदि के कारण स्वास्थ्य समस्याओं और बीमारियों में वृद्धि कर सकता है।</p> <p>निर्माण चरण के दौरान भारी परिवहन से आसपास के गांवों में वायु और ध्वनि प्रदूषण बढ़ सकता है।</p>	<p>स्थानीय लोगों और PAF के लिए रोजगार और व्यापार के अवसरों में वृद्धि।</p> <p>स्थानीय लोगों के पास प्रयोज्य आय में वृद्धि।</p> <p>आर्थिक गतिविधियों और खपत पैटर्न में वृद्धि।</p> <p>इन-माइग्रेशन के कारण क्षेत्र में वस्तुओं और सेवाओं की खपत में वृद्धि होगी, जिससे स्थानीय व्यापार को लाभ होगा।</p>	<p>इन-माइग्रेशन के कारण लोग दूसरे राज्यों से आएंगे और अपनी संस्कृति, विश्वासों, धार्मिक प्रथाओं, कपड़ों के पैटर्न आदि को लेकर आएंगे, जो मौजूदा सांस्कृतिक प्रथाओं और स्थानीय आवासों की परंपराओं को प्रभावित कर सकते हैं।</p>

अवस्था	सामाजिक समाघात	आर्थिक समाघात	सांस्कृतिक समाघात
निर्माण के बाद का चरण	निर्माण गतिविधियों के कारण होने वाले प्रदूषण में कमी आएगी और यह क्षेत्र बेहतर जीवन के माहौल का गवाह बन सकता है। निर्माण चरण के दौरान आय के स्तर में वृद्धि के कारण लोगों को जीवन स्तर बनाए रखने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है।	निर्माण गतिविधियों में गिरावट के कारण स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और व्यवसाय के अवसर कम होंगे और इससे परियोजना में शामिल अस्थायी कार्य बल को बेरोजगारी भी हो सकती है। निर्माण चरण में शामिल अस्थायी श्रमिकों के बाहर प्रवास के कारण क्षेत्र स्थानीय अर्थव्यवस्था में अचानक गिरावट देख सकता है। फंड के कारण LADA क्षेत्र निर्माण चरण के बाद भी बुनियादी ढांचे के विकास में और सुधार देख सकता है।	सांस्कृतिक स्थिरता शायद इस चरण के दौरान देखी जाए

*स्रोत: प्राथमिक सर्वेक्षण

6.3 प्रभाव क्षेत्रों की सांकेतिक सूची

प्रभाव सकारात्मक या नकारात्मक हो सकते हैं। इस परियोजना में यह सर्वेक्षण और चर्चाओं के माध्यम से पाया गया है कि लोगों को उम्मीद है कि भूमि अर्जन से उन्हें बेहतर मौद्रिक प्रतिकर मिलेगा, जो उन्हें अपनी भलाई में सुधार करने में मदद करेगा। हालांकि प्रभावित परिवारों ने महसूस किया कि भूमि और आजीविका आदि का नुकसान अपूरणीय होगा। घरेलू सर्वेक्षण का उद्देश्य परियोजना प्रभावित परिवारों पर सामाजिक प्रभावों, संपत्ति का प्रकार और स्वामित्व, प्रभाव का प्रकार और इसकी परिमाण और प्रभावित संपत्ति के विवरण की एक सूची उत्पन्न करना था। प्रभावों के प्रमुख निष्कर्षों और परिमाणों की चर्चा निम्नलिखित वर्गों में की गई है।

6.3.1 भूमि मालिकों पर प्रभाव

प्रस्तावित परियोजना के लिए जलग्रहण क्षेत्र, डंपिंग क्षेत्र, सड़कें, पावर सब-स्टेशनों की स्थापना, प्रशासनिक भवनों का निर्माण आदि की आवश्यकता होती है, वर्तमान भूमि अर्जन के तहत 1045 शीर्षकधारी सम्बंधित खसरे में अपनी भूमि का 100% खो देते हैं और 802 शीर्षकधारी अपनी भूमि का एक हिस्सा खो रहे हैं। जिसमें से 746 (93%) ने बताया कि शेष भूमि अभी भी उनके लिए उपयोग करने योग्य होगी।

केवल 19 भूमि स्वामीयों ने जवाब दिया कि वे आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से अर्जन के तहत आने वाले के अलावा उसी या किसी भी अन्य पंचायत में किसी अन्य भूमि के मालिक नहीं हैं। इन 19 भूस्वामियों में से, 10 भूस्वामी अर्जन से अपनी पूरी जमीन खो रहे हैं और उन्होंने उसी ग्राम पंचायत के भीतर परियोजना सहायता प्राप्त पुनर्वास को चुना है। शेष 9 भूस्वामियों में से 3 ने भूमि के लिए नकद के रूप में प्रतिकर का विकल्प चुना, 6 ने उसी ग्राम पंचायत के भीतर अधिमानतः भूमि के लिए भूमि के रूप में प्रतिकर का विकल्प चुना। इन 9 में से केवल 2 भूस्वामियों ने बताया कि शेष भूमि अर्जन के बाद भी उपयोग करने योग्य होगी।

अर्जन के तहत 38 आवासीय संरचनाएं आ रही हैं, जिनमें से 18 संरचना भरारा गांव में हैं। टेबल 6-2 गांव को अर्जन के तहत आने वाले आवासीय संरचनाओं का विवरण देता है।

96% ने अर्जित की जा रही भूमि पर बदलती क्रम के साथ कृषि / बागवानी करने की सूचना दी है। अनुमानित प्रभावों से भूमि का नुकसान होगा जो प्रभावित परिवारों को उनकी कृषि आय से वंचित करेगा और जीवन के तरीके को बदल देगा। इसके अलावा, परियोजना में निर्माण कार्य शामिल है जो वायु और जल प्रदूषण के कारण आसन्न भूमि मालिकों और अन्य लोगों को प्रभावित करेगा।

हालांकि, परियोजना के लिए 440.39 हेक्टेयर की कुल भूमि आवश्यकता में से केवल 53.196 हेक्टेयर (12%) निजी भूमि अर्जन के तहत आ रही है जो कि न्यूनतम विकल्प है। 53.196 हेक्टेयर में से कुल खेती योग्य भूमि 33.68 हेक्टेयर (63.3%) है और शेष 19.516 हेक्टेयर अनुपयोगी है। कम विस्थापित विकल्पों का अध्ययन करने के बारे में अधिक जानकारी, और न्यूनतम भूमि के अर्जन के अध्याय 7 में चर्चा की गई

6.3.2 आजीविका और आय पर प्रभाव

अर्जित की जा रही भूमि पर प्राथमिक आजीविका गतिविधि कृषि और बागवानी है। यद्यपि कोई भी हितधारक पूरी तरह से कृषि पर मुख्य आय स्रोत के रूप में निर्भर नहीं है। अध्ययन में पाया गया कि अधिकांश हितधारकों के पास सेवा क्षेत्र में काम करने वाले एक परिवार के सदस्य हैं, जो उनकी आय का मुख्य स्रोत है। हालांकि, 819 जमींदारों ने बताया कि कृषि उनकी समग्र पारिवारिक आय को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। PAF की आय का विवरण पहले ही अध्याय में ऊपर चर्चा की जा चुकी है।

इसके अलावा, सर्वेक्षण के दौरान कोई किरायेदार / पट्टाधारक नहीं पाए गए। हितधारकों ने बताया कि चूंकि भूमि का आकार छोटा है, इसलिए सभी कृषि / बागवानी कार्य परिवार द्वारा ही किए जाते हैं। मौसमी कृषि श्रम भी कम अवधि के लिए नियोजित होता है लेकिन यह श्रम अस्थायी होता है और अक्सर पलायन होता है।

6.3.3 भौतिक संसाधनों पर प्रभाव

6.3.3.1 निजी संपत्ति का नुकसान

प्रस्तावित निर्माण गतिविधि या जलमग्नता के कारण नदी चैनल के पास स्थित आवासीय संरचनाएं प्रभावित होंगी। सुन्नी HEP के लिए कुल 38 आवासीय संरचनाएँ प्राप्त की जा रही हैं। 38 आवासीय संरचनाओं में से 18 भराड़ा गाँव में हैं। यह भी पाया गया कि इन 38 संरचनाओं पर कुल स्वामित्व 146 है। आवासीय संरचनाओं के अलावा 4 शौचालय और 4 रसोई भी स्वतंत्र संरचनाओं के रूप में अर्जन के तहत आ रहे हैं। अर्जन के तहत भूमि से जुड़ी अन्य संपत्तियों में, कुल 14,824 फल देने वाले पेड़, 26,691 गैर-फल असर वाले पेड़ और 7 पानी की टंकियां भी प्रस्तावित अर्जन के कारण प्रभावित हो रही हैं।

नीचे दी गई तालिका गाँव को प्रस्तावित अर्जन के कारण खोई जा रही आवासीय संरचनाओं और इससे जुड़ी परिसंपत्तियों का विवरण देती है।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि फल और गैर-फल वाले पेड़ों के आंकड़े उत्तरदाताओं के अनुसार हैं। हालांकि, पेड़ों की वास्तविक संख्या की गणना की जाएगी और वास्तविक मूल्य का आकलन सक्षम अधिकारियों द्वारा किया जाएगा।

सुन्नी बांध जल विद्युत् परियोजना (382 MW) के लीये की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

तालिका 6-2: संरचनाओं की हानि

ज़िला	गाँव	आवासीय संरचनाएँ	स्वतंत्र शौचालय संरचनाएं	स्वतंत्र रसोई संरचनाएं	पानी की टंकी	फल देने वाले वृक्ष	बिना फल वाले पेड़
मण्डी	बलोग	2					
शिमला	बठोरा	0				1651	2370
मण्डी	बेलुढाँक	2				422	170
शिमला	भराड़ा	18	1	1	1	1513	1988
मण्डी	भौरा	0				1470	250
मण्डी	फ़ाफ़न	3	1	1	2	16	100
शिमला	ग्रेहना	1					75
शिमला	जैशी	2				1470	2048
मण्डी	जकलीन	0				50	100
शिमला	झुँझन	1	1	1	3	320	765
मण्डी	खरयाली	0				250	1169
शिमला	खेरा	1				4198	10806
शिमला	कोठी	1				25	460
शिमला	लुँसू	0				170	
शिमला	मझरोग	0					47
शिमला	मालगी	1				131	240
शिमला	ओगली	3	1	1	1	955	3533
शिमला	पंदोआ	2				510	910
मण्डी	परलोग	0				1330	740
शिमला	तलाह	1				343	920
Total		38	4	4	7	14824	26691

*स्रोत: प्राथमिक सर्वेक्षण

6.3.4 जैव विविधता और पर्यावरण पर प्रभाव

जैविक संसाधन इस तरह की विशाल परियोजनाओं से प्रभावित सबसे महत्वपूर्ण संसाधनों में से हैं। संभावित प्रभावों की भयावहता का अनुमान लगाने और प्रस्तावित परियोजना से होने वाले किसी भी नुकसान से बचने या कम करने के लिए इन संसाधनों का एक विस्तृत आधारभूत अध्ययन आवश्यक है। प्रस्तावित परियोजना के वन क्षेत्रों में वनस्पतियों और जीवों पर विशिष्ट प्रभावों की पहचान करने के लिए अलग से पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) किया जाना आवश्यक है।

इसके अलावा, परियोजना के तहत आने वाली कुल वन भूमि 387.19 हेक्टेयर है। अध्ययन के दौरान यह पाया गया कि ग्रामीण लोग चारे के संग्रह और ईंधन की लकड़ी के लिए जंगलों पर निर्भर थे जोकि अब खो जाएगी और इसलिए समान विकल्प उपलब्ध कराने की आवश्यकता है।

उत्तरदाताओं में से कई ने यह भी अनुमान लगाया कि जलाशय निर्माण और जल स्तर में वृद्धि के कारण आर्द्रता में भी वृद्धि होगी, जल जनित रोगों का खतरा, वायु और ध्वनि प्रदूषण में वृद्धि, निर्माण के कारण जल प्रदूषण में संभावित वृद्धि, यातायात भारी वाहनों का आवागमन आदि में वृद्धि होगी ।

6.3.5 सार्वजनिक सेवाओं और उपयोगिताओं पर प्रभाव

सामुदायिक स्वामित्व वाली संपत्ति (वनभूमि, जल निकाय, चरागाह भूमि, घाट, शमशान आदि) तक पहुंच की हानि की अक्सर अनदेखी की जाती है क्योंकि अक्सर उन्हें समुदाय को अप्रत्यक्ष लाभ प्रदान करने के लिए माना जाता है और उसकी मात्रा निर्धारित नहीं कर सकते । लेकिन इसका अभाव समुदाय के जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करता है।

चूंकि भूमि का अर्जन नदी के किनारे रैखिक रूप से हो रहा है, इसलिए निजी भूमि के अलावा दोनों किनारों पर निकटवर्ती वन क्षेत्र भी परियोजना के तहत आ रहा है। अध्ययन में पाया गया कि ग्रामीणों के पास पशुओं के चारे और जलाऊ लकड़ी के संग्रह के लिए जंगलों पर निर्भरता है। इसके अलावा, इन क्षेत्रों को ग्रामीणों द्वारा चराई के मैदान के रूप में भी उपयोग किया जाता है। मोगरा पंचायत में वनों पर निर्भरता सबसे अधिक पाई गई।

इसी प्रकार प्रस्तावित अर्जन के तहत 40 सार्वजनिक संपत्ति भी खोई जा रही है जिसमें मंडी जिले के ग्राम परलोग में 1 स्कूल, 3 पंपहाउस, 12 घर, शिमला जिले के मालगी गांव में 1 पुल, 6 रोपवे, 9 बिजली के खंभे, 3 पानी के नल, 2 हैंडपंप और 3 पानी की आपूर्ति पाइपलाइन शामिल हैं।

चूंकि कई गाँवों में पम्प हाउस और प्राकृतिक झरनों का भी नुकसान होगा, इसलिए यह उनकी मौजूदा सिंचाई और पेयजल सुविधाओं को प्रभावित करेगा। इसी तरह, बिजली के खंभे के नुकसान के कारण, क्षेत्रों को ब्लैकआउट के लिए असुरक्षित माना जाएगा, जब तक कि मौजूदा पोल को हटाने से पहले गाँवों में बिजली प्रदान करने के लिए उचित वैकल्पिक उपाय नहीं किए जाते हैं।

परियोजना के लिए रोपवे और पुलों के अर्जन से मुख्य सड़कों तक पहुँच में कमी और नदी के किनारे पर स्थित गाँवों के बीच संपर्क में अवरोध बनेगा। इसके अलावा, श्मशान घाट ज्यादातर गाँवों में डूबे होंगे क्योंकि वे ज्यादातर नदी किनारे स्थित होते हैं। इन उपयोगिताओं का नुकसान प्रभावित आबादी के आर्थिक और सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन पर सीधा नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

इसके अलावा, निर्माण चरण के दौरान लोगों, सामग्री, उपकरण और प्रवासन में वृद्धि होगी जो उपलब्ध बुनियादी ढांचे जैसे सड़क, मौजूदा स्वास्थ्य और शैक्षिक सुविधाओं आदि पर एक अतिरिक्त भार पैदा करेगा, इसलिए इसे पहले से मजबूत करने की आवश्यकता है।

नीचे दी गई तालिका गाँव को प्रस्तावित अर्जन के कारण सार्वजनिक सेवाओं और उपयोगिताओं के नुकसान का विवरण देती है।

तालिका 6-2: सार्वजनिक सेवाओं और उपयोगिताओं पर प्रभाव

ज़िला	गाँव	स्कूल	पम्प हाउस	घराट	पुल	रोप वे	बिजली के खम्बे	पानी के पाइप लाइन	हैंड पम्प	नल
शिमला	लुन्सू	0	0	0	0	0	0	0	0	0
शिमला	खैरा	0	0	0	0	0	4	0	0	0
शिमला	जैशी	0	0	4	0	1	0	0	0	0
शिमला	भराड़ा	0	1	1	0	1	1	1	1	1
शिमला	तलाह	0	0	0	0	1	0	0	0	0
शिमला	ओगली	0	1	2	0	1	0	0	0	0
शिमला	कोठी	0	1	0	0	0	0	0	0	0
शिमला	मालगी	0	0	1	1	0	0	0	0	0
शिमला	बठोरा	0	0	2	0	0	0	0	0	0
शिमला	पंदोआ	0	0	1	0	0	0	0	0	0

सुन्नी बांध जल विद्युत् परियोजना (382 MW) के लीये की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

ज़िला	गाँव	स्कूल	पम्प हाउस	घराट	पुल	रोप वे	बिजली के खम्बे	पानी के पाइप लाइन	हैंड पम्प	नल
शिमला	ग्रहना	0	0	0	0	1	0	0	0	0
शिमला	झुंझन	0	0	0	0	1	3	2	1	2
शिमला	मझरोग	0	0	1	0	0	0	0	0	0
मण्डी	भौरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0
मण्डी	बलोग	0	0	0	0	0	0	0	0	0
मण्डी	जकलीन	0	0	0	0	0	0	0	0	0
मण्डी	फ़ाफ़न	0	0	0	0	0	1	0	0	0
मण्डी	परलोग	1	0	0	0	0	0	0	0	0
मण्डी	बेलुढाँक	0	0	0	0	0	0	0	0	0
मण्डी	खरयाली	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		1	3	12	1	6	9	3	2	3

*स्रोत: प्राथमिक सर्वेक्षण

6.3.6 स्वास्थ्य, संस्कृति और सामाजिक सामंजस्य पर प्रभाव

अध्ययन में पाया गया कि परियोजना क्षेत्र में ग्रामीणों के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि बढ़ती आर्द्रता, जल जनित रोगों की चपेट में आने, वायु और ध्वनि प्रदूषण में वृद्धि, मौजूदा स्वास्थ्य सुविधाओं पर दबाव बढ़ जाएगा।

उत्तरदाताओं को स्थानीय लोगों और प्रवासियों के बीच संघर्ष में वृद्धि की संभावना के बारे में भी आशंका थी। उन्होंने कहा कि प्रवासन के कारण क्षेत्र में अपराध दर और असामाजिक गतिविधियों में वृद्धि की संभावना है। यह क्षेत्र सांस्कृतिक मिश्रण का भी गवाह बन सकता है। हालांकि, प्रवासन के कारण क्षेत्र में वस्तुओं की खपत में वृद्धि देखी जाएगी, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ होगा

6.3.7 लिंग आधारित प्रभाव

लिंग समानता: भूमि के प्रस्तावित अर्जन के संभावित प्रभावों में से एक भूमि की हानि के कारण परियोजना क्षेत्र में महिलाओं के लिए काम के अवसरों की अनुपलब्धता हो सकती है। अगर महिलाएं शिक्षित हैं, तो भी वे आजीविका कमाने के लिए गाँव से बाहर जाना पसंद नहीं करती हैं। संभावित रूप से एक और प्रभाव

महिलाओं की आर्थिक स्थिति का हास है क्योंकि उनमें से कई का भूमि पर कागजों पर कोई कानूनी दावा नहीं है, इसलिए वे भूमि-क्षति के प्रतिकर के लिए योग्य नहीं होंगे और वे अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित PAPs की श्रेणी में आते हैं। नीचे दी गई तालिका परियोजना क्षेत्र में PAPs का एक सेक्स वार वितरण प्रदान करती है:

चूंकि परियोजना क्षेत्र मुख्य रूप से कृषि प्रधान है, इसलिए आजीविका गतिविधियों के मुख्य स्रोतों में से एक भूमि निर्भर है। अध्ययन के दौरान यह देखा गया कि घर की महिलाएं भी पुरुषों के साथ क्षेत्र में कृषि गतिविधियों को करने में भाग लेती हैं। कृषि के अलावा, दिन के दौरान महिलाओं को अन्य गतिविधियों जैसे मवेशी और मुर्गी के रखरखाव, मवेशियों के चारे और घर के लिए जलाऊ लकड़ी इत्यादि को एकत्र करने के लिए अधिक शामिल पाया गया, हालांकि ये गतिविधियाँ आर्थिक भलाई के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। किसी भी घर में, हालांकि एक ही मात्रा निर्धारित करना मुश्किल हो जाता है। कुल 4683 PAPs में से 2285 महिलाएँ हैं, जिनमें से 798 महिलाएँ शीर्षक धारक हैं। PAPs के बीच 141 विधवाएँ हैं, जिनमें से 93 विधवाओं को भी जमीन का स्वामित्व है। विशेष रूप से विधवा महिलाएं अत्यधिक असुरक्षित होती हैं और प्रतिकर के वितरण के दौरान विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। PAPs और जो शीर्षक धारक हैं, के बीच कुल विधवाओं की एक सूची, जो सर्वेक्षण के दौरान पहचान की गई है, अनुबंध में दी गई है।

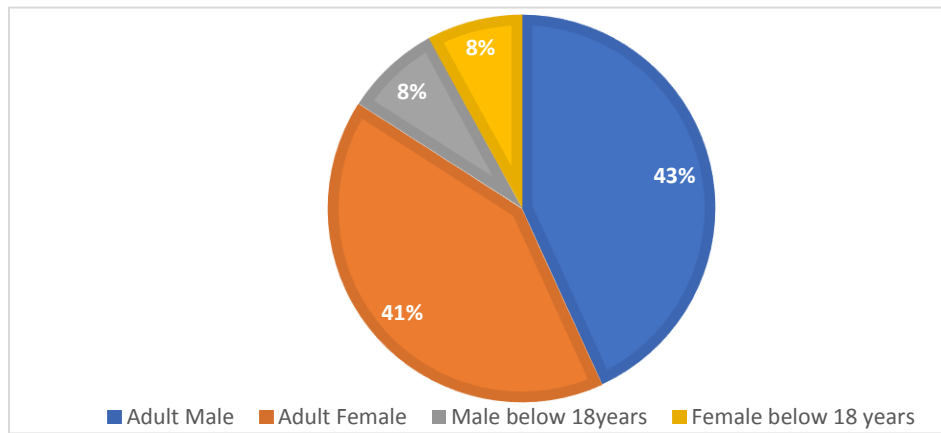
सुन्नी बांध जल विद्युत् परियोजना (382 MW) के लीये की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

तालिका 6-3: परियोजना क्षेत्र में PAPs के लिंग वार वितरण

वयस्क पुरुष	वयस्क महिला	पुरुष 18 वर्ष से कम	महिला 18 वर्ष से कम	कुल पुरुष	कुल महिला	कुल
2022	1915	376	370	2398	2285	4683

*स्रोत: प्राथमिक सर्वेक्षण

चित्र 6-1: परियोजना क्षेत्र में PAPs के लिंग वार वितरण



*स्रोत: प्राथमिक सर्वेक्षण

6.4 PAPs द्वारा प्रभावित के रूप में प्रभाव का अनुमान

प्रभावित भूस्वामियों के साथ परामर्श अनैच्छिक पुनर्वास के विषय में मुद्दों के समाधान का प्रारंभिक बिंदु था, इस परियोजना से प्रभावित लोगों को भूमि अर्जन के कारण उनके नुकसान के बारे में आशंका है।

प्राथमिक सर्वेक्षण के दौरान, उत्तरदाताओं ने साझा किया कि सुन्नी HEP गतिविधियों के कारण कुछ सकारात्मक प्रभाव होंगे। इनमें परियोजना के भीतर और अग्रामी व अधोग्रामी संबंधों के दायरे में रोजगार और आय के अवसरों में वृद्धि शामिल है। उत्तरदाताओं के अनुसार भूमि के मूल्य में वृद्धि एक और बड़ी सकारात्मक बात है। उनमें से अधिकांश का मानना था कि यह व्यापार के अवसरों में वृद्धि की गुंजाइश पैदा करेगा। इसके अलावा, उनमें से कुछ को उम्मीद है कि एक बेहतर सड़क नेटवर्क के कारण औसत वाहनों की गति में वृद्धि होगी और परिवहन सेवाओं की आवृत्ति में वृद्धि होगी। अधिकांश PAPs समग्र विकास के बारे में भी सकारात्मक थे, विशेष रूप से अवसंरचनात्मक विकास (सामाजिक और भौतिक) जो आगामी HEP के कारण परियोजना गांवों में होंगे।

उत्तरदाताओं को कुछ नकारात्मक प्रभावों के बारे में चिंता लग रही है इनमें से मुख्य भूमि की हानि थी। यह अपने आप में उनकी आजीविका, जीवन के मार्ग और सामाजिक रिश्तों पर एक बड़ा प्रभाव डालता है। अगला प्रभाव राज्य के विभिन्न हिस्सों से या अलग-अलग राज्यों से प्रवासियों की आमद से संबंधित है- जो स्थानीय लोगों और बाहरी लोगों के बीच टकराव पैदा कर सकता है, उनकी संस्कृति और सामाजिक जीवन के लिए घुसपैठ, बुनियादी ढांचे पर, मौजूदा प्राकृतिक संसाधनों पर अधिक दबाव बनाएगा ।

इसके अलावा, वन भूमि के अर्जन के कारण, जिस पर ग्रामीण चारे के संग्रह, ईंधन की लकड़ी के लिए निर्भर थे और अब खो जाएगी और इसलिए इसके समकक्ष विकल्प प्रदान किए जाने की आवश्यकता है।

जलाशय निर्माण और जल स्तर में वृद्धि के कारण आर्द्रता में वृद्धि होगी।, जल जनित रोगों का खतरा, वायु और ध्वनि प्रदूषण में वृद्धि, निर्माण के कारण जल प्रदूषण में संभावित वृद्धि, यातायात में वृद्धि, भारी वाहनों का आवागमन व वाहनों की गति में वृद्धि और सड़कों पर अधिक कारों के कारण अधिक सड़क दुर्घटनाएं हो सकती हैं।

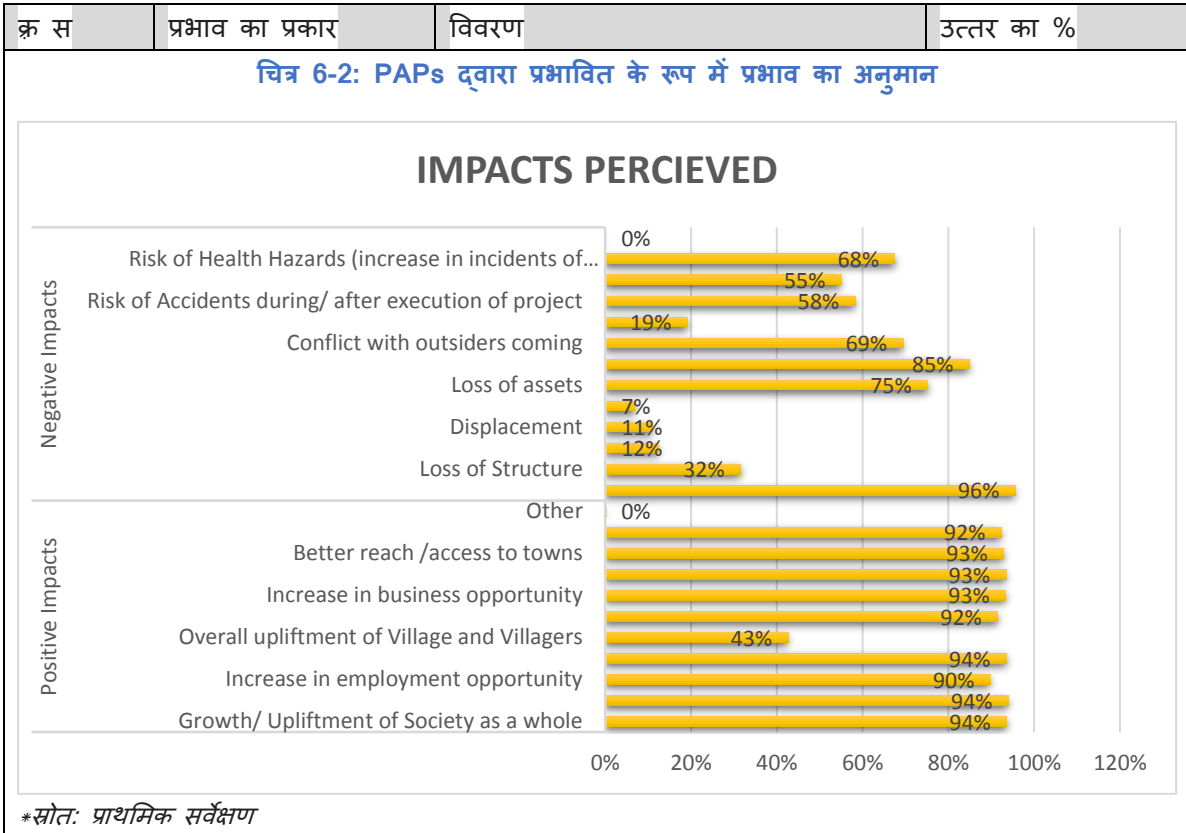
द्वारा सतलुज को पार करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रोपवे का नुकसान हो जाएगा, जिसका दोनों किनारों पर ग्रामीणों के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। ग्रामीण उन प्रभावों से भी संबंधित थे जो श्मशान घाटों के नुकसान के कारण बनेंगे।

एक अन्य प्रमुख चिंता का कारण गांवों में उनके पीने के पानी के संसाधनों जैसे आईपीएच के बुनियादी ढांचे, प्राकृतिक झरनों, नदियों और बावड़ियों और घाटों के नुकसान के कारण भी था। उत्तरदाताओं में से कुछ ने यह भी कहा कि एचआईवी / एड्स और तस्करी के जोखिमों की संभावना बढ़ जाएगी।

नीचे दी गई तालिका घरेलू सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त प्रतिक्रियाओं को दिखाती है:

तालिका 6-5: PAPs द्वारा प्रभावित के रूप में प्रभाव का अनुमान

क्र स	प्रभाव का प्रकार	विवरण	उत्तर का %
1	सकारात्मक प्रभाव	समग्र रूप से समाज का विकास / उत्थान	94%
2		जनता के लिए मौजूदा प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर उपयोग	94%
3		रोजगार के अवसर में वृद्धि	90%
4		आर्थिक स्थिति में सुधार	94%
5		ग्राम और ग्रामीणों का समग्र उत्थान	43%
6		बेहतर सेवाओं की उपलब्धता	92%
7		व्यापार के अवसर में वृद्धि	93%
8		भूमि की कीमत में वृद्धि	93%
9		कस्बों तक बेहतर पहुंच	93%
10		जीवन की बेहतर गुणवत्ता	92%
11		अन्य	0%
12	नकारात्मक प्रभाव	जमीन का नुकसान	96%
13		संरचना का नुकसान	32%
14		आजीविका का नुकसान	12%
15		विस्थापन	11%
16		वित्तीय सुरक्षा का खतरा	7%
17		संपत्ति का नुकसान (निजी और सार्वजनिक दोनों)	75%
18		प्रदूषण में बढ़ोतरी	85%
19		बाहरी लोगों के आने से विरोध	69%
20		जीवन की गुणवत्ता में गिरावट	19%
21		परियोजना के निष्पादन के दौरान / बाद में दुर्घटनाओं का जोखिम	58%
22		मौजूदा बुनियादी ढांचे पर दबाव	55%
23		स्वास्थ्य के खतरों की आशंका (एचआईवी / एड्स और तस्करी आदि की घटनाओं में वृद्धि)	68%
24		अन्य	0%
*स्रोत: प्राथमिक सर्वेक्षण			



नकारात्मक प्रभावों से इतर , लोग आशावादी है कि आगामी परियोजना के साथ सकारात्मक प्रभाव आएँगे समग्र रूप से कुल मिलाकर जीवन की बेहतर गुणवत्ता, समाज के विकास / उत्थान, जनता के लिए मौजूदा प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर उपयोग, आर्थिक स्थिति में सुधार, व्यवसाय के अवसर और भूमि की कीमतों में वृद्धि, पड़ोसी शहरों के साथ बेहतर संपर्क के कारण उन्हें बेहतर रोजगार के अवसर मिलने की उम्मीद है।

निर्माण की अवधि के दौरान मौजूदा बुनियादी ढांचे और दुर्घटनाओं का खतरा, भूमि, संरचना और परिसंपत्तियों के नुकसान के अलावा, लोगों ने निर्माण गतिविधियों के कारण प्रदूषण के बढ़ते स्तर, आजीविका की हानि, वित्तीय सुरक्षा पर जोखिम, निर्माण कार्यों के लिए अपने गांवों में आने वाले बाहरी लोगों के साथ संघर्ष, स्वास्थ्य खतरों के जोखिम, दबाव के लिए अपनी चिंता दिखाई।

उपरोक्त के अलावा, लोगों का मानना है कि प्रस्तावित अर्जन के कारण उन्हें सबसे बड़ी चुनौती होगी:

1. गाँव में कृषि के लिए कम भूमि उपलब्ध।
2. कृषि गतिविधि के लिए नई भूमि का चयन और तैयारी।
3. अच्छी उर्वरता के साथ प्रतिकर में खेती योग्य भूमि प्राप्त करना।
4. फल देने वाले पेड़ों का नुकसान

संभावित चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करने के लिए, PAPs द्वारा और पंचायतों के साथ आयोजित FGD के दौरान निम्नलिखित शमन उपाय प्रस्तावित किए गए थे:

1. सड़कों, पुलों और डिजिटल नेटवर्क के संबंध में बेहतर संपर्क, जिसमें गाँव का उन्नयन और सभी मौसम वाली सड़कों के लिए लिंक सड़कें शामिल हैं
2. परियोजना क्षेत्र की सभी पंचायतों में उचित जल निकासी की सुविधा।
3. PAPs के लिए आगामी HEP परियोजना में नौकरी के अवसर।
4. बुनियादी सुविधाओं, सेवाओं और सुविधाओं के संदर्भ में गाँव का विकास।
5. गाँव के भीतर बेहतर स्कूल और उच्च शिक्षा की सुविधा।
6. परियोजना क्षेत्र और परिवेश के लिए तकनीकी शिक्षा संस्थान।
7. बढ़ी हुई सर्कल दरों के साथ अर्जित भूमि के खिलाफ प्रतिकर।
8. एम्बुलेंस सेवाओं, एम्बुलेंस सड़कों, PHC के बेहतर बुनियादी ढांचे, क्लीनिक और गाँवों में अस्पतालों की सुविधाओं सहित बेहतर स्वास्थ्य देखभाल।
9. आय बहाली के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र।
10. विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत कामगार वर्ग की आबादी को कौशल उन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करना।
11. प्रस्तावित परियोजना के कारण प्रदूषण के स्तर पर निरंतर जाँच।
12. आगामी परियोजना में स्थानीय ग्रामीणों के लिए व्यावसायिक अवसर और अन्यथा निर्माण, आपूर्ति और परिवहन के लिए अनुबंध।
13. परियोजना क्षेत्र की सभी पंचायतों में स्ट्रीट लाइटिंग।
14. परियोजना से प्रभावित PAPs और पंचायतों को विशेष रियायती दरों पर बिजली।
15. सभी परियोजना प्रभावित पंचायतों में सिंचाई की उचित सुविधा।
16. अन्य चल रही विकास योजना से सहायता / ऋण।

6.5 सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना के बारे में जागरूकता

प्राथमिक सर्वेक्षण के दौरान, औसतन 87% उत्तरदाताओं ने कहा कि वे आगामी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, इसके उद्देश्य और प्रतिकर के बारे में आंशिक रूप से अवगत थे। 8% ने कहा कि वे पूरी तरह से जागरूक हैं और 5% ने बताया कि वे इस परियोजना, इसके उद्देश्य और पात्र प्रतिकर के बारे में बिल्कुल भी जागरूक नहीं हैं।

तालिका 6-6: विद्युत परियोजना के बारे में जागरूकता

जागरूकता	हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के बारे में जागरूकता	परियोजना के उद्देश्य के बारे में जागरूकता	पात्र प्रतिकर के बारे में जागरूकता
पूरी तरह से	8%	8%	5%
आंशिक रूप से	87%	87%	87%
बिल्कुल नहीं	5%	5%	8%
कुल	100%	100%	100%
*स्रोत: प्राथमिक सर्वेक्षण			

सर्वेक्षण के दौरान 99.5% उत्तरदाताओं ने परियोजना के बारे में और अधिक जानने के लिए अपनी रुचि व्यक्त की, इसका उद्देश्य, व्यक्तियों / परिवारों / गाँवों को लाभ, पूरे प्रतिकर के लिए वे पात्र हैं और व्यक्तियों / परिवारों / गाँव पर सकारात्मक / नकारात्मक प्रभावों के लिए संभव है।

तालिका 6-7: PAPs के लिए परियोजना के बारे में जानकारी का प्रमुख स्रोत

सूचना का स्रोत	
रेडियो	2%
समाचार पत्र	2%
सरकारी अधिकारी	17%
अन्य ग्रामीण	78%
अन्य	1%
*स्रोत: प्राथमिक सर्वेक्षण	

प्राथमिक सर्वेक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि 78% PAPs को अन्य ग्रामीणों के माध्यम से परियोजना के बारे में पता चला, 17% को इसके बारे में कुछ सरकारी अधिकारियों के माध्यम से पता चला, 2% को परियोजना और रेडियो और समाचार पत्र के माध्यम से प्रस्तावित अर्जन के बारे में जानकारी मिली से।

6.6 परियोजना के लिए सहमति

सर्वेक्षण के दौरान, 91% लोगों ने कहा कि उन्हें आगामी सुन्नी HEP परियोजना या प्रस्तावित अर्जन पर कोई आपत्ति नहीं है, दूसरी ओर 8% ने HEP परियोजना के लिए भूमि के प्रस्तावित अर्जन पर अपनी आपत्ति व्यक्त की और शेष 1% इसके बारे में निश्चित नहीं थे।

तालिका 6-8 : PAPs द्वारा अर्जन के संबंध में कोई आपत्ति

हाँ	8%
नहीं	91%
ख नहीं सकते	1%
कुल	100%
*स्रोत: प्राथमिक सर्वेक्षण	

6.7 प्रतिकर वरीयताएँ

सर्वेक्षण के दौरान, 83% भूमि खोने वालों ने जवाब दिया कि वे उस भूमि के खिलाफ प्रतिकर के रूप में नकद चाहते हैं जो वे खो रहे हैं और शेष 17% भूमि के लिए प्रतिकर के रूप में भूमि की मांग की है।

54% संरचना खोने वालों लोगों ने नकदी की मांग की और 46% ने प्रतिकर के रूप में संरचना के खिलाफ संरचना की मांग की।

100% परिसंपत्ति खोने वालों लोगों ने अपने नुकसान के खिलाफ नकद प्रतिकर की मांग की।

तालिका 6-9: PAPs द्वारा प्रतिकर वरीयताएँ

प्रतिकर वरीयताएँ	भूमि खोने वालों द्वारा चुना गया	संरचना खोने वालों द्वारा चुना गया	परिसंपत्ति खोने वालों द्वारा चुना गया
नगद	83%	54%	100%
भूमी	17%	0	0
संरचना	0	46%	0
कुल	100%	100%	100%
* स्रोत: प्राथमिक सर्वेक्षण			

सभी PAPs ने सर्वसम्मति से एकल भुगतान में नकद प्रतिकर की मांग की।

6.8 प्राप्त नकद प्रतिकर का उपयोग

प्राथमिक सर्वेक्षण के दौरान, लगभग 61% PAPs ने कहा कि वे कृषि या नए घर के लिए जमीन खरीदने के लिए प्राप्त नकद प्रतिकर का उपयोग करेंगे, लगभग 25% ने कहा कि वे इसे भविष्य में उपयोग के लिए बैंक में बचाएंगे, 2% ने जवाब दिया कि वे इसे किसी अन्य व्यवसाय में निवेश करने के लिए चाहेंगे, लगभग 12% लोगों ने कहा कि उन्होंने अभी सोचा नहीं है कि वे प्राप्त प्रतिकर का उपयोग कैसे करेंगे और 1% से भी कम ने प्रतिकर राशि के साथ एक नया घर खरीदने में अपनी रुचि व्यक्त की।

तालिका 6-10: प्राप्त नकद प्रतिकर का उपयोग

प्राप्त प्रतिकर का उपयोग	प्रतिक्रियाओं का %
1. कृषि / आश्रय के लिए भूमि खरीदकर	61.41%
2. घर खरीदने के लिए	0.23%
3. बैंक में भविष्य के लिए इसे बचा रहा है	24.52%
4. इसे किसी अन्य व्यवसाय में निवेश करना	1.93%
5. तय नहीं	11.92%
* स्रोत: प्राथमिक सर्वेक्षण	

7 अर्जन पर लागत और लाभ और सिफारिशों का विश्लेषण

इस अध्याय में लोक प्रयोजनके मूल्यांकन, कम विस्थापन के विकल्प, न्यूनतम भूमि आवश्यकताओं, व्यवहार्यता और शमन उपायों की सीमा के साथ अंतिम निष्कर्ष प्रकृति और सामाजिक प्रभावों की तीव्रता के साथ चर्चा की गई है। अंत में, अध्याय का उद्देश्य प्रस्तावित परियोजना और प्रस्तावित अर्जन के अस्थायी समग्र लाभों पर प्रदर्शित करना है और इसकी तुलना परियोजना क्षेत्र के प्रत्यक्ष हितधारकों जैसे परियोजना प्रभावित पंचायतों और निकटवर्ती क्षेत्र में होने वाले प्रभावों से की जाती है, जिससे यह अंतिम सिफारिश के लिये रखा जायगा कि इसे अर्जन की प्रक्रिया से गुजरना चाहिए या नहीं।

7.1 लोक प्रयोजन का आकलन

हिमाचल प्रदेश में पनबिजली ऊर्जा के दोहन के लिए रणनीति का पालन न्यूनतम लागत और न्यूनतम पर्यावरणीय प्रभावों के साथ अधिक से अधिक ऊर्जा का उत्पादन करना है। जलविद्युत क्षमता का तेजी से दोहन निश्चित रूप से राज्य के आर्थिक स्वास्थ्य में सुधार करेगा, क्योंकि सभी नए प्रतिष्ठानों पर परियोजना की लागत में 12 प्रतिशत मुफ्त बिजली और 1.5% LADF (स्थानीय क्षेत्र विकास निधि), से राज्य के स्रोतों में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। पनबिजली परियोजनाओं की आवश्यकता भी उत्पन्न होती है, जिससे अधिकतम बिजली की मांग में निरंतर वृद्धि और उत्तरी क्षेत्र में ऊर्जा की बढ़ती कमी को पूरा किया जा सके।

सतलुज नदी की जल क्षमता का दोहन करने के लिए सुन्नी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट (382MW) नदी प्रवाह प्रकार योजना है। SJVNL उसी के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है। परियोजना का उद्देश्य उत्तरी क्षेत्र में बिजली आपूर्ति में अंतर को कम करना और स्थानीय आवासों पर न्यूनतम खतरनाक और न्यूनतम सामाजिक-पर्यावरणीय प्रभावों के साथ अधिकतम ऊर्जा संसाधनों का दोहन करके राज्य के राजस्व में वृद्धि करना है।

सुन्नी HEP की अपेक्षित बिजली उत्पादन प्रति वर्ष 1381.77 GWH होगा। कुल परियोजना लागत रु 2,911.85 करोड़ अनुमानित है। शुरू होने के पहले वर्ष में परियोजना से अपेक्षित राजस्व पहले वर्ष में 648 करोड़ और बाद के वर्षों में 608 करोड़ रुपये होगा। परियोजना का अनुमान है कि 310 व्यक्तियों का कुल स्थायी / नियमित रोजगार और इसके निर्माण के चरण, निर्माण के चरण के दौरान और परियोजना शुरू होने के बाद 56,57,500 व्यक्ति-दिनों का अस्थायी रोजगार होगा। यह रोजगार कुशल, अर्ध-कुशल और अकुशल श्रमिकों के लिए उत्पन्न होगा। HP सरकार के नियम अनुसार, रोजगार का 70% हिमाचल प्रदेश

के निवासियों के लिए आरक्षित होना चाहिए। इस मामले में, परियोजना स्तर पर उत्पन्न रोजगार के लिए PAP को प्राथमिकता दी जाएगी।

RTFCTLARR अधिनियम, 2013 की धारा 2 उपधारा 1 (बी) के अनुसार, सुन्नी बांध जल विद्युत् परियोजना (382 मेगावाट) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए बुनियादी ढांचा परियोजनाओं (ऊर्जा उत्पादन) की परिभाषा के तहत अच्छी तरह से उचित है।

7.2 कम विस्थापन विकल्प और न्यूनतम भूमि की आवश्यकता

सुन्नी बांध जल विद्युत् परियोजना, लुहरी परियोजना का हिस्सा है, जो तीन चरणों में तीन बांधों के निर्माण पर विचार करती है। लुहरी हाइड्रो-इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्टेज- I (210 मेगावाट), लुहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्टेज- II (163 मेगावाट) और सुन्नी डैम हाइड्रो-इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट (382 मेगावाट)।

सुन्नी डैम HEP के बहाव में 800 MW कोल डैम HEP स्थित है। लुहरी परियोजना के अपस्ट्रीम पर 412 मेगावाट की रामपुर HEP है, जो आगे की ओर 1500 मेगावाट नाथपा-झाकड़ी परियोजना से छोड़े गए पानी का उपयोग करती है।

विशेष रूप से, वर्तमान में लगभग 250 किलोमीटर की दूरी पर नाथपा-झाकरी और कोल डैम के बीच सतलुज नदी पर लगातार 6 HEP चालू हैं। चूंकि सुन्नी बांध HEP लुहरी परियोजना का हिस्सा है और कोल डैम और लुहरी स्टेज -2 HEP के बीच स्थित है, इसलिए, परियोजना के लिए किसी भी वैकल्पिक स्थान के लिए सीमित गुंजाइश छोड़ रहा है।

हालांकि, डैम और पावर हाउस के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान को अंतिम रूप देने के लिए परियोजना के लेआउट के बारे में विकल्पों का विस्तार से अध्ययन किया गया है। विभिन्न भू-तकनीकी पहलुओं, स्थान, क्षमता और प्रकृति के साथ वैकल्पिक प्रस्तावों का अध्ययन करने के बाद, 382 मेगावाट और खैरा गांव में बांध स्थल की क्षमता वाले वर्तमान प्रस्ताव का चयन किया गया है। वर्तमान परियोजना डिजाइन को भूमि अर्जन की न्यूनतम आवश्यकता और सबसे व्यवहार्य इंजीनियरिंग डिजाइन के महत्वपूर्ण विचार के बाद चुना गया था। सुन्नी HEP के लिए आवश्यक कुल भूमि 440.3914 हेक्टेयर है, जिसमें से केवल 53.1964 हेक्टेयर निजी भूमि मालिकों से प्राप्त की जाएगी। यह कुल भूमि की आवश्यकता का सिर्फ 12% है। अर्जन के तहत आने वाली अधिकांश भूमि का उपयोग या तो कृषि या बागवानी गतिविधियों के लिए किया जाता है और प्रस्तावित अर्जन से केवल 38 आवासीय संरचनाएं प्रभावित हो रही हैं।

इसलिए परियोजना गतिविधियों के कारण निजी भूमि के अर्जन के साथ-साथ न्यूनतम विस्थापन को कम करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं।

7.3 सामाजिक प्रभावों की प्रकृति और तीव्रता

यदि प्रभाव, अगर स्थायी प्रकृति का है तो उसका प्रभाव, निर्माण के बाद के चरण के दौरान भी उसे तरह का होगा जैसा के निर्माण पूर्व या निर्माण चरण के रहता है दूसरी तरफ अस्थायी प्रभाव निर्माण / निर्माण चरण परियोजना चक्र के बाद के चरणों के दौरान तीव्रता में निरंतर कमी दिखाएगा। निर्माण चरण के बाद भी किसी भी प्रभाव को दीर्घकालिक प्रभाव के रूप में माना जाता है और यदि यह केवल निर्माण चरण के चलने तक रहता है, तो इसे अल्पकालिक प्रभाव माना जाता है।

नीचे दी गई तालिका परियोजना चक्र के विभिन्न चरणों के दौरान विभिन्न पहचाने गए प्रभावों की प्रकृति और तीव्रता को दर्शाती है:

तालिका 7-1: प्रभाव की प्रकृति और तीव्रता

प्रभाव	क्रमांक	प्रभाव की पहचान	परियोजना चक्र का चरण	प्रभाव की प्रकृति	प्रभाव की तीव्रता
सामाजिक		क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए हितधारकों के बीच विवाद	पूर्व निर्माण	अस्थायी	अल्पावधि
		प्रोजेक्ट से लाभान्वित हो रहे लोगों और अप्रभावित रहने वाले लोगों के बीच सामाजिक विभाजन।		अस्थायी	अल्पावधि
		इन-माइग्रेशन के कारण स्थानीय आवासों की मौजूदा सांस्कृतिक प्रथाओं और परंपराओं पर प्रभाव।	निर्माण चरण	अस्थायी	दीर्घकालिक
भूमि / संरचना		कृषि भूमि का नुकसान	निर्माण चरण	स्थायी	दीर्घकालिक
		PAP के बीच भूमिहीनता		स्थायी	अल्पावधि
		PAP के लिए आश्रय का नुकसान		स्थायी	अल्पावधि

सुन्नी बांध जल विद्युत् परियोजना (382 MW) के लीये की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

		सार्वजनिक बुनियादी ढांचे जैसे रोपवे, पुल, घाट, सड़क, पानी की पाइपलाइन, पंपघर-, स्कूल, आदि को नुकसान।		अस्थायी	अल्पावधि
		आम संपत्ति का नुकसान		अस्थायी	अल्पावधि
आजीवि का / आय		कृषि आय का नुकसान		स्थायी	दीर्घकालिक
		अप्रत्यक्ष रूप से अर्जित भूमि पर निर्भर लोगों के लिए आजीविका विकल्प का नुकसान। उदाहरण के लिए कृषि मजदूर, विक्रेता, आदि।	निर्माण के पूर्व	अस्थायी	अल्पावधि
		प्रवासन के कारण वस्तुओं की बढ़ी हुई खपत स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ पहुँचा रही है।	निर्माण चरण	अस्थायी	अल्पावधि
		निर्माण कार्य में स्थानीय ग्रामीणों और PAPs के लिए नौकरी का अवसर।	निर्माण चरण	अस्थायी	अल्पावधि
		भूमि की कीमतों में वृद्धि	निर्माण और निर्माण के बाद का चरण	स्थायी	दीर्घकालिक
	प्रतिकर के कारण PAF की वित्तीय स्थिति में अचानक परिवर्तन, उनकी क्रय क्षमता में बदलाव होगा और फंड मिस मैनेजमेंट के-जोखिम को भी बढ़ाएगा।	निर्माण के पूर्व	अस्थायी	अल्पावधि	
भौतिक संसाधन		पेड़, पानी की टंकी, शौचालय और रसोई जैसी निजी संपत्ति का नुकसान।	निर्माण चरण	अस्थायी	अल्पावधि
		मौजूदा बुनियादी ढांचे जैसे PHC, शैक्षिक संस्थानों, सड़कों, आदि पर दबाव बढ़ा।	निर्माण चरण	अस्थायी	अल्पावधि
जैव विविध ता / पर्यावर ण		प्रभावित गांवों और पड़ोसी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए चारा और जलाऊ लकड़ी संग्रह के लिए प्राथमिक स्रोत के रूप में सेवारत वन भूमि का नुकसान।	निर्माण और निर्माण के बाद का चरण	स्थायी	दीर्घकालिक

सुन्नी बांध जल विद्युत् परियोजना (382 MW) के लीये की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

		जलाशय के निर्माण के कारण आर्द्रता में वृद्धि।	निर्माण और निर्माण के बाद का चरण	स्थायी	दीर्घकालिक
		निर्माण गतिविधि और उत्खनन के कारण वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण का स्तर बढ़ा।	निर्माण चरण	अस्थायी	अल्पावधि
स्वास्थ्य		प्रदूषण स्तर बढ़ने से जल जनित रोगों का खतरा।	निर्माण चरण	अस्थायी	अल्पावधि
		परियोजना के निष्पादन के दौरान बाद में / दुर्घटनाओं का जोखिम	निर्माण चरण	अस्थायी	अल्पावधि
		स्वास्थ्य के खतरों का खतरा / एचआईवी) (एड्स और तस्करी आदि की घटनाओं में वृद्धि	निर्माण चरण	अस्थायी	अल्पावधि
जीवन की गुणवत्ता		ट्रैफिक में वृद्धि। भारी वाहनों का आवागमन	निर्माण चरण	अस्थायी	अल्पावधि
		स्थानीय ग्रामीणों और प्रवासियों के बीच संभावित विवाद।	निर्माण चरण	अस्थायी	अल्पावधि
		विभिन्न गांवों के बीच समझौता कनेक्टिविटी।	निर्माण चरण	अस्थायी	अल्पावधि
		सिंचाई सुविधा का हास।	निर्माण चरण	अस्थायी	अल्पावधि
		प्राकृतिक झरने और पम्पाउस के नुकसान के कारण पीने के पानी की उपलब्धता में गिरावट।	निर्माण चरण	अस्थायी	अल्पावधि
		इन माइग्रेशन के कारण सामाजिक सुरक्षा की-भावना में कमी।	निर्माण चरण	अस्थायी	अल्पावधि
		गाँव का समग्र विकास।	निर्माण के उपरान्त	स्थायी	दीर्घकालिक

*स्रोत: SIA टीम

7.4 सुझाये गये शमन उपाय की व्यवहार्यता

अध्ययन द्वारा सुझाए गए शमन उपायों को सामाजिक समाघात प्रबंध योजना (SIMP) के तहत विवरण में चर्चा की गई है। एक समग्र रूप में प्रभावित परिवारों, पंचायतों और समुदाय की राय और मांगों के आधार पर और परियोजना के विभिन्न पहलुओं और राज्य सरकार की भागीदारी को देखते हुए, दोनों सकारात्मक और साथ ही परियोजना के नकारात्मक प्रभाव भी हैं। प्रस्तावित HEP के कारण क्षेत्र के विकास की उम्मीद है, वहीं परियोजना के बारे में समुदाय में भय और आशंकाएं भी हैं।

स्वामियों द्वारा अपेक्षित नकारात्मक प्रभावों में भूमि की हानि, प्रदूषण के स्तर में वृद्धि, निजी और वन भूमि पर निर्भर गतिविधियों में अचानक गिरावट, बाहर की आबादी का प्रवाह शामिल है जिसके परिणामस्वरूप सुरक्षा-बचाव चिंताओं, सामाजिक संघर्षों आदि में वृद्धि होती है और सार्वजनिक उपयोगिताओं के नुकसान, परियोजना प्रभावित गांवों और आस-पास के क्षेत्र के निवासियों को सड़क संचार तक पहुंच में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, जो विभिन्न पंचायतों / गांवों के लोगों और डूबने के कारण विस्थापित होने वाले परिवारों के बीच सामाजिक संबंधों को प्रभावित करेगा। । हालाँकि, सुझाए गए बुनियादी ढाँचे के उपायों का यदि योजनाबद्ध तरीके से पालन किया जाता है, तो इन प्रभावों को लगभग नगण्य तक कम कर दिया जाएगा।

इस परियोजना के कार्यान्वयन के माध्यम से आने वाले सकारात्मक प्रभावों के बारे में एक सामान्य आशावाद है जैसे कि रोजगार के अवसरों में वृद्धि, भूमि की कीमत, और छोटे और मध्यम व्यापार उपक्रमों के लिए गुंजाइश बढ़ जाती है। बेहतर सड़क नेटवर्क जिसमें नदी के दोनों किनारों पर बेहतर कनेक्टिविटी, उच्च आवृत्ति और बेहतर गुणवत्ता वाली परिवहन सेवाएं शामिल हैं। ढांचागत सुविधाओं विशेष रूप से सिंचाई, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली और जल निकासी में सुधार होगा और यह क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के HEP मानचित्र में एक मील का पत्थर बन जाएगा।

इसके अलावा, इस परियोजना के कार्यान्वयन से राज्य को अपेक्षित राजस्व लगभग 604 करोड़ प्रति वर्ष है जिससे राज्य का समग्र आर्थिक स्वास्थ्य बढ़ रहा है। इसके अलावा, LADA और CSR जैसे धन की उपलब्धता के कारण, परियोजना क्षेत्र निर्माण और परियोजना के निर्माण के बाद के चरणों के दौरान त्वरित विकास होगा।

संभावित विकल्पों के बीच सर्वोत्तम उपलब्ध वैकल्पिक साइट और परियोजना के डिजाइन के चयन के कारण भूमि अर्जन और अनैच्छिक पुनर्वास को कम से कम किया गया है। वर्तमान प्रस्तावित अर्जन का परियोजना क्षेत्र में PAF और समुदायों पर कम से कम प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

जहां घराने (समुदायों सहित) संपत्ति खो रहे हैं, आजीविका या संसाधनों को पूरी तरह से प्रतिकर और सहायता दी जाएगी ताकि वे अपनी पूर्व आर्थिक और सामाजिक स्थितियों में सुधार कर सकें, या कम से कम बहाल कर सकें।

PAF यानी किसी भी व्यक्ति या घर या व्यवसाय को प्रतिकर, पुनर्वास और पुनर्व्यविस्थापन सहायता प्रदान की जाएगी, जो प्रस्तावित परियोजना कार्यान्वयन के कारण प्रभावित होगी:

- a) जीवन स्तर के बुरी तरह प्रभावित होने पर;
- b) किसी भी घर में अधिकार, पदवी या ब्याज, उपयोग करने का अधिकार, या उपयोग करने का अधिकार, परिसर, कृषि और चरागाह भूमि, वाणिज्यिक संपत्ति, किरायेदारी, या वार्षिक या बारहमासी फसलों और पेड़ों या किसी अन्य निश्चित या चल योग्य सहित कोई भी भूमि अस्थायी या स्थायी रूप से अर्जित की गई या संपत्ति;
- c) आय के अवसर, व्यवसाय, व्यवसाय, कार्य या निवास स्थान या निवास स्थान पर प्रतिकूल रूप से अस्थायी या स्थायी रूप से प्रभावित; या,
- d) पुनर्वास योजना की प्रक्रिया के दौरान पहचानी जा सकने वाली सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों और रिश्तों को या किसी अन्य नुकसान को प्रभावित किया जा सकता है।

खोए हुए परिसंपत्तियों की सूची सहित प्रस्तावित परियोजना प्रभावित क्षेत्रों के भीतर सभी PAF के रहने वाले, काम करने वाले, व्यवसाय करने और / या खेती करने वाले, अपनी खोई हुई संपत्ति (भूमि और गैर-भूमि संपत्ति) और आय और व्यवसायों की बहाली के लिए आनुपातिक रूप से प्रतिकर के हकदार हैं; और उनके पूर्व-परियोजना जीवन स्तर, आय-अर्जन क्षमता और उत्पादन स्तर को सुधारने या कम से कम बनाए रखने के लिए उनकी सहायता के लिए पुनर्वास उपायों के साथ पर्याप्त सहायता प्रदान की जाएगी।

पुनर्वास योजना RTFCTLARR अधिनियम, 2013 और HP RTFCTLARR नियम 2015 और नवीनतम R&R नीति के अनुसार डिजाइन की जाएगी।

सहमत कार्यान्वयन अवधि के भीतर भूमि अर्जन (क्षतिपूर्ति और आय बहाली उपायों सहित) की लागत को कवर करने के लिए परियोजना अधिकारियों द्वारा पर्याप्त बजटीय समर्थन पूरी तरह से प्रतिबद्ध और उपलब्ध कराया जाएगा।

प्रतिकर के प्रावधान और स्थानांतरण के लिए आवश्यक अन्य स्वीकार्य सहायता के पहले विस्थापन नहीं होगा। संपत्ति का अर्जन, प्रतिकर का भुगतान, और परियोजना निर्माण गतिविधियों से पहले PAF की आजीविका पुनर्वास गतिविधियों को फिर से शुरू करना और पूरा करना होगा। आजीविका और आय की बहाली के उपाय भी होने चाहिए, लेकिन इनमें समय लग सकता है, जरूरी नहीं कि निर्माण गतिविधियों से पहले ही पूरा कर लिया जाए।

कहा गया है कि यदि निकाय और राज्य सरकार को PAPs और समुदाय के विभिन्न नुकसानों को कम करने के लिए उचित उपाय करना चाहिए और राज्य के सकारात्मक विकास और हितों को देखते हुए, परियोजना लाभ मोटे तौर पर परियोजना की प्रतिकूल सामाजिक लागत को कम कर देगा ।

7.4.1 अंतिम सिफारिश

उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि परियोजना का लाभ केवल प्रभावित क्षेत्र के लोगों को ही नहीं बल्कि पूरे जिले और राज्य तक बढ़ाया जाएगा। इस पूरे प्रोजेक्ट से पूरे उत्तरी क्षेत्र को लाभ होगा। सुन्नी HEP परियोजना के कार्यान्वयन से परियोजना पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ेगा। हालांकि, यदि प्रस्तावित शमन योजना का पालन किया जाता है, तो यह नकारात्मक प्रभावों को कम करके सामाजिक प्रभावों को कम करने और सकारात्मक प्रभावों को बढ़ाने के लिए सामाजिक प्रभावों को कम करने में मदद करेगा, जिससे प्रतिकूल सामाजिक लागतों की निगरानी होगी।

इसलिए इस परियोजना की वृहद तस्वीर को ध्यान में रखते हुए जो राज्य के विकास के लिए लाभ और योगदान देगा और परिणामस्वरूप पूरे देश में, अध्ययन की सिफारिश है कि सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना (382 मेगावाट) के लिए प्रस्तावित भूमि अर्जन किया जा सकता है, बशर्ते कि सुझाए गए सभी उपाय न्यायिक रूप से पहचाने गए विभिन्न प्रभावों को कम कर दें।

8 सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना

8.1 कमी करने पर दृष्टीकोण

यह सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना (SIMP) RFCTLARR Act, 2013 और HP RTRFCTLARR नियम, 2015 के अनुसार सुन्नी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (382 MW) के नकारात्मक सामाजिक प्रभावों को कम करने व सकारात्मक प्रभावों को बढ़ाने के लिए तैयार की गई है। यह शमन, निगरानी और संस्थागत उपायों का एक सेट होता है जोकि प्रतिकूल सामाजिक प्रभावों को खत्म करने या उन्हें स्वीकार्यस्तर तक कम करने के लिए परियोजना के डिजाइन, निर्माण और परिचालन चरण के दौरान किए जाने चाहिए। SIMP को परियोजना के विभिन्न चरणों के दौरान कार्यान्वित किया जा सकता है जैसे की प्री-कंस्ट्रक्शनस्टेज, कंस्ट्रक्शन स्टेज और ऑपरेशनल स्टेज। परियोजना के विभिन्न चरणों के दौरान सुझाए गए विभिन्न प्रबंधन उपायों का विवरण निम्नलिखित अनुभाग में प्रदान किया गया है।

8.2 समाघात से बचने, कम करने और प्रतिपूर्ति करने के उपाय

8.2.1 सामाजिक उपाय

1. यदि हितधारकों के बीच कोई विवाद है, तो इस विवाद को पहले हल किया जाना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कानूनी मालिक को प्रतिकर दिया जाए।
2. करयाली पंचायत के स्थानीय लोगों की मांग है कि क्योंकि करयाली ग्राम पंचायत में जलाशय का निर्माण किया जा रहा हैइसलिए परियोजना का नाम सुन्नी HEP से बदलकर जैशी-करयाली HEP किया जाए।
3. गांवों में स्थानीय देवताओं के मंदिरों के निर्माण / उन्नयन के लिए धन उपलब्ध कराया जाए।
4. परियोजना क्षेत्र के सभी गांवों और पंचायतों में सामुदायिक हॉल का निर्माण किया जाए।
5. महिला मंडल, युवकमंडल और ग्राम पंचायत कार्यालयों के रूप में उपयोग किए जाने वाले भवन / संरचनाओं का निर्माण, मरम्मत और उन्नयन किया जाए।
6. महिलाओं और पिछड़े वर्ग श्रेणियों जैसे सीमांत वर्गों केपारंपरिक कौशल को बढ़ावा देकर व नए कौशल में विकसित करके उनके उत्थान के लिए प्रयास किए जाने चाहिए।
7. परियोजना प्रभावित व्यक्तियों और परिवारों ने बाजार मूल्य से प्रतिकर की गणना से पहले दरों के अद्यतन के लिए अनुरोध किया है। इसके इलावा अपने परिवार के सदस्यों के लिए नौकरी की मांग भी की है ।

8. परियोजना के चालू होने के बाद PAFs को विशेष सब्सिडी टैरिफ दरों के साथ प्रदान किया जा सकता है या प्रति माह में कुछ मुफ्त इकाइयां प्रदान की जा सकती हैं, या दोनों प्रदान की जा सकती हैं ।
9. **स्ट्रीट लाइटिंग-** लगभग सभी पंचायतों और गांवों को स्ट्रीटलाइट्स प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।
10. **खेल को बढ़ावा-** शारीरिक फिटनेस और खेल को बढ़ावा देने के लिए, खेल में लगे युवाओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। आवश्यक निकाय प्रभावित पंचायतों में खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा सकता है और स्थानीय खेल युवा क्लबों को खेल किट प्रदान / कर सकते हैं। होनहार एथलीटों को आगे चलकर परियोजना में रोजगार के अवसर प्रदान भी किए जा सकते हैं।
11. जिला प्रशासन और सम्बंधित विभागों के साथ जुड़कर खेल परिसर को भी विकसित किया जा सकता है, जो उज्ज्वल एथलीटों को बढ़ावा देगा और स्थानीय लोगों के लिए भी रोजगार पैदा कर सकता है।

8.2.2 आधारिक संरचनाओं के उपाय

1. **सर्व मौसम सड़कें** - SIA टीम के अवलोकन व ग्रामीणों की मांग के अनुसार सारे प्रोजेक्ट एरिया की सारी ग्राम पंचायतों की सभी ग्रामीण सड़कों और लिंक सड़कों को सर्व मौसम पक्की सड़कों में उन्नत किया जा सकता है जिससे क्षेत्र में बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जा सके अतः जिसका सीधा प्रभाव क्षेत्र के विकास पर होगा। इनमे से कुछ विशेष सुझाव निम्न दिए गए हैं।
 - खैरा से ओगली (चेबड़ी पंचायत) तक पक्की सड़क।
 - खैरा से शील (चेबड़ी पंचायत) तक पक्की सड़क।
 - पंचायत भवन से सेरकड़ी (चेबड़ी पंचायत) तक पक्की सड़क।
 - खैरा से रोपा (चेबड़ी पंचायत) तक पक्की सड़क।
 - खैरा से मुर्दा घाट (चेबड़ी पंचायत) तक पक्की सड़क।
 - झुँझन से लम्बिधर (मोगरा पंचायत) तक 6 की.मी. पक्की सड़क का निर्माण।
 - झुँझन से मोगरा (मोगरा पंचायत) तक 8 की.मी. पक्की सड़क का निर्माण।
 - पराकड़ा से कुन्दाधर (मोगरा पंचायत) तक 5 की.मी. पक्की सड़क का निर्माण।
 - मुख्य रोड से कोठी, मालगी, धरु, और तुलाह (ओगली पंचायत) तक लिंक रोड का निर्माण।

2. **पुल** - परियोजना प्रभावित क्षेत्र के निवासियों के साथ विचार-विमर्श करने से पता चला की इस परियोजना से पुल व नदी पार करने का लिए रस्से के मार्गों का नुकसान होगा। प्रभावित परिवारों ने बताया की इन पुलों व नदी पार करने का लिए रस्से के मार्गों का काफी सामाजिक मूल्य है और वह इन्ही के द्वारा अपने नदी पार रिश्तेदारों से संपर्क में रहते है। वह सड़क व परिवहन सेवाओं का लाभ उठाते हुए बड़े आराम से दोनों किनारों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग ले सकते है।

इसके इलावा ग्रामीणों को यह कनेक्शन चारा, आग की लकड़ियाँ व जंगली वन उपज एकत्रित करने में भी उपयोगिक होता है।

निम्न पुल सुझावित किये जा रहे है।

- झुँझन से सुकेत (मंडी) (मोगरा पंचायत) में पुल का निर्माण।
- पुल से बिन्दला पंचायत को संपर्क।
- क्योंकि ओगली पंचायत का प्रस्तुत रस्से का मार्ग जोकि अधिग्रहण में आ रहा है, ग्रामीणों द्वारा नदी पार करने के उपयोग में आता है, वहां वैकल्पिक तौर पे पुल का निर्माण किया जा सकता है ।

अतः प्रभावित पंचायतों/गावों में इन सामाजिक संबंधों व अभिगम्यताओं को बहाल करने हेतु सारे वैकल्प व उपयुक्त व्यवस्थाएं की जानी चाहिए ।

3. परियोजना क्षेत्र की सभी पंचायतों में जल निकासी की उचित सुविधा का निर्माण किया जाना चाहिए।
4. परियोजना क्षेत्र की सभी पंचायतों में लिफ्ट सिंचाई सुविधा प्रदान की जानी चाहिए।
5. करयाली ग्राम पंचायत ने परियोजना कलोनी का निर्माण जैशी व बरारा गाँव में किये जाने का अनुरोध किया है ।
6. **पेयजल आपूर्ति** - ग्रामीणों के साथ चर्चा से और FGD के दौरान अवलोकन से, यह पाया गया कि ग्रामीण लोग बावडियों और प्राकृतिक झरनों / एक्विफर पानी को पीने के पानी के रूप में उपयोग कर रहे हैं या नदी या आसपास के नाले से पानी पंप करने के लिए कुछ व्यवस्था की है। इन प्राकृतिक जल संसाधनों में से कई प्रस्तावित परियोजना के अनुसार जलमग्न / समाप्त हो जाएंगे इसलिए, परियोजना की गति विधियों को शुरू करने से पहले, ग्रामीणों को पेयजल आपूर्ति के लिए वैकल्पिक स्रोत / प्रणाली प्रदान की जानी चाहिए।

इसी तरह, ओगली पंचायत में नदी तट के करीब एक सरकारी पानी पंपिंग स्टेशन है, जोभी डूब जाएगा। इसलिए यह जरूरी होजाता है कि सभी प्रभावित गांवों में सुरक्षित पेयजल की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए परियोजना के निर्माण चरण से पहले सभी आवश्यक प्रबंध किए जाएं।

परियोजना क्षेत्र के सभी पंचायतों ने सर्वसम्मति से परियोजना क्षेत्र के सभी गांवों में स्वच्छ पेयजल सुविधा प्रदान करने की मांग की है।

7. **चिकित्सा सुविधाएँ** - प्रभावित क्षेत्र के ग्रामीणों के साथ चर्चा के अनुसार, विभिन्न स्तरों पर कुछ सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं / केंद्रस्थापित हैं, लेकिन दीजाने वाली सेवाएँ अपर्याप्त हैं और दूरियां बहुत बड़ी हैं।

मोगरा पंचायत में, परियोजना प्रभावित गाँव मजरोग और झुँझन मुख्य पंचायत से 50 किमी की दूरी पर पिछड़े गाँव हैं। यहां के ग्रामीणों ने उन्हें दोनों गांवों को सुन्नी से जोड़ने के लिए एक उन्नत स्वास्थ्य क्लिनिक, एक एम्बुलेंस सड़क और एक समर्पित टोल-फ्री एम्बुलेंस सेवा प्रदान करने की मांगकी है। इसीतरह, सभी पंचायतों में अपर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में शिकायतें हैं और उन्होंने परियोजना क्षेत्र के सभी गांवों में स्वास्थ्य सुविधाओं को उन्नत करने का अनुरोध किया है।

इसलिए, पर्याप्त चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिए मौजूदा सरकारी सुविधाओं को उन्नत किया जाना चाहिए। अर्जन करने वाली संस्था एक सुविधाजनक स्थान पर त्रितय स्तरीय स्वास्थ्य सुविधा खोल सकता है जो प्रभावित गांवों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ हो और प्रभावित क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए सुसज्जित हो । आवश्यक परीक्षण उपकरण और रेफरल प्रणाली के साथ निश्चित दिनों पर यात्रा करने के लिए निर्धारित क्षेत्र में एक मोबाइल मेडिकल वैन भी शुरू की जासकती है। इसके अलावा, टोलफ्री नंबर (जैसे एन.एच.एम की 108 सेवा) के साथ एक एम्बुलेंस सेवा शुरू की जास कती है।

8. **स्कूल और छात्रवृत्ति** - प्रभावित क्षेत्र में बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए, स्कूल भी शुरू किए जा सकते हैं जहाँ प्रभावित परिवारों के बच्चों को प्रवेश के दौरान पहली प्राथमिकता मिल सकती है। प्रभावित परिवारों के बच्चों को फीस रियायत के लिए भी माना जासकता है। आवश्यक निकाय परीक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को छात्र वृत्ति भी प्रदान किया जा सकता है।

आवश्यक निकाय उच्चशिक्षा / व्यावसायिक ट्रेडों जैसे इंजीनियरिंग, चिकित्सा, कानून और सीए / सीएस आदि के लिए चयन करने वाले छात्रों की मदद कर सकते हैं, जिसके लिए वे छात्र की फीस / आवास लागत का प्रतिशत साझाकर सकते हैं और बाद में उन्हें उनके कौशल के अनुसार संगठन

में अवशोषित कर सकते हैं। यह अर्जन करने वाली संस्था के लिए एक दीर्घ कालिक निवेश के साथ-साथ प्रभावित परिवारों के लिए एक बड़ी मदद साबित होसकता है जो अपने बच्चों की उच्चशिक्षा के लिए प्रयास कर रहे हैं।

चूंकि अर्जित निकाय पीएसयू है, इसलिए आधिकारिक तौर पर शिक्षा विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन होसकता है।

9. **तकनिकी संस्थान-** क्षेत्र में तकनिकी संस्थानों को स्थापित किया जा सकता है व मौजूदा तकनिकी संस्थानों के साथ सहयोग में खाद्य संरक्षण व प्रसंस्करण असैनिक निर्माण, व मरम्मत अथवा विद्युत् क्षेत्र से सम्बंधित पाठ्यक्रम भीशुरु करवाए जा सकते हैं। इन पाठ्यक्रम को अंतिम रूप देने से पहले क्षेत्र की भविष्य की जरूरतों व परियोजना प्रभावित परिवारों के साधन व रुचि को समझने के लिए एक स्वतंत्र सर्वेक्षण किया जाना चाहिए।
10. **शमशान घाट** - पहाड़ी इलाकों में शमशान घाट जादातर नदी किनारे स्थित होते हैं । परियोजना प्रभावित क्षेत्र की जादातर पंचायतों में भी परियोजना की वजह से शमशान घाटप्रभावित हो रहे हैं । अतः प्रभावित पंचायतों के निवासियों से परामर्श करने क पश्चात् विद्युत्/अन्य शवदाह गृह का निर्माण किया जा सकता है।

8.2.3 पुनर्वास व पुनार्व्यवस्थापन के उपाय

1. विस्थापित हुए PAF और भूमि हारे हुए लोगों के लिए भी जो अर्जित भूमि के प्रतिकर के रूप में भूमि का चयन करते हैं, अर्जित निकाय को उसी ग्राम पंचायत या पड़ोसी ग्राम पंचायत में अधिमानतः भूमि प्रदान करनी चाहिए।
2. PAF जिनके घरों का अर्जन किया जा रहा है, उन्हें उचित प्रतिकर दिया जाए और अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत पुनर्वास के कारण होने वाली असुविधा के लिए अतिरिक्त प्रतिकर दिया जाए।
3. **बागवानी और औषधि पौधों का संवर्धन:** परियोजना क्षेत्र की कृषि-जलवायु परिस्थितियाँ उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय फलों के लिए काफी उपयुक्त हैं। अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर सेब, चेरी, प्लम, खुबानी और निचले क्षेत्र आम, लीची, अमरूद और खट्टे फल पैदा करते हैं। क्षेत्र में कागजी नींबू, किन्नु और नारंगी जैसे खट्टे फलों का प्रचार किया जा सकता है। संयंत्र सुरक्षा, संगरोध और भंडारण केंद्र भी प्रभावित क्षेत्र में स्थापित किए जाने चाहिए। अर्जन करने वाली संस्था विभाग के समर्थन से क्षेत्र में हर्बल पौधों को भी बढ़ावा दिया जा सकता है ।

4. **पर्यटन को बढ़ावा देना** यदि प्रशासन द्वारा पर्याप्त ध्यान दिया जाता है ;, तो यह क्षेत्र एक पर्यटन स्थल के साथ साथ, पानी से संबंधित गतिविधियोंखेलोके लिए केंद्र के रूप में विकसित हो सकता है। पीपीपी मोड में रिवर साइड कैंप और राफ्टिंग को बढ़ावा दिया जा सकता है जो प्रभावित परिवारों के लिए नियमित आय उत्पन्न कर सकता है।
5. **मत्स्य पालन** को बढ़ावा देना यह परियोजना मत्स्य पालन के विकास के लिए : प्राकृतिक परिस्थितियाँ प्रदान करेगी। प्रभावित क्षेत्र के इच्छुक व्यक्तियों को मछली पालन में प्रशिक्षण दिया जा सकता है। संबंधित विभाग से मछली पकड़ने का लाइसेंस प्राप्त करने में इच्छुक लोगों और मछुआरों का परिवारों से) प्रभावित समर्थन किया जा सकता है।)
6. **पशुपालन प्रभावित आबादी के एक बड़े हिस्से के लिए कृषि के** : साथ में पशुपालक मुख्य धन है और हर घर में गायों या भैंसों, भेड़, बकरियों, हैं। पशुपालन, जो कि छोटे और सीमांत किसानों की आय बढ़ाने में सहायक है, का व्यवसायीकरण किया जा सकता है। एक दूध सहकारी क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा सकता है जिससे न केवल परियोजना प्रभावित परिवारों को बल्कि पूरे क्षेत्र को लाभ होगा।
7. **स्वयं सहायता समूह का गठन व सशक्तिकरण** : महिलाओं को एक साथ आने औरस्वयं सहायता समूह बनाने और मौजूदा लोगों को समुचित प्रशिक्षण के साथ मजबूत बनाने और पंजीकृत SHG को दिए गए बैंक ऋण के माध्यम से अपनी आजीविका कमाने के लिए अवसर प्रदान करना चाहिए। हस्तकला, डायरी, शॉल बनाना, सिलाई और कढ़ाई आदि पेश की जा सकती है।
8. **आय बहाली के लिए संस्थागत संपर्क और कौशल उन्नयन**: यह देखा गया कि आय बहाली के लिए पात्र परिवारों में से कुछ बागवानी, क्षुद्र व्यवसायों और पशुधन के माध्यम से अपनी आजीविका कमा रहे थे। अर्जन करने वाली संस्था कुछ व्यावसायिक कौशल प् /रशिक्षण के अवसर प्राप्त करने के लिए स्वयं सहायता समूहों)SHG को व्यवस्थित करने के लिए प्रभावित परिवार के सदस्यों (को जुटाने के लिए सक्रिय भूमिका निभा सकती है और विपणन और ऋण सुविधाओं के अलावा कच्चे माल, इनपुट के लिए अग्रामी व अधोगामी संपर्क स्थापित करने में भी सहायता कर सकता है। संस्थागत वित्तपोषण और विपणन में जिला प्रशासन और अन्य हितधारक ऐसी गतिविधियों को करने के लिए सूक्ष्म योजनाएँ तैयार करें। वैकल्पिक आजीविका योजनाओं के निर्माण के मामले में, लक्ष्य आबादी की आवश्यकताओं का अध्ययन किया जाए और भागीदारी तरीके से प्राथमिकता दी जाए। राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न गरीबी उन्मूलन और आय सृजन योजनाएं। और GOI को प्रभावित आबादी को आय बहाली के विकल्प प्रदान करने के लिए अभिसरण किया जाए।

9. **परियोजना आधारित रोजगार** परियोजना से संबंधित रोजगार के अवसर जैसे कि परियोजना : निर्माण, रखरखाव, आपूर्ति और परिवहन ठेकेदारों के तहत काम भी प्रभावित आबादी के लिए खुले हों।
10. नुकसान हुई फसलों व् बागवानी गतिविधियां जिनमे फलदार व् गैर फलदार पेड़ भी आते है, उनका उचित रूप से प्रतिकार दिया जाना चाहिए।
11. अधिग्रहण करने वाली संस्था लोगों के कौशल उन्नयन के लिए कौशल विकास कार्यक्रम भी चला सकती है जिससे उन्हें परियोजना में बेहतर रोजगार के मौके मिल सके।
12. परियोजना परिचालन व् अन्य चरणों के दौरान निर्माण, स्प्ललाई व् यातायात के छोटे ठेकों में महत्व PAPs, PAFs प्रभावित ग्राम पंचायतों के लोकल लोगो को दिया जाना चाहिए।

8.2.4 पर्यावरण उपाय

I) **वनीकरण** क्षेत्र में प्रस्तावित भूमि-अर्जन के कारण वन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। पारिस्थितिक तंत्र को बहाल करने और पारिस्थितिक नुकसान को कम करने के लिए, सरकारी भूमि में वनीकरण किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में वन विभाग, निकाय और समुदाय को शामिल करना चाहिए। ये प्रयास न केवल नुकसान को बहाल करने में मदद करेंगे बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी प्रदान करेंगे।

इसके अलावा, निजी भूमि में मिट्टी के कटाव की जांच के लिए अतिसंवेदनशील क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। यह मिट्टी की उर्वरता की हानि की जांच करेगा और संबद्ध जोखिमों को कम करेगा। इसके अलावा, नदी के किनारे वृक्षारोपण जल स्तर में वृद्धि और मानसून के दौरान भूस्खलन के खतरे को प्रभावी रूप से कम करेगा।

II) शोर प्रदूषण और वाहन यातायात

- a) शोर प्रदूषण और यातायात को कम से कम किया जा सकता है:
- b) भारी परिवहन वाहनों के प्रवेश के लिए दिन के विशिष्ट घंटे को परिभाषित करना।
- c) एक दिन में परियोजना स्थल में प्रवेश करने / छोड़ने वाले भारी वाहनों की संख्या को विनियमित करना।
- d) हॉर्न के उपयोग को कम करने के लिए ड्राइवरों को सख्त निर्देश।

- e) परिवहन वाहनों पर दबाव हॉर्न पर पूर्ण प्रतिबंध।
- f) सड़कों और यातायात स्थितियों पर अनावश्यक अधिभार से बचने के लिए पूरे दिन समान रूप से परिवहन वाहनों के समय को नियोजित करना ।
- g) भारी वाहनों के चालकों को, छोटे वाहनों को प्राथमिकता देने और गति सीमा का पालन करने के लिए नियमित ओवरटेक करने के लिए सख्त निर्देश देना

III) वायु प्रदूषण

परिवहन, निर्माण, उत्खनन, खनन और डंपिंग के दौरान धूल के कारण उत्पन्न होने वाले वायु प्रदूषण को निर्माण स्थल, परिवहन वाहनों जैसे ट्रकों, टिपरों आदि के खनन और डंपिंग साइटों को ढकने से कम किया जा सकता है। साथ ही, परियोजना क्षेत्र में पूरे दिन नियमित पानी का छिड़काव भी वायु प्रदूषण को कम करने में मदद करेगा।

चेबरी पंचायत के ग्रामीणों ने डंपिंग साइट को गांव से दूर स्थानांतरित करने का अनुरोध किया है क्योंकि वे वायु प्रदूषण से चिंतित हैं कि उन्हें इसका सामना करना पड़ेगा।

V) जल प्रदूषण, जल जनित रोग और बढ़ी हुई आर्द्रता।

1. जल प्रदूषण को सख्ती से आश्वासन देकर कम किया जा सकता है कि खुदाई और खनन के दौरान नदी में न्यूनतम डंपिंग होती है।
2. डंपिंग साइट को नदी के किनारों से दूर बनाया जाना चाहिए ताकि बारिश और मॉनसून के दौरान विशेष रूप से नदी में प्रवेश करने से बचें।
3. निर्माण सामग्री की भंडारण इकाइयों को विशेष रूप से रेत और कुल मिलाकर नदी के किनारे से दूर रखना चाहिए।
4. जलाशय के निर्माण के बाद विशेष रूप से खड़े पानी को जल जनित बीमारियों से बचने के लिए नियमित रूप से छिड़काव किया जाना चाहिए।
5. जलाशय के कारण आर्द्रता में वृद्धि हुई है जो कि वनीकरण द्वारा कम से कम हो सकती है। हालांकि विदेशी सजावटी पेड़ों के बजाय पेड़ पौधों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। इसके अलावा, केवल उन किस्मों के पेड़ों को लगाया जाना चाहिए जो नमी को कम करते हैं और परिवेश को अपेक्षाकृत ठंडा रखने में मदद करते हैं।

V) जल स्तर में वृद्धि के कारण भूमि स्लाइड का जोखिम

सक्षम अधिकारी नदी के बहाव की जांच करने और नदी में पानी के स्तर में वृद्धि के कारण भूस्खलन के जोखिम को कम करने के लिए कमजोर स्थानों पर तटबंध की दीवारों रिटेनिंग दीवारों आदि का निर्माण / सुनिश्चित कर सकते हैं।

ड्रेनेज सिस्टम प्रभावित गाँवों में उचित ड्रेनेज सिस्टम विकसित करने की आवश्यकता है। दिए गए - इलाकों की स्थितियों मेसड़कों के साथ जल निकासी पाइप की व्यवहार्यता का पता लगाया जाना चाहिए।

8.2.5 अन्य उपाय

1. परियोजना प्रभावित लोगों को प्रतिकर निश्चित समय सीमा में दिया जाना चाहिए।
2. परियोजना प्रभावित लोगों को प्रतिकर मुआवज़े का उत्पादक उपयोग व सुरक्षित निवेश क लिए तकनीकी व वित्तीय सलाह दी जानी चाहिए।
3. PAPs व PAFs जिन्होंने चरणबंध प्रतिकर को चुनना है उनके लिए प्रतिकर का वितरण करने क लिए उचित चरणबंध योजना की युक्ति की जानी चाहिए।

4. स्थानीय क्षेत्र विकास निधि

LADF योगदान परियोजना की निर्माण अवधि के दौरान परियोजना लागत का 1.5% है। तत्पश्चात LADF द्वारा परियोजना के जीवन पर निरंतर और निरंतर आधार पर आय सृजन और कल्याणकारी योजनाओं की एक नियमित धारा प्रदान करने के लिए 1% निर्धारित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश सरकार भी अपने 12% शेयर में से 1% का भाग योजना/ बजट प्रावधान में से LADF को प्रदान करेगी। यह प्रावधान PAFs के साथ विस्तार में चर्चित किये जाने चाहिए और इसीलिए स्थानीय क्षेत्र विकास कमिटी (LADC) बनाई जानी चाहिए जिसमे विभिन्न हितधारक जैसे सरकारी विभाग, परियोजना प्रभावित परिवारों के सदस्य और अपेक्षित निकाय के अधिकारी हो ।

5. **सर्किल दरों में संशोधन:** कई PAPs और PAF को लगता है कि उनकी भूमि के मौजूदा सर्कल रेट बहुत कम हैं। इसलिए उन्होंने सर्कल दरों को संशोधित करने और बढ़ाने का अनुरोध किया है। यह मंडी जिला में पड़ने वाले गांवों और मोगरा पंचायत में पड़ने वाले गांवों के साथ एक बड़ी चिंता है। 20 गांवों में से 12 के लिए लागू सर्कल रेट 250 रुपये से 800 रुपये प्रति वर्ग मीटर के बीच में आते हैं। खेती योग्य भूमि के लिए और गैर-खेती योग्य भूमि के लिए 250 रु 550 रु। शेष 6 गांवों में खेती योग्य भूमि के लिए 1011 रुपये और गैर-खेती योग्य भूमि के लिए 842 रुपये की सर्कल दरें हैं।

संबंधित अधिकारी इस मुद्दे को देख सकते हैं और संबंधित कानूनों के अनुसार पंचायतों के सर्कल दरों को उचित रूप से संशोधित कर सकते हैं।

6. **जागरूकता और वित्तीय साक्षरता शिविर-** स्वस्थ, स्वच्छता, पोषण, सामाजिक अधिकार इत्यादि से सम्बंधित जागरूकता कार्यक्रमों का क्षेत्र में बार बार आयोजन किया जाना चाहिए। यह प्रभावित ग्रामीणों को सामाजिक परिवर्तनों का सामना करने में मदद करेगा जोकि बड़े पैमाने में आई जनसंख्या में वृद्धि व स्वास्थ्य सम्बंधित पैटर्न में प्रत्यक्ष परिवर्तन का सामना करेंगे ।

इसके अलावा ग्रामीणों को सुरक्षित निवेश, निवेश योजनाओं, धन प्रबंधन इत्यादि के बारे में शिक्षित करने के लिए खास वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन किया जाना चाहिए क्योंकि इनमें से बहुत लोगों को भरी मात्रा में प्रतिकर प्राप्त होगा।

कई भूमि अर्जन परियोजनाओं में यह देखा गया है कि जब भी परिवारों को भारी मात्रा में धन दिया जाता है, उस धन का उपयोग परिवार के सदस्यों द्वारा न्यायिक रूप से उपयोग नहीं किया जाता है और आम तौर पर विलासिता और अनावश्यक वस्तुओं पर खर्च किया जाता है और व्यक्ति / परिवारों के खर्च करने के तरीके और जीवन शैली को भी बदलता है। कभी-कभी, इससे समाज में प्रचलित पारंपरिक और सांस्कृतिक प्रथाओं का नुकसान भी होता है। कई परिवारों को समग्र रूप से वित्तीय प्रबंधन के बारे में पता नहीं है, इसलिए यहां चिंता है कि प्रतिकर के पैसे लंबे समय तक नहीं रहेंगे और अंततः परिवारों के साथ-साथ समाज को भी लंबे समय में प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेंगे।

इसके अलावा, अशिक्षित ग्रामीणों और दुर्बल समूहों के साथ धोखाधड़ी और धोखाधड़ी के कई मामले हैं, जब उन्हें प्रतिकर मिला है।

इसलिए, आवश्यक निकाय विशेष बाहरी एजेंसी की सहायता से प्रभावित परियोजना क्षेत्र में वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित कर सकते हैं।

8.3 R&R और अधिनियम 2013 में शामिल उपाय

यह एस आई ए रिपोर्ट भूमि अर्जन प्रक्रिया को करने के लिए आवश्यक निकाय के लिए और सार्वजनिक परामर्श और सर्वेक्षण के दौरान परियोजना प्रभावित परिवारों और अन्य हितधारकों द्वारा बताई गई आकांक्षा

के अनुसार कार्ययोजना तैयार करने के लिए फायदेमंद होगी। अध्ययन के निष्कर्षों के प्रकाश में, अपेक्षित सामाजिक प्रभावों के शमन के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं।

तालिका 8-2: पहचाने गए और संबंधित शमन उपाय

क्र० सं	प्रभाव	सुझाव/ शमन उपाय
1	निजी भूमि का नुकसान (53.19 हेक्टेयर)	RTFCTLARR अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार शीर्षक धारकों और हितधारकों को उचित प्रतिकर
2	निजी संपत्तियों के नुकसान के कारण अर्जन जैसे आवासीय और वाणिज्यिक संरचनाएं, सीमा की दीवारें, फसलें, फल असर और गैर-फल वाले पेड़। प्राप्त की जा रही निजी संपत्तियों की सूची तालिका 4.2 और 4.3 में उल्लिखित है	RTFCTLARR अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार मालिकों और हितधारकों को उचित प्रतिकर
	सर्किल दरों का संशोधन	जिला कलेक्टर व अपेक्षित निकाय के फैसले के अनुसार
3	विस्थापित परिवारों और व्यक्तियों के लिए अर्जन के कारण असुविधा	नए स्थान के निर्माण और नए घरों के निर्माण के लिए RTFCTLARR अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार मालिकों और हितधारकों को उचित प्रतिकर
4	भूमि पर निर्भर रोजगार / आय / आजीविका का नुकसान।	RTFCTLARR अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार व्यक्तियों को उचित प्रतिकर। 2) अर्जित निकाय परियोजना के निर्माण और निर्माण के बाद के चरण में इन व्यक्तियों का रोजगार सुनिश्चित कर सकता है जो उनके कौशल सेट, योग्यता, आयु और मौजूदा आय पर निर्भर करता है। 3) अर्जन करने वाला निकाय परियोजना में बेहतर रोजगार के अवसर प्राप्त करने में सक्षम होने के लिए इन व्यक्तियों के कौशल उन्नयन के लिए कौशल विकास कार्यक्रम भी चला सकता है।

क्र० सं	प्रभाव	सुझाव/ शमन उपाय
		4) इस परियोजना के परिचालन और अन्य चरणों के दौरान PAP और पफ को और प्रभावित ग्राम पंचायतों के स्थानीय लोगों को निर्माण, आपूर्ति और परिवहन में छोटे अनुबंधों को देने के लिए प्राथमिकता दीजानी चाहिए।
5	सामुदायिक आस्तियों का नुकसान जैसे कि घाट, श्मशान घाट, बावड़ी, रिवर क्रॉसिंग रोपवे, मंदिर आदि।	प्रभावित होने वाले सभी सांस्कृतिक और सामुदायिक आस्तियों को या तो स्थानांतरित किया जाना चाहिए या निर्माण शुरू होने से पहले संबंधित समुदाय की पूर्व सहमति के साथ एक समान / उन्नत विकल्प के साथ प्रदान किया जाना चाहिए।
6	आम संसाधनों की हानि जैसे जल संसाधन जिसमें पेयजल संसाधन जैसे स्प्रिंग्स / और बावड़ियां शामिल हैं। चरागाहों / चरागाहों की हानि, जलाऊ लकड़ी के संग्रहण के लिए जंगल।	प्रभावित होने वाली सभी सामान्य संपत्तियों को निर्माण शुरू करने से पहले संबंधित समुदाय की पूर्व सहमति के साथ एक समान / उन्नत विकल्प के साथ प्रदान किया जाना चाहिए।
7	दुर्बल समूहों पर प्रभाव: सर्वेक्षण से पता चलता है कि 33% महिलाएं HH, 21 तलाक, 192 विधवा, 42 शारीरिक रूप से अक्षम PAP हैं।	1) RTFCTLARR अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार व्यक्तियों को उचित प्रतिकर प्रदान करें। 2) इसके अलावा, उन्हें विशेष सहायता प्रदान की जा सकती है जैसे कौशल विकास और आय की बहाली के संदर्भ में अतिरिक्त सहायता प्रदान करने के लिए प्रत्येक कमजोर परिवार से कम से कम एक सदस्य। 3) अधिकारी यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि प्रतिकर का संबंधित हिस्सा कमजोर व्यक्तियों को सीधे हस्तांतरित किया जाए ताकि धोखाधड़ी और धोखाधड़ी की संभावना से बचा जा सके।

क्र० सं	प्रभाव	सुझाव/ शमन उपाय
8	खाद्य सुरक्षा और पशुपालन पर प्रभाव: खेती योग्य भूमि और चरागाह के नुकसान से कृषि और पशुपालन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।	<p>कृषि विभाग को सलाह दी जाती है कि वह प्रभावित परिवारों को बची हुई भूमि या वैकल्पिक भूमि में गहन खेती करने में मदद करे।</p> <p>इसी तरह, उन्हें पशुपालन प्रथाओं को चलाने के लिए सहायता और बढ़ावा दिया जाना चाहिए</p>
9	शोर प्रदूषण और वाहनों का आवागमन	<p>1) स्थानीय लोगों के परामर्श से स्वीकार्य सीमा के भीतर शोर, यातायात, धूल के बढ़े हुए स्तर को कम करने के लिए एक प्रबंधन योजना का विकास और कार्यान्वयन,</p> <p>2) ध्वनि प्रदूषण और यातायात को कम से कम किया जा सकता है:</p> <p>a) भारी परिवहन वाहनों के प्रवेश के लिए दिन के विशिष्ट घंटों को परिभाषित करना।</p> <p>b) एक दिन में परियोजना स्थल में प्रवेश / छोड़ने वाले भारी वाहनों की संख्या को विनियमित करना।</p> <p>c) सींगों के उपयोग को कम करने के लिए ड्राइवर्स को सख्त निर्देश।</p> <p>d) परिवहन वाहनों पर दबाव सींगों पर पूर्ण प्रतिबंध।</p> <p>e) सड़कों और यातायात स्थितियों पर अनावश्यक अधिभार से बचने के लिए पूरे दिन समान रूप से परिवहन वाहनों के समय को डगमगाते हुए।</p> <p>f) भारी वाहनों के चालकों को सख्त निर्देश देने के लिए छोटे वाहनों को प्राथमिकता देने और गति सीमा का पालन करने के लिए नियमित ओवरटेक करना।</p>

क्र० सं	प्रभाव	सुझाव/ शमन उपाय
10	वायु प्रदूषण	3) परिवहन, निर्माण, उत्खनन, खनन और डंपिंग के दौरान धूल के कारण उत्पन्न होने वाले वायु प्रदूषण को निर्माण स्थल, ट्रकों जैसे परिवहन वाहनों, टिपरों आदि के खनन और डंपिंग स्थलों को स्नेहपूर्वक कम किया जा सकता है। साथ ही, परियोजना क्षेत्र में पूरे दिन नियमित पानी का छिड़काव भी वायु प्रदूषण को कम करने में मदद करेगा।
11	जल प्रदूषण, जल जनित रोग और बढ़ी हुई आर्द्रता।	1) जल प्रदूषण को सख्ती से आश्वासन देकर कम किया जा सकता है कि खुदाई और खनन के दौरान नदी में न्यूनतम डंपिंग होती है। 2) डंपिंग साइट को नदी के किनारों से दूर बनाया जाना चाहिए ताकि बारिश और मॉनसून के दौरान विशेष रूप से नदी में प्रवेश करने से बचें। 3) निर्माण सामग्री की भंडारण इकाइयों को विशेष रूप से रेत और कुल मिलाकर नदी के किनारे से दूर रखना चाहिए। 4) जलाशय के निर्माण के बाद विशेष रूप से खड़े पानी को जल जनित बीमारियों से बचने के लिए नियमित रूप से छिड़काव किया जाना चाहिए। 5) जलाशय के कारण आर्द्रता में वृद्धि हुई है जो कि वनीकरण द्वारा कम से कम हो सकती है।
12	जल स्तर में वृद्धि के कारण भूमि स्लाइड का जोखिम	सक्षम अधिकारी नदी के पाठ्यक्रम की जांच करने और नदी में पानी के स्तर में वृद्धि के कारण भूस्खलन के जोखिम को कम करने के लिए कमजोर स्थानों पर तटबंध की दीवारों /

सुन्नी बांध जल विद्युत् परियोजना (382 MW) के लीये की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

क्र० सं	प्रभाव	सुझाव/ शमन उपाय
		रिटेनिंग दीवारों आदि का निर्माण सुनिश्चित कर सकते हैं। 2) नदी के किनारों पर वृक्षारोपण और वृक्षारोपण, विशेष रूप से कमजोर और अतिसंवेदनशील स्थलों पर भी भूस्खलन के खतरे को कम करेगा।

*स्रोत: टीम SIA

8.4 SIMP कार्यान्वयन का व्यय

परियोजना प्रभावित के लिए लागू कानूनी प्रावधानों की पृष्ठभूमि में पात्रता ढांचे और पुनर्वास और पुनर्वास की प्रक्रिया नीचे दी गई है।

भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों, नियमों और नीतियों के अनुपालन में एक एंटाइटेलमेंट मैट्रिक्स विकसित किया गया है। एंटाइटेलमेंट मैट्रिक्स नुकसान और संबंधित प्रकृति और एंटाइटेलमेंट के दायरे के प्रकार को सारांशित करता है।

तालिका 8-3: एंटाइटेलमेंट मैट्रिक्स

क्र.सं.	प्रभाव श्रेणी	हक की इकाई	पात्रता का विवरण	टिप्पणी
भू मालिकों के परिसम्पत्ती का नुकसान-				
	निजी भूमि	भूमि मालिक / शीर्षकधारी	बाजार मूल्य पर भूमि के) लिए नकदप्रतिकर, जिसे RFCTLARR अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा खोए हुए परिसंपत्तियों के प्रतिस्थापन के लिएप्रतिकर की राशि पर वर्तमान स्टांप शुल्क के बराबर राशि।	

सुन्नी बांध जल विद्युत् परियोजना (382 MW) के लीये की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

क्र.सं.	प्रभाव श्रेणी	हक की इकाई	पात्रता का विवरण	टिप्पणी
			<p>प्रशिक्षण सहायता</p> <p>गबारहमासी और गैर- (बारहमासी फसलों और पेड़ों के नुकसान की भरपाई बागवानी और कृषि विभागके प्रावधानों के अनुसार लागू की जाएगी।</p> <p>d) 25,000 रुपये का अनुदान पशु शेड या अल्प दुकानों का प्रतिस्थापन।</p>	
	<p>संरचना का नुकसान आवासीय वाणिज्यिक आवासीय-सह- (वाणिज्यिक</p>	<p>भूमि मालिक / शीर्षकधारी</p>	<p>क स्वीकार्य मानदंडों के (अनुसार वर्तमान दरों के आधार परनिर्धारित नकद प्रतिकर (बी रुपये का स्थानांतरण (भत्ता के प्रावधानों के अनुसार 50000 RFCTLARR अधिनियम, 2013 के लिए विस्थापित परिवार</p> <p>(c) RFCTLARR अधिनियम 2013 के अनुसार मुक्त घर का प्रावधान पूरी तरह से विस्थापित आवासीय / वाणिज्यिक या इसके बदले में घर की समान लागत की पेशकश की जा सकती है घर का निर्माण किया</p>	

सुन्नी बांध जल विद्युत् परियोजना (382 MW) के लीये की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

क्र.सं.	प्रभाव श्रेणी	हक की इकाई	पात्रता का विवरण	टिप्पणी
			(घ विस्थापित परिवारों के (लिए 36,000 रुपये का अनुदान भत्ता)RFCTLARR अधिनियम 2013) () विस्थापित परिवारों के लिए ५०,००० रुपये का पुनर्वास भत्ता)RFCTLARR Act 2013)	
	किरायेदारों और पट्टे धारकों	किरायेदारों और पट्टे धारकों	पंजीकृत पट्टियां लागू स्थानीय कानूनों के अनुसार संरचना के मालिक को देय प्रतिकर के एक परिशोधन के लिए हकदार होंगी।	
आवासीय और वाणिज्यिक संरचनाओं का नुकसान गैर-शीर्षकधारक -				
	कब्जा करने वालों के	प्रभावित व्यक्ति (व्यक्ति/ परिवार((ए (अतिक्रमणकारियों को दिया जाएगा 2 महीने की अग्रिम सूचना जो परिसंपत्तियों फसलों को / हटाने के लिए। (b) प्रभावित संरचना से बचाव सामग्री का अधिकार	
आजीविका की हानि शीर्षक और गैर-शीर्षकधारक -				
	आजीविका का नुकसान - शीर्षक धारक, कृषि श्रम और वाणिज्यिक बोली	(व्यक्ति/ परिवार(एक बार का अनुदान 25,000 रु (मान के तहत निर्धारित RFCTLARR अधिनियम 2013)	वाणिज्यिक के लिए स्क्वाटर्स, जनगणना सर्वेक्षण की तारीख से पात्रता होगी

सुन्नी बांध जल विद्युत् परियोजना (382 MW) के लीये की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

क्र.सं.	प्रभाव श्रेणी	हक की इकाई	पात्रता का विवरण	टिप्पणी
	निर्माण के चरण के दौरान संभावित और अप्रत्याशित प्रभाव की संभावना है	स्वामी, प्रभावित व्यक्ति	यदि कोई हो, तो हर्जाना का भुगतान संरचनाएं अस्थायी पहुंच होगी जहाँ भी आवश्यक हो, प्रदान किया गया	जैसे संरचनाओं पर अस्थायी प्रभाव, पहुंच या मार्ग के लिए अस्थायी व्यवधान
	मोबाइल कियोस्क की आय का अस्थायी नुकसान, यदि कोई हो	कियोस्क मालिक	दो महीने का अग्रिम नोटिस क्षेत्र खाली करें	
	SC, ST		सरकारी मानदंड योजनाओं में शामिल करने के लिए सहायता यदि शामिल नहीं है, तो सरकारी मानदंडों के अनुसार पात्र; और RFCTLARR अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार एससी और एसटी को अतिरिक्त लाभ अनुसूची	
	प्रभावहीन प्रभाव		किसी भी अप्रत्याशित प्रभाव को अधिनियम के सिद्धांतों और उद्देश्यों के अनुसार प्रलेखित और कम किया जाएगा।	

पुनर्वास और पुनर्वास की लागत का विवरण निम्नलिखित अनुभाग में तालिकाओं में दिया गया है।

परियोजना प्रभावितों के लिए लागू कानूनी प्रावधानों की पृष्ठभूमि में पहले से ही पात्रता की रूपरेखा और पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया है। पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन की लागत का विवरणकाम किया गया है और इसे 8.3 से 8.6 तक दिया गया है।

सुन्नी बांध जल विद्युत् परियोजना (382 MW) के लीये की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

तालिका 8 3: भूमि पर अनुमानित प्रतिकर का विवरण

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
जिला	पंचायत	क्र.सं.	गांव	कुल निजी भूमि (वर्ग मीटर)	खेती की गई भूमि (वर्गमीटर)	गैर-संवर्धित भूमि (वर्ग मीटर)	संवर्धित भूमि के लिए सर्किलदर (₹ / वर्गमीटर)	गैर-संवर्धित भूमि के लिए सर्किलदर (₹ / वर्गमीटर)	संवर्धित भूमि का मूल्य (6 * 8) (₹)	गैर-संवर्धित भूमि का मूल्य (7 * 9) (₹)	निजी भूमि का कुल मूल्य रुपये में)10 + 11)	भूमि का कुल प्रतिकर ₹ में 100% सोलेटियम सहित
शिमला	चबड़ी	1.	लुन्सू	11729	0	11729	677	564	-	6,615,156	6,615,156	13,230,312
		2.	खेरा	99689	62128	37561	677	564	42,060,656	21,184,404	63,245,060	126,490,120
	करयाली	3.	जैशी	37634	24486	13148	677	564	16,577,022	7,415,472	23,992,494	47,984,988
		4.	भरारा	61109	47128	13981	677	564	31,905,656	7,885,284	39,790,940	79,581,880
	ओगली	5.	तलाह	32225	4964	27261	710	592	3,524,440	16,138,512	19,662,952	39,325,904
		6.	ओगली	47889	27058	20831	1011	842	27,355,638	17,539,702	44,895,340	89,790,680
		7.	कोठी	5522	5431	91	1011	842	5,490,741	76,622	5,567,363	11,134,726

सुन्नी बांध जल विद्युत् परियोजना (382 MW) के लीये की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
जिला	पंचायत	क्र.सं.	गांव	कुल निजी भूमि (वर्ग मीटर)	खेती की गई भूमि (वर्गमीटर)	गैर-संवर्धित भूमि (वर्ग मीटर)	संवर्धित भूमि के लिए सर्किलदर (रु / वर्गमीटर)	गैर-संवर्धित भूमि के लिए सर्किलदर (रु / वर्गमीटर)	संवर्धित भूमि का मूल्य (6 * 8) (रु)	गैर-संवर्धित भूमि का मूल्य (7 * 9) (रु)	निजी भूमि का कुल मूल्य रुपये में)10 + 11)	भूमि का कुल प्रतिरु रु में 100% सोलैटियम सहित
	बाग	8.	मलगी	85650	43407	42243	1011	842	43,884,477	35,568,606	79,453,083	158,906,166
		9.	बथोरा	38662	30923	7739	1011	842	31,263,153	6,516,238	37,779,391	75,558,782
		10.	पन्दोअ	4448	3689	759	1011	842	3,729,579	639,078	4,368,657	8,737,314
		11.	ग्रेहना	6941	6600	341	393	328	2,593,800	111,848	2,705,648	5,411,296
	मोगरा	12.	झुझन	8678	4869	3809	343	286	1,670,067	1,089,374	2,759,441	5,518,882
		13.	मजरोग	2365	1815	550	343	286	622,545	157,300	779,845	1,559,690
		14.	भौरा	29055	21295	7760	766	638	16,311,970	4,950,880	21,262,850	42,525,700
मंडी	बिन्दला	15.	Balog	17213	15983	1230	766	638	12,242,978	784,740	13,027,718	26,055,436
		16.	जक्ली न	4981	3381	1600	561	468	1,896,741	748,800	2,645,541	5,291,082

सुन्नी बांध जल विद्युत् परियोजना (382 MW) के लीये की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

जिला	पंचायत	क्र.सं.	गांव	कुल निजी भूमि (वर्ग मीटर)	खेती की गई भूमि (वर्गमीटर)	गैर-संवर्धित भूमि (वर्ग मीटर)	संवर्धित भूमि के लिए सर्किलदर (रु / वर्गमीटर)	गैर-संवर्धित भूमि के लिए सर्किलदर (रु / वर्गमीटर)	संवर्धित भूमि का मूल्य (6 * 8) (रु)	गैर-संवर्धित भूमि का मूल्य (7 * 9) (रु)	निजी भूमि का कुल मूल्य रुपये में)10 + 11)	भूमि का कुल प्रतिरु रु में 100% सोलेटियम सहित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	परलोग	17.	फफान	6308	5428	880	431	360	2,339,468	316,800	2,656,268	5,312,536
		18.	परलोग	11722	10025	1697	431	360	4,320,775	610,920	4,931,695	9,863,390
		19.	बेलुधां क	19823	18190	1633	292	243	5,311,480	396,819	5,708,299	11,416,598
	शौट	20.	खरिया ली	321	0	321	279	232	-	74,472	74,472	148,944
कुल				531,964	336,800	195,164			253,101,186	128,821,027	381,922,213	763,844,426

*स्रोत: टीम SIA

*ध्यान दें: क्योंकि हिमाचल प्रदेश क लिए प्रतिरु फैक्टर अभी निश्चित नहीं किया गया है, इसीलिए ऊपर किया गया हिसाब में इस फैक्टर को 1 माना गया है ।

भूमि की उपर्युक्त लागत एक अनुमानित क्षतिपूर्ति है जिसके लिए आवश्यक निकाय को प्रावधान करना पड़ सकता है। यह राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुसार परिवर्तन के अधीन है, लेकिन दिए गए अनुमान से कम नहीं हो सकता.

सुन्नी बांध जल विद्युत् परियोजना (382 MW) के लीये की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

तालिका 8 4: पेड़ों पर प्रतिकर का विवरण

	फलदार पेड़	गैर फलदार पेड़	कुल पेड़
अर्जन के तहत पेड़	14,824	26,691	41,515
दर	Rs. 5000/tree	Rs. 3000/tree	-
राशि (रु)	7,41,20,000	8,00,73,000	15,41,93,000

*स्रोत: टीम SIA

उपरोक्त अनुमान और पेड़ों की दर (फलदार और गैर फलदार पेड़) सक्षम प्राधिकारी द्वारा पेड़ों की गणना, सत्यापन और मूल्यांकन के अनुसार बदलने के अधीन हैं।

तालिका 8 5: पुनर्वास और पुनार्व्यस्थापन के लिए प्रतिकर

आवास इकाई के नुकसान के कारण परिवार विस्थापित हो गए	लागत का विवरण	राशि
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत एक घर प्रदान किया जाएगा। प्रत्येक परिवार को केवल एक घर मिलेगा। अगर घर के लिए चुना नहीं है, की बराबर लागत घर की पेशकश की जाएगी।	PMAY 2016 की अधिसूचना के तहत HP सरकार, के लिए भत्ता प्रत्येक घर में 1.30 लाख रुपये होंगे पहाड़ी राज्य 38x 130000 (अनुमानित = (4,680,000	4,940,000
प्रति PAF पर 5 लाख का एकमुश्त भुगतान या, वार्षिकी नीति के तहत, 20 साल के लिए प्रति परिवार 2000 / - प्रति माह	38 x 500000 = 18000000	19,000,000
प्रत्येक परिवार के लिए 3000 / - का अनुदान एक साल**	38 x 36000 = 1296000	1,368,000
एक बार की शिफ्टिंग लागत 50000 / - प्रति परिवार	38 x 36000= 1296000	1,368,000
एक बार का "रिसेटमेंट अलाउंस" 50000 / - प्रति परिवार	38 x 50000= 1800000	1,900,000
कुल अनुमान		2,85,76,000
* एससी एसटी के मामले में /, प्रत्येक परिवार को 50000 / - का अतिरिक्त एकमुश्त अनुदान दिया जाना चाहिए।		

*स्रोत: टीम SIA

उपरोक्त अनुमान लागत की गणना अधिनियम 2013 के तहत किए गए प्रावधानों के तहत की जाती हैं।

तालिका 6 8 : भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनावस्थापन के लिए कुल लागत का विवरण

क्र० सं०	लागत का विवरण	राशि
1	भूमि के लिए प्रतिकर **	763,844,426
2	प्रतिकर पर 12% ब्याज (जमीन)	91,661,331
3	पेड़ों के लिए प्रतिकर	15,41,93,000
4	पुनर्वास और पुनर्वास लागत ***	2,85,76,000
5	कुल लागत	103,82,74,757
6	विविध कुल लागत का)10%)	10,38,27,476
7	गैंड टोटल)5 + 6)	114,21,02,233
** भूमि अर्जन के प्रतिकर में खड़ी फसलों का प्रतिकर शामिल नहीं है, जिसकी गणना सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जाएगी		
*** प्रतिकर में घाटों का प्रतिकर शामिल नहीं है, जिसकी गणना सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जाएगी		

*स्रोत: टीम SIA

सर्वेक्षण के दौरान एकत्र की गई जानकारी उत्तरदाताओं के साक्षात्कार पर आधारित है और उनके द्वारा प्रदान की गई जानकारी को सत्य माना जाता है लेकिन यह स्वामित्व के अधिकार का प्रामाणिक संस्करण नहीं है। निजी अनुमानों से संबंधित कुल भूमि क्षेत्र 53.1934 हेक्टर है।, जिसके लिए क्षतिपूर्ति फार्मूले की गणना के आधार पर, अस्थायी भूमि क्षतिपूर्ति (खड़ी फसलों के प्रतिकर को छोड़कर) रु 76,38,44,426 / - तक आती है (सत्तर-छह करोड़ इकतीस लाख चालीस-चार हजार छब्बीस)। भूमि के प्रतिकर पर 12 प्रतिशत की दर से, अधिनियम 2013 की धारा 30 (3) के अनुसार भुगतान के लिए 9,16,61,331 / - की राशि का अनुमान लगाया गया है।

पेड़ों के प्रतिकर का अनुमान 15,41,93,000 / - है। हालांकि, पेड़ों की संख्या की गणना की जाएगी और सक्षम अधिकारियों द्वारा वास्तविक मूल्य का आकलन किया जाएगा।

भूमि अर्जन के प्रतिकर के अनुमान में खड़ी फसलों का प्रतिकर शामिल नहीं है। फसलों के खिलाफ नकद प्रतिकर औसत उत्पादन के आधार पर परिपक्व फसलों की बाजार लागत पर प्रदान किया जाएगा।

R&R खर्चों के लिए पात्रता कुल मिलाकर रु 2,85,76,000/- है। R&R सहित भूमि अर्जन की कुल लागत अनुमानित है रु 114,21,02,233/- है। हालांकि, भूमि अर्जन और संरचनाओं के लिए अंतिम प्रतिकर राशि अधिनियम 2013 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की जाएगी। इसके अलावा, उक्त गणना में शमन योजना की लागत को शामिल नहीं किया गया है।

8.5 आवश्यक निकाय द्वारा दिए गए उपाय

आवश्यक निकाय द्वारा साझा की गई कोई योजना नहीं है।

8.6 पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजना के कार्यान्वयन के लिए संस्थागत व्यवस्था

अधिनियम 2013 के अनुसार, जहां अधिगृहीत की जाने वाली भूमि 100 एकड़ से अधिक के बराबर है, सरकार कलेक्टर की अध्यक्षता में एक "पुनर्वास और पुनर्वास समिति" का गठन करेगी। इस समिति का उद्देश्य पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजनाओं या योजना के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करना और ग्राम सभा के परामर्श से कार्यान्वयन के बाद के सामाजिक अंकेक्षण को अंजाम देना है।

उसके बाद कार्यान्वयन और सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया में शामिल होने वाले सदस्य निम्नानुसार हो सकते हैं:

1. प्रभावित क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं का प्रतिनिधि।
2. प्रभावित क्षेत्र में रहने वाली एससी आबादी का एक प्रतिनिधि।
3. क्षेत्र में काम करने वाले एक स्वैच्छिक संगठन (एनजीओ) का प्रतिनिधि।
4. परियोजना का भूमि अर्जन अधिकारी।
5. प्रभावित क्षेत्र के पंचायत अध्यक्ष या उनके नामित / अध्यक्ष। /
6. संसद सदस्य और असंबद्ध क्षेत्र की विधानसभा के सदस्य या उनके सदस्य, ग्राम पंचायत प्रधान)
7. आवश्यक शरीर का एक प्रतिनिधि।
8. R&R के संयोजक के रूप में प्रशासक।

8.7 शिकायत निवारण समिति (G.R.C)

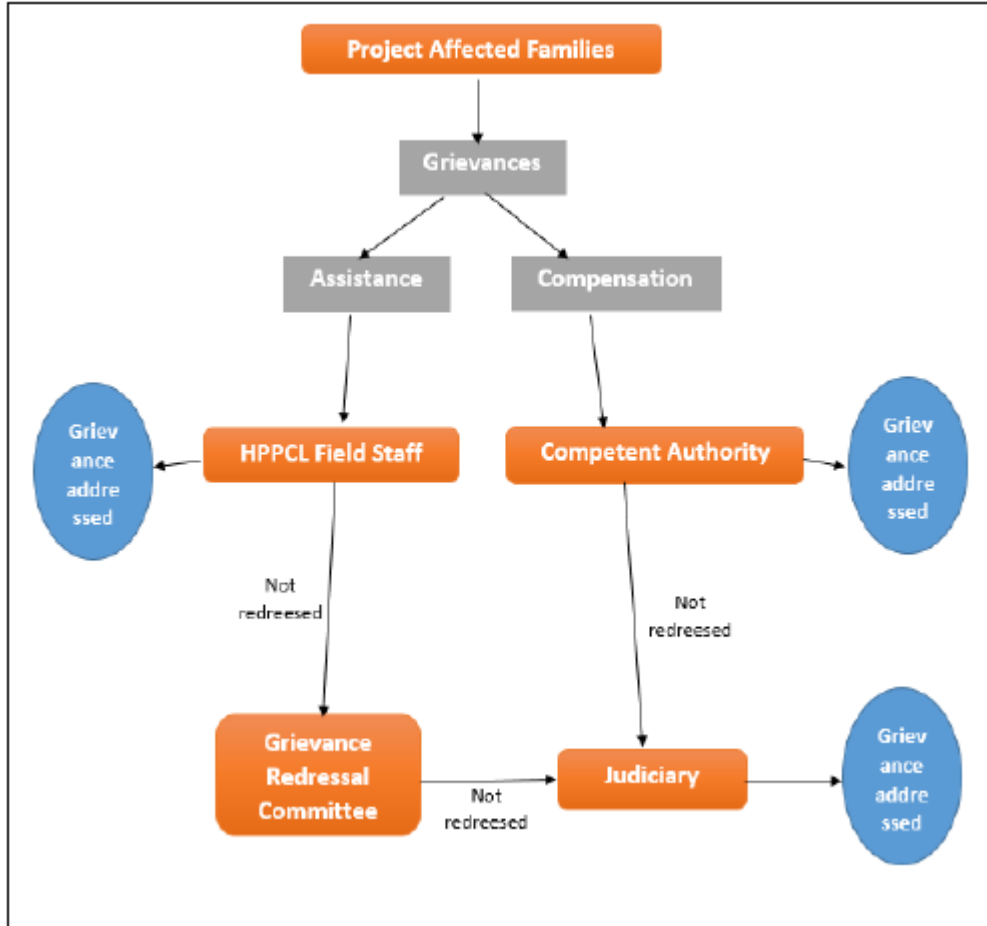
PAF की सहायता के लिए उनकी जिज्ञासाओं और शिकायतों को सुलझाने के लिए कुशल शिकायत निवारण तंत्र विकसित किया जाएगा। PAF की शिकायतों को पहले परियोजना के क्षेत्र स्तर के अधिकारियों के ध्यान में लाया जाएगा। यदि उनके द्वारा निवारण ना हो तो शिकायतों को शिकायत निवारण समिति (जीआरसी)

में लाया जाएगा। प्रस्तावित जीआरसी की संरचना R&R समिति के समान हो सकती है। यह समिति मासिक आधार पर मिल सकती है या राज्य सरकार द्वारा मामले को परिभाषित किया जा सकता है।

G.R.C की मुख्य जिम्मेदारियां हो सकती हैं:

- I. भूमि संपत्ति /अर्जन से उत्पन्न समस्याओं पर PAFको सहायता प्रदान करें ;
 - II. PAF की शिकायतों को रिकॉर्ड करें, शिकायतों को वर्गीकृत करें और प्राथमिकता दें और उन्हें हल करें; तथा,
 - III. जीआरसी की उनकी शिकायतों और निर्णयों के बारे में घटनाक्रम पर PAF को रिपोर्ट करें।
- कानून की अदालत के तहत मालिकाना हक से संबंधित विवादों के अलावा, जीआरसी सभी पुनर्वास लाभों, प्रतिकर, पुनर्वास, प्रतिस्थापन लागत और अन्य सहायता से संबंधित शिकायतों की समीक्षा करेगी। जब किसी भी शिकायत को क्षेत्र स्तर के अधिकारियों के पास लाया जाता है, तो उसे शिकायत की तारीख से 15 दिनों के भीतर हल किया जाना चाहिए। जीआरसी हर महीने (यदि शिकायत समिति के पास लाई जाती है) मिलेंगे, प्रत्येक शिकायत की योग्यता का निर्धारण करेंगे, और शिकायत प्राप्त होने के एक महीने के भीतर शिकायतों का समाधान करेंगे - जिसे विफल करते हुए, शिकायत को निवारण के लिए उपयुक्त विधि न्यायालय में भेजा जाएगा। प्राप्त होने वाली सभी शिकायतों का रिकॉर्ड रखा जाएगा: शिकायत का विवरण, शिकायत की तारीख, शिकायत की प्रकृति, सुधारात्मक कार्रवाइयाँ और इन तारीखों से प्रभावित थे, और अंतिम परिणाम। शिकायत निवारण तंत्र का प्रवाह चार्ट नीचे चित्र में दर्शाया गया है:

चित्र 3: शिकायत निवारण तंत्र



* स्रोत: SIA टीम

8.7.1 शिकायत निवारण के चरण

8.7.1.1 निगरानी और मूल्यांकन

SIMP कार्यान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन आवश्यक है क्योंकि गतिविधियों को कई एजेंसियों द्वारा समयबद्ध तरीके से निष्पादित किया जाना है। मॉनिटरिंग में यह पता लगाने के लिए समय समय पर-जाँच शामिल है कि क्या कार्यक्रम अनुसूचीप्रगति कर रहे हैं, जबकि मूल्यांकन SIMP के प्रदर्शन का आकलन करना है। इस प्रयोजन के लिए, परियोजना अधिकारियों को प्रतिक्रिया देने के लिए एक निगरानी

और मूल्यांकन योजना विकसित करने की आवश्यकता है। R&R की निगरानी और मूल्यांकन R&R उद्देश्यों, रणनीतियों और दृष्टिकोणों की सफलता को प्रतिबिंबित करने और R&R गतिविधियों, उनके प्रभाव और स्थिरता के कार्यान्वयन में दक्षता और प्रभावकारिता का आकलन करने का अवसर देता है। निगरानी परियोजना प्रभावित कमजोर परिवारों और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, BPL परिवारों, महिलाओं के नेतृत्व वाले घरों, विधवाओं, वृद्धों और शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों जैसे समूहों पर विशेष ध्यान देगी। SIMP कार्यान्वयन के मध्य और अंतिम अवधि के मूल्यांकन के लिए तीसरे पक्ष के माध्यम से एक स्वतंत्र मूल्यांकन भी आवश्यक है।

8.7.1.2 आंतरिक निगरानी

SIMP कार्यान्वयन के लिए आंतरिक निगरानी परियोजना अधिकारियों द्वारा की जाएगी जहां मुख्य उद्देश्य SIMP अनुसूची के खिलाफ प्रगति की रिपोर्ट करना होगा; प्रभावित परिवारों और लोगों को पूर्ण रूप से वितरित पात्र ताकी जाँच करें; SIMP कार्यान्वयन से उत्पन्न कि सीभी समस्या, समस्या या कठिनाई की पहचान करना और सुधारात्मक कार्रवाई करना; शिकायत प्रणाली की प्रभावशीलता की निगरानी करें और PAF की संतुष्टि को मापें। आंतरिक निगरानी SIMP में परिभाषित कार्यों की अनुसूची के खिलाफ प्रगति को मापने पर ध्यान केंद्रित करेगी। परियोजना अधिकारियों द्वारा की जाने वाली गतिविधियों में भूमि अर्जन टीम, निर्माण एजेंसियों और परियोजना प्रभावित समुदायों के साथ संपर्क और प्रगति की समीक्षा करना शामिल होगा; SIMP के अनुसार पात्रता के विरुद्ध भूमि अर्जन प्रतिकर वितरण का सत्यापन; पीएफ की आय और जीवनस्तर को बहाल करने के लिए सहमत उपायों के कार्यान्वयन का सत्यापन; पुनर्वास समस्याओं से उत्पन्न किसीभी समस्या, मुद्दे या कठिनाई की पहचान; पुनर्वास प्रभावित परिणामों के साथ परियोजना प्रभावित परिवारों और लोगों की संतुष्टि का आकलन करें; और PAF की शिकायतों का निवारण करने के लिए उस उपयुक्त सुधारात्मक कार्यों का पालन करना। SIMP कार्यान्वयन के प्रभारी HPPCL के फील्डस्तर के अधिकारी R&R प्रगति को ट्रैक करेंगे। इस उद्देश्य के लिए, सुझाए गए संकेत नीचे तालिका में दिए गए हैं।

तालिका 8-7 :SIMP प्रगति की निगरानी के लिए संकेतक

1	भौतिक	अर्जित भूमि की संख्या, ध्वस्त संरचनाओं की संख्या, परिवारों की संख्या प्रभावित, भूमि खरीदने वाले परिवारों की संख्या और खरीदी गई भूमि की सीमा, PAF की सहायता /प्रतिकरप्राप्त करने की संख्या , प्रदान की गई PAF की संख्या परिवहन सुविधाओं स्थानांतरण भत्ता /, सरकारी भूमि की पहचान की सीमा
---	-------	--

सुन्नी बांध जल विद्युत् परियोजना (382 MW) के लीये की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

		घर साइटों के लिए, भूमि उपयोगकर्ताओं और निजी संरचना मालिकों की संख्या ने प्रतिकर का भुगतान किया
2	वित्तीय	भूमि संरचना के लिए /प्रतिकरकी राशि , स्थानांतरण के लिए नकद अनुदान, PAF के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए भुगतान की गई राशि।
3	सामाजिक	PAF अपने अधिकारों, सांप्रदायिक सद्भाव, रुग्णता और के बारे में जान रखता है मृत्यु दर, कमजोर आबादी की देखभाल आदि।
4	आर्थिक	हकदार परिवारों को प्रदान की गई नौकरियों की संख्या, व्यवसाय की संख्या फिर से स्थापित, प्रतिकर का उपयोग, घर साइटों व्यापार /साइटों को खरीदा आय बहाली योजनाओं का सफल क्रियान्वयन
5	शिकायत	सामुदायिक स्तर की बैठक की संख्या, शिकायत निवारण बैठकों की संख्या की संख्या, परियोजना अधिकारियों द्वारा संतुष्टि के लिए निपटाए गए मामलों की संख्या, PAF, संबंधित अधिकारियों द्वारा संदर्भित और संबोधित शिकायतों की संख्या

*स्रोत: टीम SIA

8.7.1.2.1 स्वतंत्र मूल्यांकन

एक स्वतंत्र मूल्यांकन एजेंसी को निम्नलिखित प्राप्त करने के लिए मध्य और अंतिम अवधि के मूल्यांकन के लिए परियोजना द्वारा काम पर रखा जा सकता है: (a) आंतरिक निगरानी के परिणामों को सत्यापित करना; (b) मूल्यांकन करें कि क्या पुनर्वास उद्देश्यों को पूरा किया गया है, विशेष रूप से, क्या आजीविका और जीवन स्तर को बहाल किया गया है; (c) पुनर्वास क्षमता, प्रभावशीलता, प्रभाव और स्थिरता का आकलन; (d) यह पता लगाना कि क्या पुनर्वास पात्रता उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उपयुक्त थी और (तुलना) जीवन स्तर की यह तुलना उपलब्ध आधारभूत जानकारी के संबंध में होगी। SIMP के बाह्य मूल्यांकन में संकेतक के लिए निम्न तालिका को आधार माना जाना चाहिए।

तालिका 8 8 परियोजना के मूल्यांकन के संकेतक

क्र० सं०	उद्देश्य	खतरे	परिणाम
1	परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों पर नकारात्मक प्रभाव कम से कम होगा	पुनर्वास योजना के कार्यान्वयन में	प्रतिकर की सहायता से भूस्वामियों की संतुष्टि। भूस्वामियों द्वारा प्रतिकर और सहायता के उपयोग का प्रकार प्रतिकर और उत्पीड़न के साथ संरचना के मालिकों की संतुष्टि

सुन्नी बांध जल विद्युत् परियोजना (382 MW) के लीये की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

क्र० सं०	उदेश्य	खतरे	परिणाम
		प्रत्याशित से अधिक समय लग सकता है	संरचना मालिकों द्वारा प्रतिकर और सहायता के उपयोग का प्रकार
2	परियोजना के लिए संपत्ति खोने वाले व्यक्तियों और परिवारों को अधिनियम और नियमों के अनुसार प्रतिकर दिया जाएगा	संस्थागत व्यवस्था अपेक्षा के अनुरूप कुशलतापूर्वक कार्य नहीं कर सकती है	PAF के प्रतिशत ने केवल आर्थिक गतिविधि के रूप में हासिल किए गए कौशल को अपनाया। PAF के प्रतिशत ने माध्यमिक आर्थिक गतिविधि के रूप में हासिल किए गए कौशल को अपनाया
3	प्रभावित व्यक्तियों और परिवारों को सुधारने में सहायता की जाएगी या उनके जीवन स्तर को पुनः प्राप्त करना	SIMP को लागू करने वाले अधिकारी कार्य निष्पादित नहीं कर सकते हैं उम्मीद के मुताबिक कुशलता से	PAF के प्रतिशत में वृद्धि के कारण आय में वृद्धि की सूचना है, PAF के प्रतिशत को उनकी पसंद के कौशल में प्रशिक्षित किया गया कौशल सुधार के लिए चयनकर्ता में PAF की मदद करने में परियोजना अधिकारियों की भूमिका एक समय के आर्थिक पुनर्वास अनुदान के तहत PAF को प्रदान की जाने वाली उत्पादक परिसंपत्तियों का उपयोग
4	दुर्बल समूहों की पहचान की जाएगी और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने में सहायता की जाएगी	PAF के नीचे गिरने की अप्रत्याशित संख्या में शिकायतें आ सकती हैं उनके मौजूदा जीवन स्तर	दुर्बल समूह द्वारा अतिरिक्त सहायता राशि के उपयोग का प्रकार प्राप्त शिकायतों के प्रकार शिकायत के लिए अग्रेषित शिकायतों की संख्या निवारण समिति (जीआरसी) और हल करने में लगने वाला समय) PAF के प्रतिशत के बारे में अवगत कराना जीआरसी तंत्र के बारे में PAF के प्रतिशत को पात्रता के बारे में पता है परियोजना अधिकारियों के दृष्टिकोण और पहुंच के बारे में PAF की राय

* स्रोत :टीम SIA

9 सन्दर्भ

- अग्रवाल, (m.n.d) भारत में दुर्बल समूह- स्थिति, योजनाएँ, भारत का संविधान।
- प्राधिकरण, सी। ई। (2015)। हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्कीमों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए दिशानिर्देश, सहमति के लिए उनकी स्वीकृति और परीक्षा। नई दिल्ली ।
- (2011)। जनगणना।
- कंपनी प्रोफाइल: SJVN Limited (२०१ ९, फरवरी)। SJVN Limited वेब साइट से प्राप्त किया गया: www.sjvn.nic.in
- एमपीपी और पावर विभाग, जी। ओ। (2019)। अधिसूचना, सुन्नी HEP परियोजना।
- हिमाचल प्रदेश वन मंजूरी: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। (२०१ ९, फरवरी)। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से प्राप्त: <http://forestsclearance.nic.in/viewreport.aspx?pid=FP/HP/HYD/31019/2017>
- (एन.डी.)। भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम, 2013 में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार।
- SJVNLI (2017)। इनसाइट रिपोर्ट (संशोधित), SUNNI HEP की पर्यावरणीय सफाई।
- SJVNLI (2018)। सुन्नी HEP (382 मेगावाट) की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के लिए स्थापना।
- (एन.डी.)। हिमाचल प्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन (सामाजिक समाघात निर्धारण और सहमति) नियम, 2015 में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार।

सुन्नी बांध जल विद्युत् परियोजना (382 MW) के लीये की जा रही प्रस्तावित भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ।

10 अनुलग्नक